January 2021

IASBABA'S MONTHLY MAGAZINE

- महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद
- इकोनॉमिक सर्वे 2020-21
- 2021 में जलवायु परिवर्तन और भारत
- COVID-19 टीकाकरण अभियान

प्रस्तावना

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षा प्रारूप में वर्तमान बदलाव के साथ, सामान्य अध्ययन-II और सामान्य अध्ययन III को साधारणतः समसामसयकी सेप्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा, यूपीएससी की हालिया प्रवृत्ति के अनुसार, लगभग सभी प्रश्न समाचार-आधारित होने के बजाय मुद्दों पर आधारित हैं। इसलिए, तैयारी के लिए सही दृष्टिकोण केवल समाचार पढ़ने के बजाय मुद्दों को तयैार करना है।

इसे ध्यान में रखते हुए, हमारी वेबसाइट **www.iasbaba.com**दैनिक आधार पर मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए वर्तमान मामलों को कवर करती है। यह आपको विभिन्न राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों जैसे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइवमिंट, बिजनेस लाइन और अन्य महत्वपूर्ण ऑनलाइन स्रोतों से दिन के प्रासंगिक समाचार प्राप्त करने में मदद करेगा। समय के साथ, इनमें से कुछ समाचार प्रसंग महत्वपूर्ण मुद्दे बन जाएंगे।

UPSC ऐसे मुद्दों से सम्बंधित प्रश्न और इन पर सामान्य राय पर आधारित प्रश्न पूछती है। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए सामान्य जागरूकता और मुद्दे की समग्र समझ की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम उम्मीदवारों के बीच सही समझ पैदा करना चाहते हैं – 'इन मुद्दों को कैसे कवर किया जाए?

यह IASbaba की मासिक पत्रिका का 68 वां संस्करण है। यह संस्करण उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करता है जो NOVEMBER-2020 के महीने में खबरों में थे, जिन्हें **https://iasbaba.com/current-affairs-for-ias-upsc-exams/**से भी एक्सेस किया जा सकता है।

IASBABA से VALUE ADDITIONS

- Think और Connectng the dots अवश्य पढ़ें और कनेक्ट करें।
- इसके अलावा, हमने Prelim और mains पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्निsnippets और टेस्ट योर नॉलेज (दैनिक करंट अफेयर्स पर आधारितPrelims MCQs) प्रस्तुत किया हैं जो आपको बेहतर revisionके लिए मार्गदर्शन करेंगे।
- '**Must Read' section,**आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करेगा कि, आप दैनिक आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों से किसी भी महत्वपूर्ण समाचार / संपादकीय को याद नहीं करेंगे।
- प्रत्येक समाचार लेख के तहत, **Connectng the dots**एक मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर जुड़ने और विचार करने की आपकी सोच को सुविधाजनक बनाता है। मूल रूप से, यह आपको बहु-आयामी दृश्य-बिंदु से एक मुद्दे को समझने में मदद करता है। आप मेन्स या इंटरव्यू देते समय इसके महत्व को समझेंगे।

'**Must Read' section**: हमने उन्हें पत्रिका में शामिल नहीं किया है। दैनिक आधार पर DNA का अनसुरण करने वाले इसका अनुसरण कर सकते हैं-

https://iasbaba.com/current-affairs-for-ias-upsc-exams/

"Tell my mistakes to me not to others, because these are to be corrected by me, not by them."

इतिहास / संस्कृति / भूगोल

- समाचार में स्थल: रामतीर्थम मंदिर
- मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाई जा रही है
- जल्लीकट्टू: गर्व और राजनीति
- समाचारों में मंदिर: गवी गंगाधरेश्वर मंदिर
- कलारिपयट्टू को केरल पर्यटनद्वारा वेल्लार शिल्प ग्राम के तर्ज पर पढ़ाया जाएगा
- नव अनुभव मंडप
- माउंट सेमरू में ज्वालामुखी विस्फोट
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) नए मानसून मॉडल पेश कर सकता है
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है
- त्रिपुरा सरकार ने टेक्सटाइल रूप में रीसा को बढ़ावा देने की योजना बनाई है
- श्री नारायण गुरु की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद का उद्घाटन
- भारतीय बोडो सामाजिक कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि दी गयी
- धनीपुर मस्जिद परियोजना का शुभारंभ
- मंजम्मा जोगती: पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित जिन्होंने ग्रामीण लोक कलाओं कोलोक प्रिय बनाया
- असम में पथराघाट विद्रोह

नीति / शासन

- खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा के स्तर के लिए स्लैश सीमा
- COVID-19 वैक्सीन ड्राई रन
- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण कानून की स्थिति को स्पष्ट किया
- जी किशन रेड्डी समिति ने गठन किया
- पशु क्रूरता की रोकथाम के लिए (मामला संपत्ति जानवरों की देखभाल और रखरखाव) नियम, 2017 पर SC का आदेश
- केंद्र एजीएमयूटी के साथ जम्मू और कश्मीर कैडर के अधिकारियों को शामिल किया
- बागसारा प्रान्त: गुजरात में निर्मित नवीन जिला
- पुडुचेरी में सत्ता का बिगुल: उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच
- SC ने फार्म कानून समिति का गठन किया
- मणिपुर स्थानीय शहरी निकाय सुधारों को पूरा करने वाला चौथा राज्य बना

- विवाह के सूचना का प्रकाशन अनिवार्य नहीं
- रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा)
- IBC की धारा 32A
- गणतंत्र दिवस पर हिंसा
- महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

सामाजिक मुद्दें और वेलफेयर

- हनी मिशन में लगे प्रवासी श्रमिक
- भारत का अनुदैर्ध्य एजिंग अध्ययन (LASI) वेव -1, भारत रिपोर्ट जारी
- महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मासिक धर्म महिलाओं के लिए पीरियड रूम सेट स्थापित किया गया
- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 3.0) का तीसरा चरण
- मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM)
- जाति और जनगणना के आसपास एक नई रूपरेखा
- परेशान करने वाले रुझान: असमानता में वृद्धि
- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21: शिक्षा
- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21: कौशल विकास

महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे

- गृहकार्य के लिए वेतन
- यौन हिंसा के लिए दंडात्मक प्रतिक्रिया की जरूरत है
- विकलांग महिलाएं

स्वास्थय

- भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया (INSACOG) लॉन्च
- चार राज्यों में काला अजार की स्थिति की समीक्षा
- ZyCoV-D: COVID -19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित डीएनए वैक्सीन
- देश में एवियन इन्फ्लुएंजा की स्थिति
- COVID-19 टीकाकरण अभियान के पैन इंडिया रोलआउट को शुरू करने के लिए पीएम
- भारत में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक के प्रबंधन में टेलीमेडिसिन उपयोग के लिए रूपरेखा
- राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण (NNMS)

- आयू संवद: सबसे बड़ा जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम
- विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD) दिवस
- परमाणु दवाओं के उत्पादन के लिए प्रथम पीपीपी अनुसंधान रिएक्टर
- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21: स्वास्थ्य

सरकारी योजनाएँ

- स्कूल बैग नीति, 2020
- खबर में जगह: IIM संबलपुर
- प्रधान मंत्री आवास बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) सफलतापूर्वक 5 साल के संचालन को पूरा करती है
- विनियामक अनुपालन पोर्टल शुरू किया

अंतरराष्ट्रीय

- संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)
- GIBRALTAR (यूके-स्पेन डील)
- वियतनाम ने पहली बार भारत से चावल का आयात किया
- कैबिनेट ने "निर्दिष्ट कुशल कार्यकर्ता" में भारत और जापान के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी
- समाचार में स्थल: हजार द्वीप
- खाड़ी को पाटना: खाड़ी में सुलह शिखर सम्मेलन
- Apple, Amazon और Google द्वारा Parler को निलंबित कर दिया गया
- समाचार में स्थल: भारत ने साहेल और लेक चाड क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है
- यूएस के संचार निर्णय अधिनियम की धारा 230
- भारत - सिंगापुर रक्षा मंत्रियों का 5 वां संवाद
- टेक दिग्गज बनाम रेगुलेटर
- यूएस फिलिस्तीन के साथ संबंधों को बहाल किया है
- अंतरसरकारी वार्ता ढांचा (IGN)
- भविष्य निवेश पहल मंच
- WEF के सामान्य ट्रस्ट नेटवर्क द्वारा क्रॉस बॉर्डर गतिशीलता को बहाल करना

भारत और विश्व

- एडीबी, भारत हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए $ 10 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किया
- भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की तीन प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा।
- नेपाल में राजनीतिक संकट
- 2020 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सार्क का पुन: प्रवर्तन
- भारत और यूएई के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग हेतु समझौते को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
- आईसीटी में भारत-जापान समझौता ज्ञापन
- भारत-नेपाल विकास
- भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों का मुद्दा
- 2021: हरित वातावरण की दिशा में भारत-फ्रांस के गठबंधन का वर्ष
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए रूपरेखा
- भारत के वस्त्र मंत्रालयऔर एम/एसनिसेनकेन क्वालिटी इवैल्युएशन सेंटर जापान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
- भारत-जीसीसी संबंध
- स्टार्स परियोजना को वित्तीय मदद के लिए डीईए और विश्व बैंक में समझौता

अर्थव्यवस्था

- भारत ने मोरिंगा पाउडर का निर्यात शुरू किया
- ब्रिटेन ने मासिक धर्म उत्पादों पर 'टैम्पोन टैक्स' को समाप्त कर दिया है।
- RBI द्वारा डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (DPI)
- बैंकिंग स्वास्थ्य: एनपीए और सीओवीआईडी -19
- जम्मू और कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना (जम्मू और कश्मीर आईडी, 2021) को मंजूरी दी
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2020-21 के लिए जीडीपी के अग्रिम अनुमान जारी
- स्पेक्ट्रम नीलामी
- 'मेरा गाँव मेरा गौरव' ड्राइव
- जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (RBIA) ढांचा
- भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना
- कॉलेज ऑफ़ सुपरवाइज़र्स (COS) के लिए शैक्षणिक सलाहकार परिषद की स्थापना
- कानूनी इकाई पहचानकर्ता (LEI) का परिचय

- K-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी
- नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड (NEVF) स्टार्ट-अप्स और युवा उद्यमियों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है
- बीएसएनएल और एमटीएनएल ईबीआईटीडीए को सकारात्मक बना दिया है।
- कोयला खनन के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल लॉन्च किया गया
- आरबीआई वर्किंग ग्रुप डिजिटल लेंडिंग पर गठित
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा
- लौह-अयस्क नीति 2021
- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट: RBI की चेतावनी
- ओपन स्काई संधि से अलग हुआ रूस
- फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर
- एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक
- बैड बैंक
- मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (MII)
- रसद पर राज्यों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन
- SBI ने विदेश में बॉन्ड बिक्री से जुटाए 60 करोड़ डॉलर
- राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद
- भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण
- पावर सब्सिडी
- RBI SBI, ICICI और HDFC बैंकों को। TO BIG TO FAIL 'बैंकों के रूप में बरकरार रखता है
- RBI ने NBFC के लिए एक कठिन नियामक ढांचा सुझाया है
- ग्रीन बांड जारी करने की लागत अन्य बांडों की तुलना में अधिक होती है
- संकट के समय में बजट

कृषि

- कैबिनेट ने इथेनॉल आसवन क्षमता को बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दी
- मेघालय में नॉर्थ ईस्ट का पहला विशिष्ट "जिंजर" प्रोसेसिंग प्लांट पुनर्जीवित किया जा रहा है
- किसानों की मदद के लिए, सही दृष्टिकोण एफपीओ के माध्यम से है, एपीएमसी मंडियों 139 के माध्यम से नहीं
- कृषि के लिए सरकार के समर्थन की तुलना
- गुणवत्तायुक्त धनिये के उत्पादन एवं इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ऑफ कोरिऐन्डर वेबिनार आयोजित

- छोटे किसानों को आय का दूसरा स्रोत
- असम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एरी सिल्क प्रदान किया जाएगा
- कृषि कानून, उनकी संवैधानिक वैधता, और उम्मीद
- ज्वार निर्यातकों के साथ वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन
- केन्या के कृषि प्रयोग से सबक
- राजस्थान में पोटाश के समाधान खनन की व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए
- सीसीईए वर्ष 2021 के लिए कोपरा के एमएसपी के लिए अपनी मंजूरी देता है
- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21: कृषि

पर्यावरण प्रदूषण

- अपशिष्ट प्रबंधन: भारत के उत्तर पूर्व में शासन में सुधार
- 2021 में जलवायु परिवर्तन और भारत
- दीपोर बील में सामुदायिक मछली पकड़ने की मनाही
- 1901 से 2020 तक 8 वां सबसे गर्म वर्ष था
- यमुना नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का किया गया गठन
- सरकारने देश भर में मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए परामर्श को मंजूरी दी
- NCAVES इंडिया फोरम 2021 का आयोजन
- इलेक्ट्रिक वाहन: नॉर्वे केस स्टडी
- 30 वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) समारोह आयोजित किया गया
- भारतीय चिड़ियाघरों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई-ज़ू) फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया
- मीलवॉर्म (येलो ग्रब) यूरोप का पहला कीट खाद्य बन जाता है
- म्यूचुअल फंड (एमएफ) के लिए जोखिम-ओ-मीटर जनवरी से प्रारंभ
- सकशम: जीवाश्म ईंधन के उपभोक्ताओं के लिए एक महीने का लंबा अभियान
- वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार सार्वजनिक खरीद के लिए मॉडल निविदा
- अनुपचारित अप्रयुक्त औद्योगिक प्रवाह के अनियंत्रित वृद्धि से गुजरात की नदियों में प्रदूषण बढ़ गया है
- ड्रैगन फल
- CSIR-CMERI ने भारत के पहले एक्वा कायाकल्प संयंत्र का अनावरण किया
- भारत में खोजी गई एक दुर्लभ चींटी की दो नई प्रजातियां
- आर्कटिक नीति मसौदा

- यूएसए का नये राष्ट्रपति ने पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका की भागीदारी को पुनर्स्थापित किया
- कृषि-ऋण में, छोटे किसान अभी भी बाड़ के बाहर हैं
- यूएसए पेरिस समझौते में फिर से शामिल हो रहा है
- जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021
- समाचार में जगह: सिगुर पठार
- राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना

समाचारों में प्रजातीयां / राष्ट्रिय उद्यान

- खबरों में प्रजाति: कोलार लीफ-नोस बैट
- गंगा नदी डॉल्फिन
- लाल पांडा की दोनों प्रजातियों का भारत निवास स्थल है: ZSI
- सुंदरबन पक्षियों की 428 प्रजातियों का निवास स्थल है: ZSI

इन्फ्रास्ट्रक्चर / ऊर्जा

- कैबिनेट ने पारादीप बंदरगाह पर इनर हार्बर सुविधाओं के गहनीकरण और अनुकूलन को मंजूरी दी
- भारतीय रेलवे ने नए विस्टाडोम कोचों की 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार का सफल परीक्षण
- किया
- जम्मू और कश्मीर में रेलवे राष्ट्रीय परियोजना पर कार्य की प्रगति की समीक्षा
- एडीबी ने भारत असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 231 मिलियन $ ऋण पर हस्ताक्षर किया
- कोच्चि-मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
- सागरमाला विमान सेवा (एसएसपीएस)
- डबल स्टैक लॉन्ग हेल कंटेनर ट्रेन ऑपरेशन को हरी झंडी दिखाई गयी
- नई रेवाड़ी - डब्ल्यूडीएफसी के नए मदार खंड को हरी झंडी
- विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में जलमार्ग में सुधार के लिए $ 105 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए
- फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल
- भारतीय रेल ने स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्णिम कोणीय (डायगोनल) खंडों में 130 किमी प्रति घंटा तक गति बढ़ाई

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- कैबिनेट ने CBIC के तहत कृष्णापटनम और तुमकुरु में औद्योगिक कॉरिडोर नोड्स को मंजूरी दी
- अमेरिकी ड्रगमेकर मॉडर्न इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन (EUA) के लिए आवेदन किया

- तिहान-आईआईटी हैदराबाद
- लेह (लद्दाख) में मौसम विज्ञान (मेट) सेंटर का उद्घाटन किया
- नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव
- अंटार्कटिका में 40 वाँ भारतीय वैज्ञानिक अभियान
- ज्वार के कारण वर्षा में बाढ़ की आशंका: एक नया मापदंड
- Covid-19 के रोगियों पर 'स्वस्थ वायु' का उपयोग किया जा सकता है
- डीबीटी-टीएचएसटीआई फरीदाबाद में सीईपीआई केंद्रीकृत नेटवर्क लैब का उद्घाटन किया गया
- बायो-डाइजेस्टर प्रौद्योगिकी
- अरुणाचल प्रदेश में भारत का प्रमुख निर्माता वैनेडियम बनने की संभावना
- लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग सर्वे (लिडार) तकनीक से नई दिल्ली-वाराणसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया
- सुपरमैसिव ब्लैक होल लापता हो गया लगता है

आपदा प्रबंधन

- हिमाचल प्रदेश में जंगल की आग
- DRDO ने भू-खतरा प्रबंधन हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ फ्रेमवर्क एमओयू पर हस्ताक्षर किए

परिभाषा / आंतरिक सुरक्षा / सुरक्षा

- स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर कंटेनर SAHAYAK-NG
- भारतीय सेना में स्वदेशी ब्रिजिंग प्रणाली का निर्माण
- भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 10 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम की आपूर्ति के लिए MoD ने बीईएल के साथ अनुबंध किया
- बीईएल ने भारतीय नौसेना के साथ स्वदेशी रूप से विकसित लेजर डैजलर्स की प्रारंभिक आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
- MARCOS को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया जा रहा है
- एलसीए तेजस की खरीद को मंजूरी
- भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 9 मिमी मशीन पिस्तौल
- भारतीय सेना ने विचार-पत्र के साथ $ 20 मिलियन का अनुबंध किया है
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को सौंप दिया है
- स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन (SAAW

विविध

January 2021 महीने के करेंट अफेयर्स MCQs की उत्तरकुंजी

विषय वस्तु

इतिहास / संस्कृति / भूगोल

समाचार में स्थल: रामतीर्थम मंदिर

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-I- संस्कृति

समाचार में-

- हाल ही में, 16 वीं शताब्दी के कोदंडाराम स्वामी मंदिर परिसर में स्थित रामतीर्थम मंदिर के अन्दर स्थित भगवान राम की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, जिसके कारण इसे समाचारों में देखा गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य

- विजयनगरम से 12 किमी की दूरी पर स्थित ऐतिहासिक रामतीर्थम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति को 29 दिसंबर को खंडित कर दिया गया था।
- यह आंध्र प्रदेश में स्थित है।
- चांदी के कवच में भगवान रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों को इस मंदिर में देखा जा सकता है।

मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाई जा रही है

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-I- संस्कृति

समाचार में-

- राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पौष के त्योहारों की पूर्व संध्या पर सभी नागरिकों को बधाई दी है
- इन त्योहारों को पूरे भारत में विविध प्रकार से मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर में देवता सूर्य के संदर्भ भारत का प्रमुख पर्व है।
- मकर संक्रांति सौर चक्रों के अनुसार मनाया जाता है।
- वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के चौदहवें या पन्द्रहवें दिन ही पड़ता है, इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है।
- कुछ क्षेत्रों में उत्सव चार दिनों तक चल सकते हैं और इसके अनुष्ठानों में बहुत भिन्नता हो सकती है।
- मकर संक्रान्ति (मकर संक्रांति) मकर संक्रांति (संक्रान्ति) पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है।
- इसे फसल महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है।

क्या आप जानते है?

एक ही त्योहार के विभिन्न नाम

- मकर संक्रांति - ओडिशा, महाराष्ट्र-गोवा, आंध्र-तेलंगाना, केरल और अधिकांश उत्तर भारत
- **पौष परबोन** - बंगाल
- **पोंगल** - तमिलनाडु
- **भोगली बिहू** - असम
- **लोहड़ी** - पंजाब और जम्मू
- **माघी** - हरियाणा और हिमाचल
- **खिचड़ी पर्व** - बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से

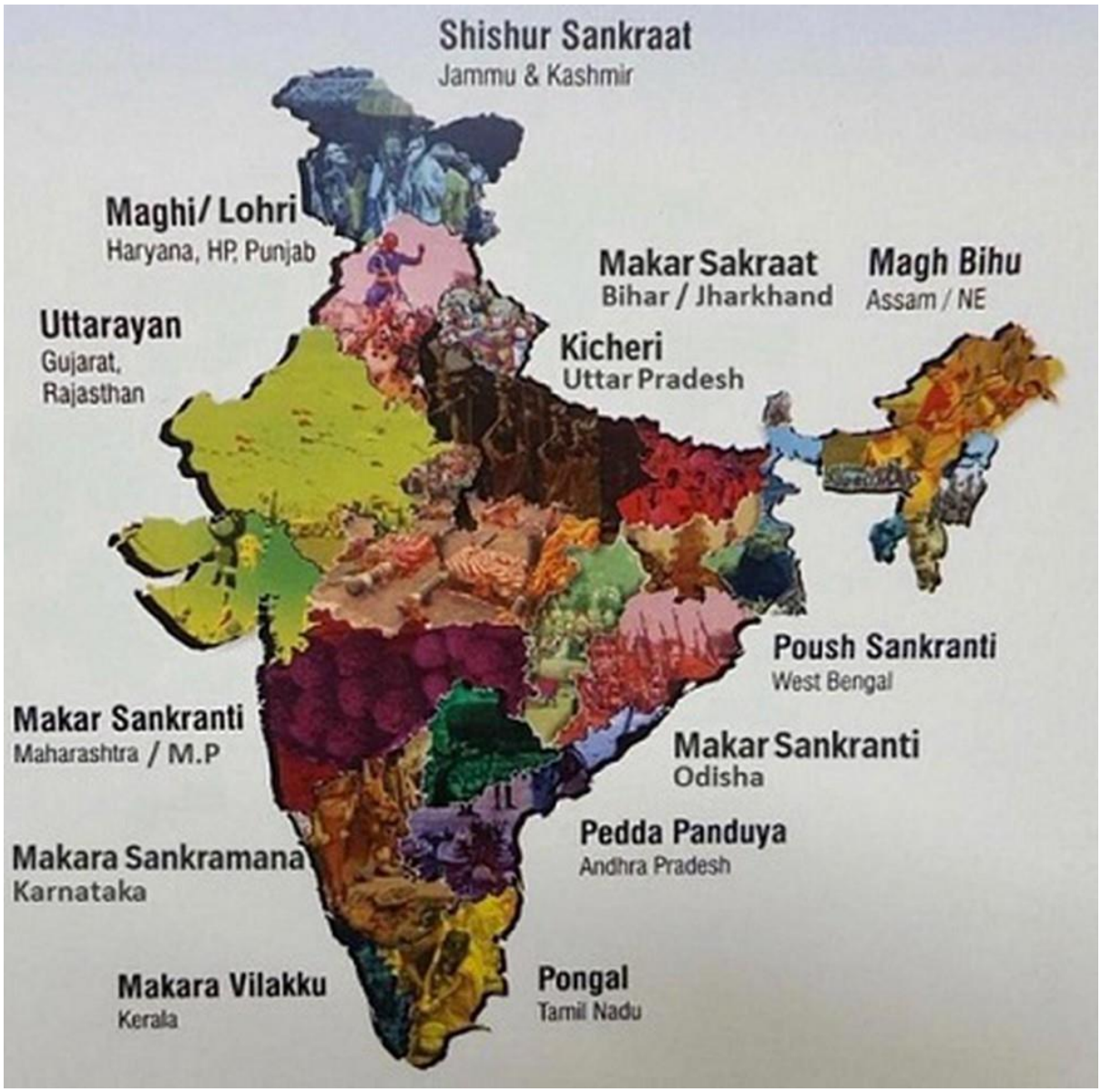

जल्लीकट्टू: गर्व और राजनीति

संदर्भ: तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के लिए\ पोंगल उत्सव और जल्लीकट्टू -पारंपरिक बुल-टैमिंग खेल ने राजनीतिक दलों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। चुनावों से पहले इन सांस्कृतिक उत्सव को मनाने के प्रयासों में, दोनों राष्ट्रीय दलों ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है।

जल्लीकट्टू क्या है?

- 2,000 साल पुरानी एक परंपरा जल्लीकट्टू, एक प्रतिस्पर्धी खेल है और साथ ही साथ इसके द्वारा सांड मालिकों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है, जो इन सांडों को पाल-पोषकर, उनके उच्च नस्लों का आनुवांशकीय संरक्षण प्रदान करते हैं। यह एक हिंसक खेल है जिसमें प्रतियोगी, पुरस्कार के लिए बैल को वश में करने का प्रयास करते हैं, यदि वे असफल होते हैं, तो ऐसी स्थिती में बैल मालिक पुरस्कार जीतता है।
- सांड को वश में करने (bull-taming) का यह खेल मदुरै, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुक्कोट्टई और डिंडीगुल (Madurai, Tiruchirappalli, Theni, Pudukkottai and Dindigul) जिलों में लोकप्रिय है ,जिसे जल्लीकट्टू के क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है।
- जल्लीकट्टू, तमिल फसल त्योहार, पोंगल के समय जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है।

तमिल संस्कृति में जल्लीकट्टू क्यों महत्वपूर्ण है?

- **मूल नस्लों का संरक्षण:** जल्लीकट्टू को किसान समुदाय के लिए अपने शुद्ध नस्ल के सांडों के संरक्षण का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है।
- वध को रोकता है: ऐसे समय में जब मवेशी प्रजनन अक्सर एक कृत्रिम प्रक्रिया होती है, संरक्षणवादियों और किसानों का तर्क है कि जल्लीकट्टू इन नर पशुओं की रक्षा करने का एक तरीका है जो अन्यथा केवल मांस के लिए उपयोग किया जाता है। जल्लीकट्टू को, किसान समुदाय द्वारा अपनी शुद्ध नस्ल के सांडों को संरक्षित करने का एक पारंपरिक माध्यम माना जाता है।
- **प्रीमियम नस्लों के पालन-पोषण से सम्बंधित :** जल्लीकट्टू के लिए प्रयोग की जाने वाली लोकप्रिय देशी मवेशी नस्लों में कंगायम**,** पुलिकुलम**,** उमबलाचेरी**,** बारुगुर और मलाई मडु (Kangayam, Pulikulam, Umbalachery, Barugur and Malai Maadu) सम्मिलित हैं।

जल्लीकट्टू कानूनी लड़ाई का विषय क्या है?

- भारत में, 1990 के दशक की शुरुआत में पशु अधिकारों के मुद्दों के करंद कानूनी लड़ाई सामने आई।
- 1991 में पर्यावरण मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन में भालू, बंदर, बाघ, पैंथर और कुत्तों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे भारतीय सर्कस संगठन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
- 1998 में, कुत्तों को अधिसूचना से बाहर रखा गया था।
- जल्लीकट्टू पहली बार 2007 में कानूनी जांच के दायरे में आया, जब भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और पशु अधिकार समूह PETA ने जल्लीकट्टू के साथ-साथ बैलगाड़ी दौड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
- हालांकि, 2009 तमिलनाडु सरकार ने एक कानून पारित करके प्रतिबंध से बाहर निकलने का काम किया, जिस पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर किए थे।
- 2011 में, केंद्र में संप्रग शासन ने उन जानवरों की सूची में बैल को शामिल किया, जिनके प्रशिक्षण और प्रदर्शन निषिद्ध हैं।
- मई 2014 में, भाजपा द्वारा सत्ता में चुने जाने के कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने बुल-टैमिंग खेल पर प्रतिबंध लगा दिया, 2011 की अधिसूचना का हवाला देते हुए एक याचिका पर फैसला सुनाया

क्या यह कानूनी रूप से वैध है या वर्तमान में प्रतिबंधित है?

- यह उच्चतम न्यायालय में लंबित विषय है। राज्य सरकार ने इन घटनाओं को वैध कर दिया है, जिसे अदालत में चुनौती दी गई है।
- जनवरी 2017 में, मुख्यमंत्री जे जयललिता की मृत्यु के बाद, प्रतिबंध के खिलाफ पूरे तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, चेन्नई शहर में 15 दिनों तक जल्लीकट्टू का विद्रोह हुआ।
- उसी वर्ष, तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय अधिनियम में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया और राज्य में जल्लीकट्टू की अनुमति दे दी; इसकी बाद में राष्ट्रपति द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। PETA ने इसे असंवैधानिक बताते हुए राज्य के कदम को चुनौती दी थी।
- मुख्य प्रश्न यह है कि क्या जल्लीकट्टू परंपरा को तमिलनाडु के लोगों के सांस्कृतिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया जा सकता है, जो एक मौलिक अधिकार है।
- अनुच्छेद 29 (1) में कहा गया है कि "भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों या किसी भी हिस्से की अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले किसी भी हिस्से को समान संरक्षण का अधिकार होगा"।
- 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू मामले को एक संविधान पीठ को संदर्भित किया, जहां यह अभी भी लंबित है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- तमिलनाडु की तरह, कर्नाटक ने भी इसके समकक्ष खेल को बचाने के लिए एक कानून पारित किया, जिसे कंबाला कहा जाता है। महाराष्ट्र द्वारा इसी तरह के एक एक खेल को भी अदालत में चुनौती दी गई थी, जबकि इसे कानून के रूप में पारित किया गया था।
- तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर, जहां बुल-टैमिंग और रेसिंग का आयोजन जारी है, सुप्रीम कोर्ट के 2014 के प्रतिबंध आदेश के कारण आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र सहित अन्य सभी राज्यों में इन खेलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

Connecting the dots:

क्या आपको लगता है कि जल्लीकट्टू की सदियों पुरानी परंपरा पर प्रतिबंध लगाना एक विशेष समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और इसलिए यह संविधान का उल्लंघन है? समालोचनात्मक परिक्षण कीजिये?

समाचारों में मंदिर: गवी गंगाधरेश्वर मंदिर

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I - कला और वास्तुकला

समाचार में-

- गवीपुरम का गवी गंगाधरेश्वर मंदिर, हाल ही में खबरों में था।
- 50 वर्षों में पहली बार, सूर्य की किरणें संक्रांति के दिन मूर्ति पर नहीं पड़ी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- गवी गंगाधरेश्वर मंदिर को गव्यपुरम गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
- यह भारतीय रॉक-कट वास्तुकला का एक उदाहरण है।
- यह गुफा शिव मंदिर को समर्पित है और एकाश्मक पत्थर को काट कर बनाया गया है।
- यह बैंगलोर, कर्नाटक में स्थित है।
- इसे 16 वीं शताब्दी में शहर के संस्थापक **केम्पे गौड़ा प्रथम** द्वारा बनाया गया था।
- यह मंदिर अपने रहस्यमयी पत्थर की डिस्क और सटीक योजना के लिए प्रसिद्ध है, जिससे सूर्य वर्ष के कुछ समय में इस तीर्थस्थल पर चमक सकता है।
- हर साल मकर संक्रांति के दिन लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं।
- यह एक विशेष दिन है, जब सूर्य की किरणें नंदी के सींगों के बीच से गुजरते हुए एक घंटे के लिए शिवलिंग पर पड़ती हैं।

कलारिपयट्टू को केरल पर्यटन द्वारा वेल्लार शिल्प ग्राम के तर्ज पर पढ़ाया जाएगा

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I - संस्कृति

समाचार में-

- केरल सरकार ने पारंपरिक मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय के अंदर कलारीपयट्टू अकादमी (kalaripayattu academy) कि तिरुवनंतपुरम में स्थापना की जाएगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- कलारीपयट्टू को केरल पर्यटन के कोवलम के वेल्लार शिल्प ग्राम के तर्ज पर सिखाया जाएगा।
- **3,500** वर्गमीटर। फीट। गाँव में अकादमी दो महीने में पूरी होने वाली है।
- केरल के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पुनर्निर्मित शिल्प ग्राम के उद्घाटन के दौरान कलारीपयट्टू अकादमी का पाठ्यक्रम जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

कलारीपयट्टू

- इसे कलारी के नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक भारतीय मार्शल आर्ट और फाइटिंग स्टाइल है, जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी।
- इसे अभी भी अस्तित्व विद्धमान सबसे पुरानी मार्शल आर्ट माना जाता है, इसकी उत्पत्ति कम से कम तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुई थी।
- इसमें स्ट्राइक, किक्स, ग्रेपलिंग, प्रीसेट फॉर्म, हथियार और उपचार के तरीके शामिल हैं।

- कलरीपायट्टु के चिकित्सकों के पास मानव शरीर और चिकित्सा तकनीकों पर दबाव बिंदुओं का गहन ज्ञान है, जो आयुर्वेद और योग के ज्ञान को शामिल करता है।
- भारत के अन्य हिस्सों के विपरीत, केरल में योद्धा सभी जातियों के थे।
- कलरीपायट्टू में केरल के समाज में महिलाओं ने भी प्रशिक्षण लिया, और आज भी यह प्रथा विद्धमान हैं।

Related articles:

- Indigenous Games to be a part of Khelo India Youth Games 2021: Click here

नव अनुभव मंडप

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I - संस्कृति

समाचार में-

- कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बसवकल्याण में 'नव अनुभव मंडप' की आधारशिला रखी है
- यह वह स्थान है जहाँ 12वीं शताब्दी के कवि-दार्शनिक बसवेश्वरा ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया था।

महत्वपूर्ण बिंदु-

- यह 7.5 एकड़ भूखंड में बनी छह मंज़िल की संरचना होगी, जो कि बसवेश्वरा के दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करेगी।
- यह 12वीं शताब्दी में बसवेश्वरा द्वारा बसवकल्याण में स्थापित 'अनुभव मंडप' (जिसे प्रायः विश्व की पहली संसद के रूप में संदर्भित किया जाता है) को प्रदर्शित करेगी। विदित हो कि बसवेश्वरा द्वारा स्थापित 'अनुभव मंडप' में विभिन्न दार्शनिकों और समाज सुधारकों द्वारा वाद-विवाद किया जाता था।
- इसका निर्माण वास्तुकला की कल्याण चालुक्य शैली में किया जाएगा।
- कल्याण चालुक्य, मध्ययुगीन काल के प्राचीन कर्नाटक इतिहास का एक अभिन्न अंग है। कल्याण चालुक्य शासकों ने अपने पूर्वर्ती शासकों की तरह ही मंदिरों का निर्माण करवाया और नृत्य तथा संगीत कलाओं का संरक्षण किया।
- 770 स्तंभों द्वारा समर्थित इस भव्य संरचना में 770 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक सभागार भी बनाया जाएगा।

- ऐसा माना जाता है कि 770 शरणों (बसवेश्वरा के अनुयायी) ने 12वीं शताब्दी में 'वचन' सुधारवादी आंदोलन का नेतृत्त्व किया था।
- इसके शीर्ष पर एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया जाएगा।
- इस परियोजना में अत्याधुनिक रोबोट प्रणाली, ओपन-एयर थिएटर, आधुनिक जल संरक्षण प्रणाली, पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र, प्रार्थना हॉल और योग केंद्र आदि की भी परिकल्पना की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

बसवेश्वर

संक्षिप्त परिचय

- गुरु बसवेश्वर का जन्म 1131 ईसवी में बागेवाड़ी (कर्नाटक के अविभाजित बीजापुर ज़िले में) नामक स्थान पर हुआ था।
- गुरु बसवेश्वरा, एक भारतीय दार्शनिक, समाज सुधारक व नेतृत्त्वकर्त्ता थे, जिन्होंने जातिविहीन समाज बनाने का प्रयास किया और जाति तथा धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया।
- गुरु बसवेश्वरा को लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है।
- उनका आध्यात्मिक अनुशासन निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित था:
  - अरिवु (सत्य ज्ञान),
  - आचार (सही आचरण),
  - अनुभव (दिव्य अनुभव)
- उन्हीं के प्रयासों के कारण धर्म के दरवाज़े जाति, पंथ या लिंग के आधार पर भेदभाव किये बिना सभी के लिये खोल दिये गए।
- उन्होंने 'अनुभव मंडप' की स्थापना की, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिये सामान्य मंच था।यह भारत की पहली और सबसे बड़ी सामाजिक-धार्मिक संसद थी।
- 14 नवंबर 2015 को, भारत के प्रधान मंत्री ने लंदन में लामिथ में टेम्स नदी के किनारे बसवन्ना की प्रतिमा का भी उद्घाटन किया।

माउंट सेमरू में ज्वालामुखी विस्फोट

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I – संस्कृति

समाचार में-

- इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी 'माउंट मेरापी' में हाल ही विस्फोट हो गया। 2,968 मीटर (9,737 फुट) ऊँचा यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के घनी आबादी वाले द्वीप जावा और वहाँ के प्राचीन शहर याग्याकार्टा के पास है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- सेमरू - जिसे "द ग्रेट माउंटेन" के रूप में भी जाना जाता है - जावा में उच्चतम ज्वालामुखी है और यह सबसे सक्रिय जवालामुखी में से एक है।
- यह सबडक्शन ज़ोन में स्थित है, जहाँ इंडो-ऑस्ट्रेलिया प्लेट यूरेशिया प्लेट के नीचे समाहित हो रही है।
- यह इंडोनेशिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन पर्वतारोहण स्थलों में से एक है।

क्या आप जानते है?

- माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित दर्जनों ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है और बीते कुछ वर्षों में इसमें लगातार विस्फोट हो रहा है।
- इंडोनेशिया 270 मिलियन लोगों की आबादी वाला एक द्वीपसमूह है, जिसके 'रिंग ऑफ फायर' (Ring of Fire) या परिप्रशांत महासागरीय मेखला (Circum-Pacific Belt) में अवस्थित होने के कारण यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और यह क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रिंग ऑफ फायर' प्रशांत महासागर के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विवर्तनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं।

Related article:

- About Sulawesi**:** Click here

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) नए मानसून मॉडल पेश कर सकता है

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I - भूगोल

समाचार में-

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) वर्षा में बेहतर बदलाव के लिए इस साल 2021 में नए मानसून मॉडल पेश कर सकता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इससे सम्बंधित तीन अलग-अलग मॉडल थे जिनका परीक्षण इस वर्ष किया जा सकता है।
- उनमें से दो गतिशील मॉडल (dynamical models) और एक सांख्यिकीय मॉडल (statistical model) था।
- पूर्व में, किसी भी विशेष दिन पर जलवायु सुपर कंप्यूटर पर सिम्युलेटेड होती है और मौसम विज्ञानी बदलते दैनिक उत्पादन का निरीक्षण करते हैं।
- दूसरा पारंपरिक सांख्यिकीय मॉडल है जो भौतिक मापदंडों के संबंधो पर आधारित है, उदाहरण के लिए समुद्र की सतह के तापमान, बर्फबारी, भूस्खलन, तापमान आदि का अध्ययन।
- वर्तमान में तीन मॉडल विचाराधीन हैं:
  - 12 वैश्विक संचलन मॉडल (डायनामिकल) जिनके आउटपुट को एक एकल में जोड़ा जाएगा;
  - यह मॉडल, उष्णकटिबंधीय समुद्र की सतह के तापमान के आधार पर वर्षा का अनुमान लगाता है (प्रोफेसर सुमंत निगम, मैरीलैंड विश्वविद्यालय, यू.एस. द्वारा विकसित)
  - सांख्यिकीय मॉडल प्री-मानसून के दौरान देखे गए जलवायु चर पर आधारित।
- यह सभी छोटे मॉडल हैं जिन्हें एक औसत मूल्य पर पहुंचने के लिए संयुक्त किया जाता है।
- इस वर्ष पारंपरिक सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग जारी रहेगा।

Related articles:

- Subdued Northeast Monsoon: Click here
- Why predicting monsoons in India is a tricky job? Click here

---

नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I - आधुनिक इतिहास

समाचार में-

- भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाने का फैसला किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 वीं जयंती वर्ष को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 23 जनवरी 2021 से शुरू करने का फैसला किया है।

- कार्यक्रमों को तय करने, और पर्यवेक्षण की निगरानी और मार्गदर्शन के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
- **उद्देश्य:** राष्ट्र के प्रति नेताजी की अदम्य भावना और निस्वार्थ सेवा को याद करना और देश के लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करने के लिए।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सुभाष चंद्र बोस दो बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, (1938-हरिपुर और 1939-त्रिपुरी)।
- राजनीतिक मतभेदों के कारण, उन्होंने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बंगाल में कांग्रेस के भीतर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया।
- कलकत्ता में, बोस ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
- बाद में उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया जहाँ से वह भाग निकले। वह अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी गए।
- हालांकि, 1943 में बोस ने उम्मीद खो दी कि जर्मनी भारत की स्वतंत्रता हासिल करने में किसी भी तरह की मदद कर सकता है।
- फिर उन्होंने एशिया की ओर रुख किया, जहां वे अंततः भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के शीर्ष नियुक्त हुए।
- आईएनए ने प्रवासी भारतीयों के बीच समर्थन प्राप्त किया और बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन किया जिसने अपनी मुद्रा, डाक टिकट, अदालत और नागरिक संहिता का निर्माण किया।
- इसे एक्सिस राज्यों (Axis states) द्वारा मान्यता दी गई थी।
- युद्ध के अंतिम दो वर्षों के दौरान, बोस ने जापानी समर्थन के साथ- अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया।
- भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) अनिवार्य रूप से गैर-सांप्रदायिक थी, जिसके कारण यह अधिकारियों और रैंकों के बीच मुस्लिम में काफी प्रमुख थे, और इसने झांसी की रानी के नाम पर एक महिला टुकड़ी का भी निर्माण किया था।

त्रिपुरा सरकार ने टेक्सटाइल के रूप में रिसा को बढ़ावा देने की योजना बनाई है

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I – भूगोल

समाचार में-

- **त्रिपुरा** सरकार अब राष्ट्रीय स्तर पर त्रिपुरा के टेक्सटाइल के रूप में रीसा को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- रीसा त्रिपुरा के स्वदेशी जनजातीय समुदायों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रथागत हाथ का कपड़ा है।
- इसे एक प्रतिष्ठित प्राप्तकर्ता को सम्मानित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
- रीसा महत्वपूर्ण सामाजिक उपयोगिताओं की मेजबानी करता है।
- इसका उपयोग धार्मिक त्योहारों जैसे कि गरिया पूजा, आदिवासी समुदायों के एक प्रथागत त्योहार, या शादियों और त्यौहारों के दौरान पुरुष लोगों द्वारा सिर पर पगड़ी के रूप में भी किया जाता है।

क्या आप जानते है?

- रिसा एक प्रथागत त्रिपुरी महिला पोशाक के तीन भागों में से एक है, अन्य दो रिग्नाई और रिकुटु हैं।
- इसका उपयोग मुख्य रूप से शरीर के निचले हिस्से को कवर करने के लिए किया जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ है 'पहनने के लिए'।
- रितुकु शरीर के ऊपरी आधे हिस्से को ढंकता है, इसे चारों ओर से लपेटता है।
- हालांकि, इसका उपयोग भारतीय साड़ी के 'चुनरी' या 'पल्लू' की तरह भी किया जाता है।
- इसका उपयोग नवविवाहित त्रिपुरी महिलाओं के सिर को कवर करने के लिए भी किया जाता है।

श्री नारायण गुरु की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद का उद्घाटन

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I - इतिहास; संस्कृति

समाचार में-

- हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने श्री नारायण गुरु (Sree Narayana Guru) की कविताओं का अंग्रेज़ी अनुवाद, "नॉट मैनी, बट वन" (Not Many, But One) लॉन्च किया है।

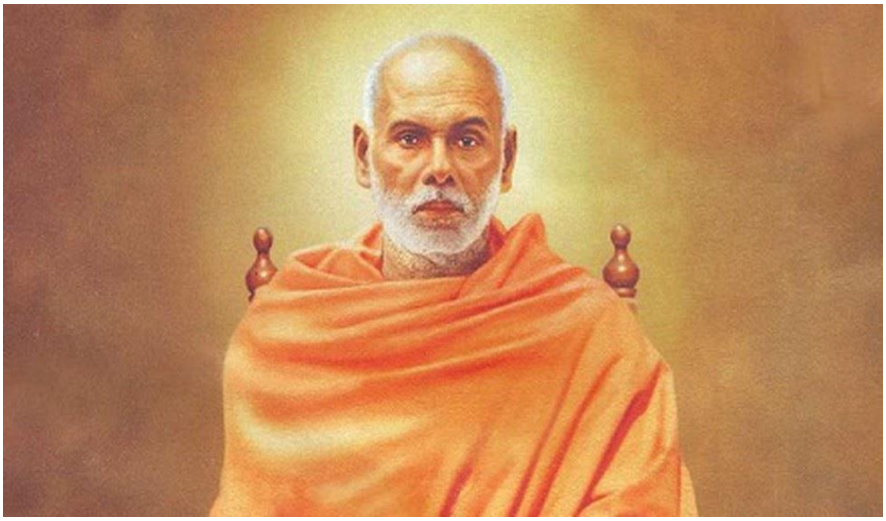

महत्वपूर्ण तथ्य

- श्री नारायण गुरु का जन्म 22 अगस्त, 1856 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास एक गाँव चेमपज़ंथी (Chempazhanthy) में मदन असन और उनकी पत्नी कुट्टियम्मा (Kuttiyamma) के घर हुआ था।
- उनका परिवार एझावा (Ezhava) जाति से संबंध रखता था और उस समय के सामाजिक मान्यताओं के अनुसार इसे 'अवर्ण'' (Avarna) माना जाता था।
- जातिगत अन्याय के खिलाफ: उन्होंने "एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर" (ओरु जति, ओरु माथम, ओरु दैवम, मानुष्यानु) का प्रसिद्ध नारा दिया। उन्होंने वर्ष 1888 में अरुविप्पुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनाया, जो उस समय के जाति-आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था।
- उन्होंने एक मंदिर कलावन्कोड (Kalavancode) में अभिषेक किया और मंदिरों में मूर्तियों की जगह दर्पण रखा। यह उनके इस संदेश का प्रतीक था कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है।
- उन्होंने लोगों को समानता की सीख दी, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि असमानता का उपयोग धर्म परिवर्तन के लिये नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे समाज में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है।
- श्री नारायण गुरु ने वर्ष 1923 में अलवे अद्वैत आश्रम (Alwaye Advaita Ashram) में एक सर्व-क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे भारत में इस तरह का पहला कार्यक्रम बताया जाता है। यह एझावा समुदाय में होने वाले धार्मिक रूपांतरणों को रोकने का एक प्रयास था।
- श्री नारायण गुरु बहुआयामी प्रतिभा, महान महर्षि, अद्वैत दर्शन के प्रबल प्रस्तावक, कवि और एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति थे।
- उन्होंने विभिन्न भाषाओं में अनेक पुस्तकें लिखीं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं: अद्वैत दीपिका, असरमा, थिरुकुरल, थेवरप्पाथिंकंगल आदि।
- श्री नारायण गुरु मंदिर प्रवेश आंदोलन में सबसे अग्रणी थे और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थे।

- श्री नारायण गुरु ने वयकोम सत्याग्रह (त्रावणकोर) को गति प्रदान की। इस आंदोलन का उद्देश्य निम्न जातियों को मंदिरों में प्रवेश दिलाना था। इस आंदोलन की वजह से महात्मा गांधी सहित सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीयता के सार को समाहित किया और दुनिया की विविधता के बीच मौजूद एकता को रेखांकित किया।
- श्री नारायण गुरु ने स्वच्छता, शिक्षा, कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प और तकनीकी प्रशिक्षण पर ज़ोर दिया।
- श्री नारायण गुरु का अध्यारोप (Adyaropa) दर्शनम् (दर्शनमला) ब्रह्मांड के निर्माण की व्याख्या करता है। इनके दर्शन में दैवदशकम् (Daivadasakam) और आत्मोपदेश शतकम् (Atmopadesa Satakam) जैसे कुछ उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि कैसे रहस्यवादी विचार तथा अंतर्दृष्टि वर्तमान की उन्नत भौतिकी से मिलते-जुलते हैं।

Related article:

- Centre to revive Narayana Guru spiritual circuit plan: Click here

---

भारतीय बोडो सामाजिक कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि दी गयी

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I - संस्कृति

समाचार में-

- केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ऐतिहासिक बोडोलैंड टेरीटोरियल रीजन (BTR) समझौते की पहली वर्षगाँठ मनाने के लिए असम के कोकराझार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए।
- कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल,वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हेमंत विस्व शर्मा,बीटीआर के प्रमुख और अन्य नेता भी शामिल हुए।
- उन्होंने श्री उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पर संस्थान खोलकर, उन्हें श्रद्धांजलि दी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- उपेंद्रनाथ ब्रह्मा (1956 - 1990) एक भारतीय बोडो सामाजिक कार्यकर्ता और ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष थे।
- उनकी दृष्टि और नेतृत्व के लिए में 8 मई 1990 को बोडोफा (गोडियन का संरक्षक) खिताब मरणोपरांत ब्रह्मा को प्रदान किया गया।

बोडो

- बोडो असम का सबसे बड़ा नृवंशविज्ञान समूह है।
- वे मुख्य रूप से असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में केंद्रित हैं।
- बोडो एक टिबेटो-बर्मी-भाषी जातीय समूह हैं।
- बोडो लोग बोडो भाषा बोलते हैं, टिब्बो-बर्मन भाषा को भारतीय संविधान में बाईस अनुसूचित भाषाओं में से एक माना जाता है।

- बोडो लोगों को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में एक मैदानी जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

Related articles:

- Bodoland University develops fungal powder to boost immunity: Click here
- Bodoland Territorial Council (BTC): Click here

धनीपुर मस्जिद परियोजना का शुभारंभ

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I - संस्कृति

समाचार में-

- उत्तर प्रदेश के अयोध्या के धनीपुर गाँव में पाँच एकड़ के भूखंड पर गणतंत्र दिवस पर धनीपुर मस्जिद परियोजना का औपचारिक शुभारंभ किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूखंड आवंटित किया गया था।
- इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (IICF) इस मस्जिद के निर्माण की देखरेख कर रहा है।
- इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 30 महीने लगेंगे।
- परियोजना में तीन भाग शामिल हैं: एक मस्जिद जो एक आधुनिक डिजाइन पर आधारित है; एक बहु-विशेषता 200-बेड अस्पताल और सामुदायिक रसोई; और एक इंडो-इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर।

Related articles:

- Ram Temple History & Significance**:** Click here

Image source : Click here

मंजम्मा जोगती: पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित है जिन्होंने ग्रामीण लोक कलाओं को लोकप्रिय बनाया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I - संस्कृति

समाचार में-

- मंजम्मा जोगती एक पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकरता हैं जो कर्नाटक की एक ट्रांसजेंडर हैं।
- उसने पिछले कई दशकों से प्रयास किया और ग्रामीण लोक कलाओं को एकल रूप से लोकप्रिय बनाया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इन्हें इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
- वह कर्नाटक जनपद अकादमी की पहली किन्नर महिला अध्यक्षा थीं।
- मंजम्मा जोगती कुछ वर्षों से जोगती नृत्य, जनपद गीत और अन्य विधाओं के लिए काम कर रही है।
- जोगती नृत्य, जनपद गीत, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में काफी प्रचलित है।
- उन्हें 2006 में कर्नाटक जनपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- 2010 में कर्नाटक सरकार ने उन्हें वार्षिक कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार से नवाज़ा था।

Image source: Click here

असम में पथराघाट विद्रोह

संदर्भ: जलियांवाला बाग हत्याकांड (1919) से लगभग पच्चीस साल पहले, असम में 28 जनवरी, 1894 को सौ से अधिक किसानों पर अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गयी थी। जिसमें निहत्थे किसान औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा लगाए गए भू-राजस्व में वृद्धि का विरोध कर रहे थे, जब सेना ने उनपर गोली चलाई।

पथराघाट विद्रोह का कारण ?

- **असम अनुबंध और भूमि का सर्वेक्षण:** 1826 में असम के ब्रिटिश शासन के बाद, राज्य की विशाल भूमि का सर्वेक्षण शुरू हुआ। यह मुख्य रूप से भूमि का सटीक मूल्यांकन करने के लिए था ताकि क्षेत्र से भू राजस्व में वृद्धि हो सके।
- **भूमि करों पर लगाम:** इस तरह के सर्वेक्षणों के आधार पर, अंग्रेजों ने भूमि करों को लागू करना शुरू कर दिया, किसानों के मध्य इसे लेकर नाराजगी थी।
- **करों में वृद्धि:** 1893 में, ब्रिटिश सरकार ने कृषि भूमि कर में 70- 80 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया।
- **असम भर में ने रैज़े मेल्स,:** 1893 तक, किसान कर का भुगतान या नकद या कर के बदले मेंएक सेवा प्रदान करके करते थे। असम के भार, किसानों ने रैज़े मेल्स, या शांतिपूर्ण लोगों के सम्मेलनों का आयोजन करके करों में वृद्धि के ब्रिटिश कदम का विरोध करना शुरू कर दिया।
- **ब्रिटिशों द्वारा दमन:** रैज मेल्स के इन सभाओं के लोकतांत्रिक होने के बावजूद, अंग्रेजों ने उन्हें "देशद्रोह का स्थल" माना।
- **28 जनवरी, 1894 को पथराघाट विद्रोह में फायरिंग:** गुवाहाटी से लगभग 60 किमी उत्तर पूर्व में एक छोटा सा गाँव है, जब अंग्रेज अधिकारी किसानों की शिकायतें सुनने से इनकार कर रहे थे, तब चीजें \उत्तेजित हुईं और लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद \ गोलीबारी हुई, जिसमें गुवाहाटी से लगभग 60 किमी उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटे से गाँव, पथरुघाट में इकट्ठा हुए कई किसानों की मौत हो गई।

घटना का महत्व:

- **असम समुदाय के लिए प्रेरणादायक:** बड़े असमिया समुदाय के लिए, पथराघाट, साराघाट की लड़ाई में दूसरे स्थान पर आता है, जब अहोमों ने 1671 में मुगलों को हराया था। यह राष्ट्रीय जागरण की तरह, इसे असमिया समुदाय के लिए बेहद प्रेरणादायक माना जाता था।

घटना का महत्वपूर्ण विश्लेषण:

- **अपनाए गए साधन:** जबकि कई बार ब्रिटिश इसे "पथरुघाट रॉन" या "पथरुघाट की लड़ाई" के रूप में संदर्भित करते हैं, यह एक "मिथ्या नाम" है। यह सामूहिक विरोध शांतिपूर्ण और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अग्रदूत था, जिसे बाद में महात्मा गांधी ने प्रचारित किया।

- **मुख्यधारा के ऐतिहासिक प्रवचन में यह सुविधा नहीं है:** इस घटना को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा में सबसे दुखद और प्रेरक अवसरों में से एक माना जाता है। हालाँकि, यह स्वतंत्रता संग्राम के मुख्यधारा के ऐतिहासिक प्रवचन में शायद ही कभी दिखाई पड़े।

पथराघाट अप्सरिंग का सम्मान:

- शहीद स्तंभ: जहां घटना हुई थी, वंहा ऐतिहासिक पथराघाट विद्रोह के किसान शहीदों की याद में, एक "शहीद स्तंभ" का निर्माण किया गया है। यह औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ लड़ाई में किसानों के बलिदान और वीरता को याद करने में मदद करता है।
- कृषक स्वाहिद दिवस: हर साल 28 जनवरी को, सरकार और स्थानीय लोग एक आधिकारिक समारोह में घटना (कृषक स्वाहिद दिवस) के शहीदों को सम्मान देते हैं। 29 जनवरी को, भारतीय सेना सैन्य शैली में अपने सम्मान का भुगतान करती है।
- **कृषक स्वाहिद दिवस (Krishak Swahid Diwas)-** हर साल 28 जनवरी को, सरकार और स्थानीय लोग कृषक स्वाहिद दिवस मनाते हैं .
- **लोकप्रिय संस्कृति:** इन वर्षों में, फिल्म, थियेटर, लोककथाएं और धारावाहिक इस विषय पर बनाए गए हैं, जो कि लोकप्रिय कल्पना में धीरे-धीरे प्रवेश कर रहा है।
- **कौशल विकास केंद्र:** 28 जनवरी, 2021 को, असम के सीएम ने किसानों के लिए एक एकीकृत प्रशिक्षण और कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया, जो किसानों को नए कौशल और प्रौद्योगिकी सिखाने के लिए सुसज्जित होगा।

नीति / शासन

खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा के स्तर के लिए एफएसएसएआई स्लैश की सीमा

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II- गवर्नेंस

समाचार में-

- हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा(**trans fat)** के स्तर को कम करने के लिए नई सीमा (**limit)** निर्धारित की है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 'खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) विनियम'**[Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations]** में संशोधन करके खाद्य पदार्थों (यथा- तेल और वसा) में ट्रांस फैटी एसिड (**trans fatty acids -TFA)** की मात्रा कम करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत उत्पादकों को तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को 2021 तक 3% और 2022 तक 2% लाना है।
- एफएसएसएआई ने हितधारकों के साथ परामर्श के लिए इस विषय पर एक मसौदा जारी करने के एक साल से अधिक समय बाद **29** दिसंबर को संशोधन को अधिसूचित किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 'खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) विनियम' में संशोधन जिसके तहत उत्पादकों को तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को 2021 तक 3% और 2022 तक 2% लाना है।
- इसे 1 अगस्त, 2011 को केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) के तहत अधिसूचित किया गया था।
- इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है।
- एफएसएसएआई मानव उपभोग के लिये पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम करता है।
- इसके अलावा, यह देश के सभी राज्यों, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तकर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है।
- यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य-पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच भी करता है
- ट्रांस वसा, या ट्रांस-फैटी एसिड, असंतृप्त वसा का एक रूप हैं। वे प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूपों में आते हैं।
- ट्रांस फैट दिल के दौरे के बढ़ते जोखिम और कोरोनरी हृदय रोग से मृत्यु के साथ जुड़े हुए हैं।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर ट्रांस फैट अथवा ट्रांस फैटी एसिड (टीएफए) के सेवन से हर वर्ष लाखों लोगों की मौत हृदय संबंधी बीमारियों (**Cardiovascular Disease**) के कारण होती है। वैश्विक खाद्य आपूर्ति से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2023 तक ट्रांस वसा को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है।

COVID-19 वैक्सीन ड्राई रन

संदर्भ: भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण **(EUA)** के अंतिम चरणों में भारत के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवाक्सिन की कोविशल्ड के साथ दो वैक्सीन आने की उम्मीद है, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वैक्सीन का ड्राई रन किया। इसके लिए कुल 259 वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं।

ड्राई रन में किसी वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है बल्कि सिर्फ इसकी जांच की जा रही है कि वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई योजना कितनी कारगर है। यानी ड्राई रन और कुछ नहीं बल्कि वास्तविक टीकाकरण अभियान से पहले रिहर्सल या मॉक ड्रिल है।

भारत का प्रतिरक्षण अनुभव

- भारत के 'टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम' के तहत, इसे 1978 में शुरू किया गया था, देश ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आवश्यक टीकों के प्रशासन में अनुभव को एकत्र किया है।
- 1985 में, इस कार्यक्रम का नाम बदलकर 'यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम' कर दिया गया, जिसके तहत सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से लगभग 12 अलग-अलग टीके प्रदान किए जाते हैं।
- टीकाकरण के अलावा, कवरेज और प्रतिकूल घटनाओं की निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर यह त्रि-स्तरीय प्रणाली है और इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि टीके की गुणवत्ता मानदंडों का पालन किया जाये।
- यूनिसेफ के अनुसार, भारत में सालाना **9** मिलियन टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाते हैं। इसके बावजूद, राज्यों में व्यापक बदलाव के साथ लगभग **60%** पात्र बच्चे पूरी तरह से प्रतिरक्षित हैं।

यह क्यों जरूरी था?

- क्योंकि एक **COVID-19** वैक्सीन में कम से कम चार सप्ताह के अंतराल पर दो खुराक शामिल होंगे, और इसके लिए एक अरब से अधिक भारतीयों को संभावित रूप से प्रशासित करने की आवश्यकता होगी, इसके लिए अधिक नियोजन, कर्मियों और तार्किक व्यवस्था की आवश्यकता होती है।
- लाभार्थियों की भारत की प्राथमिकता सूची में स्वास्थ्य वर्कर, नगरपालिका कर्मी, पुलिस कर्मी, **50** वर्ष से अधिक आयु के लोग और कम उम्र के लोग शामिल हैं।
- सरकार ने ऐसे **300** मिलियन लोगों की गणना की है, और वैक्सीन उत्पादन और प्रशासन की गति को देखते हुए, यह अगस्त तक पूरा होगा, जब तक कि प्राथमिकता सूची में सभी को सम्मिलित नहीं किया जाता है।
- यूरोपीय संघ की सूची में कम से कम दो टीकों के साथ, पूरे अभ्यास के लिए एक अभूतपूर्व स्तर का डिजिटलीकरण (co-win एप्लीकेशन) शामिल है।

- ड्राई रन का उद्देश्य क्षेत्र के वातावरण में को-विन एप्लीकेशन के उपयोग की परिचालन व्यवहार्यता का आकलन करना था, योजना और कार्यान्वयन के बीच संबंधों का परीक्षण करना और वास्तविक कार्यान्वयन से पहले आने वाली चुनौतियों और मार्गदर्शन मार्ग की पहचान करना था।
- इससे विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को परिक्षण प्रदान करने की भी उम्मीद है

ट्रायल रन का अनुभव कैसा रहा?

- पंजाब सरकार ने दो जिलों में 12 स्थलों पर सफलतापूर्वक अभ्यास पूरा किया।
- असम में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने "सॉफ्टवेयर प्रभावकारिता" पर ध्यान केंद्रित किया और ड्रिल के भौतिक भाग को दो जिलों में 300 लोगों को शामिल किया जाएगा।
- आंध्र प्रदेश में दो दिवसीय अभ्यास प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर **25** डमी लाभार्थियों **(**हेल्थकेयर वर्कर्स**)** के साथ सार्वजनिक और निजी चिकित्सा संस्थानों सहित पांच सत्र स्थलों पर आयोजित किया गया था।

डमी परिक्षण के बाद, क्या वास्तविक टीके तैयार किए जा सकते हैं?

- अब तक, केवल दो वैक्सीन, पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने क्लिनिकल परीक्षण और 'कोविशिल्ड' के निर्माण के लिए ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका के साथ और भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च **(ICMR)** के साथ मिलकर 'कोवैक्सीन' विकसित की है, जिन्हें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा मंजूरी दे दी गई है।।
- डीसीजीआई द्वारा एक औपचारिक अनुमोदन आसन्न है, जो फिर वितरण के लिए कंपनियों को सरकार को खुराक की आपूर्ति करने की अनुमति देगा।
- एसआईआई ने कहा है कि उसने पहले ही **50** मिलियन डोज का स्टॉक कर लिया है और अगले हफ्ते तक **50** मिलियन डोज और तैयार हो जाएंगे।

आगे की चुनौतियां

- डमी रन वार्म-अप अभ्यास के रूप में उपयोगी होते हैं, लेकिन वे टीकाकरण प्रक्रिया के सबसे कठिन भागों के बारे में बहुत कम प्रतिक्रिया प्रकट करेंगे, अर्थात वास्तविक टीकाकरण, प्रतिक्रिया, गंभीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया और संभावित अस्पताल की स्थिती के बारे में स्पष्टता अभी नहीं है।
- अब तक, भारत में वैक्सीन परीक्षणों के भाग के रूप में, हजारों लोगों को अस्पताल की सेटिंग में परीक्षण टीके लगाए गए हैं। कई भविष्य के टीकाकरण ग्रामीण सेटिंग्स में आयोजित किए जाने की उम्मीद है, जहां आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा अवसंरचना अनुपस्थित है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने फाइजर और मॉडर्न टीकों को मंजूरी दे दी है, ने एक महीने के भीतर **20** मिलियन लोगों को टीका लगाने की उम्मीद की थी, लेकिन मुश्किल से **2.8** मिलियन का ही लक्ष्य प्राप्त कर पाये।

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को **2: 1** के फैसले में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी।

एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली के लुटियंस में **86** एकड़ भूमि का नवीनीकरण और पुनर्विकास करना है, इस योजना के तहत संसद भवन, सेंट्रल विस्टा, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का भी पुनर्विकास किया जाएगा।
- याचिकाओं के एक बैच ने राष्ट्रीय राजधानी में लगभग **86** एकड़ भूमि पर एक नई संसद सहित पुरानी संरचनाओं को विध्वंस करने और नए निर्माण की योजना को चुनौती दी थी।

इसे क्यों चुनौती दिया गया और अदालत ने क्या निर्णय लिया है?

- सही प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं: मोटे तौर पर, केन्द्रीय विस्टा उपसर्गों में परिवर्तन करने के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन और अपनाए जाने वाले तरीके और प्रक्रिया को चुनौती दी गई।
- इसे मंजूरी प्रदान किया गया था: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस प्रक्रिया में अनियमितताएं थीं, जिनमें डिजाइन की मंजूरी, मौद्रिक आवंटन पर मंजूरी और निविदा प्रक्रियाएं, और पर्यावरण पर और स्थानीय नगर निकायों से अन्य नियामक मंजूरी शामिल थीं।
- धरोहर की स्वीकृति: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि सरकार विरासत संरक्षण समिति से परामर्श करने में विफल रही है, जो विरासत संरचनाओं से जुड़े मामलों में एक विशेषज्ञ निकाय है और डिजाइन की सहमति होने से पहले ही परियोजना के प्रारंभिक चरण से परामर्श किया जाना चाहिए।
- जल्दबाजी में निर्णय: याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कई स्थानीय निकायों को शामिल करने की पूरी प्रक्रिया सिर्फ तीन महीनों में पूरी हो गई (दिसंबर **2019** और मार्च **2020** के बीच), जिसके दौरान सार्वजनिक परामर्श आयोजित नहीं किया गया था, आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गईं, इनपर सही से विचारन हीं किया गया।

मास्टर प्लान को कैसे संशोधित किया गया?

- केंद्र सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली के मास्टर प्लान को संशोधित करने की शक्ति दी गई है जिसे **2007** में **2021** तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास की दिशा का मार्गदर्शन करने के लिए अधिसूचित किया गया था।
- इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को शामिल करने के लिए मार्च **2020** में संशोधित किया गया था। भूमि के अनुभागों को मनोरंजन, सरकार, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सौंपा गया है, जिन्हें सेंट्रल विस्टा परियोजना को समायोजित करने के लिए संशोधित किया गया था।

कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया?

- अपने **2: 1** के फैसले में, अदालत ने माना है कि दी गई मंजूरी में कोई अनदेखी नहीं हुई है।

- जस्टिस ए एम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि दिल्ली सरकार के मास्टर प्लान **2021** में परियोजना के लिए भूमि उपयोग में बदलाव की अपनी शक्तियों का एक वैध प्रयोग किया है।
- अदालत ने कहा कि यह परिवर्तन "मामूली संशोधन का मामला है" और "यह इस बात के लिए समझ से बाहर है कि प्रस्तावित परिवर्तनों को योजना की मूल पहचान को बदलने के लिए पर्याप्त रूप कैसे कहा जा सकता है।"
- अदालत का दृष्टिकोण इस समझ पर आधारित है कि परिवर्तनों को पूरी योजना को ध्यान में रखते हुए देखना होगा न कि केवल उन क्षेत्रों में जिनमें परिवर्तन प्रभावित होंगे।
- उदाहरण के लिए, प्रस्तावित नई संसद मध्य विस्टा के प्लॉट नंबर **2** में आने के लिए निर्धारित है जो वर्तमान में एक पार्क है। भूखंड के लिए भूमि उपयोग को मनोरंजन से सरकारी उपयोग में बदल दिया गया था।
- हालांकि, अदालत ने विचार किया कि चूंकि पार्क को सुरक्षा कारणों से जनता के लिए बंद कर दिया गया है, इसलिए भूमि उपयोग में परिवर्तन से सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध क्षेत्र की वास्तविक कमी नहीं होगी।
- सत्तारूढ़ ने यह भी कहा कि इस परिवर्तन की भरपाई के लिए, भूमि उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन पड़ोस में तीन अलग-अलग स्थानों पर मनोरंजक स्थान प्रदान करता है।
- अदालत ने कहा कि "प्रस्ताव की प्रकृति के कारण तेजी से और समय के अनुसार वैध कदम / कार्रवाई करना, जल्दबाजी में किए गए प्रस्ताव के रूप में नहीं कहा जा सकता है"।

असंतोषी राय क्या कहती है?

- न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने खंडपीठ के तीसरे न्यायाधीश ने असंतोष ने भी एक नोट दिया। बहुमत के फैसले से उनकी असहमति मुख्य रूप से दिल्ली के मास्टर प्लान में भूमि उपयोग में परिवर्तन के मुद्दे से संबंधित है।
- न्यायमूर्ति खन्ना का विचार था कि भूमि उपयोग में परिवर्तन को प्रक्रियात्मक और पर्याप्त दोनों आधारों पर माना जाना चाहिए।
- प्रक्रिया पर, न्यायाधीश ने कहा कि यह एक परामर्श प्रक्रिया के बिना शुरू किया गया था।
- उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनता की चिंताओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया और न ही उन लोगों के लिए पर्याप्त समय दिया जिन्होंने अपना मामला बनाने के लिए आपत्तियां उठाईं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा कमेटी द्वारा दी गई अनुमति पूर्व निर्धारित है।
- न्यायमूर्ति खन्ना भी बहुमत के दृष्टिकोण से असहमत थे कि संशोधन पर्याप्त था और "मामूली परिवर्तन" नहीं हुआ था।

जटिल अन्वेषण

- न्यायालय मामले की वैधता तक सीमित है: सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए डेक को मंजूरी दे दी है। अदालत मामले की वैधता तक खुद को सीमित करने में शांत और चौकस रही है।
- सहभागी प्रक्रियाओं की पवित्रता: भारत के हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम यूनियन ऑफ़ जस्टिस, न्यायमूर्ति खन्ना के नोटों में सुप्रीम कोर्ट के **2019** के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि , "सार्वजनिक परामर्श महज औपचारिकता नहीं है। निर्णय जो लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, उनकी चिंताओं का कारक होना चाहिए"

- सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता: "याचिकाकर्ताओं की प्राथमिक शिकायत," को असंतुष्ट नोट बताते हैं, "जानकारी और विवरण की कमी" माना गया है। पूरी तरह से और प्रासंगिक रूप से जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया होता, तो जनता सार्थक तरीके से सरकार के साथ जुडती।

सुप्रीम कोर्ट ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण पर कानून की स्थिति स्पष्ट किया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II- न्यायपालिका

समाचार में-

- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण पर कानून की स्थिति स्पष्ट की।
- सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णय ने राज्य में कांस्टेबलों के पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया में आरक्षण के विभिन्न वर्गों को लागू करने के तरीके से उत्पन्न मुद्दों से निपटाया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- अदालत ने फैसला सुनाया कि अगर ऊर्ध्वाधर-क्षैतिज आरक्षित श्रेणी के एक चौराहे से संबंधित व्यक्ति ने ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बिना अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उच्च अंक प्राप्त किए हैं, तो व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बिना योग्यता के रूप में गिना जाएगा, और उसे सामान्य श्रेणी के क्षैतिज कोटे से बाहर नहीं किया जा सकता है।
- यह तर्क भी दिया गया कि यदि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों कोटा एक साथ लागू किए जाने थे, तो समग्र चयन में कम अंक वाले उम्मीदवार होंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहा जाता है।
- यह कानून के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक समूह के लिए अलग से लागू होता है।
- क्षैतिज आरक्षण महिलाओं, बुजुर्गों, ट्रांसजेंडर समुदाय और लाभार्थियों के अन्य श्रेणियों जैसे लाभार्थियों की अन्य श्रेणियों के लिए प्रदान किए गए समान अवसर को संदर्भित करता है।
- क्षैतिज कोटा प्रत्येक ऊर्ध्वाधर श्रेणी में अलग से लागू किया जाता है।
- दो प्रकार के आरक्षणों का इंटरलॉकिंग कुछ समूहों की पहचान करता है कि कैसे कुछ समूहों की पहचान की जाए।
- उदाहरण के लिए एक एससी महिला को महिलाओं या एससी की श्रेणी में रखा जाएगा?

जी किशन रेड्डी समिति का गठन किया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II- नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में-

- केंद्र सरकार ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है और केंद्रशासित प्रदेश के विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- समिति का नेतृत्व गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे।
- इसमें लद्दाख, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- समिति के गठन का निर्णय लद्दाख के **10** सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद लिया गया, जिन्होंने लद्दाख की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए।

पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (संपत्ति व जानवरों की देखभाल और रखरखाव) नियम, 2017 पर SC का आदेश

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II- न्यायपालिका

समाचार में-

- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अपने तीन साल पुराने कानून को हटाने के लिए कहा है।
- पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (संपत्ति व जानवरों की देखभाल और रखरखाव) नियम, **2017** को **23** मई, **2017** को अधिसूचित किया गया है।
- अधिनियम के तहत ये नियम न्यायाधीश को मुकदमे का सामना कर रहे किसी व्यक्ति के मवेशियों को जब्त करने की अनुमति देते हैं।
- इन नियमों को क्रूरता निवारण अधिनियम, **1960** के तहत बनाया गया था।
- इसने उन लोगों से पशुधन को जब्त करने की अनुमति दी, जो आजीविका के लिए इन जानवरों पर निर्भर थे और उन्हें उनके प्रति क्रूरता का दोषी पाया जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- विधी के अनुसार, इन जानवरों को अदालत के फैसले तक संपत्ति के रूप में गौशालाओं में रखा जाएगा।

- इस प्रकार, एक किसान, एक पशुधन मालिक या एक पशु व्यापारी क्रूरता के आरोप का दोषी पाए जाने से पहले अपने पशुओं को खो देता है।
- ये नियम स्पष्ट रूप से पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 29 के विपरीत हैं, जिसके तहत क्रूरता का दोषी पाया गया व्यक्ति केवल अपने जानवरों को खो सकता है। सरकार से कहा गया है कि या तो वह इन नियमों में बदलाव करे या न्यायालय से स्टे ले ले।

क्या आप जानते है?

- **2017** के नियम मजिस्ट्रेट को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमे का सामना करने वाले मालिक के मवेशियों को जब्त करने की अनुमति दे सकता हैं।
- इसके बाद जानवरों को पशु चिकित्सालय (**Infirmaries),** पशु आश्रयों इत्यादि में भेज दिया जाता है।
- ऐसे जानवरों को अधिकारियों द्वारा गोद भी दिया जा सकता है।

केंद्र ने AGMUT के साथ जम्मू और कश्मीर कैडर के अधिकारियों को शामिल किया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II- नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में-

- हाल ही में, केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT) के साथ-साथ ऑल इंडिया सर्विसेज - आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस अधिकारियों के लिए जम्मू-कश्मीर कैडर को एक अध्यादेश के माध्यम से विलय किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, **2019** में संशोधन करने और जम्मू-कश्मीर के मौजूदा कैडर के आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को एजीएमयूटी कैडर का एक हिस्सा बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है।
- इस कदम से इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर में काम करने वाले अधिकारियों को काम करने की सुविधा मिलेगी।
- यह जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के अधिकारियों को जम्मू और कश्मीर राज्य सिविल सेवा (कश्मीर प्रशासनिक सेवा) से पदोन्नत करने के लिए **67:33** के बजाय **50:50** पर पदोन्नत करने के लिए पहले के नियम के कारण जम्मू और कश्मीर में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की कमी से निपटने में मदद करेगा। अन्य राज्यों में इस नियम का पालन किया गया।

Related articles:

- MARCOS being deployed in the Eastern Ladakh: Click here
- DAY-NRLM Special Package for J&K and Ladakh: Click here

बगसरा प्रान्त: गुजरात में निर्मित नवीन जिला

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II- नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में-

- गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अमरेली जिले में नया बगसरा प्रांत बनाने का निर्णय लिया है।

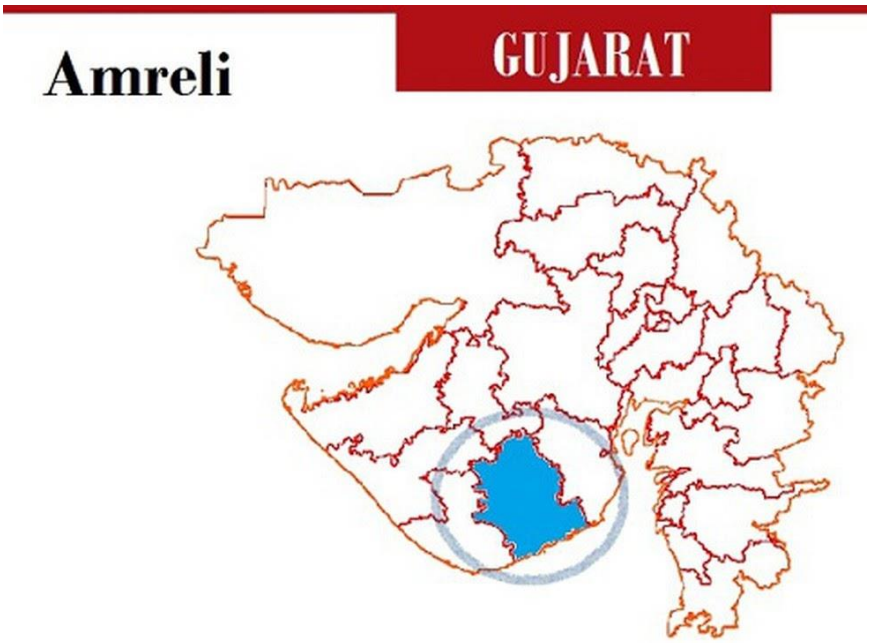

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह राज्य की राजस्व सेवाओं को लोगों के पास ले जाएगा और तेजी से सेवाएं प्रदान करेगा।
- इससे राज्य की राजस्व सेवाएं आम जनता तक तेज़ी और आसानी से पहुंच जाएंगी।
- चूंकि बड़े भौगोलिक क्षेत्रों वाले जिले लोगों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं, राज्य सरकार प्रशासनिक सुविधा, तेजी से विकास के लिए छोटे जिलों और तालुकाओं का पुनर्गठन कर रही है, जिससे लोगों के समय की बचत के साथ-साथ काम का बोझ भी कम हो रहा है।

क्या आप जानते है?

- प्रांत का यह नाम ऐतिहासिक क्षेत्रों के कुछ हिस्सों के लिए पारंपरिक नाम हैं, जैसे गुजरात में सौराष्ट्र प्रायद्वीप पर काठियावाड़ के मूल क्षेत्र।

पुडुचेरी में सत्ता का बिगुल: उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच

संदर्भ: लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी के खिलाफ सेक्युलर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव एलायंस के बैनर तले पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के नेतृत्व में हाल ही में तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन हुआ।

पुडुचेरी के सीएम, उपराज्यपाल के खिलाफ क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं?

- **दिन-प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप:** सत्तारूढ़ गठबंधन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर पर सरकार के दिन-प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप करने और विकास योजनाओं को बाधित करने का आरोप लगाया है।
- **राज्य निर्वाचन आयोग के लिए नियुक्ति:** वे कई मामलों में लॉगरहेड्स पर रहे हैं, हाल ही में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर, केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए एक कार्यालय महत्वपूर्ण है।
- **कल्याणकारी योजना के कार्यान्वयन पर रोक:** बेदी पर चुनी हुई सरकार की अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों को रोकने का आरोप लगाया था। इन कार्यक्रमों में राशनकार्ड धारकों को मुफ्त चावल और पोंगल बोनस दिया जाना और कॉरपोरेशन, सोसायटी और सरकार द्वारा वित्त पोषित निजी स्कूलों के लिए योजनाएं लागू किया जाना शामिल था।
- **लोकतांत्रिक भागीदारी:** पुलिस ने उच्च और तकनीकी शिक्षा के निदेशक को सभी छात्रों को एक सलाहकार जारी करने के लिए कहा, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने से बचना चाहिए। इससे पहले पुलिस ने कथित रूप से कांग्रेस द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया, जिसमें मांग की गई कि केंद्र एमबीबीएस पाठ्यक्रम में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे।
- **आंदोलन की मांग:** आंदोलन उपराज्यपाल को वापस बुलाने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों की मांग को उजागर करने के लिए था। निर्वाचित सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर सुश्री किरण बेदी पर "निरंकुश तरीके से कार्य करने" का आरोप लगाया कि उन्होंने लोगों की प्रगति और कल्याण सुनिश्चित करने में "रुकावटवादी रवैया" अपनाया है।

सीएम और उपराज्यपाल के बीच पावर टसल के पिछले उदाहरण

- **विधान सभा में मनोनीत सदस्य:** जुलाई 2017 में, कांग्रेस के सदस्यों ने मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना केंद्र द्वारा भाजपा के तीन मनोनीत सदस्यों को विधानसभा में शामिल करने का विरोध किया।
- **शासन और नीति निर्माण:** 2018 में, उपराज्यपाल बेदी ने घोषणा की कि ग्रामीणों को सरकार की मुफ्त चावल वितरण योजना को इस प्रमाणन के लिए सशर्त बनाया जाएगा कि गाँव खुले में शौच, कचरा और प्लास्टिक से मुक्त हो। सीएम ने दावा किया कि बेदी का कदम एनएफएसए, 2013 के खिलाफ था और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं और इसे अपने परामर्श के बिना लागू कर सकते हैं
- **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:** 2019 में, बंद औद्योगिक इकाइयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को फिर से खोलने की मांग करते हुए, सीएम द्वारा एक समान विरोध प्रदर्शन किया गया था।
- **महामारी के बीच नए साल का जश्न:** 31 दिसंबर 2020 को, बेदी ने महामारी को देखते हुए नए साल के जश्न की अनुमति देने के सरकार के कदम पर आपत्ति जताई और सरकार से इसे प्रतिबंधित करने का आग्रह किया। हालांकि, सीएम अपने फैसले पर अडिग थे और कहा कि नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति या अधिकार किसी के पास नहीं है, यह कहते हुए कि केंद्र शासित प्रदेश फ्रांस की संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इसकी एक अलग पहचान है।

विरोध का समालोचनात्मक विश्लेषण

- राजनीतिक कारण: अप्रैल या मई में विधानसभा चुनाव होने की संभावना के साथ, उपराज्यपाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले सीएम राजनीतिक लामबंदी का कार्य कर सकते हैं और अपनी सरकार की "गैर-कामकाज" के खिलाफ किसी भी आलोचना को दूर करने के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं।
- आम आदमी पर प्रभाव: एलजी और सीएम के बीच सत्ता का टकराव दैनिक प्रशासनिक गतिविधियों को धीमा कर देता है, जिसके कारण जनता को उचित सेवाएं नहीं मिलने का खामियाजा उठाना पड़ेगा।
- केंद्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता: उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संचार के निकट टूटने के साथ, केंद्र को सुचारू प्रशासन के हित में कदम उठाना चाहिए।

पुडुचेरी के एलजी की शक्तियां क्या हैं?

- केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, **1963** "पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश" पर शासन करने के लिए मंत्रिपरिषद के साथ पांडिचेरी की एक विधान सभा का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि संघ शासित प्रदेश को प्रशासक (एलजी) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाएगा। इसके निम्नलिखित प्रावधान भी हैं।
- **विधायी शक्ति का विस्तार** - विधायक "राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में पूरे या केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकते हैं।"
- **मंत्रिपरिषद -** एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद उन मामलों के संबंध में अपने कार्यों के अभ्यास में प्रशासक को सलाह देगी, जिनके संबंध में केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा में कानून बनाने की शक्ति है।
- **एलजी का विवेक:** केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, **1963** की धारा **44,** एलजी को कानून बनाने के मामले में "अपने विवेक से काम करने" की अनुमति देता है, भले ही मंत्रिपरिषद का काम उसे सलाह देने का है।
- किसी भी मामले पर एलजी और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद के मामले में, प्रशासक इसे राष्ट्रपति के एक निर्णय के लिए संदर्भित करने और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है।
- हालांकि, प्रशासक यह भी दावा कर सकता है कि अगर मामला जरूरी है, और वह तुरंत कार्रवाई कर सकता है क्योंकि यह आवश्यक है।
- मुख्यमंत्री के साथ संबंध**: 22** जून, **1963** को जारी किए गए पांडिचेरी, **1963** के एलजी ने जिस तरह से चुनी हुई सरकार (मंत्रिपरिषद) के नियमों को लागू किया है, वह सरकार के व्यापार के नियमों में वर्णित है।
- प्रशासक, मुख्यमंत्री के परामर्श पर, यूटी सरकार में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करता है।
- यदि एलजी के पास मुख्यमंत्री के साथ मतभेद है, तो वह राष्ट्रपति के निर्णय के लिए केंद्र सरकार को मामले को संदर्भित कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- दिल्ली और पुदुचेरी दोनों में एक निर्वाचित विधायिका और सरकार है, लेकिन पुडुचेरी के एलजी की शक्तियाँ दिल्ली के एलजी से अलग हैं।

- दिल्ली के एलजी के पास "कार्यकारी कार्य" हैं जो उन्हें सार्वजनिक आदेश, पुलिस और भूमि से जुड़े मामलों में अपनी शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं "मुख्यमंत्री के परामर्श से, यदि यह राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश के तहत अनुच्छेद 239 के तहत प्रदान किया जाता है"।
- जबकि दिल्ली के एलजी को दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 द्वारा निर्देशित किया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 के अनुसार पुदुचेरी के एलजी को सरकार द्वारा निर्देशित किया जाता है।
- संविधान के अनुच्छेद 239 और 239AA, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991, स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां केंद्र परिवेक्षक हैं, यह पुदुचेरी की तुलना में अधिक प्रमुख भूमिका है।
- संवैधानिक योजना के तहत, दिल्ली विधानसभा में कानून और व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है।
- हालांकि, पुडुचेरी विधानसभा किसी भी मुद्दे पर समवर्ती और राज्य सूची के तहत कानून बना सकती है। यदि कानून संसद द्वारा पारित कानून के विरोध में है, तो संसद द्वारा पारित कानून प्रबल होता है।
- सीधे शब्दों में कहें, तो दिल्ली का एलजी को पुदुचेरी के एलजी की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त है।

SC ने फार्म कानून समिति का गठन किया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II- न्यायपालिका

समाचार में-

- सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है।
- इसने गतिरोध को हल करने के लिए केंद्र और किसान यूनियनों के बीच बातचीत की सुविधा के लिए कृषि विशेषज्ञों की एक समिति भी बनाई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सदस्यों में शामिल हैं: (1) भारतीय किसान यूनियन और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान; (2) डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, एक कृषि अर्थशास्त्री जो दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक भी हैं; (3) कृषि अर्थशास्त्री और कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुलाटी; (4) शेतकारी संगठन के प्रमुख अनिल घणावत, जिन्होंने मीडिया में लिखे लेखों में कृषि कानूनों के पक्ष में विचार व्यक्त किए हैं।
- मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समिति एक आदेश पारित नहीं करेगी या दंडित नहीं करेगी और सर्वोच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- SC ने कहा है कि समिति इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया है।

Related articles :

- Your views on farm laws: Click here
- Failed negotiations on farm laws: Click here

मणिपुर स्थानीय शहरी निकाय सुधारों को पूरा करने वाला चौथा राज्य बना

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II- शहरी स्थानीय निकाय

समाचार में-

- "शहरी स्थानीय निकाय (ULB)" सुधारों को सफलतापूर्वक करने के लिए मणिपुर देश का 4 वां राज्य बन गया है
- सुधारों को 17 मई, 2020 के राज्यों को लिखे अपने पत्र में वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मणिपुर अब ओपन मार्केट उधार के माध्यम से 75 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है।
- यह अब तीन अन्य राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के साथ उस सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने इस सुधार को पूरा कर लिया है।
- शहरी स्थानीय निकायों में सुधार और शहरी उपयोगिताओं में सुधार का उद्देश्य राज्यों में यूएलबी की वित्तीय प्रगति करना और उन्हें बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाना है।
- आर्थिक रूप से पुनर्जीवित यूएलबी भी अच्छे नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में सक्षम होंगे।

विवाह की सूचना का प्रकाशन अनिवार्य नहीं

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I - सोसायटी और GS- II - न्यायपालिका

समाचार में-

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह के नोटिस के प्रकाशन का प्रावधान अनिवार्य नहीं है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- न्यायालय ने कहा कि विवाह संबंधित नोटिस के अनिवार्य प्रकाशन से संबंधित प्रावधान दोनों पक्षों की स्वतंत्रता और गोपनीयता संबंधी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, विवाह में शामिल दोनों पक्षों को राज्य एवं गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं के हस्तक्षेप के बिना विवाह के लिये अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार है।
- अधिनियम की धारा 5 के तहत नोटिस देते समय, यह विवाह के लिए पार्टियों के लिए वैकल्पिक होगा कि वे विवाह अधिकारी से लिखित रूप में अनुरोध करें कि वह धारा 6 के तहत नोटिस प्रकाशित न करें और आपत्तियों की प्रक्रिया का पालन करें। अधिनियम के तहत निर्धारित।
- धारा 5 और 6 के तहत विवाह करने के इच्छुक पक्षों के लिये यह अनिवार्य है कि वे अथवा उनमें से कोई एक पक्ष जो कि पिछले तीस दिनों से जिस क्षेत्र में निवास कर रहा है, वहाँ के संबंधित विवाह अधिकारी को अपने विवाह संबंधी नोटिस दे। इसके पश्चात् विवाह अधिकारी अपने कार्यालय में विवाह की सूचना प्रकाशित करता है।
- यदि पक्षकार ऐसा कोई अनुरोध नहीं करते हैं, तो अधिकारी "इस तरह के नोटिस को प्रकाशित नहीं करेगा या विवाह पर आपत्ति नहीं जताएगा और विवाह की पूर्णता के साथ आगे बढ़ेगा"।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा)

प्रावधान

- यह अधिनियम निर्धारित करता है कि किसी भी परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजना योजनाओं के बिना बेचा नहीं जा सकता है और परियोजना को नियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए,यह धोखेबाजी के आधार पर विज्ञापनों के द्वारा रियल एस्टेट को बेचने की प्रथा को समाप्त कर सकता है।
- फंड डायवर्जन को रोकने के लिए प्रमोटरों को "प्रोजेक्ट आधारित अलग बैंक खाते" बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
- अनुचित व्यापार प्रथाओं के मूल में "कालीन क्षेत्र" के आधार पर यूनिट के आकार का अनिवार्य प्रकटीकरण।
- प्रमोटर या खरीदार द्वारा डिफ़ॉल्ट के मामले में इक्विटी के "ब्याज की समान दर" के भुगतान का प्रावधान।

लाभ

- इन और कई अन्य प्रावधानों ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाया है, इस क्षेत्र में प्रचलित विद्युत विषमता को सुधारते हुए।
- RERA ने एक गैर-अधिकृत रियल एस्टेट क्षेत्र में शासन को प्रभावित किया है।
- विमुद्रीकरण और GST के साथ, इसने काफी हद तक काले धन के अचल संपत्ति क्षेत्र को साफ कर दिया है।
- इसमें कई परिवर्तनकारी प्रावधान हैं, कर्तव्यनिष्ठा से उन मुद्दों को संबोधित किया गया है जो इस क्षेत्र के लिए एक निरंतर प्रतिबंध रहा है।

सहकारी संघवाद

- RERA सहकारी संघवाद में एक मौलिक प्रयास है।

- हालांकि अधिनियम को केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया गया है, नियमों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाना है, और नियामक अधिकारियों और अपीलीय न्यायाधिकरणों को भी उनके द्वारा नियुक्त किया जाना है।

निष्कर्ष

- आरईआरए रियल एस्टेट क्षेत्र में वैसे ही कार्यरत है, जिस प्रकार सेबी प्रतिभूति बाजार के लिए है।

IBC की धारा 32 A

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड **(IBC)** की धारा 32 A के तहत एक कॉर्पोरेट देनदार के लिए सफल बोलीदाता इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड **(IBC)** के तहत किसी भी जांच एजेंसियों जैसे प्रवर्तन निदेशालय **(ED)** या अन्य वैधानिक निकायों द्वारा कि गयी जाँच की प्रतिरक्षा करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- समयबद्ध तरीके से कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के दिवालिया होने और दिवालियापन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए **28** मई, **2016** को **IBC** लागू किया गया था।
- इसने इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन से संबंधित कानूनों में प्रतिमान बदलाव को प्रस्तुत किया है
  - उद्यमिता को बढ़ावा देना
  - संपत्ति का अधिकतम मूल्य
  - एक मजबूत दिवालालिया रिज़ॉल्यूशन को ढांचा प्रदान करना
  - अव्यवहारिकता और व्यापार असफलता के बीच अंतर करना
- **IBC** कानून का एक परिवर्तनकारी भाग है और संहिता के उद्देश्यों में बाधा डालने वाली समस्याओं के समाधान के लिए इसमें चार बार संशोधन किया गया है।
- धारा **32A (IBC** (द्वितीय संशोधन) विधेयक, **2019** द्वारा पेश) के सम्मिलन से पहले एक सफल संकल्प आवेदक को कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व कृत्यों के लिए अदालतों और न्यायाधिकरणों के समक्ष अभियोजन और देनदारियों की परेशानी का सामना करना पड़ाता था
- धारा **32** A में प्रावधान है कि एक बार रिज़ॉल्यूशन अथॉरिटी (RA) द्वारा रिज़ॉल्यूशन प्लान को मंजूरी दिए जाने से पहले और कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस **(CIRP)** शुरू करने से पहले किए गए अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?

- **IBC की धारा 32A को बरकरार रखा:** अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने **IBC** की धारा **32 A** की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि **IBC** के लिए ऐसे बोलीदाताओं को आकर्षित करना महत्वपूर्ण था जो कॉरपोरेट देनदार के लिए उचित मूल्य की पेशकश करेंगे। इससे कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस **(CIRP)** समय पर पूरा होगा।

- **संरक्षण प्रदान करना:** ऐसे बोलीदाताओं को, हालांकि, अतीत के किसी भी अपराध से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि उनके पास इसके लिए कुछ भी नहीं था। इस प्रकार इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदार की आपराधिक देयता को समाप्त करना है।
- **देनदार की परिसंपत्तियों के लिए विस्तारित सुरक्षा:** इस तरह की सुरक्षा के लिए, अदालत ने कहा, एक कॉर्पोरेट देनदार को संपत्ति का भी विस्तार किया जाना चाहिए, जो संभावित बोलीदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण बनाता है और कंपनी के लिए उचित बोली का आकलन करने और रखने में उनकी मदद करता है, जो बदले में, बैंकों को बुरे ऋणों की अपने खतों से हटाने में मदद करेगा।
- **प्रतिरक्षा के लिए शर्तें:** सफल बोलीदाताओं को सुरक्षा और एक कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति IBC की धारा 32 A के तहत नियमों द्वारा प्रदान की जाती है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि इस तरह की प्रतिरक्षा तभी लागू होगी जब कोई अनुमोदित संकल्प योजना हो, और कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन नियंत्रण में बदलाव करती हो
- "नया प्रबंधन पुराने प्रबंधन का प्रच्छन्न अवतार नहीं हो सकता है। यह कॉरपोरेट देनदार की संबंधित पार्टी भी नहीं हो सकती है। नया प्रबंधन एक जांच का विषय नहीं हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अपराध के कमीशन के लिए अभियोग या साजिश दिखाने वाली सामग्री और रिपोर्ट या शिकायत दायर की गई है, इसे "शीर्ष अदालत ने आयोजित किया।

SC के अनुसार धारा 32 ए को क्यों बरकरार रखा जाना जरूरी है?

- **संकल्प में देरी:** 2016 में जब से IBC अस्तित्व में आया है, कई बड़ी टिकट मामलों की संकल्प योजना के कार्यान्वयन में देरी हुई है, क्योंकि इसकी अपनी एजेंसियों और नियामकों द्वारा विभिन्न चुनौतियों का सामना किया गया है।
- **भूषण पावर एंड स्टील का उदाहरण:** 2017 में इन्सॉल्वेंसी में भर्ती हुई कर्ज से भरी कंपनी का बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों पर 47,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है और इसके परिचालन लेनदारों को 780 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। लंबे समय तक बोली लगाने की लड़ाई के बाद, JSW स्टील ने 19,700 करोड़ रुपये की बोली के साथ भूषण पावर पर अधिकार कर लिया।
- हालांकि, इससे पहले कि सज्जन जिंदल की अगुवाई वाली कंपनी भूषण पावर को अपने कब्जे में ले सकती थी, ईडी ने छापा मारा और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कंपनी के पूर्व मालिकों द्वारा लिए गए बैंक ऋण और अन्य मामलों में कथित धोखाधड़ी का हवाला देते हुए 4,000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली।।

SC का फैसला

- **इन्सॉल्वेंसी केसेस का त्वरित समाधान:** SC निर्णय IBC की धारा 32 A में स्पष्टता लाता है और कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन की प्रक्रिया को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करता है। धारा 32 A की वैधता को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट, भूषण पावर जैसे मामलों की उम्मीद करता है
- **IBC के विश्वास में वृद्धि**: विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि इससे अन्य बोलीदाताओं को ऐसी विवादित कंपनियों और उनकी परिसंपत्तियों पर बोली लगाते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा

- **नए प्रबंधन को स्वच्छ बनाने में मदद करता है:** कॉरपोरेट देनदार की आपराधिक देनदारी का बुझना नए प्रबंधन के लिए अतीत के साथ एक साफ ब्रेक बनाने और एक साफ स्लेट पर शुरू करने के लिए स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है।

गणतंत्र दिवस पर हिंसा

संदर्भ: दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के सिलसिले में 200 लोगों को हिरासत में लिया है। लाल किले में और उसके आसपास हुई हिंसा में 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

वास्तव में क्या हुआ?

- **घटना की पृष्ठभूमि:** लगभग दो महीने से पंजाब के किसान मुख्य रूप से नई दिल्ली के बाहरी इलाके में डेरा डाले हुए थे और नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। सरकार और किसानों की यूनियनों के बीच कई दौर की वार्ता विफल रही है।
- **ट्रैक्टर रैली नियोजित:** प्रदर्शनकारी किसानों ने अपनी मांगों को व्यक्त करने और उनकी आवाज़ सुनने के लिए गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली की ओर ट्रैक्टर रैली की योजना बनाई थी। यह लाखों किसानों और ट्रैक्टरों द्वाराआयोजित एक ऐतिहासिक परेड थी।
- **रैली ने हिंसात्मक मोड़ लिया:** जबकि ट्रैक्टर रैली शुरू में शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई, प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग पुलिस बैरिकेड्स के माध्यम से टूट गया और उनके विरोध के लिए राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में प्रवेश नहीं किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई स्थानों पर झड़पें हुईं जिसमें लगभग 400 पुलिस कर्मी घायल हो गए।
- **प्रस्तावित पथ और समय से विचलन:** अनियंत्रित अनुभाग द्वारा लिया गया पथ कथित रूप से उस मार्ग से भटक गया है, जो किसान यूनियनों ने दिल्ली पुलिस के साथ उनकी वार्ता में सहमति व्यक्त की थी। इसके अलावा, किसानों ने निर्धारित समय से पहले ही राजधानी में प्रवेश करने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने उन पर आंसू गैस और बैटन के हमले शुरू किए।
- **लाल किले पर धार्मिक ध्वज:** गणतंत्र दिवस की सैन्य परेड के लिए जगह में विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए, प्रदर्शनकारियों ने लाल किले में प्रवेश किया, जहाँ मुख्य रूप से सिख किसानों ने एक धार्मिक झंडा भी लगाया।
- **कानून और व्यवस्था नियंत्रण के उपाय:** बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों ने कई मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के लिए मजबूर किया, जबकि राजधानी और इसके आस-पास के कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं। पुलिस ने रात में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया।
- पुलिस ने कई वरिष्ठ कृषक नेताओं का नाम लेते हुए FRI दर्ज की है जिन्होंने सरकार के साथ बातचीत की थी और जिन्होंने परेड के लिए निर्धारित शर्तों का पालन करने का वादा किया था।

घटना का आलोचनात्मक विश्लेषण

- **थके हुए आंदोलनकारी:** आंदोलनकारियों द्वारा हिंसा की संभावना अधिक थी क्योंकि हिंसा के कारण निहित स्वार्थों को पूरा करने की संभावनाएं थीं। इसलिए, विरोध के नेताओं को इस बारे में अधिक सचेत होना चाहिए था।

- बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट को कृषि नेतृत्व द्वारा समन्वित किया गया: नेतृत्व, जो खुद को असमान व्यक्तियों और संगठनों का एक संघ मानता है, उसे इस तरह के एक सभा को प्रबंधित करने की क्षमता के बारे में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए था।
- **मुट्ठी भर हिंसक विचलन:** राष्ट्रीय राजधानी पर किसानों द्वारा गणतंत्र दिवस पर विरोध प्रदर्शन करने की एक धारा द्वारा फैलायी गयी अराजकता और नासमझी की हिंसा घृणास्पद थी। ऐसी भी संभावना है कि एजेंटों ने किसानों के मार्च में घुसपैठ की और हिंसा की ओर ले जाने वाली पूरी योजना को पटरी से उतार दिया।
- **पुलिस द्वारा संयम:** अंत में, दिल्ली की सड़कों पर अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ दिया, पुलिस वालों पिटाई की और पुलिस कर्मियों को नीचे उतारने की कोशिश की। पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन हालात को देखते हुए, फायरिंग और अन्य कठोर उपायों का प्रयोग नहीं करने में संयम दिखाया।
- **किसानों के विरोध की योजना में बदलाव:** गणतंत्र दिवस हिंसा को लेकर दो किसान यूनियनें कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन से पीछे हट गए। यूनियनों ने 1 फरवरी को संसद में मार्च करने की अपनी योजना को रद्द कर दिया है, जब केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखने की कसम खाई है।
- **सरकार के साथ बातचीत को बदल सकते हैं:** ट्रैक्टर रैली के दौरान जो हिंसा हुई थी, वह आंदोलनकारी किसानों के लिए असहमति लेकर आई है और उनके आंदोलन और मांगों को खारिज करने के लिए किए गए प्रयास हैं। उचित समय में, यह सरकार को किसानों के साथ बातचीत के लिए संलग्न करने के तरीके को बदल सकता है।

आगे की रह

- **उचित जांच:** दिल्ली पुलिस को हिंसा के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और समूहों की जांच करनी चाहिए। किसान नेताओं के पास जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने का अकल्पनीय कार्य है।
- **सांप्रदायिक रूप देने से रोकना:** आंदोलनकारियों के झूठे दोस्तों और असली दुश्मनों ने उन्हें एक सांप्रदायिक स्वरुप (धार्मिक ध्वज फहराना) के साथ चित्रित किया है। अपराधियों को पुस्तक में लाना न केवल एक आंदोलन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, जो लगभग दो महीनों तक काफी हद तक शांत रहा, बल्कि नियंत्रण से बाहर, एक खतरनाक सांप्रदायिक स्वरूप देने का भी प्रयास है।
- **प्रदर्शनकारियों की अधिकतम स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता है:** आंदोलनकारी चाहते हैं कि कानून लॉक, स्टॉक और बैरल पर जाएं, लेकिन उनका अधिकतम दृष्टिकोण अप्रभावी है। बाद में इसे फिर से शुरू करने के विकल्प को नष्ट करते हुए, उन्हें अभी के लिए विरोध बंद करना चाहिए और भीड़ को तितर-बितर करना चाहिए। उन्हें कानूनों के पूर्ण निरसन के विकल्पों पर विचार करना चाहिए।
- **केंद्र को बातचीत के लिए जारी रखना चाहिए:** केंद्र को और अधिक रियायतों पर विचार करना चाहिए, जिसमें कानूनों का निलंबन शामिल है जब तक कि एक व्यापक समझौता नहीं किया जा सकता है। इन सुधारों से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों के डर को दूर करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे।

निष्कर्ष

- केंद्र ने कहा है कि वह प्रदर्शनकारियों को बातचीत में शामिल करना जारी रखेगा। सरकार के प्रस्ताव को **18** महीने तक बरकरार रखने के लिए तीन विवादास्पद कृषि कानून जो वर्तमान विवाद के केंद्र में हैं, कृषक नेताओं के लिए एक समझौता का अवसर है।

Connecting the dots

- Why farmers are protesting against farm laws: Click here and here
- Why earlier government negotiations have failed: Click here
- What is the long term solution advocated by experts: Click here

---

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

संदर्भ: हाल ही में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद: संघर्ष और प्रतिज्ञा नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक लेखों, समाचारों और अन्य सामग्रियों का संग्रह जो इस पर आधारित है कि कर्नाटक में मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में एकीकृत किया जाना चाहिए।

समाचार में

- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार कर्नाटक के क्षेत्रों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां मराठी भाषी लोग अपने राज्य में बहुमत में हैं, इससे पिछले छह दशकों से चल रहे सीमा विवाद को उकसाने वाले तत्व के रूप में देखा जा सकता है।
- बेलगाम या बेलगावी, एक बड़ी मराठी भाषी आबादी है, वर्तमान में यह कर्नाटक का हिस्सा है और महाराष्ट्र द्वारा इस पर अधिकार का दावा किया जाता है।
- महाराष्ट्र इस भूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया है और दूसरी तरफ कर्नाटक ने बेलागवी को अपनी दूसरी राजधानी घोषित किया है

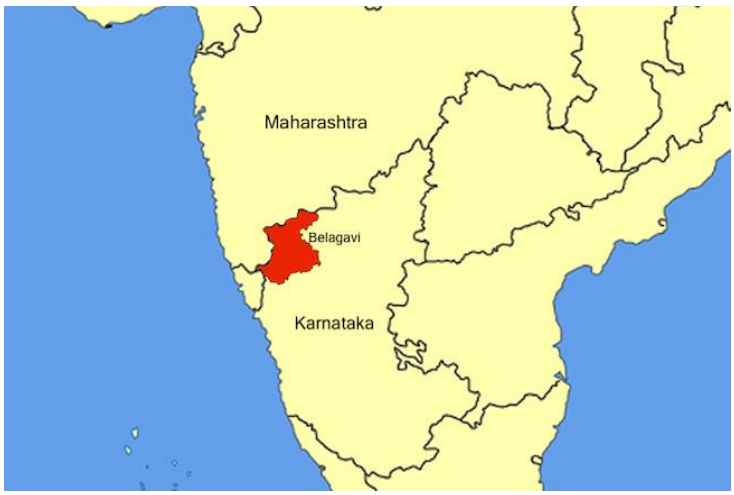

चित्र स्रोत: न्यूज़ मिनट

समस्या की प्रारंभ

- **सीमावर्ती जिले में बहुभाषी जनसंख्या:** बेलगाम, जिसे बाद में बेलगावी नाम दिया गया था, वर्तमान के कर्नाटक के उत्तरी भाग में स्थित है और महाराष्ट्र के कोहलापुर जिले के साथ एक सीमा साझा करता है। बेलगावी जिले में कन्नड़ और मराठी भाषी दोनों हैं।
- **औपनिवेशिक टाइम्स:** ब्रिटिश राज के दौरान, बेलगाम क्षेत्र बॉम्बे प्रेसीडेंसी का हिस्सा था, जिसमें विजयपुरा, बेलागवी, धारवाड़ और उत्तर-कन्नड़ जैसे कर्नाटक जिले शामिल थे।
- **1881 जनगणना के आंकड़े:** 1881 की जनगणना के अनुसार, बेलगाम में 864,014 लोग थे, जिनमें से 556,397 कन्नड़ भाषी (64.39%) थे, जबकि **225,008** मराठी भाषी (26.04%) थे। हालाँकि, 1948 में, मराठी भाषी राजनेताओं के प्रभुत्व वाले बेलगाम नगर पालिका ने केंद्र से अनुरोध किया कि जिले को प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य में शामिल किया जाए।
- **स्वतंत्रता के बाद का पुनर्गठन:** 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून लागू हुआ तो बेलगाम को महाराष्ट्र की जगह मैसूर स्टेट का हिस्सा बना दिया गया और मैसूर स्टेट का नाम बदलकर 1973 में कर्नाटक हो गया। बेलगाम में मराठी बोलने वालों की संख्या काफी होने की वजह से इसे महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की मांग राज्य पुनर्गठन के समय से ही हो रही है।
- **महाराष्ट्र द्वारा उठाए गए आपत्ति:** महाराष्ट्र ने इस पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि 1956 में, मराठी भाषियों ने उन क्षेत्रों में कन्नड़ बोलने वालों को पछाड़ दिया था। इसने गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें 7,000 वर्ग किमी की मांग की गई जिसमें 814 गाँव शामिल थे, और बेलगावी, कारवार और निप्पनी (ब्रिटिश राज में सभी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे) की तीन शहरी बस्तियों को महाराष्ट्र में जोड़ा जाना था।
- **कर्नाटक द्वारा मांगें:** दूसरी ओर, कर्नाटक ने महाराष्ट्र से कोल्हापुर, शोलापुर और सांगली जिलों और केरल से कासरगोड को अपने राज्य में शामिल करने के लिए क्षेत्र की मांग की है।

विवाद को हल करने के लिए बात करता है

- समिति का गठन: जैसा कि विवाद चल रहा था, दोनों राज्यों ने बातचीत के माध्यम से मामले को सुलझाने का फैसला किया। 1960 में, दोनों राज्यों ने एक अध्ययन और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, प्रत्येक राज्य के दो सदस्यों के साथ एक चार-सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया।
- **क्षेत्रों के आदान-प्रदान की पेशकश:** इस प्रक्रिया के दौरान, महाराष्ट्र ने 814 गांवों और तीन शहरी बस्तियों की मांग के बदले 260 कन्नड़ भाषी गांवों को स्थानांतरित करने की पेशकश की।
- **सर्वसम्मति का अभाव:** हालाँकि, दोनों राज्य समिति के निष्कर्षों के बाद किसी भी आम सहमति में नहीं आ सके। इसके बाद के वर्षों में, दोनों सरकारों के बीच कई वार्ताएं हुईं, जो बिना किसी प्रस्ताव के समाप्त हो गईं

महाजन आयोग

- **संघ सरकार द्वारा गठित आयोग:** महाराष्ट्र सरकार के विरोध के बाद, 1966 में, केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को देखने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन के अधीन आयोग का गठन किया। केरल में कासरगोड में कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के एकीकरण के लिए कर्नाटक की मांग को देखने के लिए भी कहा गया था। आयोग ने 1967 में केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी और 1972 में संसद में रखा गया।
- **आयोग की सिफारिश:** आयोग ने महाराष्ट्र के सीमावर्ती महाराष्ट्र के **260** गाँवों और महाराष्ट्र के **250** गाँवों को कर्नाटक में स्थानांतरित करने की सिफारिश करते हुए बेलगावी शहर पर महाराष्ट्र के दावे को खारिज कर दिया।
- **कासरगोड मुद्दा:** महाजन आयोग ने केरल में क्षेत्रों के लिए मैसूर के दावों को भी बरकरार रखा और केरल में कासरगोड तालुक, चंद्रगुरी नदी के दक्षिण में स्थित आठ गांवों को मैसूर में स्थानांतरित करने की सिफारिश की।

महाजन आयोग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया

- **महाराष्ट्र:** महाराष्ट्र सरकार ने रिपोट को अस्वीकार कर दिया और रिपोर्टों के निष्कर्षों को पक्षपाती और आत्म-विरोधाभासी करार दिया क्योंकि बेलगाम के लिए कासरगोड के लिए "सूत्र" लागू नहीं किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने जोर देकर कहा कि रिपोर्ट बेलगाम के "लोगों की इच्छा" के खिलाफ है।
- **केरल:** केरल सरकार ने रिपोर्ट की सिफारिशों का खंडन किया और कासरगोड को कर्नाटक को सौंपने से इनकार कर दिया।
- **कर्नाटक:** कर्नाटक सरकार ने रिपोर्ट के क्रियान्वयन या यथास्थिति बनाए रखने के लिए रिपोर्ट का स्वागत करना जारी रखा।
- **केंद्र:** कर्नाटक की मांगों के बावजूद, केंद्र ने कभी भी रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू नहीं किया। बल्कि यह सीमा विवाद को सुलझाने पर गैर-कमिटेड रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में मामला

- 2004 में, महाराष्ट्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 (B) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
- अपनी याचिका में, महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया कि कर्नाटक में मराठी भाषी आबादी को दरकिनार किया जा रहा था और उनके बीच असुरक्षा की भावना व्याप्त है।'
- महाराष्ट्र ने कहा है कि कर्नाटक में बेलगाम, कारवार, बीदर और गुलबर्गा जिलों के 814 गाँवों को उनके अधिकार क्षेत्र में लाया जाये, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक मराठी भाषी लोग शामिल थे।
- इस मामले की सुनवाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है।

महाराष्ट्र के तर्क

- महाराष्ट्र ने अपनी सीमा के पुन: निर्धारित करने का दावा किया था, जो कि आकस्मिकता, सापेक्ष भाषाई बहुमत और लोगों की इच्छाओं के आधार पर था।
- यदि बेलागवी और आसपास के क्षेत्रों का दावा मराठी भाषी लोगों और भाषाई समरूपता पर आधारित था, तो उसने करवार और सुपा पर अपना दावा रखा जहां कोंकणी को मराठी की बोली के रूप में उद्धृत किया जाता है।
- इसका तर्क गाँव के सिद्धांत की गणना पर आधारित था और प्रत्येक गाँव में भाषाई आबादी की गणना करना था।

- महाराष्ट्र ऐतिहासिक तथ्य यह भी इंगित करता है कि इन मराठी भाषी क्षेत्रों में राजस्व रिकॉर्ड भी मराठी में रखे गए हैं।

कर्नाटक के तर्क

- कर्नाटक के अनुसार, **1920** में भाषाई आधार पर हलकों के विभाजन में कांग्रेस ने बेलगावी को कर्नाटक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में शामिल किया था। इसके अलावा, राज्य पुनर्गठन आयोग ने कर्नाटक के साथ बेलगावी को निहित किया था।
- कर्नाटक का मानना है कि राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार सीमाओं का निपटान अंतिम है। यह तर्क दिया जाता है कि राज्य की सीमा न तो अस्थायी थी और न ही लचीली।
- राज्य का तर्क है कि यह मुद्दा उन सीमावर्ती मुद्दों को फिर से खोल देगा, जिन पर अधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया है, और ऐसी मांग को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- जैसा कि कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है, कर्नाटक ने बेलागवी को अपनी दूसरी राजधानी घोषित किया, बेलगाम का नाम बदलकर बेलगावी कर दिया और बेलगावी में नवनिर्मित विधान सौधा में अपना शीतकालीन सत्र भी आयोजित किया।

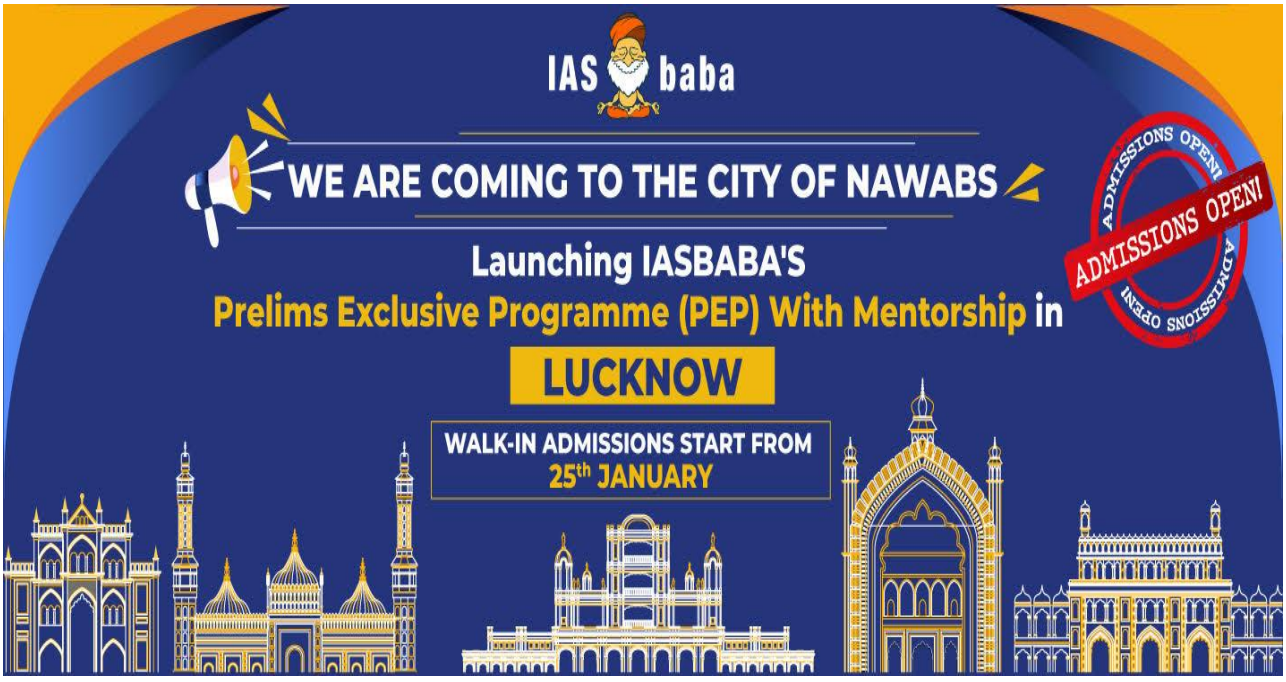

सामाजिक मुद्दे/ वेलफ़ेयर

हनी मिशन में लगे प्रवासी श्रमिक

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II- नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में-

- प्रधानमंत्री के भारत के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग **(KVIC)** ने हनी मिशन जैसी अपनी प्रमुख योजना के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में सैकड़ों प्रवासी कामगारों को शामिल किया।
- व्यथित प्रवासी श्रमिक जो अगस्त के महीने में उत्तर प्रदेश में केवीआईसी के हनी मिशन के साथ जुड़े थे, उन्होंने अपनी पहली शहद की फसल काट ली है और बम्पर पैदावार का इंतजार कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

हनी मिशन

- **हनी मिशन का उद्देश्य:** किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन और भारत के शहद उत्पादन में वृद्धि करके रोजगार उत्पन्न करना।
- **लॉन्च:** 3 साल पहले KVIC
- हनी मिशन के तहत, KVIC किसानों, मधुमक्खी पालकों और बेरोजगार युवाओं सहित लाभार्थियों को लाइव कॉलोनियों के साथ प्रशिक्षण और 10 मधुमक्खी बक्से प्रदान करता है।
- KVIC मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम भी चलाता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

- यह अप्रैल 1957 में (एक आरटीआई के अनुसार) भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम, 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956' के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है।
- **दृष्टि**- ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी आवश्यक हो, अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास की योजना, प्रचार, सुविधा, आयोजन और सहायता करना।
- अप्रैल 1957 में इसने पूर्व अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का काम संभाला।
- **प्रधान कार्यालय**: मुंबई
- **छह क्षेत्रीय कार्यालय**: दिल्ली, भोपाल, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी।

भारत के अनुदैर्ध्य एजिंग अध्ययन (Longitudinal Ageing Study of India (LASI)LASI) वेव -1, भारत रिपोर्ट जारी

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I - सोसायटी

समाचार में-

- भारत का अनुदैर्ध्य एजिंग अध्ययन **(LASI)** वेव **-1,** भारत रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी।
- जारीकरता **:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत में अनुदैर्ध्य एजिंग अध्ययन **(LASI)** इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज**,** हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और रैंड कॉर्पोरेशन के बीच एक साझेदारी है। यह भारत में स्वास्थ्य**,** आर्थिक और सामाजिक निर्धारकों और जनसंख्या की बढ़ती उम्र के निहितार्थ की वैज्ञानिक जांच का एक पूर्ण पैमाने पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण है।
- **LASI** की एक अनूठी विशेषता व्यापक बायोमार्कर की कवरेज क्षमता है।
- भारत में कोई अन्य सर्वेक्षण स्वास्थ्य और बायोमार्कर के बारे में विस्तृत डेटा एकत्र नहीं करता है जो परिवार और सामाजिक नेटवर्क**,** आय**,** संपत्ति और खपत की जानकारी के साथ हो।
- **LASI** स्वास्थ्य**,** आर्थिक**,** और सामाजिक निर्धारकों और भारत में जनसंख्या के बुढ़ापे के परिणामों की वैज्ञानिक जांच का एक पूर्ण पैमाने पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण है।
- **LASI,** वेव **1** ने **45** और उससे अधिक आयु वर्ग के **72,250** व्यक्तियों और पति-पत्नी सहित **60** और उससे अधिक आयु वर्ग के **31,464** बुजुर्ग और भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के **75** और उससे अधिक आयु वर्ग के **6,749** बुजुर्गों **(** सिक्किम को छोड़कर**)** के आधारभूत नमूने को कवर किया।
- यह भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है जो वृद्ध आबादी के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए एक अनुदैर्ध्य डेटाबेस प्रदान करता है।
- एलएएसआई के साक्ष्य बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के दायरे को और मजबूत करने और व्यापक बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा।
- यह पुरानी आबादी के लिए निवारक और स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों की एक श्रृंखला स्थापित करने में मदद करेगा और उनमें से सबसे कमजोर होगा।
- **उद्देश्य:** बुजुर्गों के लिये सामाजिक, स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण के व्यापक क्षेत्रों में नीतियों और कार्यक्रमों के अभिकल्पन के लिये एक अनुदैर्ध्य डेटाबेस प्रदान करना।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में महिलाओं के लिए मासिक धर्म हेतु पीरियड रूम सेट'स्थापित किया गया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I - सोसायटी

समाचार में-

- भीड़भाड़ वाली झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान होने वाले कष्टों को कम करने के लिए और उन्हें स्वच्छता संबंधी स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए, महाराष्ट्र के ठाणे शहर के एक सार्वजनिक शौचालय में एक "पीरियड रूम" स्थापित किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- कई बुनियादी सुविधाओं से लैस, पीरियड रूम का उद्देश्य मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता की सुविधा प्रदान करना है।
- यह सुविधा छोटे घरों में रहने वाली महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिनके पास अलग स्नान स्थल नहीं है।
- कई बार उन्हें पीरियड्स के दौरान पेड को बदलना मुश्किल हो जाता है।
- यह सुविधा ऐसी महिलाओं के लिए एक वरदान होगी और अच्छी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी।
- ठाणे नगर निगम द्वारा ठाणे में वागले एस्टेट क्षेत्र के शांति नगर इलाके में एक झुग्गी-झोपड़ी में, एक सार्वजनिक शौचालय में ऐसी पहली तरह की पहल होने का दावा करते किया है, ठाणे नगर निगम द्वारा एक एनजीओ के सहयोग से बहुत आवश्यक सुविधा स्थापित की गई है।
- शहर के सभी **120** सामुदायिक शौचालयों में **45,000** रुपये से कम लागत वाली इस सुविधा को स्थापित किया जाएगा।

Related articles:

- Menstruation and associated stigma: Click here
- Period Products (Free Provision) Scotland Bill: Click here

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 3.0) का तीसरा चरण

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- III - कौशल विकास

समाचार में-

- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना **(PMKVY 3.0)** के तीसरे चरण को हाल ही में भारत के सभी राज्यों के **600** जिलों में लॉन्च किया गया।
- मंत्रालय**:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय।

महत्वपूर्ण बिंदु

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय **(MSDE)** द्वारा प्रायोजित, यह चरण नए-युग और **COVID-** संबंधित कौशल पर केंद्रित होगा।
- कौशल भारत मिशन (PMKVY **-3.0**) रुपये के परिव्यय के साथ **2020-2021** की योजना अवधि में आठ लाख उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की परिकल्पना करता है।
- **729** प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों **(**PMKK**),** गैर-PMKK प्रशिक्षण केंद्रों और कौशल भारत के तहत **200** से अधिक आईटीआई को कुशल पेशेवरों का एक मजबूत पूल बनाने के लिए PMKVY **3.0** प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

कौशल भारत मिशन

- स्किल इंडिया मिशन भारत सरकार की एक पहल है, जिसे प्रधानमंत्री ने **2022** तक विभिन्न कौशलों में भारत में **40** करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से **16** जुलाई **2015** को लॉन्च किया था।
- इसमें सरकार की विभिन्न पहल शामिल हैं जैसे
  - राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन,
  - कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति, **2015**
  - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
  - कौशल ऋण योजना

फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट (FSSM)

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I - सामाजिक मुद्दे

समाचार में-

- नीति आयोग ने शहरी क्षेत्रों में मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन **(FSSM)** पर एक पुस्तक जारी की।

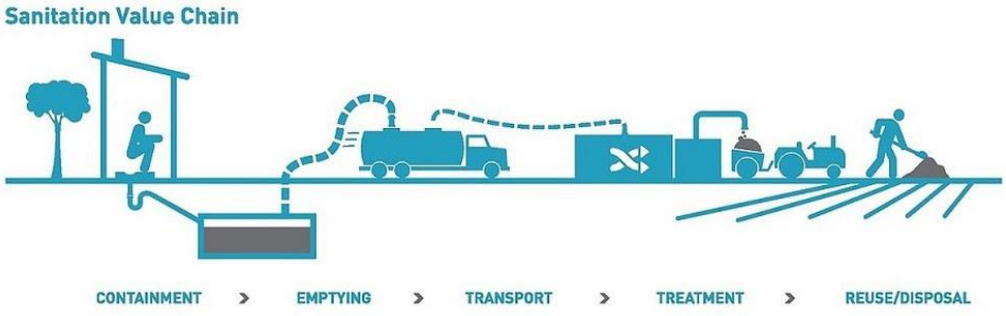

महत्वपूर्ण बिंदु

- नेशनल फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट (एनएफएसएसएम) एलायंस के साथ संयुक्त रूप से विकसित, पुस्तक एफएसएसएम पहल को लागू करते हुए 10 राज्यों में 27 केस अध्ययन और भारतीय शहरों द्वारा अपनाई गई विभिन्न सेवा और व्यवसाय मॉडल प्रस्तुत किया है।
- लगभग 60% शहरी परिवार ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियों पर भरोसा करते हैं, जिन्हें इन प्रणालियों के नियंत्रण संरचनाओं में एकत्र कचरे के प्रबंधन के लिए समर्पित योजना की आवश्यकता होती है।
- तदनुसार, एफएसएसएम योजना मानव उत्सर्जन प्रबंधन को प्राथमिकता देती है, जो रोगों को फैलाने की उच्च क्षमता वाली एक अपशिष्ट धारा है।

क्या आप जानते है?

- एफएसएसएम समाधानों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2017 में एफएसएसएम पर राष्ट्रीय नीति बनाई।
- 24 से अधिक राज्यों ने इसे अपनाया है और उनमें से 12 राज्य अपनी नयी नीतियों के साथ आए हैं।
- शहरी भारत में 66 लाख घरेलू शौचालयों और 6 लाख से अधिक सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के साथ शौचालयों की सार्वभौमिक पहुंच हासिल की गई।
- ओपन-डेफिकेशन-फ्री(ODF) के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, भारत अब ODF + और ODF ++ बनने की ओर बढ़ गया है।
- ये लक्ष्य शौचालय के कचरे के पर्याप्त उपचार और सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता के लिए उपयोग की अवधारणा से परे हैं और सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों के लिए लक्ष्य रखते हैं।

जाति और जनगणना के आसपास एक नया ढांचा

प्रसंग: भारत की जनगणना, अपनी तरह के जनगणना के सबसे बड़े प्रयासों में से एक है, भारतीय जनगणना जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक जानकारी की गणना करता है।

भारत में जनगणना के बारे में

- सौहार्दपूर्ण जनगणना देश की आबादी के आकार, वितरण और सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकीय और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। भारत में पहली समकालिक जनगणना 1881 में हुई थी। तब से लेकर अब तक, दस वर्षों में एक बार बिना किसी रुकावट के जनगणना किया जाता हैं।
- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC), जिसने 1931 के बाद से जाति पर पहला आंकड़ा एकत्र किया, यह जाति की गणना का सबसे बड़ा अभ्यास है। SECC आवास, शैक्षिक स्थिति, भूमि के आधार पर घरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

को अलग करने के लिए डेटा की आपूर्ति करती है, अलग-अलग तरीके से पालन, व्यवसाय, संपत्ति पर कब्जा, एससी / एसटी परिवारों, आय आदि विवरण रखता है।

जनगणना और SECC में क्या अंतर है?

- जनगणना और SECC के अलग-अलग उद्देश्य हैं।
- चूंकि जनगणना 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत आती है, इसलिए सभी आंकड़ों को गोपनीय माना जाता है
- एसईसीसी वेबसाइट के अनुसार, "सामाजिक विभागों की जनगणना (एसईसीसी) में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी सरकारी विभागों द्वारा घरों को लाभ देने और / या प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग के लिए खुली है"।
- SECC कार्यप्रणाली उपभोग के बजाय अभाव से गरीबी को परिभाषित करती है।
- जनगणना इस प्रकार भारतीय आबादी का एक चित्र प्रदान करती है, जबकि SECC राज्य समर्थन के लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपकरण है।
- यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल संग्रह के तरीकों को प्रभावित करता है बल्कि डेटा के दुरुपयोग के लिए उपयोग और क्षमता भी है।

जनगणना के लाभ (सौ साल और SECC)

- **साक्ष्य आधारित नीति निर्माण:** किसी समाज की आबादी की गणना करना, वर्णन करना और समझना और लोगों की पहुंच क्या है और उन्हें किस चीज से बाहर रखा गया है, यह न केवल सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए बल्कि नीति चिकित्सकों और सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- **शासन में समानता सुनिश्चित करता है:** आजादी के बाद से, कुछ मानकों जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर एकत्रित जनगणना के आंकड़े जैसे कि शिक्षा एकत्र की गई है। यह डेटा सरकार को समाज में मौजूद असमानताओं को दूर करने में मदद करेगा।
- **परिसीमन आयोग:** परिसीमन आयोग जनगणना की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करता है
- **विकासात्मक उद्देश्य:** व्यवसाय कारखानों, कार्यालयों और दुकानों का निर्माण करने के लिए निर्णय लेने के लिए जनगणना डेटा का उपयोग करते हैं, और यह रोजगार उत्पन्न करता है। डेवलपर्स नए घरों के निर्माण और पुराने पड़ोस को पुनर्जीवित करने के लिए जनगणना का उपयोग करते हैं।
- **सहकारी संघवाद:** राज्यों और स्थानीय सरकारों को केंद्र सरकार के फंड, अनुदान और सहायता, सेक्स, उम्र, जाति और अन्य कारकों द्वारा जनसंख्या के योग और टूटने पर विचार करते हैं।
- **शासन में नागरिक भागीदारी:** 1941 की जनगणना पर टिप्पणी करते हुए, जनगणना आयुक्त येट्स ने कहा कि, "सामुदायिक आंकड़ों में तीव्र रुचि के लिए धन्यवाद, व्यावहारिक रूप से इस समय सभी समुदाय जनगणना के प्रति जागरूक थे" इस प्रकार जनगणना यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र प्रकृति में सहभागी है।

जनगणना की आलोचना

- विशेष जांच के लिए अनुपयुक्त: डब्ल्यू.डब्ल्यू.एम. 1941 की जनगणना के लिए भारत की जनगणना आयुक्त, यीट्स, ने कहा था कि, "जनगणना एक बड़ी, बेहद शक्तिशाली है, लेकिन विशेष जांच के लिए अप्रशिक्षित साधन है"
- यह समाज को व्यापक समझ प्रदान नहीं कर सकता: कुछ विद्वान जनगणना को एक डेटा संग्रह प्रयास और शासन की तकनीक के रूप में मानते हैं, लेकिन एक जटिल समाज की विस्तृत और व्यापक समझ के लिए पर्याप्त उपयोगी नहीं है।
- जाति की जनगणना की जटिलता: जाति और उसकी जटिलताओं को पकड़ने की यह बड़ी प्रशासनिक कवायद न केवल कठिन है, बल्कि सामाजिक रूप से अक्षम भी है। यह तर्क दिया जाता है कि गिनती जाति संदर्भ-विशिष्ट हो सकती है, और इस तरह मापना मुश्किल है
- एक जाति की जनगणना के राजनीतिक और सामाजिक नतीजे: ऐसी चिंताएं हैं कि जाति की गिनती से पहचान को मजबूत या कठोर बनाने में मदद मिल सकती है जो राष्ट्रीय पहचान के विकास में बाधा बनती है।
- समय अंतराल और योजना: उदाहरण के लिए SECC के लगभग एक दशक बाद, डेटा की एक बड़ी मात्रा अप्रभावित रहती है। डेटा देरी से सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए महत्वपूर्ण नतीजे हैं क्योंकि डेटा अन-रिलीज़ या केवल भागों में जारी हो सकता है।

आगे की राह

- **बेहतर सहयोग की आवश्यकता:** जबकि जनगणना अधिकारी पारदर्शिता की एक नीति के हिस्से के रूप में कार्यप्रणाली पर दस्तावेज़ प्रस्तुत करते हैं, वहाँ जनगणना और SECC के कार्यकत्र्ताओं के साथ-साथ संबंधित शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के बीच घनिष्ठ और निरंतर जुड़ाव होना चाहिए।
- **पिछली जनगणना से सीखना:** एक और SECC आयोजित करने से पहले, पिछले अभ्यास का एक स्टॉकटेकिंग, जो कि इससे सीखा गया है, और राज्य समर्थन के लाभार्थियों के लिए मानदंड बदलने में परिवर्तन के लिए आवश्यक हैं, जनगणना को सक्षम करने के लिए प्रभावी नीति कार्य और शैक्षिक प्रतिबिंब की सुविधा महत्वपूर्ण हैं।

Connecting the dots

- Tamil Nadu Commission for Caste-wise Data: Click here
- NPR and Census

परेशान करने वाले रुझान: असमानता में वृद्धि

संदर्भ: COVID-19 महामारी से होने वाली तबाही से विश्व अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे ठीक हो रही है, लेकिन यह केवल आंशिक हल है।

मुद्दे:

- असमान रिकवरी: रिकवरी देशों के बीच और राज्यों के बीच असमान है। उदाहरण के लिए: यू.एस. और चीन के क्रमशः 5% और लगभग 11% बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन तुर्की की अर्थव्यवस्था मात्र 0.4% बढ़ने का अनुमान है।

- **बढ़ती असमानता:** दुनिया भर में अंतर आर्थिक सुधार के बावजूद, उभरती हुई सार्वभौमिक सच्चाई यह है कि सभी देशों में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ रही है।
- **अमीर तेजी से उबरने में सक्षम हो गए:** ऑक्सफैम की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया भर में 1,000 सबसे अमीर लोगों ने नौ महीने के भीतर महामारी से अपने नुकसान की भरपाई कर ली, जो दुनिया के सबसे गरीब लोगों के विपरीत है, जिन्हें अपने पूर्व-महामारी की स्थिति में आने में एक दशक लग सकता है।
- **भारत में असमानता:** भारत में असमानता पिछले स्तरों पर बढ़ गई है जब इसे उपनिवेशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार मार्च के बाद से भारत के 100 अरबपतियों द्वारा अधिग्रहित की गई अतिरिक्त संपत्ति, 138 मिलियन गरीबों के 94,045 में से प्रत्येक को देने के लिए पर्याप्त है।
- अकुशल कार्यकर्ता पर प्रभाव: भारत में एक अकुशल कार्यकर्ता को कमाने में तीन साल लगेंगे, जो कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति ने पिछले एक साल में कमाया था, रिपोर्ट की गणना करता है।
- अनुपातहीन प्रभाव: आय और अवसरों में बिगड़ती असमानता लिंग, जाति और अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव के कारण कुछ वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। गरीब लोग बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित थे।
- असमानता का सामान्यीकरण: विकास पर ध्यान देने के कारण राजनेताओं और नीति निर्माताओं ने दशकों से बढ़ती असमानता को अपरिहार्य माना। असमानता को आर्थिक विकास के एक सौम्य परिणाम के रूप में देखा गया जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण गरीबी में कमी आई।
- असमानता के साथ वैचारिक मुद्दा: असमानता के बारे में चिंताओं को भी आसानी से खारिज किया जा सकता है क्योंकि समाजवाद द्वारा सूचित किया जा रहा है। दुनिया भर में उदारवाद और पूंजीवाद को अपनाने की ओर बढ़ रहा है। इसका कोई भी विरोध विकास की बहस की मुख्य धारा में संदेह के साथ देखा गया
- श्रम-पूंजी संबंध व्यापक असमानता: अर्थशास्त्रियों के बीच अब सार्वभौमिक समझौता है कि पूंजी और श्रम के बीच नए धन का वितरण इतना एकतरफा हो गया है कि श्रमिकों को लगातार पारे के लिए धकेला जा रहा है जबकि अमीर अमीर हो रहे हैं।
- पर्यावरणीय प्रभाव: उच्च और उच्च विकास पर टिका एक विकास मॉडल की पर्यावरणीय लागत भी स्पष्ट है। पर्यावरण के क्षरण का बोझ समाज के सबसे गरीब तबके को महसूस होता है।

निष्कर्ष

- इस सप्ताह दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम 'द ग्रेट रिसेट 'है, जो यह कहता है कि" संयुक्त रूप से और अधिक निष्पक्ष, टिकाऊ और लचीला भविष्य के लिए हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रणाली की नींव बनाने के लिए प्रतिबद्धता है"।
- असमानता से निपटने के लिए वर्तमान प्रयास पर्याप्त नहीं है; समाज में बढ़ती असमानता को दूर करने के लिए ठोस उपाय करने होंगे।

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21: शिक्षा

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II - शिक्षा

समाचार में-

- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कहा गया है कि COVID-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन स्कूली शिक्षा बड़े पैमाने पर बंद हुई।

महत्वपूर्ण बिंदु

- ग्रामीण भारत में 2020 में सरकारी और निजी स्कूलों के नामांकित बच्चों का प्रतिशत 2018 में 36.5% से बढ़कर 2020 में 61.8% हो गया है।
- PM eVIDYA डिजिटल / ऑनलाइन / ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट करने और छात्रों और शिक्षकों के लिए शिक्षा के लिए न्यायसंगत पहुंच को सक्षम करने के लिए एक व्यापक पहल है।
- लगभग 92 पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं और 1.5 करोड़ छात्रों का नामांकन स्वयं एमओओसी के तहत किया गया है जो एनआईओएस से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रम हैं।
- डिजिटल शिक्षा पर PRAGYATA दिशानिर्देश उन छात्रों के लिए ऑनलाइन / मिश्रित / डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ विकसित किए गए हैं जो वर्तमान में स्कूल बंद होने के कारण घर पर हैं।
- मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए MANODARPAN पहल को आत्मनिर्भार भारत अभियान में शामिल किया गया है।
- भारत प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लगभग 96% साक्षरता स्तर प्राप्त कर चुका है।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की साक्षरता दर 77.7 प्रतिशत थी।

Related articles:

- Steps taken by the Government to ensure quality education: Click here

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21: कौशल विकास

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- III - कौशल विकास

समाचार में-

- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कहा गया है कि 15-59 वर्ष की आयु के केवल 2.4% कार्यबल ने औपचारिक व्यावसायिक/ तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अन्य 8.9% कार्यबल ने अनौपचारिक स्रोतों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- गैर-औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 8.9% कार्यबल में से, सबसे बड़ा हिस्सा नौकरी प्रशिक्षण (3.3 प्रतिशत), उसके बाद सेल्फ लर्निंग (2.5 प्रतिशत) और वंशानुगत स्रोत (2.1 प्रतिशत) का योगदान है।
- औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में, पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच सबसे पसंदीदा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम IT-ITeS है।
- **यूनिफाइड स्किल रेगुलेटर-** नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (NCVET) को हाल ही में चालू किया गया था।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 को प्रवासियों सहित 8 लाख उम्मीदवारों को कौशल के लिए एक स्थायी लक्ष्य के साथ 2020-21 में रोल आउट किया गया था।

Related articles:

- Third Phase Of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY 3.0) launched: Click here

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21: जरूरी आवश्यकताएं

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I - सोसायटी

समाचार में-

- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर एक जरूरी आवश्यकताएं सूचकांक (बीएनआई) का निर्माण करता है।

Figure 1: Improvement in the Bare Necessities Across India (Rural + Urban) from 2012 to 2018

BNI for India (Rural + Urban) 2012 BNI for India (Rural + Urban) 2018

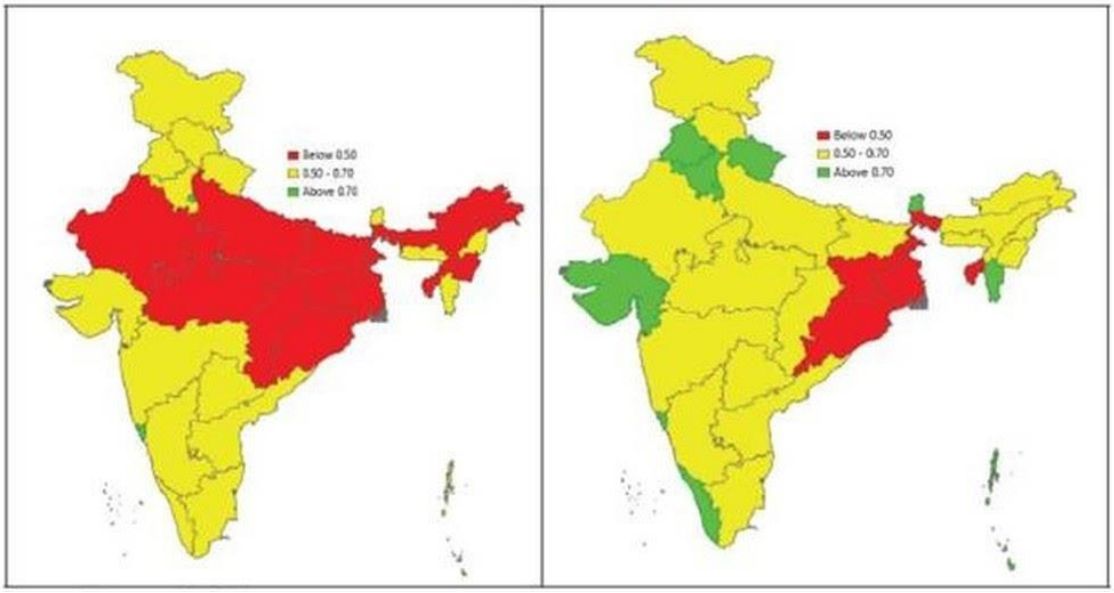

महत्वपूर्ण बिंदु

- BNI पाँच आयामों पर 26 संकेतकों का सारांश देता है। जल, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाएं।
- बीएनआई को 2012 और 2018 के लिए सभी राज्यों के लिए बनाया गया है, जो भारत में दो एनएसओ राउंड्स, 69, और 76 वें पेयजल, स्वच्छता और आवास स्थिति के आंकड़ों का उपयोग करते हैं।
- अधिकांश राज्यों में 2012 की तुलना में 2018 में घर के लिए जरूरी आवश्यकताओं की पहुंच काफी बेहतर है।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2012 की तुलना में अधिकांश राज्यों में पीने के पानी की पहुंच 2018 में बेहतर हुई है।
- स्वच्छता के लिए क्षेत्रीय असमानता में गिरावट आई है क्योंकि 2012 में स्वच्छता के लिए कम पहुंच वाले राज्यों को अधिक फायदा हुआ है।
- आर्थिक सर्वेक्षण में 2012 की तुलना में शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण और ओडिशा और असम को छोड़कर 2018 में सभी राज्यों के लिए सूक्ष्म वातावरण में सुधार पर भी ध्यान दिया गया है।
- सर्वेक्षण जरूरी आवश्यकताओं और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणाम तक पहुंच के बीच सकारात्मक सहसंबंध की ओर भी इशारा करता है। यह बाल अस्तित्व में सुधार, अभी भी जन्मों में गिरावट, कुपोषण और शिशु मृत्यु दर में सुधार और स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल के उपयोग को ध्यान में रखता है।

महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे

गृहकार्य के लिए वेतन

संदर्भ: तमिलनाडु में आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, अनुभवी अभिनेता कमल हासन के नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी ने गृहकार्य को एक वेतनभोगी पेशे के रूप में मान्यता देने का एक चुनावी वादा किया है और अपने काम के लिए गृहणियों को भुगतान का आश्वासन दिया है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दे को इंगित करता है और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि अगर महिलाओं के आंदोलनों के इतिहास में यह महत्वपूर्ण है।

गृहकार्य के लिए मजदूरी की मांग की उत्पत्ति

- 2018 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि, वैश्विक स्तर पर, महिलाएं पुरुषों की तुलना में तीन गुना से भी ज्यादा, बिना किसी देखभाल के काम के कुल घंटे का **76.2%** प्रदर्शन करती हैं। एशिया और प्रशांत में, यह आंकड़ा 80% तक बढ़ जाता है।
- उत्तरी अमेरिका और यूरोप में महिलाओं के आंदोलन की दूसरी लहर **(1970** के दशक के दौरान) से जुड़े संघर्ष और चेतना बढ़ाने के संदर्भ में 'गृहकार्य के लिए मजदूरी' की मांग उठी।
- सेल्मा जेम्स के तहत **1972** में अंतर्राष्ट्रीय मजदूरी का अभियान इटली में शुरू हुआ। यह इस आधार पर था कि गृहकार्य औद्योगिक कार्य का आधार था और इसके लिए विधिवत भुगतान किया जाना चाहिए। यह आंदोलन आगे ब्रिटेन और अमेरिका तक फैल गया।
- सामाजिक और राजनीतिक समानता के लिए अन्य मांगों के साथ-साथ, महिलाओं के अधिकार प्रचारकों ने घरेलू महिलाओं के घर के निजी दायरे में गृहकार्य और बाल देखभाल के रोजमर्रा के अनुभव का राजनीतिकरण किया।
- 1960 और 1970 के दशक की अग्रणी महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए, इस मिथक को तोडना अत्यधिक महत्वपूर्ण था कि घर में महिलाओं का काम एक निजी सेवा थी जिसका पूंजीवादी उत्पादन से कोई संबंध नहीं था।

हाउसवर्क के लिए मजदूरी के पक्ष में क्या हैं?

- **अधिक सटीक राष्ट्रीय आय लेखांकन:** महिलाओं को इस घरेलू श्रम में दिन के कुछ घंटों के बावजूद, कार्य अक्सर दैनिक कार्यों के सेट के रूप में खारिज कर दिया जाता है (बाजार के लिए उत्पादों और सेवाओं को उत्पन्न नहीं करता है)। नतीजतन, यह या तो जीडीपी या रोजगार मैट्रिक्स के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसे शामिल करने की उपेक्षा करना इस प्रकार अर्थव्यवस्था की जीडीपी को कम करके आंका जाएगा।
- **महिला स्वायत्त बनाती है:** गृहकार्य एक महिला की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए आया था जिसने महिला को वास्तविक कार्य 'या सामाजिक अनुबंध के रूप में देखने से रोक दिया था। मजदूरी के लिए गृहकार्य 'के पैरोकारों के लिए, राज्य द्वारा महिलाओं को भुगतान करने के लिए जो वेतन चाहिए, वह उन्हें उन पुरुषों की स्वायत्तता देगा, जिन पर वे निर्भर थे।
- **गृहकार्य में पूंजीवादी उत्पादन लिंक है:** घर पर काम करने वाली महिला ने 'जीवित इंसान - मजदूर खुद' का उत्पादन किया। घर में मुफ्त सेवाएं प्रदान करके, महिलाओं ने निर्वाह स्तर के मजदूरी पर काम करने वाले परिवारों के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से संभव बनाया, जिससे उद्योग और पूंजी के लिए लाभ प्राप्त हुआ

- **महिलाओं की भूमिका को पुनर्परिभाषित करता है:** मूल रूप से, महिलाओं के स्वभाव की अभिव्यक्ति के रूप में मजदूरी की बहुत मांग गृहकार्य का प्रतिकार थी। यह महिलाओं की सौंपी गई सामाजिक भूमिका के खिलाफ विद्रोह हुआ था। इसमें मजदूरी की मांग की मूल प्रकृति निहित है, न कि केवल धन में।
- **जनसंख्या के बड़े हिस्से का कल्याण: 2011** में जनगणना के अनुसार, घरेलू कर्तव्यों में लगे लोगों को गैर-श्रमिक माना जाता है, तब भी जब **159.9** मिलियन महिलाओं ने कहा था कि "घरेलू काम" उनका मुख्य व्यवसाय था।
- **समानता के पहले कदम के रूप में मान्यता:** मान्यता सशक्तिकरण में सबसे केंद्रीय प्रक्रियाओं में से एक है। यह उन्हें पितृसत्तात्मक भारतीय घर के भीतर समानता का दावा देता है जो केवल पुरुषों द्वारा किए गए कार्यों को पहचानता है।
- **यह हमें श्रम की एक अधिक समग्र समझ की ओर अग्रसर करता है:** श्रम विशुद्ध रूप से बाजार पर एक सेवा के विनिमय मूल्य से बंधा नहीं है, और श्रम के एक अत्यंत अंतरंग रूप को पहचानता है जो परिवार की इकाई को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक साबित हुआ है।
- **जेंडर जस्टिस:** एक बार काम के रूप में मान्यता प्राप्त, अवैतनिक घरेलू श्रम का मुद्दा जो लगभग पूरी तरह से महिलाओं पर हावी है, वह एक ऐसा मुद्दा बन सकता है जहां महिलाएं समय के संदर्भ में कुछ हद तक समानता की मांग कर सकती हैं।
- **घरेलू हिंसा को नियंत्रित करने में मदद करता है: 2014** में, एक इतालवी वकील और पूर्व सांसद गियुलिया बोंगीओनो ने प्रस्तावित किया कि घरेलू हिंसा पर बहस को संबोधित करने के तरीके के रूप में गृहणियों को वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। उसने तर्क दिया कि ज्यादातर महिलाएं अपमानजनक रिश्ते में रहती हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वे आर्थिक रूप से अपने साथी पर निर्भर हैं।

चुनौतियां

- **यहूदी बस्ती की महिलाएं:** यह कुछ लोगों द्वारा तर्क दिया जाता है कि गृहकार्य के लिए मजदूरी केवल महिलाओं को घर के भीतर कैद करेगी, उनके सामाजिक अलगाव को बढ़ाएगी और पुरुषों को गृहकार्य साझा करने से रोक देगी।
- **फेमिनिस्ट मूवमेंट का गलत लक्ष्य:** दूसरों का तर्क है कि महिलाओं के आंदोलन का लक्ष्य मजदूरी माँगना नहीं, बल्कि महिलाओं को नियमित घरेलू कामों से दूर रखना और उन्हें सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाना है।
- **अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डालता है:** अभी भी इस बात पर बहस चल रही है कि महिलाओं द्वारा किए गए गृहकार्य का भुगतान कौन करेगा, अगर यह राज्य द्वारा किया जाना है तो इससे सरकार के वित्त पर अतिरिक्त राजकोषीय बोझ पड़ेगा।

निष्कर्ष

- कहने की जरूरत नहीं है कि महिलाओं की आबादी लगभग आधी है और उनकी जरूरतों और मुद्दों पर ध्यान देना होगा। एक गृहिणी को किसी एहसान की जरूरत नहीं होती है। वह पहले से ही अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। घर पर उसके काम के लिए एक वेतन उसके सशक्तीकरण के लिए एक उपकरण होगा,जो उसे गरिमा का जीवन दे।

यौन हिंसा के लिए दंडात्मक प्रतिक्रिया की जरूरत है

संदर्भ: मानवाधिकार दिवस 2020 पर, महाराष्ट्र कैबिनेट ने शक्ति विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें कठोर दंड और अनिवार्य वाक्य - मृत्युदंड सहित - गैर-समलैंगिक बलात्कार के लिए, कथित तौर पर यौन अपराधों को रोकने के लिए मंजूरी दी गई थी।

क्या आपको पता है?

- 2018 में बाल बलात्कार के लिए मौत की सजा की शुरुआत के साथ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा देने के लिए हालिया विधायी प्रवृत्ति के बीच शक्ति विधेयक आता है।
- 2020 में, आंध्र प्रदेश सरकार के इस विधेयक को राष्ट्रपति ने लंबित रखा है, जो वयस्क महिलाओं के बलात्कार के लिए मौत की सजा प्रदान करता है।

शक्ति विधेयक की आलोचना

1. रिपोर्टिंग और जांच तंत्र को संबोधित नहीं करता है

- मौत की सजा एक आपराधिक मुकदमे का अंतिम चरण है जबकि बलात्कार से बचे लोगों को गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ता है, खासकर शिकायत के पंजीकरण के समय।
- न्याय वितरण प्रणाली में सबसे गंभीर अंतराल एक पुलिस शिकायत की रिपोर्टिंग से संबंधित हैं।
- आपराधिक न्याय प्रणाली का ध्यान, इसलिए, सजा और रिपोर्टिंग, जांच और पीड़ित-सहायता तंत्र के चरणों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। विधेयक इन चिंताओं को संबोधित नहीं करता है।

2. काउंटर-उत्पादक

- दूसरा, कठोर दंड अक्सर अपराध के लिए सजा की दर को कम करने का परिणाम होता है।
- उदाहरण के लिए, दिल्ली में बलात्कार के निर्णयों पर आधारित भारतीय कानून की समीक्षा में प्रकाशित एक अध्ययन 2013 में न्यायिक विवेक को हटाने के बाद दोषसिद्धि की कम दर को दर्शाता है।
- कठोर दंड का परिचय देना न्यायाधीशों और पुलिस के दिमाग से प्रणालीगत पूर्वाग्रहों को दूर नहीं करता है, जो शिकायतें दर्ज करने से इनकार कर सकते हैं, या ऐसे मामलों में अपराधियों को बरी कर सकते हैं जिन्हें वे "गंभीर" नहीं मानते हैं जो अनिवार्य न्यूनतम वारंट के लिए पर्याप्त हैं

3. अनुभवजन्य साक्ष्य को अनदेखा करता है

- तीसरा, बाल यौन शोषण पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि सजा के कुछ मामलों में, न्यूनतम सजा आदर्श थी और अधिकतम सजा अपवाद था।

- इसके अलावा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अपराध डेटा से पता चलता है कि इन मामलों में 93.6 प्रतिशत अपराधियों को पीड़ितों के लिए जाना जाता था।
- पूंजी की सजा का परिचय शिकायतकर्ताओं को शिकायत दर्ज करने से रोक देगा। शक्ति विधेयक इन मामलों पर महत्वपूर्ण अनुभवजन्य साक्ष्यों की अनदेखी करता है।

4. सहमति से संबंधित समस्या

- विधेयक में अन्य महिला विरोधी जोर वयस्क पीड़ितों और अपराधियों से जुड़े मामलों में सकारात्मक सहमति के मानक से हटकर है।
- महिलाओं के आंदोलन से महत्वपूर्ण वकालत के लिए सहमति का एक पुष्ट मानक शुरू किया गया, जो कि शब्दों, इशारों या मौखिक या गैर-मौखिक संचार के किसी भी रूप के माध्यम से महिलाओं द्वारा असमान स्वैच्छिक समझौते में निहित है।
- एक तीव्र प्रस्थान में, बिल यह निर्धारित करता है कि मान्य सहमति "पार्टियों के आचरण" और "इसके आसपास की परिस्थितियों" से ली जा सकती है।
- बिल में अस्पष्ट शब्दों में व्याख्या केवल एक निश्चित तरीके से जवाब देने के लिए बचे लोगों की अपेक्षा करने की खतरनाक संभावनाएं रखती है, इस प्रकार एक "आदर्श" पीड़ित के स्टीरियोटाइप का निर्माण करती है।
- यह इस तथ्य को भी अनदेखा करता है कि अपराधियों को लगभग 94 प्रतिशत बलात्कारों में जीवित बचे लोगों के लिए जाना जाता है, जिसमें अक्सर कोई क्रूर हिंसा शामिल नहीं होती है।

निष्कर्ष

- शक्ति विधेयक, जनता को जनता का एजेंडा बनाने के एजेंडे को मानते हुए कि राज्य "कुछ" कर रहा है, इससे अधिक हासिल नहीं करता है।
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए केवल सजा बढ़ाने के बजाय व्यापक सामाजिक सुधारों, निरंतर शासन के प्रयासों और खोजी एवं रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करना आवश्यक है।
- यौन हिंसा के लिए गंभीर प्रतिक्रियाओं को गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता है, बलात्कार के बचे हुए लोगों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने की आवश्यक है।

विकलांग महिलाएं

संदर्भ: सामान्य रूप से कई महिलाएं और विशेष रूप से विकलांग लोगों को गरीबी, खराब स्वास्थ्य स्थितियों, कम या कोई आय नहीं, शिक्षा के निम्न स्तर और अलगाव का सामना करना पड़ता है।

संसाधनों के दुर्लभ होने के साथ, महिलाओं को आमतौर पर संसाधनों का छोटा भाग मिलता है, और इससे भी ख़राब स्थिती तब होती है, अगर वे किसी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित हैं।

महामारी के समय उन्हें कई मुद्दों का सामना करना पड़ा

- आवश्यक वस्तुओं तक पहुँच: विकलांग लोग भोजन तक पहुँचने के लिए दुकानों का दौरा करने में सक्षम नहीं थे और वायरस ने आवश्यक सेवाओं के वितरण में बाधा के रूप में काम किया।
- आरोग्य सेतु ऐप तक पहुंच: दृष्टि विकलांग कई लोग आरोग्य सेतु ऐप तक पहुंचने में सक्षम नहीं थे क्योंकि यह उनकी आवश्यकताओं में कारक नहीं है।
- डिजिटल भुगतानों तक पहुंच: कई भुगतान ऐप नेत्रहीनों के लिए सुलभ नहीं हैं और कई ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं।
- डिजिटल वर्क प्लेटफॉर्म तक पहुंच: जबकि घर से काम विकलांग महिलाओं के लाभ के लिए हो सकता है, वीडियो कॉल और वॉयस कॉल तक पहुंचने में सक्षम होने में कई चुनौतियां हैं और निश्चित रूप से, कई क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का अभाव है।
- दुर्व्यवहार के लिए कमजोर: घर पर फंसे हुए, वे दुर्व्यवहार के लिए भी असुरक्षित हैं और पुलिस के साथ शिकायत दर्ज करने या नागरिक समाज संगठन के ध्यान में लाने में सक्षम होने में बाधाओं का सामना करते हैं।

आगे की राह

- विकलांग लोगों का एक डेटाबेस बनाएं, विशेष रूप से महिला लिंग का। यह उनकी चिकित्सा जरूरतों को समझने और तदनुसार योजनाओं को ट्विस्ट करने में मदद करेगा
- जमीनी स्तर की प्रणाली: सरकार विकलांग लोगों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर समझौता नहीं करने की आवश्यकता के बारे में परिवारों में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ अपने मजबूत जमीनी स्तर की प्रणालियों का उपयोग कर सकती है।
- समावेशी कौशल प्रशिक्षण: कौशल विकास, सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए जो उनके साथ परामर्श में अक्षम हैं।
- राजनीतिक भागीदारी: इनमें से कुछ महिलाओं को स्थानीय निर्णय लेने वाली संस्थाओं में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे प्रक्रियाओं में भाग ले सकें, जो उनके कौशल का निर्माण करती हैं।
- विकलांगता के अनुकूल शिकायत निवारण प्रणाली: विकलांग महिलाओं के लिए सुलभ एक कामकाजी टेलीफोन नेटवर्क स्थापित करें, ताकि वे स्थानीय प्रशासन प्रणाली में एक प्रासंगिक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं से अवगत करा सकें।

निष्कर्ष

- विकलांग महिलाएं बहुत लंबे समय से हाशिये पर हैं।
- महामारी उनके लिए विशेष रूप से क्रूर रही है, लेकिन अगर सरकार ठोस प्रयास करती है, तो उन्हें अधिक स्वतंत्र और उत्पादक बनने में सक्षम बनाने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।

स्वास्थय समस्या

भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया (INSACOG) लॉन्च

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II - स्वास्थ्य

समाचार में-

- भारतीय **SARS-CoV-2** जीनोमिक कंसोर्टिया **(INSACOG)** हाल ही में लॉन्च किया गया था।
- समन्वित: MoH & FW, ICMR और CSIR के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग **(DBT)**

महत्वपूर्ण बिंदु

- संघ देश में SARS-CoV-2 के नए संस्करण की स्थिति का पता लगाएगा।
- INSACOG की एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति होगी।
- इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार समूह होगा।
- उद्देश्य: एक बहु-प्रयोगशाला नेटवर्क के माध्यम से नियमित आधार पर **SARS-CoV-2** में जीनोमिक विविधता की निगरानी करना।
- यह महत्वपूर्ण अनुसंधान भविष्य में संभावित टीके विकसित करने में भी सहायता करेगा।
- कंसोर्टियम सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थ के साथ जीनोमिक वेरिएंट के शुरुआती पता लगाने के लिए एक प्रहरी निगरानी स्थापित करेगा, और असामान्य घटनाओं/ प्रवृत्तियों (सुपर-स्प्रेडर घटनाओं, उच्च मृत्यु दर/ रुग्णता प्रवृत्ति क्षेत्रों) में जीनोमिक वेरिएंट का निर्धारण करेगा।

क्या आप जानते है?

- एक नया संस्करण, जो यूके में पाया गया, विशेष रूप से लंदन क्षेत्र में, स्पाइक क्षेत्र में कई म्यूटेशन के साथ-साथ अन्य जीनोमिक क्षेत्रों में म्यूटेशन द्वारा परिभाषित किया गया है।
- डीबीटी के अनुसार, ये उत्परिवर्तन तेजी से वायरस के वेरिएंट की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं।
- यह वेरिएंट पहले से चल रहे वेरिएंट की तुलना में काफी अधिक ट्रांसमीसेबल है, अनुमानित संख्या में **70%** तक की वृद्धि हुई।

चार राज्यों में काला अजार की स्थिति की समीक्षा

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II - स्वास्थ्य

समाचार में-

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में चार राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में काल-अजर की स्थिति की समीक्षा की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- **कालाजार:** परजीवी से होने वाली मृत्यु का दुनियाभर में मलेरिया के बाद कालाजार दूसरा सबसे बड़ा कारण है, अगर समय रहते मरीज का इलाज न किया जाए, तो इससे 95 फीसदी मरीजों की मौत हो जाती है।
- इसके अलावा, जो मरीज सही इलाज मिलने से ठीक हो जाते हैं, उनमें से करीब 20 फीसदी मरीजों के शरीर में 'पोस्ट-कालाजार डर्मल लीशमैनियासिस' **(Post-Kala-Azar Dermal Leishmaniasis- PKDL)'** नामक त्वचा संबंधी रोग हो जाता है।
- वर्तमान में देश के चार राज्य- बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 54 जिले कालाजार बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
- 30 नवंबर, 2020 तक झारखंड के 12 खण्डों और बिहार के 4 खण्डों में प्रति 10,000 आबादी पर कालाजार का एक से अधिक मामला सामने आया है।
- कालाजार से सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार में सिवान और सारण जिलों के 4 खण्डों को छोड़कर (कुल 458 खण्ड में से) बाकी सभी खण्डों में इसके उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है।
- झारखंड ने प्रति 10000 आबादी पर एक से अधिक मामलों वाले खण्डों के साथ-साथ कालाजार और **PKDL** के मामलों में कमी दर्ज की है।
- उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने कालाजार उन्मूलन के लक्ष्यों को हासिल कर लिया है

केंद्र सरकार ने रोग के उन्मूलन को लक्षित करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों के महत्व को रेखांकित किया है:

- स्थानिक क्षेत्रों में "सबसे कमज़ोर गरीब" या वंचित वर्गों के लिए एक योजना का विकास।
- सामुदायिक स्तर पर अधिकतम लाभ के लिए पोषन अभियान के भीतर कला-अज़र उन्मूलन कार्यक्रम का लाभ उठाना।
- प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण **(PMAY-G)** के प्रमुख कार्यक्रम के तहत बेहतर आवास प्रदान करने के अवसर की खोज।
- राज्य योजनाओं के तहत बेहतर आवास प्रदान करने के अवसर की खोज।
- ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सकों (आरएचपी) का समावेश

- ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय और जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, पर्यावरण प्रबंधन और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ जुड़ना।

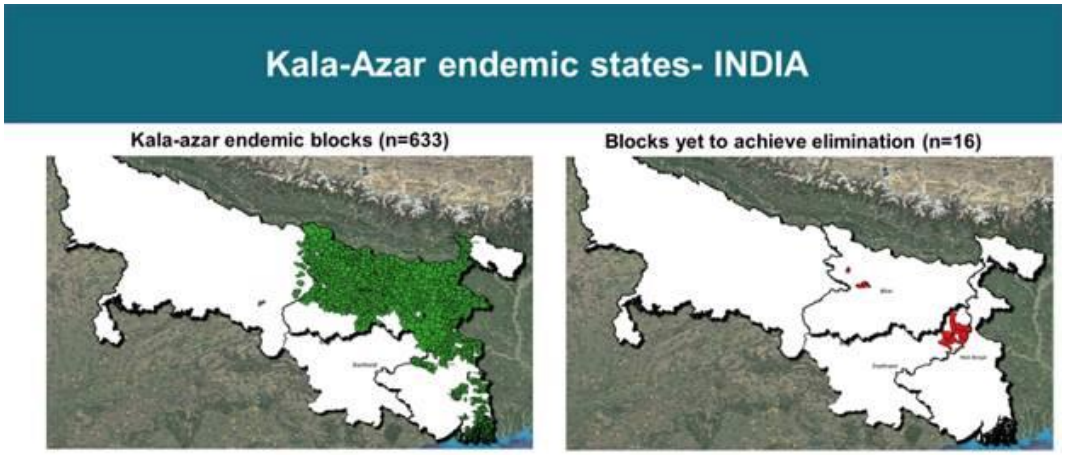

महत्वपूर्ण तथ्य

काला अजार

- लीशमैनियासिस (Leishmaniasis) एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है।
- यह लीशमैनिया (Leishmania) नामक एक परजीवी के कारण होता है जो रेत मक्खियों (Sand Flies) के काटने से फैलता है।
- मानव शरीर में आंत का (Visceral) लीशमैनियासिस को आमतौर पर भारत में कालाज़ार (Kala-azar) के रूप में जाना जाता है।
- इस तरह के लीशमैनियासिस आंतरिक अंगों को प्रभावित करते हैं, आमतौर पर प्लीहा, यकृत और अस्थि मज्जा को।
- कुछ लोगों में इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं।
- दूसरों के लिए, लक्षणों में बुखार, वजन में कमी और प्लीहा या यकृत की सूजन शामिल हो सकती है।
- इस परजीवी को मारने के लिए दवा उपस्थित है।
- यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाता है, तो गंभीर मामले आमतौर पर घातक होते हैं।

क्या आप जानते है?

- काला अजार मलेरिया के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा परजीवी हत्यारा है।
- यदि रोगियों का इलाज नहीं किया जाता है तो 95% यह घातक दर का परिणाम है।
- 20% तक मरीज जिनका सही इलाज किया जाता है और वे ठीक हो जाते हैं, पोस्ट-काला-अजार त्वचीय लीशमैनियासिस (पीकेडीएल) नामक एक त्वचा की स्थिति विकसित करते हैं, जो उपचार के बाद महीनों से लेकर सालों तक बनी रहती है।

COVID -19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी विकसित डीएनए वैक्सीन

भाग-GS प्रीलिम्स और GS- II - स्वास्थ्य और GS- III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- भारत का COVID-19 के विरुद्ध निर्मित पहला स्वदेशी रूप से विकसित कैडिला का डीएनए आधारित जेडवाईकोवी-डी (ZyCoV-D) को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल (DCGI) द्वारा तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों के संचालन के लिए अनुमोदित किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- उम्मीदवार को BIRAC और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (NBM) द्वारा समर्थित किया गया है।
- जायडस कैडिला ने भारत में इस डीएनए वैक्सीन उम्मीदवार के चरण- I / II नैदानिक परीक्षणों को 1,000 से अधिक प्रतिभागियों में पूरा किया।
- अंतरिम डेटा ने संकेत दिया है कि वैक्सीन सुरक्षित और इम्युनोजेनिक है जब तीन खुराक को अंतःस्रावी रूप से (त्वचा में) प्रशासित किया गया था।
- DCIG ने 26,000 भारतीय प्रतिभागियों में चरण- III नैदानिक परीक्षण आयोजित करने की अनुमति दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य'

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (एनबीएम)

- यह देश में बायोफार्मास्यूटिकल विकास में तेजी लाने वाला एक उद्योग-अकादमिक सहयोगी मिशनफोर्स है।
- यह 2017 में लॉन्च हुआ था और इसकी कुल लागत 1500 करोड़ रु थी।
- यह विश्व बैंक के ऋण द्वारा 50% सह-वित्त पोषित है।
- इसे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) द्वारा लागु किया जायेगा।
- इस मिशन के तहत, सरकार ने जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्यमिता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए इनोवेट इन इंडिया (i3) कार्यक्रम शुरू किया है।
- इसमें चार वर्टिकल का अनुसरण करने पर ध्यान दिया गया है: (1) उत्पाद का विकास वैक्सीन, बायोसिमिलर और मेडिकल डिवाइसेस के लिए होता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक हैं; (2) साझा अवसंरचना सुविधाओं का उन्नयन; (3) विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करके मानव पूंजी का विकास करना; (4) उद्योग अकादमिया अंतर-लिंक को बढ़ाने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालयों का विकास करना।

देश में एवियन इन्फ्लुएंजा की स्थिति

भाग-GS प्रीलिम्स और GS- II - स्वास्थ्य

समाचार में-

- **ICAR-NIHSAD** से सकारात्मक नमूनों की पुष्टि के बाद, एवियन इन्फ्लुएंजा निम्नलिखित राज्यों (12 उपकेंद्र) में सूचित किया गया है: (1) राजस्थान (कौवा); (2) मध्य प्रदेश (कौआ); (3) हिमाचल प्रदेश (प्रवासी पक्षी); (4) केरल (मुर्गी पालन)
- सुझाए गए उपाय: (1) पोल्ट्री फार्मों की जैव सुरक्षा को मजबूत करना; (2) प्रभावित क्षेत्रों की कीटाणुशोधन; (3) मृत पक्षियों/ शवों का उचित रूप से निपटान; (4) पुष्टि और आगे की निगरानी के लिए नमूने का समय पर संग्रह और जमा करना, आदि।
- पक्षियों की किसी भी असामान्य मृत्यु की रिपोर्ट के लिए वन विभाग के साथ समन्वय भी राज्यों को सुझाया गया था।
- अन्य राज्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे पक्षियों के बीच किसी भी असामान्य मृत्यु दर पर निगरानी रखें और आवश्यक उपाय करने के लिए तुरंत रिपोर्ट करें।

महत्वपूर्ण तथ्य

एवियन इन्फ्लुएंजा (AI)

- **कारण:** एवियन (पक्षी) इन्फ्लूएंजा (फ्लू) टाइप A वायरस।
- ये वायरस दुनिया भर में जंगली जलीय पक्षियों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं और घरेलू मुर्गी और अन्य पक्षियों और जानवरों की प्रजातियों को संक्रमित कर सकते हैं।
- एवियन फ्लू वायरस आम तौर पर मनुष्यों को संक्रमित नहीं करते हैं।
- एवियन इन्फ्लुएंजा (एआई) वायरस सदियों से दुनिया भर में घूम रहे हैं, जो पिछली शताब्दी में दर्ज चार प्रमुख प्रकोपों के कारण थे।
- भारत ने 2006 में एवियन इन्फ्लूएंजा के पहले प्रकोप को अधिसूचित किया।
- भारत में मनुष्यों में संक्रमण अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है, हालांकि यह बीमारी ज़ूनोटिक है।
- इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि एआई वायरस दूषित पोल्ट्री उत्पादों की खपत के माध्यम से मनुष्यों को प्रेषित किया जा सकता है।
- जैव सुरक्षा सिद्धांतों, व्यक्तिगत स्वच्छता, और सफाई एवं कीटाणुशोधन प्रोटोकॉल को शामिल करने वाले प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना एआई वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के प्रभावी साधन हैं।
- भारत में, यह बीमारी मुख्य रूप से प्रवासी पक्षियों द्वारा सर्दियों के महीनों के दौरान भारत में आती है, यानी सितंबर-अक्टूबर से फरवरी-मार्च तक।

- मानव हैंडलिंग (फ़ोमाइट्स के माध्यम से) माध्यमिक प्रसार भी संभव हो सकता है।

COVID-19 टीकाकरण अभियान के पैन इंडिया रोलआउट का शुभारंभ करने के लिए पीएम

भाग-GS प्रीलिम्स और GS- II - स्वास्थ्य

समाचार में-

- भारतीय प्रधानमंत्री **16** जनवरी, **2021** को **COVID-19** टीकाकरण अभियान के अखिल भारतीय रोलआउट का शुभारंभ करेंगे।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा जो पूरे देश की पूरी को कवर करेगा।
- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कुल **3006** सत्र स्थल लॉन्च के दौरान वस्तुतः जुड़े रहेंगे।
- उद्घाटन के दिन प्रत्येक सत्र स्थल पर लगभग **100** लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा।
- यह टीकाकरण कार्यक्रम प्राथमिकता समूहों के टीकाकरण के सिद्धांतों पर आधारित है।
- **ICDS** श्रमिकों सहित सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी, इस चरण के दौरान टीका प्राप्त करेंगे।
- टीकाकरण कार्यक्रम को-विन एप्लीकेशन का उपयोग करेगा, जो टीके स्टॉक, भंडारण तापमान और COVID **-19** वैक्सीन के लिए लाभार्थियों के व्यक्तिगत ट्रैकिंग की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा।
- यह डिजिटल प्लेटफॉर्म टीकाकरण सत्रों का संचालन करते हुए सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों की सहायता करेगा।
- एक समर्पित 24x7 कॉल सेंटर - 1075 - भी COVID-19 महामारी से संबंधित प्रश्नों को संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया है।
- नागर विमानन मंत्रालय के सक्रिय समर्थन से **COVISHIELD** और **COVAXIN** दोनों की पर्याप्त मात्रा पहले ही पूरे देश / केंद्रशासित प्रदेशों में पहुंचा दी गई है।

क्या आप जानते है?

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित यह एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

भारत में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक के प्रबंधन में टेलीमेडिसिन उपयोग के लिए रूपरेखा

भाग-GS प्रीलिम्स और GS- II - स्वास्थ्य

समाचार में-

- हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारत में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक के प्रबंधन में टेलीमेडिसिन उपयोग के लिए रूपरेखा जारी की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- टेली-परामर्श, टेली-निगरानी के अपने घटकों के साथ टेलीमेडिसिन को प्रमुख गैर संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए देखभाल मॉडल की निरंतरता बनाने के लिए एकीकृत किया जा सकता है।
- भारत में एनसीडी के बढ़ते बोझ के लिए बहुस्तरीय हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है जो एनसीडी देखभाल और प्रबंधन के प्रचारक, निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास संबंधी पहलुओं को संबोधित कर सकते हैं।
- टेलीमेडिसिन इन सभी पहलुओं को पुल और लिंक कर सकता है।
- इसे राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क और अन्य समान प्लेटफार्मों के माध्यम से भारत में प्राथमिक से तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल स्तर तक चिकित्सा चिकित्सकों द्वारा अनुकूलित और उपयोग किया जा सकता है। ”

राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण (NNMS)

भाग-GS प्रीलिम्स और GS- II - स्वास्थ्य

समाचार में-

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने **NON-COMMUNICABLE DISEASE (NCDs)** के जोखिम कारकों और स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारियों पर सबसे बड़ा व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 'नेशनल नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे **(NNMS)'** जारी किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- जबकि भारत में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए पांच में से दो वयस्कों में तीन या उससे ज्यादा एनसीडी रिस्क फैक्टर्स थे। एनडीसी के दबाव में हेल्थ सिस्टम की कार्यप्रणाली को भी यहां रेखांकित किया गया।
- पाँच में से दो से ज्यादा वयस्क और चार किशोरों में से एक ने अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि की; हर चार वयस्कों में से एक और 6.2% किशोर अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त थे;
- दस वयस्कों में से लगभग तीन का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था
- 9.3% का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ था।
- प्रत्येक तीन वयस्कों में से एक और एक-चौथाई से अधिक पुरुषों ने तंबाकू के किसी भी रूप का इस्तेमाल किया और क्रमशः पिछले **12** महीनों में शराब का सेवन किया।

क्या आप जानते है?

- 2017-18 की अवधि के दौरान आयोजित किए गए, सर्वेक्षण का उद्देश्य राष्ट्रीय एनसीडी निगरानी ढांचे और एनसीडी एक्शन प्लान से संबंधित प्रमुख संकेतकों (जोखिम कारकों, चुनिंदा एनसीडी और स्वास्थ्य प्रणालियों की प्रतिक्रिया) पर विश्वसनीय आधारभूत डेटा एकत्र करना था।
- मानकीकृत औजारों और विधियों का उपयोग करते हुए एनसीडी पर यह अपने तरह का एक व्यापक सर्वेक्षण है, जो देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं के **15-69** वर्ष आयु वर्ग को कवर करता है।

आयू संवद: सबसे बड़ा जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम

भाग-GS प्रीलिम्स और GS- II - स्वास्थ्य

समाचार में-

- "आयु समाविद" (मेरा स्वास्थ्य मेरी ज़िम्मेदारी), आयुर्वेदा और कोविद **19** महामारी पर आयोजित किए जा रहे सबसे बड़े जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम में से एक है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- आयोजन: आयुष मंत्रालय द्वारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद नई दिल्ली और इसे AYUSH का समर्थन प्राप्त है।
- भारत के नागरिकों के लिए आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा पूरे देश में **5** लाख से अधिक व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे।
- **मुख्य उद्देश्य**: आम लोगों को "COVID 19 महामारी के लिए आयुर्वेद" विषय के बारे में जागरूक करने के लिए व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से जागरूकता पैदा करना।

विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD) दिवस

भाग-GS प्रीलिम्स और GS- II - स्वास्थ्य

समाचार में-

30 जनवरी, **2021** को दूसरे वार्षिक विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (एनटीडी) दिवस के रूप में चिन्हित किया जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जीवन में कष्ट लाने वाली इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के रूप में ये दिन मनाया जाता है।

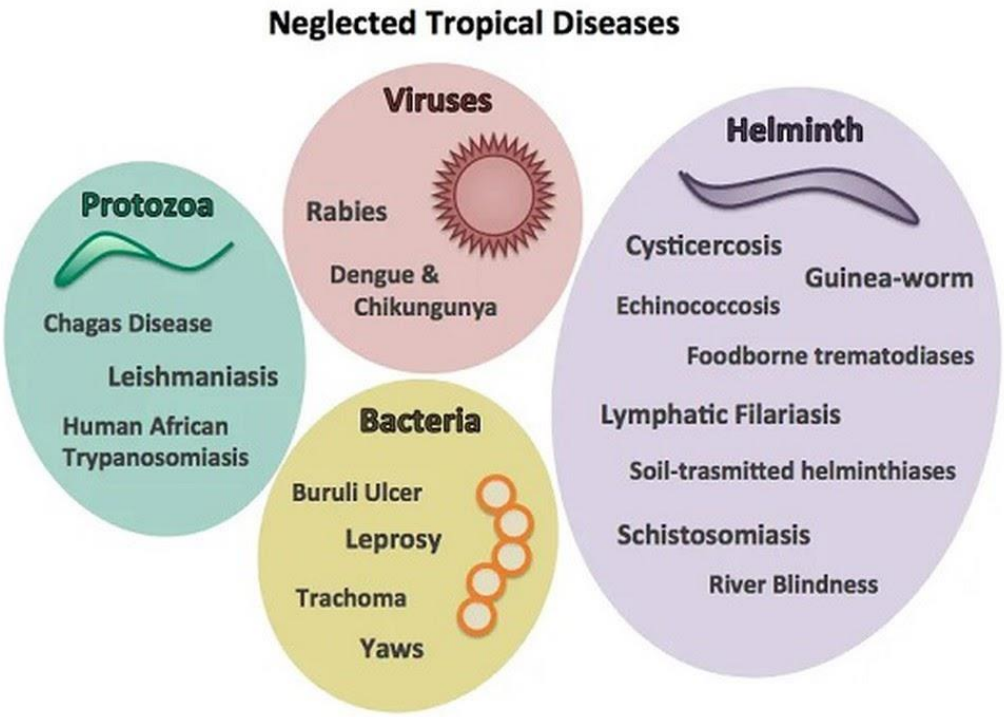

महत्वपूर्ण बिंदु

- विश्व एनटीडी दिवस के रूप में 30 जनवरी, 2021 को 25 देशों के 50 से ज्यादा ऐतिहासिक स्थलों को रोशनी से जगमगाया जाएगा ताकि इन रोगों के खिलाफ आपसी एकता और प्रतिबद्धता को बल दिया जा सके।
- अपनी यही वैश्विक प्रतिबद्धता दर्शाते हुए भारत भी अपनी युनेस्को विश्व धरोहर कुतुब मीनार को रोशन करेगा।

पृष्ठभूमि: मूल रूप से 2019 लास्ट माइल फोरम पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कोर्ट द्वारा इसे घोषित किया गया था, सैकड़ों भागीदारों ने विश्व एनटीडी दिवस को चिह्नित करने और फेस एनटीडी और एंड द नेगलेक्ट के लिए कार्रवाई की मांग करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए।

क्या आप जानते है?

- उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTDs) उष्णकटिबंधीय संक्रमणों के एक विविध समूह हैं जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में कम आय वाली आबादी में सामान्य हैं।
- यह विभिन्न प्रकार के रोगजनकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी कीड़े (हेल्मिंथ) के कारण होते हैं।
- उनमें डेंगू, रेबीज, ब्लाइंड ट्रैकोमा, बरुली अल्सर, एंडीमिक ट्रेपोनमेटोस (यवस), कुष्ठ (हैन्सन रोग) आदि शामिल हैं।
- ये रोग बड़ी तीन संक्रामक बीमारियों (एचआईवी / एड्स, तपेदिक और मलेरिया) के विपरीत हैं, यह आमतौर पर अधिक उपचार और अनुसंधान निधि प्राप्त करते हैं।
- दुनिया भर के 5 लोगों में NTDs से प्रभावित हैं।

- भारत इन प्रमुख उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों के कम से कम 11 दुनिया के सबसे बड़े बोझ का घर है।

परमाणु दवाओं के उत्पादन के लिए प्रथम पीपीपी अनुसंधान रिएक्टर

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II - स्वास्थ्य और GS- III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के प्रमुख अनुसंधान संगठन, ने न्यूक्लियर मेडिसिन के उत्पादन के लिए पहले पीपीपी रिसर्च रिएक्टर के लिए एक डिजाइन तैयार किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रस्तावित साझेदारी में, निजी संस्थाओं को रिएक्टर और प्रसंस्करण सुविधाओं में निवेश के एवज में अनुसंधान रिएक्टर में उत्पादित आइसोटोप को संसाधित करने और विपणन करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त होंगे।
- **पृष्ठभूमि:** मई 2020 में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने DE के लिए आत्मनिर्भार भारत पहल के एक भाग के रूप में मेडिकल आइसोटोप के उत्पादन के लिए पीपीपी मोड में एक शोध रिएक्टर की स्थापना की घोषणा की।
- यह परियोजना चिकित्सा और औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख रेडियो आइसोटोप में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
- वैश्विक स्तर पर, परमाणु चिकित्सा USD 6 बिलियन बाजार है और 2030 तक 30 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने के लिए तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। भारत BARC के तत्वावधान में देश में सभी प्रमुख आइसोटोप का उत्पादन करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21: स्वास्थ्य

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II - स्वास्थ्य

समाचार में-

- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में परिकल्पित जीडीपी के 1% से 2.5-3% तक स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च में वृद्धि की सिफारिश की है।

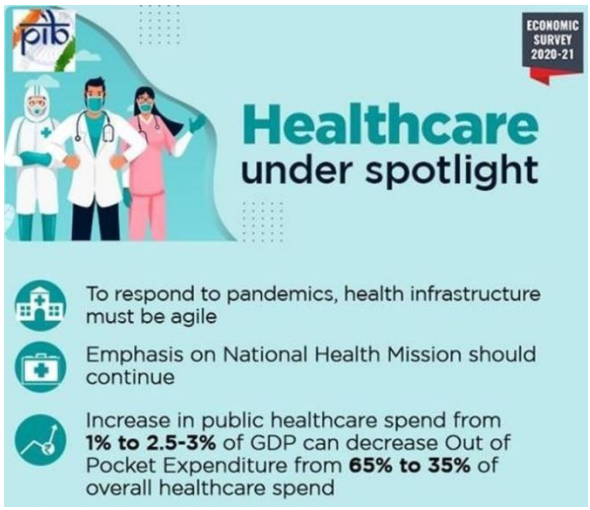

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह बताता है कि यह आउट-ऑफ-पॉकेट-व्यय (OOPE) को समग्र स्वास्थ्य व्यय के 65% से 35% तक कम किया जा सकता है।
- सर्वेक्षण ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) को आयुष्मान भारत योजना के संयोजन में जारी रखा जाना चाहिए।
- COVID-19 की चल रही वैश्विक महामारी के दौरान सीखे गए पाठों से आकर्षित होकर, आर्थिक सर्वेक्षण देश में स्वास्थ्य सेवा के अंतिम-मील की चुनौतियों को पूरा करने के लिए टेलीमेडिसिन को अपनाने के लिए एक मजबूत मामला बनाता है।

सरकारी योजनाएँ

स्कूल बैग नीति, 2020

भाग- GSप्रीलिम्स और GS- II - शिक्षा

समाचार में-

- शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा जारी 'स्कूल बैग नीति, 2020' का पालन करने के लिए स्कूलों को एक परिपत्र जारी किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- परिपत्र के अनुसार, स्कूली छात्रों को एक विशेष दिन पर किताबों और नोटबुक को स्कूल में लाने के बारे में छात्रों को पहले से सूचित कर देना चाहिए।
- उन्हें अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए अपने बैग की जांच करनी चाहिए कि वे अनावश्यक सामग्री तो नहीं ले जा रहे हैं।
- स्कूल बैग का वजन, पॉलिसी के अनुसार, होना चाहिए: (i) कक्षा I और II के छात्रों के लिए 1.6 से 2.2 किलोग्राम, (ii) कक्षा III, IV और V के लिए 1.7 से 2.5 किलोग्राम, (iii) 2 कक्षा VI और VII के लिए 3 किग्रा, (iv) कक्षा VIII के लिए 2.5 से 4 किग्रा, (V) कक्षा IX और X के लिए 2.5 से 4.5 किग्रा और (vi) कक्षा XI और XII के लिए 3.5 से 5 किग्रा।
- शिक्षकों को पूरी कक्षा के लिए चुने गए दिन में हर तीन महीने पर छात्रों के स्कूल बैग के वजन की जाँच करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
- माता-पिता को भारी बैग के बारे में कोई भी जानकारी बताई जानी चाहिए।
- स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए, स्कूल प्रबंधन को स्कूल के सभी छात्रों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना चाहिए।

क्या आप जानते है?

- भारी स्कूल बैग छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक गंभीर खतरा हैं।
- भारी स्कूल बैग से बढ़ते बच्चों के कशेरुक स्तंभ और घुटनों को नुकसान हो सकता है।

खबर में जगह: IIM संबलपुर

भाग- GSप्रीलिम्स और GS- II - शिक्षा

समाचार में-

- भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में IIM संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी।

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन

संबलपुर

- संबलपुर ओडिशा में एक शहर है, जो महानदी नदी के तट पर स्थित है।
- संबलपुर भारत के प्राचीन स्थानों में से एक है, जो प्रागैतिहासिक युग में दर्ज बस्तियों के साथ है।

- यह संबलपुरी साड़ी के लिए जाना जाता है जो शंख (शैल), चक्र (पहिया), फूला (फूल) जैसे पारंपरिक रूपांकनों को शामिल करने के लिए जाना जाता है। यह एक हाथ-करघा पर बुने हुए कपड़े से बनाया जाता है।
- हीराकुंड बांध, दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध और एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, संबलपुर में है।
- संबलपुर का नाम देवी संमेली से लिया गया है, जिसे इस क्षेत्र का शासन देवता माना जाता है।

प्रधान मंत्री आवास बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) सफलतापूर्वक 5 साल के संचालन को पूरा करती है

भाग- GSप्रीलिम्स और GS- II - **नीतियां और हस्तक्षेप**

समाचार में-

- **फसल बीमा योजना**- 13 **जनवरी** 2021 **को प्रधान मंत्री फैसल सीमा यज्ञ (पीएमएफबीवाई) ने सफलतापूर्वक** 5 **वर्षों के संचालन को पूरा किया।**

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन

- **प्रधान मंत्री आवास बीमा योजना** (PMFBY) 2016 **में शुरू की गई थी।**
- **यह किसानों के लिए उनकी पैदावार के लिए एक बीमा सेवा योजना है।**
- **इसका उद्देश्य किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करना और पूर्ण बीमित राशि के लिए फसल आश्वासन दावे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है।**
- **इसे पूर्व की दो योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना** (NAIS) **और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना** (MNAIS) **के स्थान पर वन नेशन-वन स्कीम के अनुरूप तैयार किया गया था।**
- **यह योजना सभी खाद्य और तिलहन फसलों और वार्षिक वाणिज्यिक / बागवानी फसलों को कवर करती है, जिसके लिए पिछले उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं और जिसके लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (जीसीईएस) के तहत फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) की अपेक्षित संख्या का संचालन किया जाता है।**
- **इसके द्वारा कार्यान्वित: सामान्य बीमा कंपनियाँ।**
- **द्वारा प्रशासित: कृषि मंत्रालय**
- **अधिसूचित फसलों और अन्य लोगों के लिए स्वैच्छिक फसलों के लिए ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य है।**

विनियामक अनुपालन पोर्टल शुरू किया

भाग- GSप्रीलिम्स और GS-III - **अर्थव्यवस्था**

समाचार में-

- **उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने व्यवसायों और नागरिकों के लिए नियामक अनुपालन बोझ को कम करने के लिए एक नियामक अनुपालन पोर्टल शुरू किया है।**

महत्वपूर्ण बिंदु

- **उद्देश्य: बोझिल अनुपालन को कम करने के लिए नागरिकों, उद्योगों और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना।**
- **यह सभी केंद्रीय और राज्य-स्तर के अनुपालन का एक पहला-अपनी तरह का केंद्रीय ऑनलाइन भंडार के रूप में भी कार्य करेगा।**
- **सभी केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के कानूनों / नियमों / नियमों की जांच उनके दायरे में होगी और सभी प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने और सरल बनाने और बोझिल अनुपालन को दूर करने के लिए एक कार्य योजना को लागू किया जाएगा।**
- **इन विवरणों को विनियामक अनुपालन पोर्टल पर कैप्चर और ट्रैक किया जाएगा।**
- **सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसे व्यापार निकायों के उद्योग हितधारक भी अनुपालन और प्रस्तावित सिफारिशें प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे।**
- **इसका आकलन संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और नियामक अनुपालन बोझ को कम करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।**

अंतरराष्ट्रीय

संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II- अंतर्राष्ट्रीय मामले

समाचार में-

- ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सूचित किया है कि वह 20 प्रतिशत शुद्धता तक समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन करने का इरादा रखता है, जो कि 2015 वियना समझौते (जेसीपीओए के रूप में भी जाना जाता है) द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है।

JCPOA के बारे मे

- वर्ष 2015 में वैश्विक शक्तियों (**P**5 + 1) के समूह जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, चीन, रूस और जर्मनी शामिल हैं, के साथ ईरान द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम के लिये दीर्घकालिक समझौते पर सहमति व्यक्त की गई।
- जेसीपीओए के तहत, ईरान ने मध्यम-समृद्ध यूरेनियम के अपने भंडार को खत्म करने पर सहमति व्यक्त की, इसके कम-समृद्ध यूरेनियम के भंडार को **98%** तक कम कर दिया, और **13** साल के लिए इसके गैस सेंट्रीफ्यूज की संख्या को लगभग दो-तिहाई कम कर दिया।
- अगले **15** वर्षों के लिए ईरान केवल **3.67%** तक यूरेनियम को समृद्ध करेगा। ईरान ने समान अवधि के लिए किसी भी नई भारी जल-रिएक्टर की सुविधा का निर्माण नहीं करने पर भी सहमति व्यक्त की।
- यूरेनियम-संवर्धन गतिविधियां **10** साल के लिए पहली पीढ़ी के सेंट्रीफ्यूज का उपयोग करके एकल सुविधा तक सीमित रहेंगी। प्रसार जोखिमों से बचने के लिए अन्य सुविधाओं को परिवर्तित किया जाएगा।
- समझौते के साथ ईरान के अनुपालन की निगरानी और सत्यापन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी **(IAEA)** की सभी ईरानी परमाणु सुविधाओं तक नियमित पहुंच होगी।
- यह समझौता प्अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने के बदले में, ईरान को अमेरिकी, यूरोपीय संघ और **UNSC** के परमाणु-प्रतिबंधों से राहत प्रदान करेगा।
- **5** जनवरी **2020** को, बगदाद हवाई अड्डे हमले में जिसने ईरानी सेनापति कासिम सोलेमानी को निशाना बनाया और मार डाला, ईरान ने घोषणा की कि यह अब सौदे की सीमाओं का पालन नहीं करेगा, लेकिन आईएईए के साथ समन्वय करना जारी रखेगा, जिससे संभावना खुलेगी।

GIBRALTAR (यूके-स्पेन डील)

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II- अंतर्राष्ट्रीय मामले

समाचार में-

नए साल की पूर्व संध्या पर ब्रेक्सिट संक्रमण की अवधि समाप्त होने से कुछ घंटे पहले, स्पेन ने घोषणा की कि इसने ब्रिटेन के साथ और जिब्राल्टर से मुक्त आवागमन बनाए रखने के लिए एक सौदा किया है

- जिब्राल्टर इबेरियन प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर भूमि का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे ब्रिटेन नियंत्रित करता है लेकिन स्पेन इसपर दावा करता है।

सौदे के बारे में

- आधिकारिक तौर पर एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र, शेष जिब्राल्टर अब शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा होगा और यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करेगा, इस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया है कि एक कठोर सीमा इसे शेष यूरोप से अलग नहीं करती है।
- **2016** ब्रेक्सिट जनमत संग्रह के परिणाम ने जिब्राल्टर और यूरोप के बाकी हिस्सों के बीच सख्त सीमा की संभावना को जन्म दिया, बावजूद जिब्राल्टर में **96** प्रतिशत वोट यूरोपीय संघ में शेष रहने के पक्ष में थे।
- जिब्राल्टेरियन ने मुख्य रूप से 'रिमेन' को वोट दिया क्योंकि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था स्पेन के साथ एक खुली सीमा पर निर्भर करती है, जो रोज़ाना **15,000** से अधिक श्रमिकों और **200** ट्रकों को भेजती है।
- हालांकि, स्वतंत्र आवागमन अब स्पेन-ब्रिटेन सौदे के लिए धन्यवाद जारी रखेगा, क्योंकि जिब्राल्टर को शेंगेन क्षेत्र में रखा जा रहा है, जिसमें स्पेन एक गारंटर के रूप में काम करता है।
- **शेंगेन पासपोर्ट-** मुक्त क्षेत्र में यूरोपीय संघ से **22** देश, और चार अन्य क्षेत्र शामिल हैं-नॉरवे, स्विटजरलैंड, आइसलैंड और लियोन्टेनस्टीन। ब्रिटेन कभी भी इस क्षेत्र का हिस्सा नहीं रहा है
- यूरोपीय संघ अब जिब्राल्टर से और उसके लिए मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अगले चार वर्षों के लिए फ्रोंटेक्स बॉर्डर गार्ड्स रखेगा और क्षेत्र का बंदरगाह और हवाई अड्डा शेंगेन क्षेत्र की बाहरी सीमा बन जाएगा।
- इस सौदे का मतलब होगा कि यूरोपीय संघ की निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा नियम जैसे श्रम बाजार और पर्यावरण जिब्राल्टर पर लागू होते रहेंगे।
- हालांकि यह सौदा मुक्त आंदोलन को कवर करता है, लेकिन यह स्पेन और यूके के बीच संप्रभुता विवाद को संबोधित नहीं करता है। ब्रिटेन ने इस समझौते को एक अलग संधि के लिए "राजनीतिक ढांचा" कहा है, वह जिब्राल्टर के बारे में यूरोपीय संघ के साथ हस्ताक्षर करना चाहता है।

- स्रोत: ब्रिटानिका

जिब्राल्टर के बारे में

- जिब्राल्टर, केवल 6.8 वर्ग किमी के क्षेत्र और लगभग 34,000 लोगों की आबादी के साथ, सदियों से स्पेन और ब्रिटेन के बीच तीव्र विवाद का विषय रहा है। यह मुख्य रूप से अपने रणनीतिक स्थान के कारण चर्चा में रहा है।
- यह क्षेत्र, स्पेन की जमीन से एक छोटी सी पट्टी से जुड़ा हुआ है और तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में एकमात्र उद्घाटन के रूप में कार्य करता है, जिससे यह यूरोप और यूरोप के बीच सबसे छोटे समुद्री मार्ग पर एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्वेज नहर के माध्यम से एशिया से जुड़ा है।
- 1713 में एक युद्ध के बाद जिब्राल्टर ब्रिटिश हाथों में चला गया, और तब से ब्रिटेन द्वारा इसे फिर से लेने के कई प्रयासों के बावजूद यह ब्रिटेन के साथ बने रहे।
- अपने रणनीतिक महत्व के कारण, जिब्राल्टर 18 वीं शताब्दी के बाद से ब्रिटेन द्वारा अत्यधिक किलेबंद हो गया, इस प्रकार इसे आमतौर पर "द रॉक" कहा जाता था।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी, मित्र देशों के लिए जिब्राल्टर का बंदरगाह महत्वपूर्ण था, और यह नाटो के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है।
- जब यह 1973 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ में शामिल हुआ, तब जिब्राल्टर एक "क्राउन कॉलोनी" थी, लेकिन 2002 में ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र के रूप में इसे पुनःवर्गीकृत किया गया।
- दो जनमत संग्रह में, एक 1967 में और दूसरा 2002 में, जिब्राल्टेरियन लोगों ने ब्रिटिश क्षेत्र बने रहने के लिए भारी मतदान किया।

- वर्तमान में, यह क्षेत्र रक्षा और विदेश नीति को छोड़कर, सभी पहलुओं में स्व-शासित है, और जिब्राल्टेरियन के पास ब्रिटिश नागरिकता है।

वियतनाम ने पहली बार भारत से चावल का आयात किया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध; GS- III - व्यापार

समाचार में-

- सीमित घरेलू आपूर्ति के बीच, स्थानीय स्तर पर नौ वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर कूदने के बाद वियतनाम ने पहली बार भारत से चावल खरीदना शुरू किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश वियतनाम अब भारत से चावल खरीद रहा है।
- 10 सालों के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब विश्व बाजार में चावल निर्यातक देशों की गिनती में भारत को चुनौती देने वाला देश हमसे चावल ले रहा है।
- नौ सालों में पहली बार वहां चावल के दाम पीक पर हैं जिसके कारण वह भारत से चावल खरीद रहे है।
- वियतनाम में चावल का उत्पादन काफी अधिक होता है और वहां चावल खाया भी सबसे अधिक जाता है।
- एशियाई देशों ने चावल की सप्लाई को कड़ा कर दिया है जिसके कारण साल 2021 में चावल के दाम और बढ़ सकते हैं। यही कीमतों में बढ़ोतरी थाईलैंड और वियतनाम जैसे चावल के पारंपरिक खरीदारों को भारत से खरीदने की तरफ मोड़ रहा है।

- इंडस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि भारतीय व्यापारियों को जनवरी-फरवरी में 70,000 टन 100 फीसदी टूटे चावल का निर्यात करने का अनुबंध किया गया है। ये शीपमेंट करीब 310 डॉलर प्रति टन का है।
- भारत की चावल की कीमतें विश्व बाजार में सभी को आकर्षित कर रही हैं। कीमतों में अंतर के कारण ही एक्सपोर्ट संभव हो पाया है।

क्या आप जानते है?

- 2020 में भारत ने रिकॉर्ड 14 मिलियन टन चावल का निर्यात किया।
- दिसंबर में, दुनिया के सबसे बड़े चावल आयातक चीन ने थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम से आपूर्ति को कड़ा करने और तीव्र रियायती कीमतों की पेशकश के कारण कम से कम तीन दशकों में पहली बार भारतीय चावल खरीदना शुरू किया।
- वियतनाम दुनिया का चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

कैबिनेट ने "निर्दिष्ट कुशल कार्यकर्ता" में भारत और जापान के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जापान के बीच "निर्दिष्ट कुशल श्रमिक" में भागीदारी पर समझौता ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- वर्तमान एमओसी जापान में चौदह निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम करने के लिए आवश्यक कौशल और जापानी भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुशल भारतीय श्रमिकों को भेजने और स्वीकार करने पर भारत और जापान के बीच साझेदारी और सहयोग के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करेगा।
- वर्तमान मेमोरंडम ऑफ कोऑपरेशन जापान में चौदह निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम करने के लिए आवश्यक कौशल और जापानी भाषा की परीक्षा पास करने वाले कुशल भारतीय श्रमिकों को भेजने और स्वीकार करने पर भारत और जापान के बीच साझेदारी और सहयोग के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करेगा।
- इन भारतीय श्रमिकों को जापान सरकार द्वारा "निर्दिष्ट कुशल श्रमिक" के निवास का एक नया दर्जा दिया जाएगा।
- कार्यान्वयन रणनीति: इस MOC के तहत, इस MOC के कार्यान्वयन का पालन करने के लिए एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना की जाएगी।
- गहरा असर: मेमोरैंडम ऑफ कोऑपरेशन (एमओसी) लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाएगा, श्रमिकों की गतिशीलता और भारत से जापान के कुशल पेशेवरों को बढ़ावा देगा।

- लाभार्थियों: चौदह सेक्टरों से कुशल भारतीय कामगार। देखभाली करना; भवन की सफाई; सामग्री प्रसंस्करण उद्योग; औद्योगिक मशीनरी विनिर्माण उद्योग; इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक जानकारी संबंधित उद्योग; निर्माण; जहाज निर्माण और जहाज से संबंधित उद्योग; ऑटोमोबाइल रखरखाव; विमानन; आवास; कृषि; मछली पालन; खाद्य और पेय पदार्थ निर्माण उद्योग और खाद्य सेवा उद्योग ने जापान में काम करने के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाया होगा।

समाचार में स्थल : हजार द्वीप

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- **9** जनवरी **2021** को, श्रीविजय एयर फ़्लाइट **182** का संचालन करने वाला एक बोइंग **737-500 (PK-CLC)** जकार्ता सोएकरनो-हट्टा हवाई अड्डे से पोंटियानक सुपेडियो हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने के बाद लापता हो गया।
- विमान हजार द्वीपों के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन

- हजार द्वीप (आधिकारिक तौर पर केपुलाआन सेरिबू) जकार्ता के तट के उत्तर में द्वीपों की एक श्रृंखला है।
- यह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का एकमात्र रीजेंसी बनाता है।
- यह पश्चिम जकार्ता खाड़ी में जावा सागर में 45 किमी (28 मील) उत्तर में फैली 342 द्वीपों की एक स्ट्रिंग और वास्तव में बंटेन प्रांत के उत्तर में स्थित है।

खाड़ी में अंतर को कम करना: खाड़ी में सुलह शिखर सम्मेलन

प्रसंग: सऊदी अरब के अल-उल्ला में, जहां खाड़ी और उसके सहयोगियों ने कतर की अपनी नाकाबंदी को खत्म करने का फैसला किया, इसके साथ अब उनकी लंबी लड़ाई खत्म हो गई है।

कतर और सऊदी सहयोगियों के बीच क्या झगड़ा था?

- **कतर पर आतंकवाद के वित्तपोषण का आरोप:** 2017 में, सऊदी अरब ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में, यूएई, बहरीन और मिस्र ने नाकाबंदी लागू की और राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया, जिसमें छोटे खाड़ी देश पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया गया।
- **सामान्यीकरण की मांगों की सूची:** उन्होंने इसे हटाने के लिए 13 मांगें भी जारी कीं, जिसमें कतर से वित्त पोषित टीवी नेटवर्क, अल जजीरा को बंद करना, एक तुर्की सैन्य अड्डे को बंद करना और ईरान के साथ राजनयिक संबंधों को कम करना शामिल था।

क्या कतर ने सऊदी अरब और उसके सहयोगियों की जबरदस्त रणनीति को प्रस्तुत किया?

- भारी आर्थिक लागत के बावजूद क़तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
- जब सऊदी और एमिरती हवाई जहाज सेवा बंद हो गए, तब ईरान ने कतर को वैश्विक कनेक्टिविटी की पेशकश की।
- अल जज़ीरा अभी भी संचालित हो रहा है।
- कतर ने अंकारा के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए और अधिक तुर्की सैनिकों को आमंत्रित किया है, जो पश्चिम एशिया में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए उत्सुक है।
- इसके अलावा, इसने अमेरिकी-तालिबान सौदे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तालिबान प्रतिनिधियों और अफगान सरकार के बीच बातचीत की मेजबानी करना जारी रखा।
- अगर मूल सऊदी योजना कतर को अलग-थलग करने और घुटने टेकने की थी, तो उसने बैकफायर कर दिया है।
- और ट्रम्प प्रशासन के अंतिम हफ्तों में, मोहम्मद बिन सलमान और उनके सहयोगियों ने अपने रणनीतिक मूर्खता का एहसास किया है।

सामंजस्य शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों द्वारा सामंत को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए थे?

- क़तर ने सुलह तक पहुँचने के लिए कुछ रियायतें दी हैं।

- 13 विशिष्ट मांगों को अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग पर एक व्यापक समझौते द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो विभिन्न पक्षों के लिए अलग-अलग व्याख्याओं के लिए खुला हो सकता है।
- शिखर सम्मेलन के बाद, कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश का ईरान और तुर्की के साथ संबंधों को बदलने का कोई इरादा नहीं था।
- व्यवहार में, सऊदी पक्ष ने अपनी मांगों से पीछे हट गया और एक अस्थिर कतर के साथ संशोधन किया।

सऊदी अरब के अपनी मांगों से हटने के क्या कारण हैं?

- सऊदी यू-टर्न एक वास्तविक सामरिक पुनर्विचार का परिणाम हो सकता है।
- खाड़ी में दरार ने ईरान और तुर्की, रियाद के मुख्य प्रतिद्वंद्वियों की मदद की, जबकि यह कतर के खड़े होने में विफल रहा। अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत ईरान को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने के लिए कतरी भुगतान से कुछ वित्तीय राहत भी मिली।
- हवाई और समुद्री अवरोधों को उठाकर, सउदी और अमीरात लोग उन पैसों से ईरान को मना कर सकते हैं और ईरान पर आर्थिक दबाव डालने की भी कोशिश कर सकते हैं।
- सऊदी अरब एक संयुक्त अरब क्षेत्रीय मोर्चे को बनाने की कोशिश करता है क्योंकि जो बिडेन ईरान परमाणु समझौते को फिर से संगठित करने की तैयारी कर रहा है।
- सउदी भी उम्मीद कर रहे होंगे कि दो अमेरिकी सहयोगियों (सऊदी अरब और कतर) के बीच खाड़ी को पाटने से उन्हें बिडेन प्रशासन को उत्तेजित करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

- झगड़े का अंत स्वागत योग्य है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इस अनावश्यक संकट का जन्म जोर-जबरदस्ती की सोची-समझी सऊदी-अमीरीकि रणनीति से हुआ था। यह उन पर खराब असर डालता है।
- सऊदी और उसके सहयोगियों को गलतियों से सीखना चाहिए और आपसी हितों और सहयोग के आधार पर संबंध बनाने चाहिए, न कि खतरों और जबरदस्ती पर।

Apple, Amazon और Google द्वारा Parler को निलंबित कर दिया गया

भाग- GSप्रीलिम्स और GS-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध और GS- III - प्रौद्योगिकी

समाचार में-

- Apple, Amazon और Google ने Parler नामक सोशल नेटवर्क को निलंबित कर दिया है क्योंकि इस मंच ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं कि हिंसा भड़काने वाली सामग्री जांच में बनी रहे।

महत्वपूर्ण बिंदु

- Parler एक अमेरिकी ऑल-टेक माइक्रोब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है।
- यह खुद को एक मुफ्त भाषण और मुख्यधारा के सामाजिक नेटवर्क जैसे कि ट्विटर और फेसबुक के लिए निष्पक्ष विकल्प के रूप में बाजार प्रदान करता है।
- Parler ने डोनाल्ड ट्रम्प समर्थकों, रूढ़िवादियों और दक्षिणपंथी चरमपंथियों का एक महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता आधार भी प्रदान किया है।
- इसका निलंबन 6 जनवरी की घटनाओं के बाद हुआ, जब ट्रम्प समर्थकों की एक सशस्त्र भीड़ ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया और पुलिस के साथ भिड़ गए, जिसे कांग्रेस ने जो बिडेन की राष्ट्रपति की जीत की पुष्टि करने के लिए बुलाया था।
- इस प्लेटफ़ॉर्म को दक्षिणपंथी झुकाव वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा पसंद किया गया है और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कैपिटल हिल घेराबंदी में भाग लेने वालों में से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थकों द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग किया गया था।

समाचार में स्थल: भारत ने साहेल और लेक चाड क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है-

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- भारत ने पश्चिम अफ्रीका में साहेल और लेक चाड क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
- भारत ने नाइजीरिया और लेक चाड क्षेत्र में बोको हरम द्वारा और पश्चिम अफ्रीका में इस्लामिक स्टेट द्वारा आतंकवादी हमलों की भी निंदा की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- लेक चाड मध्य अफ्रीका में एक ऐतिहासिक रूप से बड़ी, उथली, बेचान झील है, जिसका आकार सदियों से भिन्न है।
- एक एंडोरिक बेसिन एक जल निकासी बेसिन है जो सामान्य रूप से पानी को बरकरार रखता है और पानी के अन्य बाहरी निकायों के लिए कोई बहिर्वाह नहीं करता है।
- मीठे पानी की झील पश्चिम-मध्य अफ्रीका के सहेलियन क्षेत्र में स्थित है।
- चाड झील मुख्यतः चाड के पश्चिम में स्थित है, जो उत्तरपूर्वी नाइजीरिया के साथ सीमा साँझा करता है।
- यह चाड बेसिन की सबसे बड़ी झील है।
- चैरी नदी, अपनी सहायक नदी द लॉगोन से तंग आकर, झील के पानी को **90%** से अधिक प्रदान करती है, जिसमें एक छोटी राशि नाइजीरिया / नाइजर में योब नदी से आती है।
- वाष्पीकरण के उच्च स्तर के बावजूद, यह झील ताजे पानी की झील है।

यूएस के संचार निर्णय अधिनियम की धारा 230

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध और GS- III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थकों की एक भीड़ ने पिछले हफ्ते यूएस कैपिटल पर धावा बोल दिया था, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बिग टेक कंपनियों जैसे ट्विटर और फेसबुक द्वारा हिंसा भड़काने और गलत सूचना फैलाने में उनकी कथित भूमिका के लिए निलंबित कर दिया गया था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस घटना ने यूएस के संचार निर्णय अधिनियम की धारा **230** के बारे में नए सिरे से बहस की।
- अधिनियम इंटरनेट कानून का एक विवादास्पद टुकड़ा है।
- यह इन तकनीकी कंपनियों को अपनी शक्तियों का उपयोग करने और पहली जगह में राष्ट्रपति को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है।
- इसे अधिनियम **1996** में पारित किया गया था।
- यह इंटरनेट कंपनियों को उनकी वेबसाइटों पर साझा की जाने वाली सामग्री के लिए कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
- पोर्नोग्राफी को ऑनलाइन विनियमित करने के लिए अधिनियम को पहली बार लाया गया था।
- धारा **230** अधिनियम का एक संशोधन है, जो उपयोगकर्ताओं को उनकी टिप्पणियों और पदों के लिए ऑनलाइन जिम्मेदार रखता है।
- इसके अलावा, अधिनियम के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित ऑनलाइन कंपनियां, अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनी वेबसाइट पर साझा की गई सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।
- इसलिए यदि कोई उपयोगकर्ता वेबसाइट पर कुछ अवैध पोस्ट करता है, तो कंपनी मुकदमों से सुरक्षित है।

क्या आप जानते है?

धारा 230 की व्यापक आलोचना क्यों की जाती है?

- इसे सोशल मीडिया के वर्तमान स्वरूप में मौजूद होने से पहले पारित किया गया था।
- राजनीतिक नेताओं और इंटरनेट कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से कानून को अद्यतन करने के लिए कहा है।

Related articles:

- US Capitol Violence: Click here

भारत - सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों के मध्य 5 वां संवाद

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- भारत और सिंगापुर के बीच **5** वें रक्षा मंत्रियों के संवाद **(DMD)** को हाल ही में एक वीडियो सम्मेलन के माध्यम से सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस 5 डीएमडी में, दोनों मंत्रियों ने दोनों नौसेनाओं के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- दोनों मंत्रियों ने आपदाओं की प्रतिक्रिया में निकट परिचालन सहयोग के लिए अगस्त 2020 में मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) सहयोग पर लागू समझौते का स्वागत किया।
- हाल ही में, भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना ने सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (SIMBEX) के 27 वें संस्करण का सफलतापूर्वक संचालन किया और सिंगापुर-भारत-थाईलैंड समुद्री व्यायाम (SITMEX) के दूसरे संस्करण में भी भाग लिया; दोनों नवंबर 2020 में आयोजित हुए।
- भारतीय रक्षा मंत्री ने क्षेत्रीय सुरक्षा वास्तुकला में आसियान की केंद्रीयता की पुष्टि की और आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM) -प्लस के सभी प्रयासों के लिए भारत के समर्थन का वादा किया।
- दोनों सशस्त्र बलों की साइबर एजेंसियों ने भी आपस में सहयोग का आश्वासन दिया है।

टेक दिग्गज बनाम रेगुलेटर

संदर्भ: ऑस्ट्रेलिया में संसद इस कानून पर बहस कर रही है, जिसके लिए Google और फेसबुक को अपनी सामग्री का उपयोग करने के लिए मीडिया कंपनियों के साथ भुगतान वार्ता में प्रवेश करने की आवश्यकता होगी, इस घटना में एक समझौते को स्थगित करने के लिए एक मध्यस्थ के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है।

टेक दिग्गजों से प्रतिक्रिया

- **काउंटर तर्क:** फेसबुक और गूगल ने तर्क दिया कि मीडिया उद्योग पहले से ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म द्वारा उनके लिए ट्रैफ़िक से लाभान्वित हो रहे थे, और प्रस्तावित नियम उन्हें "वित्तीय और परिचालन जोखिम के असहनीय स्तरों" को उजागर करेंगे।
- **वापसी का खतरा:** Google ने ऑस्ट्रेलिया से अपने सर्च इंजन को हटाने की धमकी दी है। फेसबुक ने कहा कि अगर वह रॉयल्टी भुगतान पर प्रस्तावित मानदंडों को अमल में लाया गया तो वह ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ताओं को समाचार लिंक पोस्ट करने या साझा करने से रोक सकता है।

ऑस्ट्रेलिया में मुख्य मुद्दा क्या है?

- **टेक जायंट्स के लिए समाचारों का महत्व:** हालांकि समाचारों के लिंक जो फेसबुक या गूगल के लिए प्रत्यक्ष विज्ञापन-पैसे वाले नहीं हो सकते हैं, दोनों ही समाचारों की उपस्थिति को अपने उत्पादों के साथ दर्शकों के जुड़ाव के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखते हैं।
- **टेक दिग्गजों के लिए रॉयल्टी का भुगतान कोई मुद्दा नहीं है:** जबकि दोनों कंपनियां समाचार प्रकाशकों को कुछ पैसे देने के लिए तैयार हैं, वे अपनी शर्तों पर सौदे करना चाहते हैं।
- **भुगतान प्रक्रिया पर नियंत्रण:** ऑस्ट्रेलिया में लड़ाई स्पष्ट रूप से इस बात पर केंद्रित है कि ये कंपनियां अपनी भुगतान प्रक्रिया पर कितना नियंत्रण रख पाएंगी - परिचालन संबंधी पहलू जैसे कि समाचार फ़ीड स्रोतों के लिए भुगतान की मात्रा तय करना और उनके परिवर्तनों को प्रकट करना।
- **सौदेबाजी की शक्ति का संतुलन:** लेकिन Google और Facebook इतिहास की सबसे बड़ी और लाभदायक कंपनियों में से दो हैं - और प्रत्येक समाचार प्रकाशक की तुलना में कहीं अधिक सौदेबाजी की शक्ति रखती है। समाचार मीडिया सौदेबाजी कोड इस असंतुलन को पूर्ववत् करने के लिए तैयार है।
- **कमर्शियल एग्रीमेंट को प्राथमिकता:** पेश किया जा रहा मीडिया कोड उनके लिए बहुत व्यवस्थित है जिसे वे स्वीकार करना चाहते हैं।
- **यूरोपीय संघ के साथ विनियमन में अंतर:** यूरोपीय अधिकारियों ने विशेष रूप से समझौतों के लिए एक मजबूर डिवाइस लगाए बिना, भुगतान को कॉपीराइट से जोड़ा है। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया का कोड लगभग पूरी तरह से समाचार आउटलेट्स की टेक मेजर की खबरों की सौदेबाजी की शक्ति पर केंद्रित है, और इसमें कुछ जबरदस्त विशेषताएं भी हैं।
- **शक्ति समीकरणों का मुद्दा:** यह ऑस्ट्रेलिया में एक प्रतियोगिता का मुद्दा है, यह पारंपरिक समाचार आउटलेट और तकनीकी प्लेटफार्मों के बीच **शक्ति समीकरणों** से सम्बंधित है।

केस स्टडी: दक्षिण कोरिया

- **Naver ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म:** लगभग चार साल पहले, दक्षिण कोरिया के सबसे लोकप्रिय समाचार साइट और सबसे बड़े सर्च इंजन (Google की तरह), Naver, ने कोरियाई समाचार प्रकाशक के साथ काम करने के लिए एक असामान्य मॉडल प्रस्तुत किया था।

- **न्यूज मीडिया से निपटने के लिए नया बिजनेस मॉडल:** Naver ने 125 आउटलेट्स को "Naver News इन-लिंक पार्टनर्स" के रूप में नामित करना शुरू किया, और उन्हें Naver पर प्रकाशित कहानियों के लिए भुगतान किया। अन्य 500 समाचार आउटलेट "सर्च भागीदार" अवैतनिक हैं। 2017 में इसके द्वारा कुल भुगतान 40 मिलियन $ से अधिक था।
- **मॉडल की आलोचना:** हालांकि यह सही मॉडल नहीं हो सकता है - समाचार आउटलेट आमतौर पर अपने हिस्से से असंतुष्ट रहे हैं; और आरोप है कि Naver ने उत्तर कोरिया के अनुरोध पर दक्षिण कोरिया के शीर्ष फुटबॉल संघ के महत्वपूर्ण लेखों की रैंकिंग में हेरफेर किया - यह टेम्पलेट उस देश में चालू है जहां लगभग 85% आबादी ऑनलाइन समाचारों तक पहुंच बनाती है।

फर्मों की प्रतिक्रिया

- फेसबुक ने यूके में अपने समाचार टैब फीचर (2019 से अमेरिका में उपलब्ध है) को द गार्जियन, द इकोनॉमिस्ट और द इंडिपेंडेंट के साथ संभावित टाई-अप लॉन्च करने की योजना बनाई है।
- Google अपने समाचार ऑफ़र प्लेटफ़ॉर्म को रोल आउट कर रहा है, Google नवीन समाचार शोकेस प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है , जिसमें कहानी पैनल हैं जो भाग लेने वाले प्रकाशकों को Google के समाचार उत्पादों के भीतर दिखाई देने वाली कहानियों को पैकेज करने की अनुमति देते हैं। यह एक दर्जन देशों में 450 से अधिक प्रकाशनों को मंच प्रदान करेगा,
- **Google** ने दिसंबर **2020** में घोषणा की थी कि वह "जल्द ही चुनिंदा समाचार प्रकाशकों के साथ साझेदारी में भुगतान की गई सामग्री तक लोगों की पहुँच शुरू कर देगा"। इसने कहा था कि यह सहभागी भागीदारों को न्यूज़ शोकेस उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान की गई सामग्री तक सीमित पहुंच प्रदान करेगा।
- फेसबुक और **Google** दोनों प्लेटफॉर्म का लक्ष्य समाचार आउटलेट्स के साथ भुगतान संधि को औपचारिक बनाना है
- हालांकि, यूरोपीय संघ के कॉपीराइट नियमों को अपनाने वाले फ्रांस के लिए **Google** की पहली प्रतिक्रिया समाचार स्निपेट को प्रदर्शित करने से बंद करना था - जब तक कि पिछले साल अक्टूबर में फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा नियामक ने सही कदम नहीं उठाया।
- **Google** ने स्पेन में अपनी **Google** समाचार सेवा भी बंद कर दी, जिससे प्रकाशकों को भुगतान करना अनिवार्य है।

क्या आपको पता है?

- भारत में, **2019** में डिजिटल विज्ञापन खर्च **24%** सालाना आधार पर बढ़कर **27,900** करोड़ रुपये हो गया, ईवाई अनुमानों के अनुसार, इसे **2022** तक बढ़कर **51,340** करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
- एडलवाइस रिसर्च के अनुसार, वैश्विक स्तर पर, फेसबुक और गूगल एक साथ डिजिटल ऐड खर्चों में **61%** बाजार हिस्सेदारी संभालते हैं; Google 37% के साथ सबसे आगे है।

भारत में बहस

- **बड़ा बाजार: 2020** के लिए भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर फिक्की-ईवाई की रिपोर्ट के अनुसार, देश में ऑनलाइन समाचार साइटों, पोर्टलों और एग्रीगेटर्स के **300** मिलियन उपयोगकर्ता हैं – जो लगभग **46%** इंटरनेट उपयोगकर्ता और **77%** स्मार्टफोन बनाते हैं। भारत में **2019** में **282** मिलियन उपयोगकर्ताओं थे, भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन समाचार पढने वाला देश है
- **मध्यस्थों का प्रभुत्व:** भारत में नीति निर्माताओं ने अब तक **Google** और फेसबुक जैसे बिचौलियों के प्रभुत्व पर ध्यान केंद्रित किया है, जो इस तरह से तैनात हैं कि सेवा प्रदाता इन प्लेटफार्मों के अलावा ग्राहकों तक नहीं पहुंच सकते हैं।
- **पर्याप्त चर्चा को कम करता है**: समाचार मीडिया आउटलेट्स के स्वास्थ्य पर मध्यस्थ प्लेटफार्मों के प्रभाव पर एक पर्याप्त चर्चा अभी तक किसी भी सार्थक तरीके से शुरू नहीं हुई है।
- **स्ट्रगलिंग स्टार्टअप:** भारत में अन्य प्रमुख समाचार एग्रीगेटर डेलीहंट और इनशॉर्ट हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की नीमन लैब की जनवरी **2020** की रिपोर्ट के अनुसार, दैनिक रूप से होस्ट किए गए कंटेंट के लिए प्रकाशकों को मासिक रूप से **5-6** लाख रुपये मासिक के बीच भुगतान किया गया था - लेकिन शर्तों में बदलाव के बाद उन्होंने मंच से दूर जाना शुरू कर दिया।
- **ऑस्ट्रेलिया की घटनाओं का निहितार्थ:** ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों पर लंबे समय तक भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के नियमन के लिए व्यापक प्रभाव हो सकते हैं।

निष्कर्ष

Google और फेसबुक ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के कानूनों को लागु करने के बाद इससे सम्बंधित सुविधाओं को बंद कर दिया है जो उन्हें अपनी सामग्री का उपयोग करने के लिए समाचार संगठनों को भुगतान करने का प्रस्ताव देते हैं। इस लड़ाई के परिणाम में भारत के लिए भी निहितार्थ शामिल है।

Connecting the dots

- Dominance of Big Tech: Click here
- Google Search Monopoly: Click here

यूएस ने फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को पुन:बहाल किया है

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रशासन ने घोषणा की कि यह फिलिस्तीनियों के साथ संबंध बहाल कर रहा है और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए नए सिरे से सहायता प्रदान कर रहा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन की कटऑफ से उलट है और इजरायल एवं फिलिस्तीनियों द्वारा सहमत किए गए दशकों पुराने संघर्ष के दो-राज्य समाधान के लिए इसके नए समर्थन का एक प्रमुख तत्व है।
- फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं द्वारा आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन के राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- यह पश्चिमी एशिया में एक डी ज्यूरे सॉवरेन राज्य है, जो वेस्ट बैंक (इज़राइल और जॉर्डन की सीमा) का दावा करता है और गाजा पट्टी (इसराइल और मिस्र की सीमा के साथ) निर्दिष्ट राजधानी के रूप में है, हालांकि इसका प्रशासनिक केंद्र वर्तमान में रामल्लाह (Ramallah) में स्थित है।
- फिलिस्तीन राज्य द्वारा दावा किए गए क्षेत्र पर 1948 से कब्जा किया गया है, पहले मिस्र और जॉर्डन द्वारा और फिर **1967** में छह-दिवसीय युद्ध के बाद इजरायल द्वारा।

अंतर सरकारी वार्ता ढांचा (IGN)

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि अंतर सरकारी समझौते **(IGN)** की शुरुआत हुए, लगभग **13** साल हो गए हैं।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों के समाधान के लिए प्रभावी रूप से कार्य करने में असमर्थ है क्योंकि इसमें समावेश की कमी थी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इंटरगवर्नमेंटल निगोशिएशन फ्रेमवर्क **(IGN)** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद **(UNSC)** के आगे सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर काम करने वाले राष्ट्र-राज्यों का एक समूह है, जो विश्व निकाय का **15**-सदस्यीय शीर्ष अंग है।
- **रचना**: आईजीएन कई अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बना है, अर्थात्: **(1)** अफ्रीकी संघ; (२) G-4 राष्ट्र (भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी); **(3)** सर्वसम्मति समूह **(UfC)** के लिए एकजुट; **(4)** विकासशील देशों का **L-69** समूह; **(5)** अरब लीग; **(6)** कैरेबियन समुदाय **(CARICOM)**।
- प्रत्येक समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए एक अलग सेट का प्रतिनिधित्व करता है।

- **2016** में, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक "मौखिक निर्णय" अपनाया गया था, जिसे "अभिसरण के तत्वों" के रूप में जाना जाता है, जो उस समय आईजीएन के सदस्यों द्वारा पहुंची सहमति की स्थिति को रेखांकित करता है।

भविष्य निवेश पहल मंच

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध ; GS- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भविष्य के निवेश पहल फोरम के चौथे संस्करण को संबोधित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव (एफआईआई) एक वार्षिक निवेश मंच है, जो रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया जाता है, ताकि विश्व अर्थव्यवस्था और निवेश के माहौल में रुझानों पर चर्चा की जा सके।
- इसे सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष **(PIF)** द्वारा होस्ट किया गया है।
- पहली घटना अक्टूबर **2017** में हुई थी।
- इस वर्ष मंच का उद्देश्य उन समाधानों को खोजना था कि कैसे व्यापार और सरकार स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ा सकती हैं, स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं, नियामक बाधाओं को दूर कर सकते हैं और उन्नत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

Image source: Click here

WEF के सामान्य ट्रस्ट नेटवर्क द्वारा क्रॉस बॉर्डर गतिशीलता को बहाल करना

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- केंद्रीय आर्थिक और परिवार कल्याण मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क द्वारा क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी को बहाल करने पर कार्यक्रम को संबोधित किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- **पृष्ठभूमि:** जैसा कि दुनिया भर के देश COVID-19 महामारी को दूर करने और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से शुरू करने के लिए काम करते हैं, वे सभी अपनी सीमाओं को फिर से खोलने और अपनी आबादी के स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए यात्रा और वाणिज्य को फिर से शुरू करने की अनुमति देने की चुनौती का सामना कर रहे हैं।
- इस चुनौती को दूर करने के लिए, कॉमन्स प्रोजेक्ट फाउंडेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सार्वजनिक और निजी हितधारकों के व्यापक स्वैच्छिक नेटवर्क के सहयोग से कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क लॉन्च किया है।
- इसे सामान्य ट्रस्ट नेटवर्क के लिए डिज़ाइन किया गया है:
  1. अपने स्वास्थ्य की जानकारी के लिए डिजिटल पहुँच के साथ व्यक्तियों को सशक्त बनाना,
  2. प्रत्येक गंतव्य की आवश्यकताओं को समझना और उनका पालन करना लोगों के लिए आसान बनाता है,
  3. सुनिश्चित करें कि सीमा पार यात्रा और वाणिज्य के लिए विश्वसनीय स्रोतों से केवल सत्यापन योग्य प्रयोगशाला परिणाम और टीकाकरण रिकॉर्ड प्रस्तुत किए जाते हैं।
- नेटवर्क विश्वसनीय प्रयोगशाला और टीकाकरण डेटा स्रोतों की वैश्विक रजिस्ट्री, प्रयोगशाला परिणामों के लिए मानक प्रारूप और टीकाकरण रिकॉर्ड और उन परिणामों एवं रिकॉर्डों को डिजिटल रूप से सुलभ बनाने के लिए मानक टूल द्वारा यह सक्षम है।

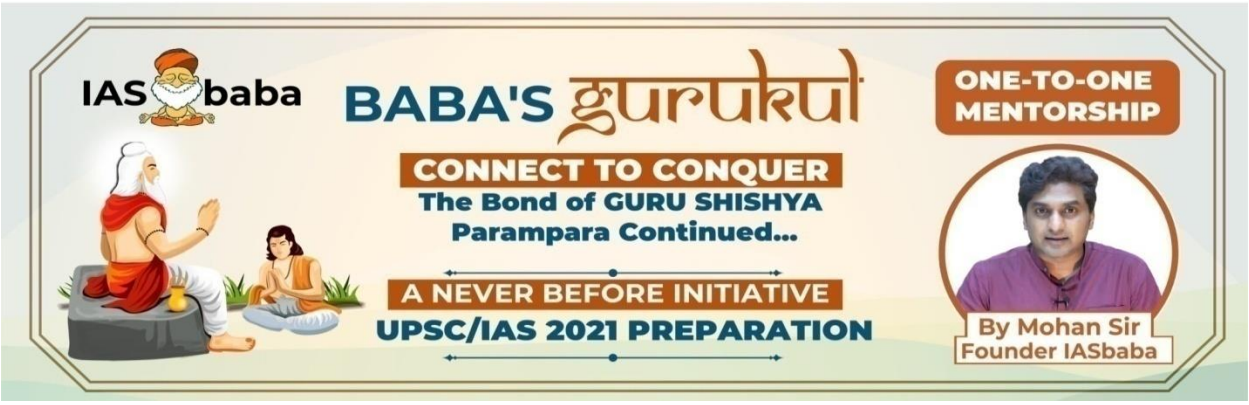

भारत और विश्व

एडीबी ने भारत के हिमाचल प्रदेश में बागवानी को समर्थन प्रदान करने के लिए 10 मिलियन $ ऋण पर हस्ताक्षर किया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध और GS- III - कृषि

समाचार में-

- एशियाई विकास बैंक **(ADB)** और भारत सरकार ने **10** मिलियन **$** की परियोजना तत्परता वित्तपोषण **(PRF)** पर हस्ताक्षर किए।
- **उद्देश्य**: हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय का विस्तार करने के उद्देश्य से एक आगामी परियोजना के लिए वित्त पायलटिंग गतिविधियों, और डिजाइन एवं क्षमता निर्माण में मदद करना।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पीआरएफ परियोजना विस्तृत डिजाइन गतिविधियों, राज्य स्तरीय एजेंसियों की क्षमता निर्माण और राज्य में उपोष्णकटिबंधीय बागवानी विकास के लिए सक्षम वातावरण बनाने के माध्यम से परियोजना तत्परता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए अग्रिम कार्यों का समर्थन करेगी।
- इसका उद्देश्य नई उत्पादन प्रौद्योगिकियों और विपणन प्रणालियों के पूर्व परीक्षण के साथ कार्यान्वयन की तत्परता सुनिश्चित करना है ताकि परियोजना लागत प्रभावी हो और समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके।
- यह परियोजना राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में फल और सब्जियों की खेती सहित उपोष्णकटिबंधीय बागवानी के विकास का समर्थन करेगी, जो वर्तमान में बारहमासी जल स्रोतों के सीमित उपयोग, जंगली जानवरों के अतिक्रमण के कारण फसलों के नुकसान और उच्च मूल्य वाले बाजारों तक सीमित पहुंच के कारण पिछड़ रही है।
- पीआरएफ पूर्ण सिंचाई योजनाओं पर जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूएएस) की स्थापना और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का भी समर्थन करता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

एशियाई विकास बैंक (ADB)

- यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है।
- **19** दिसंबर **1966** को स्थापित
- **मुख्यालय**: ऑर्टिगास सेंटर, मंडलायुंग, मनीला, फिलीपींस।
- यह बैंक एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
- इसे विश्व बैंक के तर्ज से बनाया गया है, और इसमें एक समान भारित मतदान प्रणाली है जहां सदस्यों को पूंजी सदस्यता के अनुपात में वोट वितरित किए जाते हैं।
- **31** दिसंबर **2018** तक, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में शेयरों का अनुपात **15.571%** सबसे अधिक था।
- चीन **6.429%,** भारत **6.317%** और ऑस्ट्रेलिया में **5.773%** शेयरों का भागीदार है।

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की तीन प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा।

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद **(UNSC)** की तीन प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- **पैनल :** आतंकवाद निरोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति।
- भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की भी अध्यक्षता करेगा। इस समिति की अध्यक्षता करना भारत के लिए बेहद अहम है। भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। विशेषकर सीमा पार से आतंकवाद के पीड़ितों में से भी एक है।
- तालिबान प्रतिबंध समिति, अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा विकास और प्रगति के लिए हमेशा से भारत की शीर्ष प्राथमिकता में रही है।
- लीबिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत लीबिया प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा।

नेपाल में राजनीतिक संकट

संदर्भ: नेपाल ने अपने प्रधानमंत्री (पीएम) केपी शर्मा ओली के संसद को भंग करने के फैसले के बाद एक राजनीतिक संकट में डूब गया है, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर संसद को भंग कर दिया और अप्रैल-मई में मध्यावधि आम चुनाव की घोषणा की है।

- ओली ने यह भी घोषणा की कि अप्रैल और मई **2021** में आम चुनाव तय समय से एक साल पहले होंगे

नेपाल के राजनीतिक दलों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- नेपाल की राजनीति में तीन प्रमुख दल हावी हैं: नेपाली कांग्रेस पार्टी; कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी ओली के नेतृत्व में, और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) प्रचंड के नेतृत्व में कार्यरत है।
- प्रचंड ने मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होने से पहले एक दशक (1996-2006) के लिए माओवादी विद्रोह का नेतृत्व किया। ओली हिंसा की राजनीति का घोर आलोचक थे जिसने 17,000 से अधिक मौतें हुई थी।
- लेकिन ओली ने 2017 में अपनी पार्टियों के बीच विलय के लिए माओवादियों से संपर्क किया, पूर्व में माओवादियों और नेपाली कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना को समाप्त करते हुए यह कदम हो सकता ओली की प्रधान मंत्री की महत्वाकांक्षाओं से सम्बंधित हो।
- विलय के बाद, दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त दिया कि वे बारी-बारी से सरकार का नेतृत्व करेंगे, इस वादे का ओली ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में पालन नहीं किया, जिसने अलगाव के बीज बोए।
- अब, जैसा कि एक विभाजन अपरिहार्य प्रतीत होता है, ओली इसके बाद उन लोगों के साथ सत्ता में बने रहने की उम्मीद कर रहे है।

संसद के विघटन का महत्वपूर्ण विश्लेषण

- ओली के फैसले के कारण: ओली ने यह कदम तब उठाया जब उन्होंने महसूस किया कि पार्टी के भीतर गुटबाजी अत्यधिक बढ़ गयी है और उन्हें पार्टी प्रमुख और प्रधान मंत्री के रूप में संभावित निष्कासन का सामना करना पड़ा सकता था
- गठबंधन का अंत: संसद के विघटन ने तीन साल पहले एकल, भव्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए नेतृत्व करने वाली वामपंथी ताकतों के बीच एकता को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया।
- नेपाल के नए संविधान के बारे में अनिश्चितता: नेपाल में सदन का विघटन नया नहीं है, लेकिन 2015 के नए संविधान के बाद यह पहला ऐसा उदाहरण है जो विघटन के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रस्तुत करता है। नया संविधान वैकल्पिक सरकार के गठन की खोज के बिना इस तरह के कदम की परिकल्पना नहीं करता है
- कार्यवाहक सरकार की जवाबदेही: पार्टी की सह-अध्यक्ष पुष्पा कमल दहल प्रचंड द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश के लिए एक स्थायी समिति की बैठक से कुछ घंटों पहले इस विघटन पर फैसला आया। संसद भंग होने के साथ और उनको अनुकूल राष्ट्रपति के रूप में देखा गया, ओली के पास किसी के प्रति जवाबदेह हुए बिना शासन करने की शक्ति होगी।

- थल सेना: नेपाल सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि वह चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम में तटस्थ रहेगी। इसका तात्पर्य यह है कि अगर ओली कानून और व्यवस्था बनाए रखने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए सुरक्षा बलों की मदद से शासन करने की कोशिश करता है, तो यह अनिश्चित है कि सेना इससे कितनी दूर रहेगी।
- **द चाइना फैक्टर:** 2006 के बाद से नेपाल की आंतरिक राजनीति में चीन एक बड़ा कारक रहा है। विभाजन को रोकने के लिए इसे लचर, स्पष्ट या गुप्त होने के रूप में देखा जाता है। चीन ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, पर्यटन और भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी निवेश किया है और यह नेपाल का सबसे बड़ा विदेशी निवेशकर्ता है
- **न्यायपालिका के फैसले का इंतजार:** विघटन के बाद से, उच्चतम न्यायालय में एक दर्जन याचिकाएं दायर की गई हैं, जो वर्तमान सदन के कार्यकाल के दो वर्षों के विघटन को चुनौती देती हैं। ओली के कदम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है।

भारत ने इस राजनीतिक संकट को कैसे संभाला?

- भारत में इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है: पिछले अवसरों के विपरीत, ओली ने अपने शासन को अस्थिर करने के लिए भारत को दोषी ठहराने से परहेज किया है। पीएम की इच्छा को उनके वरिष्ठ पार्टी सहयोगियों पर निर्देशित किया गया है कि वे उन्हें सुचारू रूप से शासन करने की अनुमति न दें।
- ओली के लिए भारत का सूक्ष्म समर्थन: ओली ने विरोधी बलों को चुपचाप खुश करने का प्रयास किया, लेकिन जब वे असफल हो गए, तो भारत ने हताश ओली को मदद का हाथ बढ़ाया। भारत की महत्वपूर्ण यात्राओं की एक श्रृंखला के बाद, पीएम मोदी ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर ओली के टेलीफोन पर बधाई का सकारात्मक जवाब दिया।
- निरंतर द्विपक्षीय संबंध: दोनों देशों के ऊर्जा और व्यापार अधिकारी एक-दूसरे से मिले हैं, सीमा पर बातचीत जारी है, और नेपाल के विदेश मंत्री संयुक्त आयोग के लिए भारत का दौरा कर रहे हैं
- भारत ने अपने सामरिक लक्ष्य हासिल किए हैं: इन कदमों के माध्यम से, भारत ने अपने तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त किया है। पार्टी को तोड़कर भी सत्ता में बने रहने के लिए ओली को गले लगाया गया है। इस प्रक्रिया में, ओली के अवसरवादी और राजनीतिक रूप से संचालित भारत-विरोधी राष्ट्रवाद की उथल-पुथल उजागर हुई है।
- चीन के लिए शर्मिंदगी: भारत ने सावधानीपूर्वक और मज़बूती से अपने पत्ते खेले हैं। गैर-हस्तक्षेप की नीति के साथ, इसने चीन को सत्तारूढ़ पार्टी के आंतरिक संघर्षों की सूक्ष्मता से कीचड़ में धंसने दिया। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) की एकता और प्रभुत्व बिखर गया है, और चीन, इसके संरक्षक के रूप में शर्मिंदा है।
- चुनावों के लिए समर्थन: संभवतः नेपाल में राजनीतिक ताकतों के सामने आने के कारण, भारत ने एक खारिज राजशाही के नेतृत्व में हिंदुत्ववादी ताकतों को हवा दी है, भारत अब नए सिरे से चुनाव के पक्ष में खुलकर सामने आया है।

नेपाल में राजनीतिक संकट पर भारत के कदम का गंभीर विश्लेषण

- यह सब भारत को नेपाल में अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और अवसरवादी खिलाड़ियों के पक्ष में खड़ा करता है, दक्षिणपंथी ब्लॉक के रणनीतिकारों को लगता है कि महत्वपूर्ण लाभ के लिए भुगतान किया जाना एक छोटी सी कीमत है।

- पड़ोस में एक दोस्ताना शासन की तलाश अंतरराष्ट्रीय संबंधों की वास्तविक दुनिया में एक मान्यता प्राप्त मानदंड है। भारत कोई अपवाद नहीं है। यह अक्सर नेपाल में एक दोस्ताना, यहां तक कि शासन, शासन करने के लिए भारी निवेश करता है।
- लेकिन दीर्घकालिक रूप से, इस दृष्टिकोण से भारत के महत्वपूर्ण सुरक्षा और आर्थिक हितों के समेकन के बजाय इसका क्षरण हुआ है।
- चीन के नेपाल में शासन बदलने के कारोबार में गहराई से बढ़ने के साथ, आने वाले वर्षों में इस दृष्टिकोण की संभावनाएं महंगी और अनिश्चित लगती हैं।

भारत के लिए रास्ता

- नेपाल को अपनी आंतरिक गड़बड़ी से निपटने दें: चाहे नेपाल में चुनाव हों या संसद की बहाली के साक्षी हों, भारत के लिए एक विवेकपूर्ण पाठ्यक्रम नेपाल को अपनी आंतरिक राजनीतिक गड़बड़ी का सामना करने देगा।
- अपनी लोकप्रिय प्रोफ़ाइल में सुधार करें: चूंकि मौजूदा अनिश्चितता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में कोई बड़ा विकास होने की संभावना नहीं है, इसलिए भारत को लोगों द्वारा संचालित राजनीति के समेकन को प्रोत्साहित करना चाहिए, और अपनी लोकप्रिय प्रोफ़ाइल में सुधार करना चाहिए।
- विवादास्पद मुद्दों को हल करें: भारत 1950 के संधि, कालापानी सीमा विवाद, और व्यापार और निवेश मामलों जैसे लंबित विवादास्पद मुद्दों को उठा सकता है, और श्रेणीबद्ध स्थिति को अपनी स्थिति में ला सकता है।
- नई भारत-नेपाल संधि: नेपाल ने 1950 की संधि में संशोधन के लिए कहा है, और यह भारत द्वारा स्वीकार किया गया है। लेकिन यह मुद्दा अभी भी अटका हुआ है क्योंकि नेपाल यह स्पष्ट नहीं करता है कि भारत की सुरक्षा चिंताओं और नेपाल की विकास संबंधी आकांक्षाओं के बीच उचित संतुलन कैसे बनाया जाए। इस संतुलन के बिना, कोई नई संधि संभव नहीं है, और ऐसा प्रतीत होता है कि नेपाल पुरानी संधि को निरस्त करने के लिए तैयार नहीं है।
- भारत के रुख को स्पष्ट किया जाना चाहिए: तत्काल पड़ोसियों के प्रति भारत की नीति क्षेत्रीय राष्ट्रवाद से प्रेरित नहीं है। यह श्रीलंका (कतचथेवु), बांग्लादेश (प्रादेशिक जल) और यहां तक कि पाकिस्तान और चीन के मामले में भी स्पष्ट है।
- व्यापार असंतुलन: व्यापार और निवेश के मुद्दों पर, भारत को और अधिक व्यवस्थित होने की आवश्यकता है। नेपाल लगभग 8 बिलियन $ का आयात करते हुए भारत को1 बिलियन $ से कम मूल्य के उत्पाद बेचता है। इस तथ्य के बावजूद कि व्यापार घाटा अर्थव्यवस्थाओं की प्रकृति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत को वास्तविक नेपाली वस्तुओं के भारतीय बाजारों में प्रवेश के लिए संरचनात्मक और प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाना चाहिए

चाइना फैक्टर:

- नेपाल के प्रति भारत के दृष्टिकोण को पुनर्परिभाषित करना होगा। चीन राजनीतिक रूप से मुखर और आर्थिक रूप से नेपाल में फैला हुआ है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके अधिकांश वादे, जैसे चीनी बंदरगाहों और रेलमार्गों के माध्यम से पारगमन, राजनीतिक रूप से संचालित हैं।

Connecting the dots

- India- Nepal Border dispute at Kalapani and Lipulekh: Click here

2020 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सार्क का पुन: प्रवर्तन

संदर्भ: गौरतलब है कि पिछले छह वर्षों में (वर्ष 2014 के शिखर सम्मेलन के बाद से) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) देशों के शीर्ष नेताओं ने समूह की किसी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। जिसके कारण अपनी स्थापना के 36 वर्ष बाद भी सार्क एक निष्क्रिय संगठन सा प्रतीत होता है।

- कार्रवाई में निलंबित: सार्क बनाने वाले आठ देशों के नेताओं के बीच वर्ष 2020 को छठे वर्ष के रूप चिह्नित किया।
- सार्क को कमजोर करने का प्रभाव: पिछले एक वर्ष में भारत-पाकिस्तान विवाद के मुद्दे ने भी सार्क की बैठकों को प्रभावित किया है। सदस्य देशों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच व्यापार या अन्य गतिविधियों के दौरान दक्षिण एशिया के एक सामूहिक संगठन की बजाय इसका व्यवहार एक खंडित समूह के रूप में देखा गया है। विश्व में कोई भी अन्य क्षेत्रीय शक्ति अपने निकटवर्ती पड़ोस या देशों से इतनी अलग नहीं है, जितना कि दक्षिण एशिया में भारत है। यह अलगाव भारत के आर्थिक और सुरक्षा हितों के लिये भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है।
- सार्क में शामिल नहीं होने पर भारत का रुख: 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस पर पीएम मोदी ने यह स्पष्ट किया कि पिछले तीन सालों से पाकिस्तान में स्थित आतंकवाद के नेटवर्क से क्षेत्र में उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों के कारण वह सार्क में शामिल नहीं हो रहा है।

भारत को सार्क पर अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता क्यों है?

- **पाकिस्तान का अनुचित प्रभाव:** आतंकवाद, क्षेत्रीय दावों और कनेक्टिविटी और व्यापार पर सार्क की पहल को रोकने में पाकिस्तान के साथ भारत की समस्याओं को कारण माना जाना जाता है। फिर भी, भारत द्वारा पाकिस्तान को SAARC शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की अनुमति देने से इंकार करने के कारण उन समस्याओं पर पूरी सार्क प्रक्रिया के तहत पाकिस्तान को 'वीटो' देने की आशंका है।
- **भारत द्वारा विरोधाभासी कार्रवाइयाँ:** पीएम मोदी और कैबिनेट मंत्री अपने पाकिस्तानी समकक्षों के साथ शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठकों में शामिल होते रहे, जिसमें नवंबर में एससीओ प्रमुखों की सरकार की बैठक भी शामिल थी, जहाँ नई दिल्ली ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को आमंत्रित किया था (उन्होंने एक अन्य अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की थी)।
- भारत अन्य पड़ोसियों के साथ काम कर रहा है: जबकि लद्दाख में चीन की घुसपैठ और गलवान घाटी में हुई हत्याओं ने वर्ष में इसे बड़ी चिंता का विषय बना दिया, भारत ने शंघाई सहयोग संगठन, आरआईसी त्रिपक्षीय, जी -20 और अन्य में चीनी नेतृत्व के साथ बैठकों में भाग लेने से इनकार नहीं किया। भारत सरकार ने नेपाल के साथ उलझने से खुद को रोक दिया, इसके बावजूद श्री के.पी. शर्मा ओली ने नेपाल का नक्शा और संविधान बदलने के लिए भारतीय क्षेत्र शामिल करने का निर्णय लिया।
- महामारी प्रेरित चुनौतियां: महामारी द्वारा लाई गई आम चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सभीका साथ आना महत्वपूर्ण है। महामारी, टीके वितरण की चुनौतियों, आर्थिक सुधार, विशेषकर पर्यटन क्षेत्र के पुनरुद्धार के साथ दक्षिण एशिया में कुछ ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनसे सदस्य देशों द्वारा करीबी समन्वय द्वारा प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है।

- क्षेत्रीय दृष्टिकोण के लिए उपयुक्त समय: जबकि देशों के लिए वैश्विक बाजार से खुद को पूरी तरह से काट देना असंभव होगा, ऐसे में क्षेत्रीय पहल "गोल्डीलॉक्स विकल्प" बन जाएगी।
- चीन को प्रतिवाद: चीन की चुनौती से निपटने में, भारत की सीमाओं पर और उसके पड़ोस में, एक एकीकृत दक्षिण एशियाई मंच भारत की सबसे शक्तिशाली जवाबी कार्रवाई है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि बीजिंग के सभी सार्क देशों (माइनस इंडिया और भूटान) की बैठक आयोजित करने से पहले यह केवल समय की बात है, क्योंकि यह सभी BRI के भाग हैं, और यहां तक कि उन्हें RECP में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया।
- सार्क के मूल तर्क अभी भी सही हैं: निराशा के बावजूद भी सार्क का अस्तित्व अभी तक विद्धमान है: जबकि इतिहास और राजनीतिक शिकायतों को अलग तरह से माना जा सकता है।

निष्कर्ष

नई दिल्ली को अपने स्वयं के तरीकों को ढूंढना चाहिए, जिसके साथ अपने दक्षिण एशियाई पड़ोस को देखना चाहिए: हमें एक ऐसी इकाई विकसित करनी चाहीये जिसके पास एक सामान्य भविष्य हो, और वैश्विक मंच पर भारत की महत्वाकांक्षाओं के लिए इसे बल-गुणक के रूप में देखना चाहिए।

भारत और यूएई के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग हेतु समझौते को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र **(NCM), UAE** और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय **(MoES),** भारत के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है।

उद्देश्य

- यूएई और भारत के बीच यह समझौता ज्ञापन भूकंपीय, मौसम संबंधी और महासागरीय सेवाओं जैसे उपग्रह, रडार, भूकंपीय, ज्वार गेज, और मौसम विज्ञान स्टेशनों के लिए डाटा, ज्ञान और परिचालन उत्पादों के साझाकरण के लिए सुविधा प्रदान करेगा।

भारत और यूएई के बीच संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता

- दोनों देशों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर अनुसंधान विद्वानों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के संदर्भ में यात्राओं/ अनुभवों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेंगे।
- सामान्य हित गतिविधियों से संबंधित तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी का आदान-प्रदान होगा।

- इस समझौते के माध्यम से, द्विपक्षीय तकनीकी और वैज्ञानिक कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों/ सम्मेलनों के साथ-साथ सहयोग के क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और महासागर जल पर हस्ताक्षर किए गए आपसी समझौते पर मौसम संबंधी अवलोकन नेटवर्क की तैनाती भी शामिल होगी।
- अरब और ओमान सागर के माध्यम से फैलने वाली सुनामी के अधिक विश्वसनीय और तेज पूर्वानुमान के लिए सुनामी मॉडल शोधकर्ताओं की विशेष क्षमताओं के विकास में भी सहयोग होगा, यह सुनामी यूएई के पूर्वोत्तर भाग और भारत के तटीय क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित करती है।

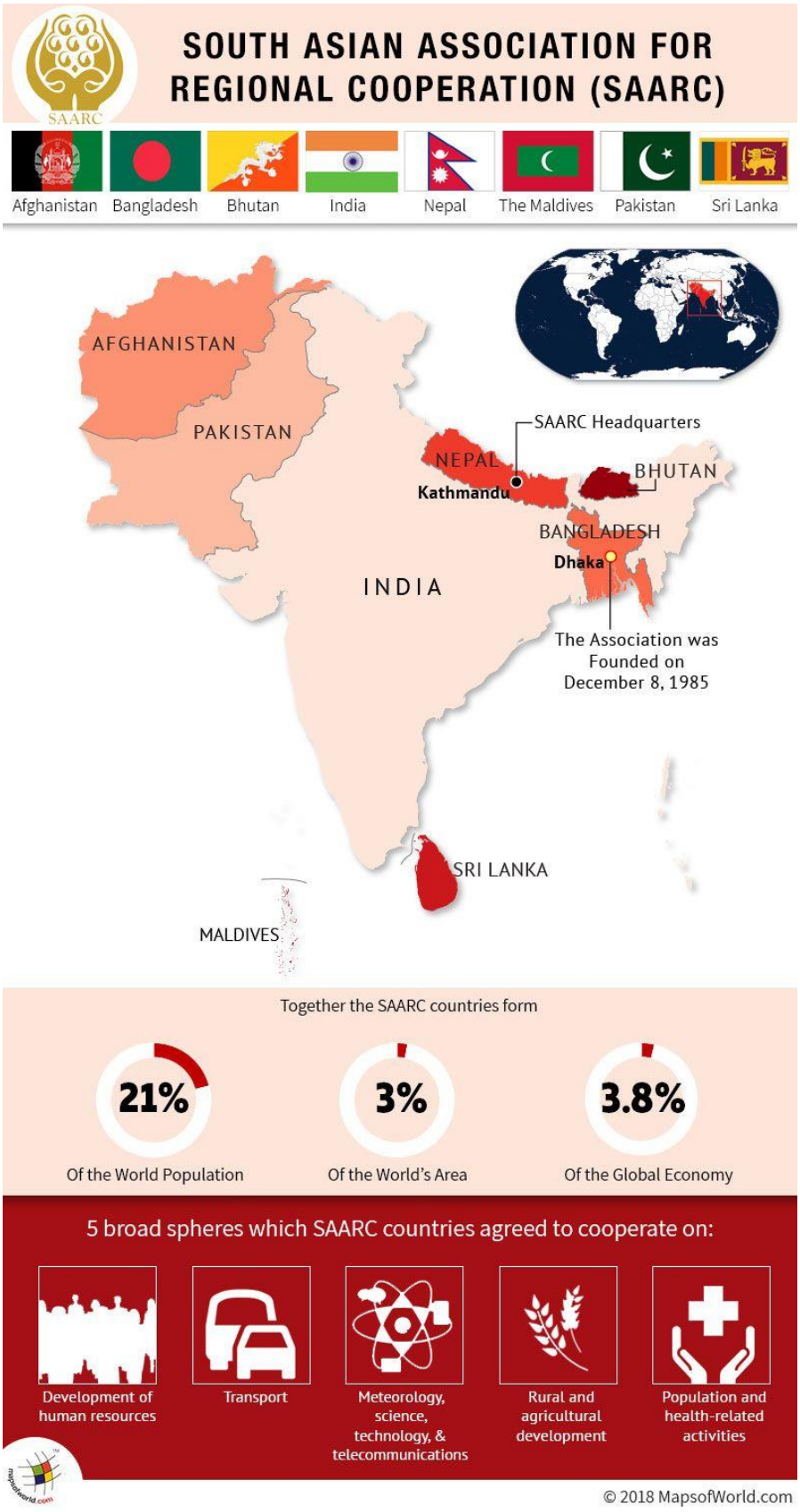
SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL COOPERATION (SAARC)
SAARC
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
India
Nepal
The Maldives
Pakistan
Sri Lanka
AFGHANISTAN
PAKISTAN
NEPAL
Kathmandu
SAARC Headquarters
BHUTAN
BANGLADESH
Dhaka
INDIA
The Association was Founded on December 8, 1985
SRI LANKA
MALDIVES
Together the SAARC countries form
21%
Of the World Population
3%
Of the World's Area
3.8%
Of the Global Economy
5 broad spheres which SAARC countries agreed to cooperate on:
Development of human resources
Transport
Meteorology, science, technology, & telecommunications
Rural and agricultural development
Population and health-related activities
© 2018 MapsofWorld.com

आईसीटी क्षेत्र में भारत-जापान समझौता ज्ञापन :

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- भारत और जापान ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- दूरसंचार विभाग और जापान के संचार मंत्रालय भारत और जापान स्मार्ट शहरों, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, असंबद्ध क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए दूरसंचार सुरक्षा, 5G टेक्नोलॉजी इत्यादि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देंगे।

भारत-नेपाल विकास

संबंध

- **COVID-19** महामारी का मुकाबला करने में दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ सहयोग विकसित हुआ है
- नेपाल को टीकों का प्रारंभिक प्रावधान।
- चितवन में मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन का विस्तार
- नेपाल में सिलीगुड़ी को झापा से जोड़ने वाली एक नई पाइपलाइन की स्थापना
- भारत और नेपाल के बीच जयनगर से कुरथा के बीच पहली यात्री रेलवे लाइन का विकास
- एक संभावित रक्सौल-काठमांडू ब्रॉड गेज रेलवे लाइन सहित सीमा-पार रेल संपर्क परियोजनाएँ
- प्रस्तावित पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना सहित संयुक्त जल विद्युत परियोजनाएँ
- नेपाल ने शक्ति के परिवर्तित संतुलन को दर्शाने के लिए विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद **(UNSC)** की भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन व्यक्त किया।

आगे की राह

- लोगों और सामानों की सीमा-पार आवाजाही को सुगम बनाने की आवश्यकता
- हाल ही में बीरगंज और विराटनगर में एकीकृत चेक पोस्ट **(ICPs)** का उद्घाटन किया गया है, जिससे लोगों के निर्बाध आवागमन और दोनों देशों के बीच व्यापार में मदद मिली है।
- नेपाल व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर भारत के बंदरगाहों पर निर्भर करता है, और माल सड़क द्वारा ले जाया जाता है, एकीकृत चेक पोस्ट से व्यापार और पारगमन में आसानी होती है।
- नेपाल में दो और सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं अर्थात् पशुपतिनाथ रिवरफ्रंट डेवलपमेंट और पाटन दरबार में भंडारखाल गार्डन रेस्टोरेशन को भारत का समर्थन प्राप्त हुआ है
- भारत की नेपाल नीति सभी वर्गों के साथ गहरे जुड़ाव की ओर बहुत स्पष्ट रूप से बढ़ रही है।

भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों का मुद्दा

संदर्भ: श्रीलंका में चार मछुआरों को कथित दौर पर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा बीच समुद्र में मारे जाने के मामले और शवों की बरामदगी ने तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शनों को तेज कर दिया है क्योंकि उनका मानना है कि राज्य से लापता चार मछुआरों बिना किसी कारण के मारा गया है।

शवों को वापस भारत को सौंपने की मांग करते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि श्रीलंकाई नौसेना ने उन्हें पीट-पीटकर मार डाला। वे मृतकों के परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी, 15 लाख रुपये मुआवजा और श्रीलंकाई नौसेना के खिलाफ हत्या के आरोपों की भी मांग कर रहे हैं।

इस ताजा घटना ने एक बार फिर भारतीय मछुआरों और श्रीलंकाई नौसेना के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष को सामने ला दिया है

लंका की नौसेना और भारतीय मछुआरों के बीच संघर्ष का क्या कारण है?

1. कच्चतीवु द्वीप का संघर्ष:

- तमिल मछुआरों के पास सदियों से निर्जन कच्चतीवु द्वीप के मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकार थे।
- हालांकि, 1974 में, दोनों देशों के बीच इंदिरा गांधी द्वारा तमिलनाडु सरकार से परामर्श किए बिना एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था।
- यह समझौता भारतीय मछुआरों को "घोंसले के सूखने के लिए और वार्षिक सेंट एंथनी के त्योहार के लिए" आराम के लिए कच्छेटेवु तक पहुंचने की अनुमति देता है, लेकिन इसने पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया।
- सेंट एंथोनी कैथोलिक श्राइन इस द्वीप पर यह एकमात्र धार्मिक स्थल है। सेंट एंटनी कैथोलिक श्राइन एक सदी से ज़्यादा पुरानी परंपराओं का पालन करती है। इसका निर्माण श्रीनिवास पादैयाची (एक भारतीय तमिल कैथोलिक) ने कराया था। कच्चतीवु जाने के लिए किसी को भारतीय पासपोर्ट या श्रीलंकाई वीजा रखने की आवश्यकता नहीं है।
- समझौते ने भारतीय मछुआरों को अपने मत्स्य पालन क्षेत्र में एक अल्प क्षेत्र तक ही सीमित रखने के लिए मजबूर किया जाता है।

2. भारतीय क्षेत्र में संसाधन का कम होना:

- अतीत की तरह, रामेश्वरम और आस-पास के तटों के मछुआरे, श्रीलंका में समृद्ध समुद्री संसाधनों के लिए प्रसिद्ध एक क्षेत्र तलाईमन्नार और कच्चतीवु (अब श्रीलंका का हिस्सा) की ओर जाना जारी रखते हैं।
- भारतीय मछुआरों ने भारतीय ओर समुद्री संसाधनों की कमी के कारण लंका के पानी में प्रवेश करना जारी रखा।

3. भारतीय तट में ट्रॉलर का प्रसार

- इस समुद्री क्षेत्र में बहुत अधिक मछलियों की स्थिति पिछले तीन दशकों में तमिलनाडु के तट में मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों के प्रसार का कारण बनी।
- ट्रैकर्स के पास श्रीलंका के तट के अधिकांश गरीब मछुआरों के विपरीत अत्यधिक मछली पकड़ने के जाल वाली मशीनीकृत नावें हैं जो मछली पकड़ने के पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं।

- कई बार मछुआरों ने नीचे की ट्रॉवेलिंग को लगाया है जो श्रीलंका में प्रतिबंधित है।
- नीचे की ओर से मछलियों को फँसना, पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी अभ्यास है, जिसमें समुद्र तल के साथ भारित जाल को खींचने वाले ट्रॉलर शामिल होते हैं, जिससे जलीय संसाधनों की बड़ी क्षति होती है।

4. आजीविका के लिए खतरा

- बेहतर लाभ की उम्मीद करते हुए, बहुत से लोगों ने रामेश्वरम और आसपास के तमिलनाडु तटों में ट्रॉलर खरीदना शुरू कर दिया।
- रामेश्वरम, मंडपम, पंबन क्षेत्रों जैसे छोटे तटीय हिस्सों में लगभग **2,500** ट्रॉलर हैं; जिसका अर्थ है कि प्रत्येक ट्रॉलर के आधार पर कम से कम दो दर्जन परिवार विभिन्न माध्यमों से जैसे कि छह लोग जो बोर्ड, मछली, झींगा, सूखी मछली व्यापारी, लोडिंग के लिए सहायक कर्मचारी आदि पर काम करते हैं।
- लेकिन हिंद महासागर में युद्ध के बाद के परिदृश्य ने तमिलनाडु तट पर व्यापार और आजीविका को पटरी से उतार दिया।
- श्रीलंकाई नौसेना ने **2017** में **450** से अधिक भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया और **2018** में अवैध शिकार के आरोप में **156** और **2019** में कुल **210** गिरफ्तारियां हुईं। इससे रामेश्वरम तट के किनारे रहने वाले मछुआरों की आबादी के काफी हिस्से की आजीविका प्रभावित हुई है।

5. श्रीलंका की नौसेना द्वारा समुद्री सीमा की बढ़ी निगरानी:

- श्रीलंकाई गृहयुद्ध के समय भारतीय मछुआरों द्वारा श्रीलंकाई जल तक पहुंच आसान थी, जहां लिट्टे के खिलाफ युद्ध के साथ इसका शिकार किया गया था।
- इसके परिणामस्वरूप, इसके उत्तरी प्रांत और पास की समुद्री सीमाओं का कभी भी कड़ा पहरा नहीं था।
- लेकिन **2009** में गृह युद्ध की समाप्ति के साथ यह बदल गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं को पार करते हुए भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी की संख्या को बढ़ाने के लिए अब श्रीलंकाई नौसेना द्वारा समुद्री सीमा की निगरानी बढ़ाई गई है।

5. मुद्दे का राजनीतिकरण

- यह पिछले एक दशक में तमिलनाडु में अक्सर एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहा है। तमिल क्षेत्रीय पार्टियां अक्सर इस मुद्दे पर अपनी उदासीनता के लिए केंद्र सरकार के साथ लड़ाई लड़ती रही हैं।
- इसने इस मुद्दे को रोकने के लिए आम सहमति के लंबे समय तक चलने वाले समाधान पर रोक लगा दी है।

आगे का रास्ता

- एक-दूसरे की चिंताओं और हितों को परस्पर मान्यता देने से दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो सकते हैं।
- भारत को श्रीलंका के साथ संबंध सुधारने के लिए अपने पारंपरिक और सांस्कृतिक संबंधों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा शुरू करने से लोगों को लोगों से जुड़ाव में सुधार हो सकता है।

2021: हरित वातावरण की दिशा में भारत-फ्रांस के गठबंधन का वर्ष

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और पारिस्थितिक संक्रमण के लिए फ्रांसीसी मंत्री ने हाल ही में पर्यावरण के इंडो-फ्रेंच वर्ष का शुभारंभ किया।
- केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री सुश्री बारबरा पोम्पिली ने नई दिल्ली में भारत-फ्रांस पर्यावरण वर्ष (इंडो-फ्रेंस ईयर ऑफ एंवायरमेंट) को लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग को मज़बूत करना, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्रवाई के प्रभाव को बढ़ाना और और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है।
- 2021-2022 की अवधि में पर्यावरण का इंडो-फ्रेंच वर्ष पांच मुख्य विषयों पर आधारित होगा: (1) पर्यावरण संरक्षण; (2) जलवायु परिवर्तन; (3) जैव विविधता संरक्षण; (4) सतत शहरी विकास; (5) अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता का विकास।
- यह पर्यावरण और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा में संलग्न होने का एक मंच भी है।
- भारतीय पक्ष से, यह पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के साथ-साथ विदेश मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, और अन्य संबंधित मंत्रालयों द्वारा समन्वित किया जाएगा।
- भारत-फ्रांस पर्यावरण वर्ष के सालभर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को के कैलेंडर को अंतिम रूप देने के लिए एक संयुक्त स्क्रीनिंग कमिची का गठन भी किया जाएगा।

क्या आपको पता है?

- भारत-फ्रांस गठबंधन पीएम द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्य स्तंभ है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए रूपरेखा

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के सदस्यों और भारत सरकार के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए इसकी रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए।

महत्वपूर्ण बिंदु

- **उद्देश्य:** आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करना और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाना।
- इस साझेदारी से ज्ञान का व्यापक आदान-प्रदान होगा और भारत की ओर IEA का पूर्ण सदस्य बनने की दिशा में यह एक कदम होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) पेरिस स्थित स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है।
- यह 1974 के तेल संकट के मद्देनजर 1974 में इसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के एक लिए एक ढांचे के रूप में स्थापित किया गया था।
- IEA 30 सदस्य देशों से बना है।
- इसके अलावा, IEA परिवार में आठ संघ देश शामिल हैं जिनमें ब्राज़ील, चीन और भारत शामिल हैं।
- तीन देश चिली, इज़राइल और लिथुआनिया की पूर्ण सदस्यता के लिए मांग कर रहे हैं।

भारत के वस्त्र मंत्रालय और एम/एसनिसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध; GS- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की वस्त्र समिति और जापान के एम/एस निसेनकेन क्वालिटी इवैल्युएशन सेंटर के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों संगठनों ने एक औपचारिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण बिंदु

- उद्देश्य: एमओयू का मुख्य उद्देश्य परीक्षण, निरीक्षण और अनुरूपता मूल्यांकन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) और परामर्श के माध्यम से जापानी खरीदारों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वस्त्र व्यापार और उद्योग को ज़रूरी सहायता प्रदान करना है।
- यह उम्मीद है कि एमओयू दुनिया के तीसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य जापान में भारत के वस्त्र और परिधानों के निर्यात को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मज़बूती बनाएगा।

क्या आपको पता है?

- संसद के एक अधिनियम के तहत वर्ष 1963 में वस्त्र समिति का गठन किया गया था।
- वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत यह एक वैधानिक इकाई है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू और निर्यात बाज़ारों के लिए सभी वस्त्र और वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
- वस्त्र समिति एकमात्र इकाई है, जो देशभर में एकीकृत तरीके से संपूर्ण टेक्सटाइल वैल्यु चैन (वस्त्र मूल्य श्रंखला) की गुणवत्ता संबंधी ज़रूरतों को पूरी करने की दिशा में सहायता प्रदान करती है। इसके देशभर में 28 कार्यालय और 19 स्टेच ऑफ आर्ट प्रयोगशालाएं , जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं।

भारत-जीसीसी संबंध

संदर्भ: भारत और जीसीसी देशों के बीच विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए महामारी ने नई संभावनाओं को प्रस्तुत किया है।

गल्फ़ कोपरेशन काउंसिल

- यह छह मध्य पूर्वी देशों-सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान का राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है।
- **GCC** की स्थापना मई **1981** में सऊदी अरब के रियाद में की गई थी।
- जीसीसी का उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच अपने सामान्य उद्देश्यों और उनकी समान राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर एकता प्राप्त करना है, जो अरब और इस्लामी संस्कृतियों में निहित हैं।

ऐसे क्षेत्र जहां भारत और जीसीसी बेहतर भविष्य के लिए सहयोग कर सकते हैं:

स्वास्थ्य देखभाल	• स्वास्थ्य सेवा और दवा उद्योगों में निवेश की बहुत गुंजाइश है। • जीसीसी देशों के निवेश को आकर्षित करना भारत सरकार की पहल के तहत भारत में औद्योगिक और विनिर्माण आधार विकसित करने के लिए अच्छी तरह से फिट बैठता है। • भारत पहले से ही चिकित्सा पर्यटन के लिए एक लोकप्रिय क्षेत्रीय गंतव्य है। • डिजिटल हेल्थकेयर सेवाएं एक ऐसा क्षेत्र है जो निकट भविष्य में अपार विकास की संभावना है। • स्वच्छता और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) उत्पादों की मांग पहले ही आसमान छू गई है। भारत फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपनी ताकत के अलावा, इन उत्पादों के लिए एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। • आयुर्वेद हेल्थकेयर उपक्रमों में निवेश को आकर्षित करने की भी संभावना है, जिसका खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता बाजार है।
शिक्षा	• उच्च शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, जो बढ़े हुए सहयोग की क्षमता के बावजूद, शोषित रहता है। • भारत में पेशेवर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का विशाल नेटवर्क जीसीसी छात्रों के लिए एक आकर्षक गंतव्य हो सकता है। • यह देखते हुए कि भारतीय इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस' को अब भारत के बाहर शाखाएं स्थापित करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है, आईआईटी और आईआईएम को जीसीसी देशों में शाखाएं खोलने के लिए संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए जो स्थानीय और प्रवासी आबादी दोनों को आकर्षित करेगी। • डिजिटल शिक्षा सेवाओं का क्षेत्र भी जीसीसी निवेश को आकर्षित करने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का क्षेत्र हो सकता है
रक्षा	• भारत और जीसीसी देशों ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में असाधारण वृद्धि देखी है। • उदार एफडीआई नीतियां निवेश को आकर्षित करने के लिए एक प्रमुख क्षेत्र हो सकता है, विशेष रूप से क्योंकि जीसीसी देश दुनिया के शीर्ष रक्षा आयातकों में से हैं। • भारत, यूएई और इजरायल के बीच एक बहुपक्षीय सहयोग की भी संभावना है, यह देखते हुए कि भारत पहले से ही इन दोनों देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग है।

विविध	• कई क्षेत्र जैसे अंतरिक्ष अन्वेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, जैव सूचना विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा आदि। भारत और जीसीसी देशों के बीच सहयोग के लिए नए क्षेत्र हो सकते हैं। • यूएई तेजी से अरब दुनिया में एक अंतरिक्ष अन्वेषण नेता के रूप में उभर रहा है। • संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब सहित जीसीसी देशों ने हाल के वर्षों में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से निवेश किया है। • भारत, ऊर्जा की कमी के साथ ऊर्जा की कमी वाला देश होने के नाते, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संभावनाओं का पता लगाना चाहिए।

Connecting the dots

- On Gulf reconciliation summit: Click here

स्टार्स परियोजना को वित्तीय मदद के लिए डीईए और विश्व बैंक में समझौता

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

राज्यों में शिक्षण, सीखने औरपरिणामोंको बेहतर बनाने की शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना (स्ट्रेन्दनिंग टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स) के क्रियान्वयन को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए आर्थिकमामलों के विभाग (डीईए) और विश्व बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **STARS** परियोजना के प्रस्ताव को अक्टूबर **2020** में मंजूरी दी गई थी।
- इस परियोजना में छह राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल औरओडिशा शामिल हैं। चिन्हांकित राज्यों को शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के कदमों के लिए सहायता दी जाएगी।
- **STARS** परियोजना को एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा।
- कार्यान्वयन एजेंसी**:** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग **(DoSEL),** शिक्षा मंत्रालय
- राज्य स्तर पर**,** परियोजना को समागम शिक्षा के लिए एकीकृत राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी **(**एसआईएस**)** के माध्यम से लागू किया जाएगा।

क्या आपको पता है?

- विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से **$ 500** मिलियन की राशि के साथ **STARS** परियोजना की कुल परियोजना लागत **5718** करोड़ रुपये है।

- **STARS** के तहत प्रस्तावित विश्व बैंक का समर्थन मुख्य रूप से परिणाम आधारित वित्तपोषण साधन के रूप में है जिसे प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स **(PforR)** कहा जाता है।
- एक राज्य प्रोत्साहन अनुदान (एसआईजी) का उपयोग राज्यों को वांछित परियोजना परिणामों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा।

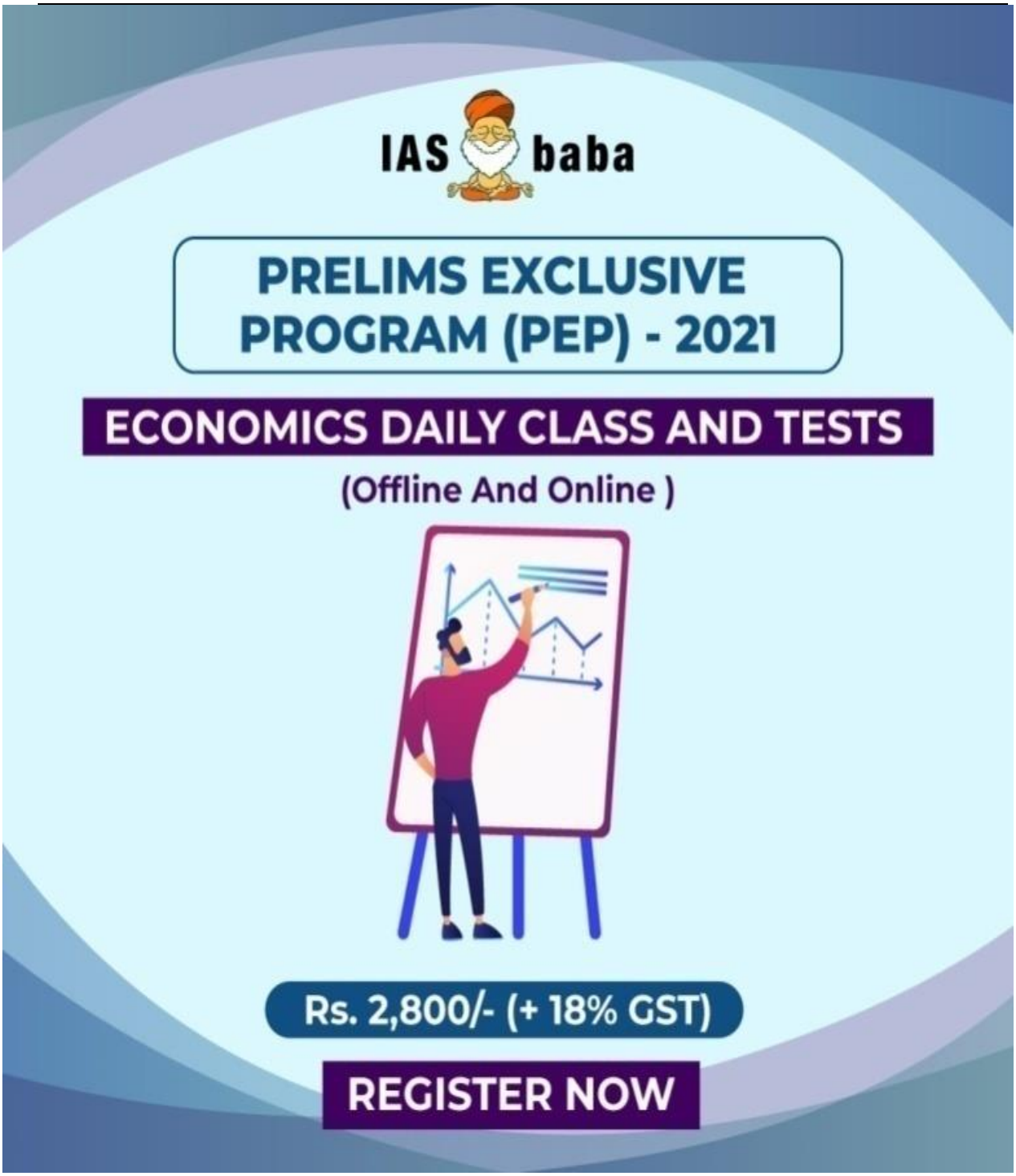

आर्थिकी

भारत ने मोरिंगा पाउडर का निर्यात शुरू किया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- III - व्यापार

समाचार में-

- भारत अपनी बढ़ती संपत्तियों की वजह से बढ़ती वैश्विक मांग को ध्यान में रखते हुए मोरिंगा पाउडर के निर्यात की शुरुआत करता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत से मोरिंगा (वानस्पतिक नाम मोरिंगा ओलीफेरा) उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, **APEDA** आवश्यक बुनियादी ढाँचे बनाने में निजी संस्थाओं का समर्थन कर रहा है।
- **APEDA** के समर्थन के माध्यम से मोरिंगा प्रसंस्करण इकाइयाँ निर्मित होने के साथ, अगले कुछ वर्षों में निर्यात बढ़ेगा जिससे किसानों को लाभ होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

मोरिंगा

- विभिन्न रूपों में इसके औषधीय गुणों और स्वास्थ्य लाभों के कारण मोरिंगा का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है।
- विश्व स्तर पर मोरिंगा लीफ पाउडर और मोरिंगा ऑयल जैसे मोरिंगा उत्पादों की मांग में अच्छी वृद्धि देखी जा रही है।
- इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएँ मोरिंगा को पोषण के पूरक के रूप में और खाद्य में उपयोग करने के सर्वोत्तम तरीकों की खोज कर रही हैं।
- दुनियाभर में मोरिंगा की कई प्रजातियां हैं।
- इसके उपयोग को वैश्विक उपभोक्ताओं के बीच इसके पोषण, औषधीय, उपयोगों के लिए अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

- यह कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक सर्वोच्च निकाय है।
- **APEDA** की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत दिसंबर **1985** में संसद द्वारा पारित कर के की गई थी।

APEDA के कुछ कार्य इस प्रकार हैं:

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। अनुसूचित उत्पादों के निर्यात उन्मुख उत्पादन और विकास को बढ़ावा देना।
- भारत के बाहर अनुसूचित उत्पादों के लिए पैकेजिंग, विपणन जैसे कई क्षेत्रों में सुधार करना।
- निर्यात के उद्देश्य से अनुसूचित उत्पादों के लिए मानक और विनिर्देश स्थापित करना।
- संबंधित उद्योगों को वित्तीय सहायता, राहत और सब्सिडी प्रदान करना।
- संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना

ब्रिटेन ने मासिक धर्म उत्पादों पर 'टैम्पोन टैक्स' को समाप्त कर दिया है।

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I- सोसायटी; GS- III- अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- पहले टैम्पोन टैक्स के रूप में महिलाओं को पांच फीसदी वैट देना पड़ता था, जो अब समाप्त हो गया है। यानी एक जनवरी 2021 से महिलाओं के सैनिटरी उत्पादों पर वैट लागू नहीं होगा।
- यह अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने पहले ही इस कर को समाप्त कर दिया है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शामिल हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 31 दिसंबर तक, यूके यूरोपीय संघ का एक हिस्सा था, जहां सेनेटरी नैपकिन और टैम्पोन जैसे उत्पादों को गैर-आवश्यक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और सदस्य राज्यों को उन पर 5 प्रतिशत कर लगाने की आवश्यकता होती है।
- अब जब यूके 27-सदस्यीय ब्लॉक से बाहर है, तो यह उसके निर्देशों से बाध्य नहीं है, जिसके तहत 1973 के बाद से सैनिटरी उत्पादों को पांच अलग-अलग वैट दरों के अधीन किया गया था - 2001 के बाद से सबसे कम 5 प्रतिशत स्लैब लागू था।
- इस कर को हटाने के इस कदम को इस समय महिला कार्यकर्ताओं और ब्रेक्सिट समर्थकों द्वारा प्रशंसा की गई है।
- यूरोपीय संघ स्वयं अवधि उत्पादों पर कर हटाने की प्रक्रिया में रहा है। 2018 में, ब्लॉक ने कर नियमों को बदलने के लिए प्रस्ताव प्रकाशित किए, लेकिन इन्हें अभी तक सभी सदस्यों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है
- ब्रिटिश सरकार ने अनुमान लगाया है कि टैम्पोन कर को समाप्त करने के कदम से उसके जीवनकाल में औसत महिला को लगभग 40 पाउंड की बचत होगी।

RBI द्वारा डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (DPI)

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- III- अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को पकड़ने के लिए RBI ने एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (DPI) का निर्माण किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- RBI-DPI का निर्माण मार्च 2018 को आधार अवधि के रूप में किया गया है।
- मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए डीपीआई क्रमशः 153.47 और 207.84 पर काम करते हैं, जो प्रशंसनीय वृद्धि का संकेत देते हैं।
- आरबीआई-डीपीआई में पाँच व्यापक पैरामीटर शामिल हैं: पेमेंट एनबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर - डिमांड-साइड फैक्टर और सप्लाई-साइड फैक्टर, पेमेंट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर सेंट्रिकिटी
- RBI-DPI को RBI की वेबसाइट पर मार्च 2021 से अर्ध वार्षिक आधार पर 4 महीने के अंतराल के साथ प्रकाशित किया जाएगा।

क्या आपको पता है?

- डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र वर्तमान में Paytm, PhonePe, Google pay और हाल ही में लॉन्च किए गए व्हाट्सएप सहित बड़े प्रौद्योगिकी खिलाड़ियों पर हावी है।
- वर्ल्डलाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के यूपीआई भुगतानों में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 2% की वृद्धि हुई है, साथ ही एक साल पहले की अवधि से 99% की वृद्धि हुई है।

बैंकिंग स्वास्थ्य: एनपीए और सीओवीआईडी -19

संदर्भ: मार्च 2018 में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (जीएनपीए) का डेटा 11.5% से गिरकर सितंबर 2020 तक बकाया ऋण का 7.5% हो गया है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) क्या है?

- एक नॉनफ़ॉर्मिंग एसेट (एनपीए) ऋण या अग्रिमों के लिए एक वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफ़ॉल्ट या बकाया में हैं।
- एक ऋण तब बकाया होता है जब मूलधन या ब्याज भुगतान देर से हो या उसे किसी भी कारण से न भरा जाये।
- एक ऋण डिफ़ॉल्ट रूप से होता है जब ऋणदाता ऋण समझौते को तोड़ने पर विचार करता है और देनदार अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होता है।

- भारत में, एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) को ऋण या अग्रिम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए मूल या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय रहा।

अर्थव्यवस्था के लिए एनपीए का प्रस्ताव क्यों महत्वपूर्ण है?

- सीधे शब्दों में, बैंकों की ऋण देने की क्षमता व्यवसायों और अर्थव्यवस्था के बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। बैड लोन (यानी एनपीए) का एक समूह बैंकों की क्षमता और उस ऋण को उधार देने की इच्छा को लागू करता है जो अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं को प्रभावित करता है।

हाल के तिमाहियों में बैंकिंग स्वास्थ्य में सुधार

- निजी क्षेत्र की लाभदायकता: लगातार दो वर्षों में घाटे के बाद, भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 2019-20 में लाभदायक हो गए।
- पीएसबी के घाटे को कम किया: हालांकि, राज्य द्वारा संचालित बैंकों ने लगातार पांचवें वर्ष लोन देना जारी रखा, लेकिन उनके नुकसान बहुत अधिक थे।
- नीतियों का प्रभाव: आरबीआई ने 2016 में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की शुरुआत के माध्यम से कुछ बड़े खातों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, और केवल 0.74% तक की लोन खातों में कम हुआ।

एनपीए समस्या की उत्पत्ति

- 2000 के दशक के उत्तरार्ध के बूम के वर्ष: 2010 के उत्तरार्ध में समस्या का एक बड़ा हिस्सा शुरू हुआ, क्योंकि लगातार उच्च आर्थिक विकास की धारणाओं ने कई बड़े कॉरपोरेटों को अपनी निवेश महत्वाकांक्षाओं में भारी बना दिया, इस प्रकार इस प्रक्रिया में खुद को अधिक लाभान्वित किया।
- बैंकों द्वारा आसान ऋण की भूमिका: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नेतृत्व में उच्च आर्थिक विकास वित्तीय क्षेत्र की संभावनाओं पर, क्रेडिट पर आसान धन के माध्यम से इन विस्तार योजनाओं को बढ़ावा दिया।
- 2008 वित्तीय संकट: विकास (और मांग) 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद फ़िज़ूल हो गया। सरकार द्वारा अग्निशमन उपायों के बावजूद, आने वाले वर्षों में वैश्विक संकट का प्रभाव महसूस किया गया। UPA-2 सरकार के नीतिगत पक्षाघात (भ्रष्टाचार घोटालों, गठबंधन राजनीति, ठहराव नौकरशाही) द्वारा संकट को और तेज कर दिया गया
- दुष्चक्र: फैली हुई कॉरपोरेट बैलेंस शीट (मंदी के कारण राजस्व प्रभावित) से संक्रमित बैंकों की अपनी किताबें और ताजा ऋण देने के लिए अभिभूत बैंकों की अपनी क्षमता। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसे भारत की इस संशय को ट्विन बैलेंस शीट समस्या 'कहा था।
- यह 2018 में अपने शीर्ष पर पहुंची : 2014-19 के दौरान, भारत के बैंकों को बुरे ऋणों के लिए सख्त मान्यता मानदंडों के लिए RBI द्वारा उच्च अलर्ट पर रखा गया था। नतीजतन, मार्च 2018 में, उनके खातों पर बुरा ऋण 10 लाख करोड़ से अधिक हो गया – यह सभी ऋणों का लगभग 11.5% है।

- समस्या को हल करने के लिए नीतिगत उपाय: जुड़वाँ बैलेंस शीट समस्या के दुष्चक्र को IBC द्वारा एक हद तक बाधित किया गया था, जिसने बुरे ऋणों के लिए सख्त मान्यता मानदंडों के साथ, समय के साथ इसको सही करने में मदद की।

सीओवीआईडी -19 को एनपीए की समस्या को और खराब कर सकता है?

खराब ऋणों और दिवालिया होने की कार्यवाही में वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि कई व्यवसाय नुकसान में चले गए हैं, यह लाखों कर्मचारियों को अपने साथ बकाया खुदरा ऋण ले रहे हैं, यह सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण है

- अधिकारियों द्वारा उठाए जाने वाले नियामक कदम: महामारी की शुरुआत के बाद ब्याज दरों में कटौती की गई, उधारकर्ताओं की वजह से ऋण किस्तों पर स्थगन की पेशकश की गई, और तरलता प्रणाली को सुचारू रूप से संचारित किया गया।
- IBC का निलंबन: इसी समय, IBC के आह्वान पर उन ऋणों को निलंबित कर दिया गया था जो लॉकडाउन शुरू होने पर या 25 मार्च के बाद डिफ़ॉल्ट रूप से चले गए थे। जबकि यह निलंबन अब 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया है, उधारकर्ताओं के लिए एक ऋण पुनर्गठन खिड़की दिसंबर 2020 में बंद कर दी गई थी।
- तनावग्रस्त क्षेत्रों को सहायता: सरकार ने अपने आत्मानिर्भर पैकेज के तहत कुछ उत्पादक और COVID-19-तनावग्रस्त क्षेत्रों को ऋण प्रवाह प्रदान किया (उदा: उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना)

बैड लोन में गिरावट अच्छी खबर है। लेकिन क्या यह असली तस्वीर है?

- **महामारी से पहले आर्थिक मंदी:** समस्या यह है कि **COVID-19** महामारी और राष्ट्रीय लॉकडाउन ने उद्योगों में राजस्व और मॉडल को बनाए रखा, जैसा कि बाकी दुनिया में था। लेकिन इसके अधिकांश साथियों के विपरीत, भारत की अर्थव्यवस्था वायरस के उभरने से पहले ही तेजी से घट रही थी।
- **अपर्याप्त समर्थन:** केंद्रीय बैंक ने कहा है, कि इस सब के बावजूद, कुछ उत्पादक और **COVID-19**-तनाव वाले क्षेत्रों के लिए पर्याप्त क्रेडिट प्रवाह के कम रहा है।
- **जब समर्थन उपायों को वापस लाया जाता है तो सच्ची तस्वीर सामने आएगी**: आरबीआई का मानना है कि उधारकर्ताओं के खातों (और इसके परिणामस्वरूप, सामान्य रूप से बैंकिंग प्रणाली और बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था) की वास्तविक तस्वीर, नीति समर्थन उपायों के एक बार सामने आएगी यह वापस गिर जायेगा। RBI ने तर्क दिया है कि अगर COVID-19 राहत उपायों के बजाय केंद्रीय बैंक के सामान्य ऋण वर्गीकरण मानदंडों का पालन किया गया होता, तो बुरा ऋण अधिक होता।
- **हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर भविष्य में एनपीए चला सकता है:** आरबीआई ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर बड़े पैमाने पर ऋण चूक के बारे में भी चेतावनी दी है, जो आवास परियोजनाओं को पूरा करने में देरी की वजह से हुई है, मजदूरों के रिवर्स माइग्रेशन के कारण लागत अधिक हो गई है, और निवेश में देरी हुई है।

भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए RBI ने क्या उपाय सुझाए हैं?

बैंकिंग क्षेत्र को बड़े पैमाने पर देरी और बैलेंस-शीट तनाव के कारण स्वस्थ बनाने के लिए कि महामारी के कगार को पीछे छोड़ दें, यह महत्वपूर्ण है

- समय समय पर विभिन्न सुविधायें प्रदान करें,
- ऋण हानि में फिर से वृधि की संभावना
- बैंकों में पर्याप्त पूंजी संचयन सुनिश्चित करें
- विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को किनारे करने के लिए करदाता को अधिक धन की आवश्यकता हो सकती है।

निष्कर्ष

- अभी के लिए, जैसा कि केंद्रीय बैंक ने कहा है, बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों के स्वास्थ्य की बहाली वास्तविक अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और उद्यमिता वापसी एक दुसे पर इतनी जल्दी निर्भर नहीं करती है।
- **2021-22** के लिए केंद्रीय बजट, जो अब सिर्फ चार सप्ताह दूर है, दो मोर्चों पर बैंकों के लिए महत्वपूर्ण होगा - यह मांग और निवेशों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या करता है, और यह सार्वजनिक क्षेत्र के पुनर्पूंजीकरण के लिए कितना पैसा अलग करने का वादा कर सकता है।

विचार कीजिये

- आत्मानिर्भर पैकेज
- **FRBM** अधिनियम पर **N.K.Singh** पैनल

जम्मू और कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना (जम्मू और कश्मीर आईडी, 2021) को मंजूरी दी

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II - नीतियां और हस्तक्षेप और GS- III - उद्योग

समाचार में-

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति **(CCEA)** ने जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए एक योजना को मंजूरी दी है।
- योजना रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित है। वर्ष **2037** तक यह **28,400** करोड़ है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह जम्मू-कश्मीर में केन्द्र शासित प्रदेशों में उद्योगों के विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- उद्देश्य: रोजगार उत्पन्न करने के लिए जो सीधे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास की ओर ले जाता है।

योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे :

- पूंजी निवेश प्रोत्साहन संयंत्र और मशीनरी (मैन्युफैक्चरिंग में) निवेश या भवन निर्माण अन्य सभी स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों (सेवा क्षेत्र में) निवेश पर जोन-ए में 30 प्रतिशत तथा जोन-बी में 50 प्रतिशत की दर पर पूंजी निवेश प्रोत्साहन उपलब्ध है।

- 50 करोड़ रुपये तक निवेश करने वाली इकाइयां इस प्रोत्साहन का लाभ उठाने की पात्र होंगी। जोन-ए तथा जोन-बी में प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा क्रमशः 5 करोड़ रुपये तथा 7.5 करोड़ रुपये है।
- पूंजी ब्याज सहायता:संयंत्र और मशीनरी (मैन्युफैक्चरिंग में)या भवन निर्माण तथा अन्य सभी स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों (सेवा क्षेत्र में) निवेश के लिए 500 करोड़ रूपये तक की ऋण राशि पर अधिकतम 7 वर्षों के लिए 6 प्रतिशत वार्षित दर से पूंजी ब्याज सहायता।
- जीएसटी से जुड़ा प्रोत्साहन :10 वर्ष के लिएसंयंत्र और मशीनरी (मैन्युफैक्चरिंग में) या भवन निर्माण तथा अन्य सभी स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों (सेवा क्षेत्र में) में वास्तविक निवेश के 300 प्रतिशत पात्र मूल्य तक प्रोत्साहन एक वित्तीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि प्रोत्साहन की कुल पात्र राशि से एक दहाई से अधिक नहीं होगी।
- कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता :सभी वर्तमान इकाइयों को अधिकतम 5 वर्षों के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं :

- योजना छोटी और बड़ी दोनों तरह की इकाइयों के लिए आकर्षक बनायी गई है। संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ रुपये तक निवेश करने वाली छोटी इकाइयों को 7.5 करोड़ रुपये तक पूंजी प्रोत्साहन मिलेगा और अधिकतम 7 वर्षों के लिए पूंजी ब्याज सहायता 6 प्रतिशत की दर से मिलेगी।
- योजना का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में ब्लॉक स्तर तक औद्योगिक विकास को ले जाना है। यह भारत सरकार की पहली बार शुरू की गई कोई औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है तथा संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में स्थायी तथा संतुलित औद्योगिक विकास के लिए प्रयास है।
- जीएसटी से जुड़े प्रोत्साहन को शामिल करके योजना को व्यापार-सुगमता के अनुरूप सहज बनाया गया है। जीएसटी से जुड़ा प्रोत्साहन पारदर्शिता से समझौता किये बिना अनुपालन बोझ को कम करना सुनिश्चित करेगा।
- योजना के पंजीकरण और क्रियान्वयन में केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर की बड़ी भूमिका निर्धारित की गई है। दावे स्वीकृत करने से पहले स्वतंत्र ऑडिट एजेंसी द्वारा उचित नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की गई है।
- यह जीएसटी की अदायगी या वापसी नहीं है बल्कि केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर के नुकसान की भरपाई के लिए सकल जीएसटी का इस्तेमाल औद्योगिक प्रोत्साहन की पात्रता निर्धारित करने में होता है।
- पहले की योजनाओं में अनेक प्रोत्साहनों की पेशकश की गई थी लेकिन उनका संपूर्ण वित्तीय प्रवाह नई योजना से काफी कम था।

Related articles:

- Forest Rights Act in J&K: Click here
- PM-JAY SEHAT for J&K: Click here

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2020-21 के लिए जीडीपी के अग्रिम अनुमान जारी

संदर्भ: **FY21** के दूसरे तिमाही के परिणामों के बाद जहां भारत ने पहली तकनीकी मंदी का अनुभव किया था, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए पहला अग्रिम अनुमान **(FAE)** जारी किया है।

जीडीपी के पहले अग्रिम अनुमान क्या हैं? उनका महत्व क्या है?

- किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय **(MoSPI)** जीडीपी के नियमित अनुमान प्रदान करता है।
- ऐसा पहला उदाहरण **FAE** के माध्यम से दिया गया है। किसी भी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए **FAE** इसे आमतौर पर **7** जनवरी को प्रस्तुत करता है।
- इसका महत्व इस तथ्य में निहित है कि वेसकल घरेलू उत्पाद का अनुमान का केंद्रीय वित्त मंत्रालय अगले वित्तीय वर्ष के बजट आवंटन का फैसला करने के लिए उपयोग करता है।
- अधिक जानकारी उपलब्ध होने पर एफएई इसे जल्द ही से अपडेट करता है।
- **26** फरवरी को, **MoSPI** चालू वर्ष के लिए **GDP** के दूसरे अग्रिम अनुमानों के साथ सामने आएगा।

संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एफएई अनुमान कैसे जारी करताहैं?

एफएई उपलब्ध आंकड़ों को एक्सट्रपलेशन करके प्राप्त किया जाता है। क्षेत्रवार अनुमान अतिरिक्त संकेतक जैसे कि अलग-अलग करके प्राप्त किए जाते हैं

- वित्तीय वर्ष के पहले **7** महीनों के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक **(IIP)**
- सितंबर, **2020** के अंत तक उपलब्ध निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में सूचीबद्ध कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन
- फसल उत्पादन के **1** अग्रिम अनुमान,
- केंद्र और राज्य सरकारों के खाते,
- वित्तीय वर्ष के पहले **8** महीनों के लिए उपलब्ध डिपॉजिट और क्रेडिट, रेलवे की यात्री और माल ढुलाई से संबंधित आय, नागरिक उड्डयन, प्रमुख समुद्री बंदरगाहों पर कार्गो, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री आदि की जानकारी।

डेटा को कैसे एक्सट्रपलेशन किया जाता है?

- अतीत में, **IIP** जैसे संकेतकों के लिए एक्सट्रपलेशन पिछले वित्त वर्ष के पहले **7** महीनों के संचयी मूल्य के अनुपात के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले **7** महीनों के लिए संचयी मूल्य को विभाजित करके किया गया था। ।
- इसलिए यदि किसी चर का वार्षिक मूल्य पिछले वर्षों में पहले **7** महीनों में मूल्य से दोगुना था, तो वर्तमान वर्ष के लिए और साथ ही वार्षिक मूल्य को पहले **7** महीनों के मुकाबले इसे दोगुना माना जाता है।
- हालांकि, इस वर्ष, महामारी के कारण मासिक डेटा में व्यापक उतार-चढ़ाव थे। इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण गिरावट भी हुइ थी, विशेष रूप से पहली तिमाही में । यही कारण है कि सामान्य प्रक्षेपण तकनीकों में मजबूत परिणाम नहीं मिले हैं।
- इस प्रकार, **MoSPI** ने अधिकांश चरों के लिए अनुपातों को बदल दिया है।

Table 1: India has been losing the GDP growth momentum

Year	GDP Growth Rate (in %)
2015-16	8
2016-17	8.3
2017-18	7
2018-19	6.1
2019-20	4.2
2020-21	—7.7

Source: MoSPI

2020-21 के लिए पहले अग्रिम अनुमानों से मुख्य बिंदु क्या हैं?

1. जीडीपी विकास दर

भारत जीडीपी वृद्धि की गति खो रहा है (तालिका 1 से ऊपर देखें)

- **अभूतपूर्व संकुचन:** एफएई के अनुसार, भारत का सकल घरेलू उत्पाद **2020-21** में **7.7** प्रतिशत की दर से अनुबंध करेगा। यह एक तीव्र विचार है कि भारत ने **1992-93** में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के बाद से औसत वार्षिक जीडीपी विकास दर **6.8** प्रतिशत दर्ज की है।
- **वर्ष की पहली छमाही में महामारी फैक्टर:** लेकिन, इस साल संकुचन का एक बड़ा कारण कोविड-प्रेरित लॉकडाउन के कारण व्यवधान रहा है, जिसने पहली तिमाही (अप्रैल, मई और जून) में अर्थव्यवस्था का अनुबंध लगभग **24%** देखा था और एनएसओ के तिमाही अनुमानों के अनुसार, 2020-21 की पहली छमाही में वास्तविक जीडीपी 15.7 प्रतिशत है।
- **वर्ष की दूसरी छमाही में रिकवरी की उम्मीद है:** हालांकि, चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में - अर्थात, अक्टूबर से मार्च में सरकार को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था लगभग उतने ही माल और सेवाओं का उत्पादन करेगी जो उसने पिछले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही (2019-20) में उत्पादित किया था।

Table 2: Real GDP in 2020-21 will be lower than the 2018-19 level

Year	GDP in Rs Lakh Crore (constant prices)
2015-16	114
2016-17	123
2017-18	132
2018-19	139
2019-20	143
2020-21	134

Source: MoSPI

2. वास्तविक जीडीपी का पूर्ण स्तर (तालिका 2 से ऊपर देखें)

- **2020-21** के एच **1** में, भारत ने **60** लाख करोड़ रुपये की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया - **2019-20** के एच **1** में उत्पादित माल की **71** लाख करोड़ रुपये की तुलना में बहुत कम।
- **2020-21** के एच **2** में, **MoSPI** को उम्मीद है कि जीडीपी **74.4** लाख करोड़ रुपये होगी, जो कि **2019-20** के एच **2** में जीडीपी के लगभग बराबर है – यह लगभग **74.7** लाख करोड़ रुपये के बराबर है
- **2018-19** के स्तर से कम: **134.4** लाख करोड़ रुपये, भारत की वास्तविक जीडीपी - यानी मुद्रास्फीति के प्रभाव के बिना जीडीपी - **2020-21** में **2018-19** के स्तर से कम होगी। दूसरे शब्दों में, शुरुआत से अगले वित्तीय वर्ष में, भारत को सबसे पहले अपने जीडीपी को **2019-20 (143.7** लाख करोड़ रुपये) के स्तर पर वापस लाना होगा।

Table 3: This year India's per capita GDP will fall to levels last seen in 2016-17

Year	Per Capita GDP in Rs (constant prices)
2015-16	88616
2016-17	94751
2017-18	100268
2018-19	105361
2019-20	108620
2020-21	99155

Source: MoSPI

3. प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (तालिका 3 से ऊपर देखें)

- **प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का महत्व:** जबकि जीडीपी एक अखिल भारतीय सकल उत्पाद प्रदान करता है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का एक बेहतर चर है अगर कोई यह समझना चाहता है कि एक औसत भारतीय कैसे प्रभावित हुआ है।
- **तीन साल की प्रगति का क्षरण:** भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी घटकर **99** रुपए हो जाएगी, **2020-21** में **155** - आखिरी बार **2016-17** के दौरान चार साल पहले देखी गई थी। वास्तव में, जबकि कुल वास्तविक जीडीपी में **7.7** प्रतिशत की गिरावट होगी, तो प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी में **8.7** प्रतिशत की गिरावट होगी।

Table 4: India's real GVA level will fall below the 2018-19 level

Year	GVA in Rs Lakh Crore (constant prices)
2015-16	105
2016-17	113
2017-18	121
2018-19	128
2019-20	133
2020-21	123

Source: MoSPI

4. वास्तविक सकल मूल्य (या GVA) का पूर्ण स्तर (तालिका 4 से ऊपर देखें)

- **जीवीए का महत्व:** सकल मूल्य वर्धन आपूर्ति पक्ष से अर्थव्यवस्था की एक तस्वीर प्रदान करता है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग और सेवाओं द्वारा मूल्य वर्धित करता है। दूसरे शब्दों में, **GVA** विभिन्न क्षेत्रों में शामिल लोगों द्वारा अर्जित आय के लिए एक प्रॉक्सी प्रदान करता है।
- **2018-19 के स्तर से नीचे जीवीए में गिरावट:** 123.4 लाख करोड़ रुपये पर, भारत का वास्तविक जीवीए स्तर भी **2018-19** के स्तर से नीचे गिर जाएगा।

Table 5: Aggregate private consumption levels of Indians will be almost what it was in 2017-18

Year	PFCE in Rs Lakh Crore (constant prices)
2015-16	63.8
2016-17	69
2017-18	73.8
2018-19	79
2019-20	83.3
2020-21	75.4

Source: MoSPI

5. निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) के अतिरिक्त स्तर (तालिका 5 से ऊपर देखें):

- **PFCE का महत्व:** वस्तुओं और सेवाओं की सबसे बड़ी मांग निजी व्यक्तियों से आती है जो अपनी खपत की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर इसमें सभी चीजें शामिल होंगी - चाहे वह टूथपेस्ट हो या कार - जो लोग अपनी निजी व्यक्तिगत क्षमता में खरीदते हैं। इस मांग को **PFCE** कहा जाता है और यह कुल **GDP** का **56%** हिस्सा है।
- **2019-20 के स्तर से 9.5% की गिरावट:** 2020-21 का PFCE स्तर 75.4 लाख करोड़ होगा जो 2019-20 के स्तर (83.3 लाख करोड़) से लगभग 9.5% कम है। यह लगभग वही होगा जो 2017-18 में था।

Table 6: But per capita private consumption level will fall below the 2017-18 level

Year	Per Capita PFCE in Rs (constant prices)
2015-16	49738
2016-17	55120
2017-18	56163
2018-19	59594
2019-20	62087
2020-21	55609

Source: MoSPI

6. प्रति व्यक्ति PFCE (तालिका 6 से ऊपर देखें)

- **महत्व:** प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की तरह, प्रति व्यक्ति **PFCE** भी एक प्रासंगिक मीट्रिक है क्योंकि यह दर्शाता है कि उसकी निजी क्षमता में औसत भारतीय कितना खर्च करता है। आमतौर पर, आय के बढ़ते मानकों के साथ, उपभोग स्तर भी बढ़ जाते हैं
- **2019-20 के स्तर से 10.4% की गिरावट:** यह अनुमान है कि **2020-21** का प्रति व्यक्ति पीएफसीई **55,609** रुपये **(2019-20** पर यह **62,807** रुपये) होगा। इस वित्तीय वर्ष का अनुमान **2017-18** के स्तर **(56,163** रुपये) से भी कम है।

Table 7: The investment demand in the economy will fall even below the 2016-17 level

Year	GFCF in Rs Lakh Crore (constant prices)
2015-16	34.9
2016-17	37.9
2017-18	40.6
2018-19	44.6
2019-20	43.3
2020-21	37.1

Source: MoSPI

7. सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) का औसत स्तर (तालिका 7 से ऊपर देखें):

- जीडीपी का दूसरा सबसे बड़ा घटक जीएफसीएफ कहा जाता है और यह उन वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले सभी खर्चों को मापता है जो व्यवसाय और फर्म बनाते हैं क्योंकि वे अपनी उत्पादक क्षमता में निवेश करते हैं। इसलिए अगर कोई फर्म समग्र उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर खरीदती है तो इसे जीएफसीएफ के तहत गिना जाएगा।
- इस प्रकार की माँग भारत के सकल घरेलू उत्पाद के **28** प्रतिशत के करीब है। अगर इन्हें एक साथ लिया जाये तो, निजी मांग और व्यापार की मांग सभी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग **85** प्रतिशत है।
- पांच साल के निचले स्तर पर**: 37** लाख करोड़ रुपये पर, **GFCF** (या अर्थव्यवस्था में निवेश की मांग) **2017-17** के स्तर से भी नीचे गिर गया है।

स्पेक्ट्रम नीलामी

संदर्भ: दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने बुधवार (**6** जनवरी) को कहा कि **1** मार्च से **700, 800, 900, 1800, 2100, 2300** और **2500** मेगाहर्ट्ज बैंड में **4** जी स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी शुरू होगी।

स्पेक्ट्रम नीलामी क्या हैं?

- संचार में भूमिका: सेलफोन और वायरलाइन टेलीफोन जैसे उपकरणों को एक छोर से दूसरे छोर तक जुड़ने के लिए संकेतों की आवश्यकता होती है। ये सिग्नल एयरवेव पर किए जाते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए निर्दिष्ट आवृत्तियों पर भेजा जाना चाहिए।
- स्पेक्ट्रम का स्वामित्व: केंद्र सरकार देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सभी संपत्तियों का मालिक है, जिसमें एयरवेव भी शामिल हैं।
- नीलामी की आवश्यकता: सेलफोन, वायरलाइन टेलीफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में विस्तार के साथ, समय-समय पर संकेतों के लिए अधिक स्थान प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इन तरंगो को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने वाली कंपनियों को इन संपत्तियों को बेचने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर इन स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है।
- स्पेक्ट्रम की वैधता: इन एयरवेव्स को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जो उन बैंडों में उप-विभाजित होती है जिनमें अलग-अलग आवृत्तियों होती हैं। ये सभी एयरवेव एक निश्चित अवधि के लिए बेची जाती हैं, जिसके बाद उनकी वैधता कम हो जाती है, जो आम तौर पर 20 वर्षों में निर्धारित की जाती है।

अब स्पेक्ट्रम की नीलामी क्यों की जा रही है?

- **पिछली नीलामी:** आखिरी स्पेक्ट्रम की नीलामी **2016** में हुई थी, जब सरकार ने **5.60** लाख करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर **2,354.55** मेगाहर्ट्ज की पेशकश की थी। यद्यपि सरकार केवल **965** मेगाहर्ट्ज - या लगभग **40%** स्पेक्ट्रम बेचने में कामयाब रही जो बिक्री के लिए रखा गया था - और प्राप्त बोलियों का कुल मूल्य सिर्फ **65,789** करोड़ रुपये था।
- **2021 में लाइसेंस की समय सीमा समाप्त:** एक नई स्पेक्ट्रम नीलामी की आवश्यकता उत्पन्न हुई है क्योंकि कंपनियों द्वारा खरीदी गई एयरवेव की वैधता **2021** में समाप्त होने वाली है। **1** मार्च से शुरू होने वाले स्पेक्ट्रम की नीलामी में, सरकार **4** जी के लिए स्पेक्ट्रम बेचने की योजना बना रही है। जिसमें **700, 800, 900, 1800, 2100, 2300,** और **2500** मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड शामिल है।
- **आरक्षित मूल्य का महत्व:** इन सभी बैंडों का आरक्षित मूल्य **3.92** लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। विभिन्न कंपनियों से मांग के आधार पर, एयरवेव की कीमत अधिक हो सकती है, लेकिन यह आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं जा सकती है।

स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने की संभावना क्या हैं?

मौजूदा खिलाड़ी: सभी तीन निजी दूरसंचार खिलाड़ी, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, भारती एयरटेल, और वीआई अपने नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की संख्या का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए योग्य दावेदार हैं।

विदेशी खिलाड़ी: इन तीनों के अलावा, विदेशी कंपनियों सहित नई कंपनियां भी एयरवेव्स के लिए बोली लगाने की पात्र हैं। हालाँकि, विदेशी कंपनियों को या तो भारत में एक शाखा स्थापित करनी होगी और एक भारतीय कंपनी के रूप में पंजीकरण करना होगा, या एक भारतीय कंपनी के साथ गठजोड़ करके उन्हें जीतने के बाद एयरवेव को बनाए रखने में सक्षम होना होगा।

बोली लगाने से तीन मौजूदा कंपनियों की लागत क्या होगी?

- भारती एयरटेल और वीआई दोनों ने बार-बार बहुत सारे पैसे निकालने में असमर्थता व्यक्त की है - या तो नए स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए या पुराने स्पेक्ट्रम लाइसेंसों को नवीनीकृत करने के लिए जो वे पहले से ही रखते हैं।
- अधिकांश विश्लेषकों को उम्मीद है कि भारती एयरटेल अपने कुछ पुराने स्पेक्ट्रम को नवीनीकृत करेगी, लेकिन नए स्पेक्ट्रम के लिए बोली नहीं लगाएगी।
- वीए पर, सभी विश्लेषकों को उम्मीद है कि कंपनी इस नीलामी में भाग नहीं ले सकती है, यह देखते हुए नकदी प्रवाह की कमी को देखते हुए।
- रिलायंस जियो ने न केवल रिलायंस संचार से खरीदे गए **44** मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को नवीनीकृत करने की संभावना है, बल्कि आगामी नीलामी में बाद वाले **55** मेगाहर्ट्ज बैंड में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए बोली भी लगाई।
- इस अंत तक, रिलायंस जियो आरक्षित मूल्य पर **240** बिलियन का कुल पूंजी व्यय करेगा, और यदि इसे दीर्घकालिक स्थगित भुगतान योजना का विकल्प चुनना था, तो इसे लगभग **60** बिलियन रुपये का अग्रिम भुगतान करना होगा।

मौजूदा निजी खिलाड़ियों द्वारा इस प्रतिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा है?

- राजस्व आय के नीचे: सरकार अपनी स्पेक्ट्रम नीलामी से अपेक्षित राजस्व प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकती है, जैसा कि 2016 में हुआ था।
- बजट अनुमानों को प्रभावित करता है: नीलामियों में प्रदर्शन बजट अनुमान को प्रभावित कर सकता है जो इस स्रोत से राजस्व को ध्यान में रखता है।
- टेलीकॉम की राजकोषीय स्थिति: मौजूदा खिलाड़ियों द्वारा की जा रही अवास्तविक भागीदारी भी टेलीकॉम कंपनियों की तंग वित्तीय स्थिति को दर्शाती है, यह भारत में 5 जी से बाहर रोल को प्रभावित कर सकती हैं।

आस्थगित भुगतान योजना कैसे काम करेगी?

- आस्थगित भुगतान योजना के हिस्से के रूप में, **700, 800** और **900** मेगाहर्ट्ज के उप **-1** गीगाहर्ट्ज बैंड के लिए बोली लगाने वाले अब बोली राशि के **25** प्रतिशत का भुगतान कर सकते हैं, और बाकी बाद में देय होगा।
- **1800, 2100, 2300** और **2500** मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड के ऊपर **-1** गीगाहर्ट्ज बैंड में, बोली लगाने वालों को **50** फीसदी का भुगतान करना होगा, और फिर समान वार्षिक किश्तों में बाकी का भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं।
- हालांकि, सफल बोलीदाताओं को वायरलाइन सेवाओं को छोड़कर, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में समायोजित सकल राजस्व **(AGR)** का **3** प्रतिशत का भुगतान करना होगा।

निष्कर्ष

- भारत में स्पेक्ट्रम की नीलामी एक खरीदार के बाजार में बदल गई है। न्यूनतम प्रतिस्पर्धा की उम्मीद है, ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम लेने के साथ जो अपने सभी एक्सपायरिंग स्पेक्ट्रम को नवीनीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पैसे के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्रदान करता है

'मेरा गाँव मेरा गौरव' ड्राइव

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III-अर्थशास्त्र

समाचार में-

- हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (**ICAR**) की पहल 'मेरा गाँव मेरा गौरव' **(Mera Gaon, Mera Gaurav)** के तहत गोवा के कुछ गाँवों में कचरा निपटान हेतु ग्राम पंचायतों के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- "मेरा गाँव मेरा गौरव" **2015** में लॉन्च किया गया था।
- यह भारत के प्रधान मंत्री प्रारंभ प्रमुख कार्यक्रम है।
- उद्देश्य: गाँवों को गोद लेकर किसानों को नियमित रूप से आवश्यक जानकारी, ज्ञान और सलाह देना।
- इस योजना के तहत वैज्ञानिकों को उनकी सुविधा के अनुसार गाँवों का चयन करने और चयनित गाँवों के संपर्क में रहने तथा किसानों को निजी यात्राओं या टेलीफोन के माध्यम से तकनीकी एवं कृषि से संबंधित अन्य पहलुओं की जानकारी प्रदान करने की परिकल्पना की गई।
- वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्रों (**Krishi Vigyan Kendras- KVKs**) और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (**Agriculture Technology Management Agency- ATMA**) की सहायता से कार्य कर सकते हैं।

जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (RBIA) ढांचा

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III-अर्थशास्त्र

समाचार में-

- **RBI** ने बैंकों की शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट **(RBIA)** फ्रेमवर्क जारी किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों की शासन व्यवस्था को मज़बूत करने के लिये जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा फ्रेमवर्क (**RBIA**) जारी किया है। आर.बी.आई. द्वारा बैंकों को बेसल समिति और अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक लेखा परीक्षा मानकों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।

- बैंकों के दृष्टिकोण में एकरूपता लाने तथा सर्वश्रेष्ठ व्यवहार के अनुसार आंतरिक लेखा कार्यों के संचालन के लिये बैंकों को निम्न सलाह दी जाती है:

- प्राधिकरण, पदानुक्रम और स्वतंत्रता: आंतरिक लेखापरीक्षण के प्रमुख (HIA) बैंक के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी होंगे, जिनके पास स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होगी।
- योग्यता: लेखापरीक्षकों को बैंकिंग परिचालन, लेखा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषिकी और फोरेंसिक जाँच आदि क्षेत्रों का अनुभव तथा उनमें पेशेवर दक्षता होनी चाहिये।
- कार्यकाल: HIA को दीर्घावधि (न्यूनतम तीन वर्ष) के लिये नियुक्त किया जाएगा।

आंतरिक लेखा कार्य को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता, आवश्यकता पड़ने पर पूर्व-कर्मचारियों सहित विशेषज्ञों को अनुबंध के आधार पर ए.सी.बी. के अधीन नियुक्त किया जा सकता है, यदि बैंक में आवश्यक विशेषज्ञों का अभाव है।

भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III-अर्थशास्त्र

समाचार में-

- RBI ने हाल ही में भुगतान अवसंरचना विकास निधि (PIDF) योजना के संचालन की घोषणा की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- उद्देश्य: देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ टियर -3 से टियर -6 शहरों में भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की तैनाती को सब्सिडी देना।
- PIDF के प्रबंधन के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद (AC) का गठन किया गया है।
- यह फंड 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी तीन वर्षों के लिए चालू होगा और इसे दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- भारतीय नेटवर्क बैंक संघ (आईबीए) और पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) की सहायता से आरबीआई द्वारा लक्ष्यों के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी।

क्या आपको पता है?

- वर्तमान में PIDF के पास 345 करोड़ रुपये का कोष है, जिसमें RBI द्वारा 250 करोड़ रुपये और देश में प्रमुख अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा 95 करोड़ रुपये का योगदान है।
- अधिकृत कार्ड नेटवर्क सभी 100 करोड़ रुपये में योगदान देगा।
- कार्ड जारी करने वाले बैंक कार्ड जारी करने की मात्रा के आधार पर कॉर्पस में भी योगदान देंगे।
- इसके अलावा, पीआईडीएफ को कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करने वाले बैंकों से वार्षिक योगदान भी प्राप्त होगा।

'पर्यवेक्षकों का कॉलेज' (COS) के लिए शैक्षणिक सलाहकार परिषद की स्थापना

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III-अर्थशास्त्र

समाचार में-

- RBI ने केंद्रीय बैंक के 'पर्यवेक्षकों का एक कॉलेज' (CoS) के पूर्णकालिक निदेशक को सलाह देने के लिए पूर्व डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन के साथ एक अकादमिक सलाहकार परिषद की स्थापना की।
- कार्य: (1) उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां कौशल निर्माण / अप-स्किलिंग आवश्यक है; (2) सभी कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम तैयार करना और विकसित करना; (3) अंतर्राष्ट्रीय मानकों / सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ कार्यक्रमों को बेंचमार्क करें; (4) उपयुक्त शिक्षण विधियों आदि का विकास करना।

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन

पर्यवेक्षकों का कॉलेज (CoS)

- आरबीआई द्वारा स्थापित
- इसे विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षण को मजबूत करने के उपायों के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था।
- उद्देश्य: प्रवेश स्तर पर और निरंतर आधार पर दोनों अपने नियामक और पर्यवेक्षी कर्मचारियों के बीच पर्यवेक्षी कौशल को बढ़ाने और सुदृढ़ करना।
- जबकि CoS मई 2020 से आभासी मोड में सीमित तरीके से काम कर रहा था, अब इसे पूरी तरह से चालू किया जा रहा है।
- यह आगे बढ़ाने और पर्यवेक्षी संसाधनों के पूल की एक सुसंगत गुणवत्ता सुनिश्चित करके विनियमित संस्थाओं के प्रभावी निरीक्षण में योगदान देगा।
- CoS के पास पूर्णकालिक सलाहकार होगा जो अकादमिक सलाहकार परिषद (AAC) द्वारा समर्थित है।
- आरबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक, रबी नारायण मिश्रा को सीओएस के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

कानूनी इकाई पहचानकर्ता (LEI) का परिचय

भाग- GSप्रीलिम्स और GS-III-अर्थशास्त्र

समाचार में-

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल से आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से बड़े मूल्य के लेन-देन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (Legal Entity Identifier) को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की जाने वाली कानूनी इकाई पहचानकर्ता (Legal Entity Identifier) अभी 50 करोड़ से अधिक के लेनदेन के मामले में ही अनिवार्य किया गया है।

क्या आपको पता है?

- कानूनी इकाई पहचानकर्ता एक 20-अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या है जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेनदेन के लिए पार्टियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में इसकी कल्पना की गई थी।
- भारत के अंदर LEI कोड को "कानूनी पहचानकर्ता इकाई इंडिया लिमिटेड (LEIL)" से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007" के तहत कानूनी पहचानकर्ता इकाई इंडिया लिमिटेड (LEIL) को भारत में LEI कोड के जारीकर्ता के रूप में भी मान्यता प्रदान की है।

विशेषताएँ:

- कानूनी इकाई पहचानकर्ता कोड एक वित्तीय इकाई के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में करता है।
- नियामक आवश्यकताओं का पालन करने में मदद करता है।
- ट्रेड रिपॉजिटरी में लेनदेन की रिपोर्टिंग को सुगम बनाता है।
- LEI को रिज़र्व बैंक ने बड़े कॉर्पोरेट कर्जदारों के साथ-साथ ओवर द काउंटर (OTC) व्युत्पन्न और गैर-व्युत्पन्न बाजारों में प्रतिभागियों के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा है।

K-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी

संदर्भ: अर्थशास्त्री कहते हैं कि **COVID** से **K**-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरीभारत और दुनिया भर में बढ़ रही हैं। भारत की आर्थिक सुधार की विशेषता तीन अलग-अलग ताकतों से है, जिन्हें विघटित करने की आवश्यकता है

1. COVID-19 को नियंत्रित करने से बेहतर रिकवरी हुई है

- वायरस फैलने का सफल नियंत्रण: पिरामिड के शीर्ष पर स्थित परिवारों में लॉकडाउन के दौरान काफी हद तक आय का संरक्षण, बचत दर में वृद्धि के साथ ही भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये धन एवं वस्तुओं का संग्रह किया गया। इन घरों में रहने वाले लोगों की नौकरियों और आय के स्थायी रूप से प्रभावित होने की संभावना है।
- उम्मीद से ज्यादा जल्दी रिकवरी: नतीजतन, पूर्व-सीओवीआईडी गतिविधि स्तरों की ओर प्रगतिशील वापसी उम्मीद से बहुत जल्दी हुई है। अक्टूबर तक गतिविधि पूर्व-COVID स्तर के 95 प्रतिशत स्तर तक वापस आ गई है, और तब से यह ऊपर उठ रही है
- सरकार द्वारा सहायक कार्रवाइयां: केंद्र सरकार के खर्च में बहुप्रतीक्षित पिक-अप द्वारा जल्द ही वसूली की अपेक्षा की जा रही है, जो नवंबर में बढ़ी है और शेष वर्ष के लिए मजबूत बने रहने की उम्मीद है

2.रिकवरी श्रम और मजदूरी के नेतृत्व में नहीं

- बेरोजगारी की बढ़ती समस्या: सीएमआईई के श्रम बाजार सर्वेक्षण में अभी भी पूर्व-महामारी स्तरों की तुलना में 18 मिलियन कम कार्यरत (कुल नियोजित का लगभग 5%) है। सितंबर तक रोजगार की दर में धीरे-धीरे सुधार हुआ, लेकिन तब से यह लगातार कमजोर हुआ है, जब तक कि अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर खुल गई है।
- यह पीएमआई सर्वेक्षणों में भी दिखाई देता है जहां रोजगार की गतिविधियों में कमी आई है, और मनरेगा नौकरियों की मांग में जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अभी भी 50 प्रतिशत अधिक है
- वसूली की संभावनाएं प्रभावित करती हैं: ये श्रम बाजार दबाव मध्यम अवधि के आर्थिक संकट के जोखिमों को बढ़ाते हैं, और एक तेज निकट अवधि के पलटाव के साथ असंगत नहीं हैं क्योंकि रिकवरी पूंजी और मुनाफे के नेतृत्व में प्रतीत होती है, न कि श्रम और मजदूरी के नेतृत्व में।
- मजदूरों पर विभेदक प्रभाव: श्रम के भीतर भी, नीले-कॉलर श्रमिकों को उनके सफेदपोश समकक्षों के विपरित रूप से प्रभावित होने की संभावना है।

3. ग्रेटर स्केल और औपचारिककरण

- छोटी फर्मों की कमजोर लचीलापन: एक तीसरी घटना बड़ी कंपनियों ने संकट को बेहतर ढंग से सहन किया है और छोटी कंपनियों की कीमत पर बाजार में हिस्सेदारी हासिल कर रही है। इसलिए, डेटा की सावधानीपूर्वक व्याख्या करना महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ चर इस प्रतिस्थापन प्रभाव को ठीक होने की गति के रूप में दर्शाएंगे।
- बड़ी कंपनियों के होने का लाभ: इस हद तक अनौपचारिक / एसएमई फर्मों से बड़ी कंपनियों के लिए गतिविधि का प्रवासन है, कर संग्रह और सेंसेक्स / निफ्टी की आय में वृद्धि होनी चाहिए, यहां तक कि आर्थिक पाई स्थिर रखना।
- एसोसिएटेड रिस्क: ग्रेटर स्केल और औपचारिकता निस्संदेह मध्यम अवधि की उत्पादकता के लिए अच्छी तरह से बढ़ती है, लेकिन निकट-अवधि के श्रम बाजार के घर्षण को बढ़ा सकती है और मूल्य निर्धारण शक्ति को बढ़ा सकती है।
- यह सब इसलिए, COVID से कश्मीर के आकार की वसूली की संभावनाओं को बढ़ाता है, जो विश्व स्तर पर एक घटना है।

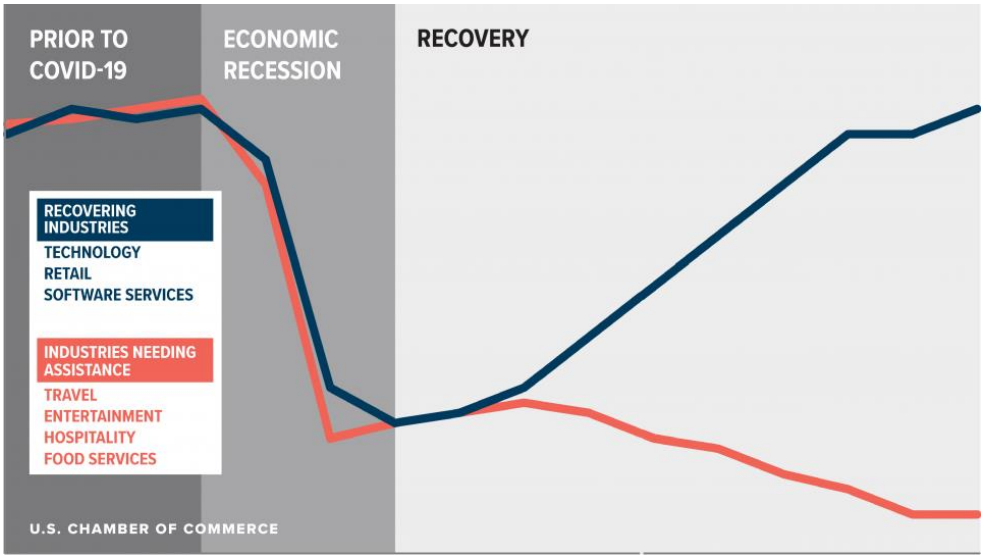

K-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी

- **K-**शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी तब होती है, जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग दर, समय या परिमाण में 'रिकवरी' होती है। यह विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों या लोगों के समूहों में समान 'रिकवरी' के सिद्धांत के विपरीत है।
- के-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी से अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक परिवर्तन होता है और आर्थिक परिणाम मंदी के पहले तथा बाद में मौलिक रूप से बदल जाते हैं।
- इस प्रकार की रिकवरी को **'K-**शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी' कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जब एक मार्ग पर साथ चलते हैं तो डायवर्ज़न के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि रोमन अक्षर **'K'** की दो भुजाओं से मिलता-जुलता है।
- **उदाहरण**: यात्री वाहन पंजीकरण (ऊपरी अंत में खपत) अक्टूबर के बाद से लगभग **4** प्रतिशत बढ़ गया है, जबकि दोपहिया वाहनों का अनुबंध **15** प्रतिशत है।

निष्कर्ष

- भारत का तेजी से अपेक्षित प्रतिक्षेप बहुत उत्साहजनक है। लेकिन दुनिया भर में श्रम बाजार के दबाव और के-आकार की रिकवरी की संभावनाओं को देखते हुए, अर्थव्यवस्था को सावधानीपूर्वक पोषण और स्टेक करने की आवश्यकता होगी।

खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में-

- एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित एक नवीन नई पेंट लॉन्च की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पर्यावरण के अनुकूल, गैर विषैले पेंट को खादी प्राकृत पेंट कहा जाता है।
- यह एंटी-फंगल, एंटी-बैक्टीरियल गुणों के साथ अपनी तरह का पहला उत्पाद है।
- पेंट को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- खादी प्राकृत पेंट दो रूपों में उपलब्ध है - डिस्टेंपर पेंट और प्लास्टिक इमल्शन पेंट।
- इसके मुख्य घटक के रूप में गाय के गोबर है और यह बिना गंध का है।
- पेंट भारी धातुओं जैसे सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम और अन्य से मुक्त है।

क्या आपको पता है?

- यह स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देगा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से स्थायी स्थानीय रोजगार पैदा करेगा।

- इस तकनीक से पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए कच्चे माल के रूप में गोबर की खपत बढ़ेगी और किसानों और गौशालाओं को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
- यह किसानों / गौशालाओं को प्रति पशु **30,000** रुपये (लगभग) प्रति वर्ष की अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का अनुमान है।
- गाय के गोबर के उपयोग से पर्यावरण भी साफ होगा और नालियों की कटाई को रोका जा सकेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

- यह संसद के अधिनियम, 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम **1956'** के तहत भारत सरकार द्वारा अप्रैल **1957** में (एक आरटीआई के अनुसार) एक वैधानिक निकाय है।
- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है।
- दृष्टि - ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी आवश्यक हो, अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास की योजना, प्रचार, सुविधा, आयोजन और सहायता करना।
- अप्रैल **1957** में इसने पूर्व अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का काम संभाला।
- प्रधान कार्यालय: मुंबई
- छह क्षेत्रीय कार्यालय: दिल्ली, भोपाल, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी।

Related articles:

- 1000-yrs Old Monpa Handmade Paper Industry brought alive in AP: Click here
- Migrant workers engaged in Honey Mission: Click here

नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड (NEVF) स्टार्ट-अप्स और युवा उद्यमियों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड **(NEVF)** स्टार्ट-अप्स और युवा उद्यमियों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड **(NEDFi)** के साथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन **(DoNER)** ने नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड की स्थापना की थी।
- यह **100** करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ पूर्वोत्तर के लिए पहला और एकमात्र वेंचर फंड है।

- फंड स्टार्ट-अप्स में निवेश करने का लक्ष्य रखता है और नए उद्यमिता के लिए संसाधन प्रदान करने के लिए अद्वितीय व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है।
- एनईवीएफ का मुख्य फोकस ज्यादातर खाद्य प्रसंस्करण, हेल्थकेयर, पर्यटन, सेवाओं के अलगाव, आईटी, आदि में शामिल उद्यमों के लिए है।

बीएसएनएल और एमटीएनएल ने EBITDA को सकारात्मक बना दिया है।

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -अवसंरचना; अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड **(BSNL)** और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड **(MTNL)** ने इस वित्तीय वर्ष के पहले **6** महीनों में **EBITDA** को सकारात्मक बना दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- **EBITDA** ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले आय के लिए खड़ा है।
- ईबीआईटीडीए मुनाफे का एक उपाय है।
- यह कंपनी के समग्र वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मीट्रिक है।
- **EBITDA** का उपयोग अब आमतौर पर कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य की तुलना करने और विभिन्न कर दरों और मूल्यह्रास नीतियों के साथ फर्मों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।
- हालांकि, **EBITDA** किसी कंपनी के नकदी प्रवाह का विश्लेषण करने के लिए एक विकल्प नहीं है और कंपनी को यह दिखा सकता है कि उसके पास ब्याज भुगतान करने के लिए अधिक पैसा है जितना वह वास्तव में करता है।

कोयला खनन के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल लॉन्च किया गया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -ऊर्जा संसाधन; अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- कोयला मंत्रालय ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल लॉन्च किया।
- यह एक एकीकृत मंच है जो भारत में कोयला खदान शुरू करने के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की भावना पर कार्य करता है।
- यह भारतीय कोयला क्षेत्र में आसानी से व्यापार करने के लिए एक मील का पत्थर होगा।
- वर्तमान में, देश में कोयला खदान शुरू करने से पहले लगभग **19** प्रमुख अनुमोदन या मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है।
- पोर्टल केवल प्रासंगिक आवेदन प्रारूपों को मैप करेगा और अनुमोदन या मंजूरी देने के लिए प्रवाह की प्रक्रिया भी करेगा।

क्या आपको पता है?

- यह पोर्टल नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था, जिसमें भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान की नीलामी के सफल बोलीदाताओं के साथ समझौते किए गए थे।
- हाल ही में, **19** सफल बोलीदाताओं को देश की पहली वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के तहत खानों का आवंटन किया गया था।
- इससे राज्यों को प्रति वर्ष लगभग **6,500** करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा और **70,000** से अधिक रोजगार भी पैदा होंगे।

आरबीआई वर्किंग ग्रुप डिजिटल लेंडिंग पर गठित

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर एक कार्य समूह का गठन किया है। यह वित्तीय क्षेत्र के साथ-साथ सभी अनरेगुलेटेड खिलाड़ियों द्वारा डिजिटल ऋण गतिविधियों के पहलुओं का अध्ययन करेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

इस कार्य समूह में आंतरिक और बाहरी दोनों सदस्य शामिल होंगे। आंतरिक सदस्य-

- आरबीआई के कार्यकारी निदेशक श्री जयंत कुमार दास
- आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग के मुख्य महाप्रबंधक श्री अजय कुमार चौधरी
- आरबीआई के भुगतान और निपटान प्रणाली के मुख्य महाप्रबंधक श्री पी वासुदेवन
- आरबीआई (सदस्य सचिव) के विनियमन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक श्री मनोरंजन मिश्रा

बाहरी सदस्य

- मोनेक्सो फिनटेक के सह-संस्थापक श्री विक्रम मेहता
- साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और **CloudSEK** के संस्थापक श्री राहुल शशी

यह कार्य समूह **RBI** विनियमित संस्थाओं में डिजिटल उधार गतिविधियों और आउटसोर्स डिजिटल ऋण गतिविधियों का मूल्यांकन करेगा। साथ ही वित्तीय स्थिरता, विनियमित संस्थाओं और उपभोक्ताओं को अनियमित डिजिटल ऋण द्वारा उत्पन्न जोखिमों की पहचान करेगा। डिजिटल उधार की क्रमिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी देगा। इतना ही नहीं, समूह डिजिटल उधार सेवाओं की तैनाती के लिए मजबूत डाटा प्रशासन, डाटा गोपनीयता और डाटा सुरक्षा मानकों के उपायों की सिफारिश भी करेगा।

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -स्टार्ट-अप; नवाचार

समाचार में-

- भारतीय प्रधान मंत्री ने **1,000** करोड़ रुपये के साथ स्टार्टअप इंडिया बीज कोष शुरू करने की घोषणा की ताकि स्टार्टअप्स के लिए बीज धन की कमी न हो।
- यह 'प्रारम्भ: स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के दौरान घोषित किया गया था।
- इससे नए स्टार्टअप शुरू करने और बढ़ने में मदद मिलेगी।
- फंड स्कीम की योजना पहले से ही इक्विटी पूंजी जुटाने में स्टार्टअप की मदद कर रही है।
- सरकार गारंटी के माध्यम से पूंजी जुटाने में स्टार्टअप्स की भी मदद करेगी।

Related articles:

- Prarambh: Startup India International Summit': Click here

लौह-अयस्क नीति 2021

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -स्टार्ट-अप; नवाचार

समाचार में-

- रेल मंत्रालय ने रेक के आवंटन और लौह-अयस्क के परिवहन को नियंत्रित करने वाली एक नई लौह-अयस्क नीति को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस नई नीति को लौह-अयस्क नीति **2021** नाम दिया गया है और यह **10** फरवरी, **2021** से लागू होगी।
- नई नीति के प्रावधानों को रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र **(CRIS)** द्वारा रेक अलॉटमेंट सिस्टम मॉड्यूल में अपडेट किया जाएगा।
- रेलवे द्वारा प्रलेखन की जांच को हटा दिया गया है।
- रेलवे बोर्ड (ईडीआरएम) कार्यालय, कोलकाता के कार्यकारी निदेशक रेक मूवमेंट, जो लौह-अयस्क यातायात के आवागमन के लिए कार्यक्रमों को मंजूरी दे रहे हैं, की नई नीति में कोई नियामक भूमिका नहीं होगी।
- ग्राहक अब किसी भी प्राथमिकता के तहत अपने ट्रैफ़िक को स्थानांतरित करने के इच्छुक हैं, उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों के नियमों और विनियमों के अनुसार सामग्री की खरीद, परिवहन और उपयोग करने का उपक्रम देना होगा।
- घरेलू विनिर्माण गतिविधि के लिए लौह-अयस्क यातायात के आंदोलन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
- जहां तक आवंटन और रेक के लोडिंग का संबंध है, पुराने और नए प्लांट को समान रूप से माना जाएगा ।

क्या आपको पता है?

- **2019-2020** में भारतीय रेलवे की कुल **1210** मिलियन टन माल ढुलाई का लगभग **17%** स्टील खातों के साथ लौह अयस्क रेलवे की यातायात की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट: RBI की चेतावनी

संदर्भ: भारतीय रिज़र्व बैंक **(RBI)** ने वित्तीय स्थिरता के जोखिम के साथ-साथ समकालीन संदर्भ में वित्तीय प्रणाली की लचीलापन को रेखांकित करते हुए अपनी द्वैमासिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के **22** वें अंक को जारी किया।

Key takeaways from the latest GDP estimates released: Click Here

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का महत्व

- **FSR** एक बेहद उपयोगी प्रकाशन है क्योंकि इसमें देश के सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों का योगदान प्राप्त होता है।
- इस प्रकार, यह अर्थव्यवस्था का सामना करने वाले तथाकथित मैक्रो-वित्तीय जोखिमों के बजाय एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एफएसआर भारतीय अर्थव्यवस्था में इस तरह के जोखिमों के प्रति सतर्क चेतावनी प्रदान करता है।

मैक्रो-आर्थिक जोखिम का एक उदाहरण - उच्च एनपीए

- यदि अर्थव्यवस्था में बहुत सारे बैंक यह पाते हैं कि विभिन्न व्यवसायों के लिए दिए गए ऋणों को चुकाने की संभावना नहीं है, तो यह एक मैक्रो-वित्तीय जोखिम है।
- क्योंकि यदि बैंकों को अपना पैसा वापस नहीं मिलता है, तो वे निवेश के अगले सेट को निधि देने में सक्षम नहीं होंगे। इस प्रकार ऋण की पहुंच में कमी आर्थिक वृद्धि को बाधित करती है क्योंकि फर्मों का विस्तार घटता है।
- अगर सरकार करदाताओं के पैसे का उपयोग बैंकों को जमानत देने के लिए करती है, तो भी उसे कुछ अन्य खर्चों पर लगाम लगानी होगी - शायद शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा या बुनियादी ढाँचे पर, इस प्रकार नागरिकों के कल्याण पर असर पड़ेगा।
- इसलिए, एक चीज दूसरे को जन्म दे सकती है और किसी देश की आर्थिक वृद्धि में भारी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बैंकों के पास एक ही समय में बहुत अधिक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए या बुरे ऋण) थे।

आरबीआई की एफएसआर रिपोर्ट द्वारा प्रमुख चिंताएं क्या हैं?

1. उच्च बैंक एनपीए

- आरबीआई के विश्लेषण के अनुसार, भारत की बैंकिंग प्रणाली में सकल एनपीए अनुपात का स्तर सितंबर **2020** (विस्तारित सभी ऋणों का **7.5%**) और सितंबर **2021** (आर्थिक गिरावट के आधार पर **13.5%** से **14.8%**) के बीच लगभग दोगुना हो सकता है।
- इन प्रतिशतों को परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए, किसी को यह ध्यान देना चाहिए कि जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी - **2008** के वित्तीय संकट से पहले - एनपीए **2.5%** के स्तर के आसपास था।
- बैंकिंग प्रणाली पूरी अर्थव्यवस्था का फाइनेंसर है। यदि इसके पहिए जाम हो जाते हैं या खराबी हो जाती है, तो यह भागती हुई आर्थिक वसूली को पटरी से उतार सकती है।

2. वित्तीय बाजारों के कुछ क्षेत्रों और वास्तविक अर्थव्यवस्था के बीच डिस्कनेक्ट

- आरबीआई ने उल्लेख किया कि अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और **COVID-19** महामारी के दौरान वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए किए गए उपायों के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, आर्थिक प्रदर्शन से काटे गए इक्विटी मूल्यांकन में"।
- यह एक तथ्य है कि भारत और अन्य जगहों पर शेयर बाजार के सूचकांकों ने वास्तविक अर्थव्यवस्था - जब कारों / टीवी / एसी / फोन / घरों / यात्रा यात्राओं आदि की संख्या में वृद्धि की है - इसके विपरीत संघर्ष किया है।

- आरबीआई ने चेतावनी दी, "वित्तीय परिसंपत्तियों का टूटा हुआ मूल्य वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करता है "बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों को इन जोखिमों से परिचित होना चाहिए और एक परस्पर वित्तीय प्रणाली में स्पिलओवर की आवश्यकता है।"

उपरोक्त स्थिति कैसे उत्पन्न हुई (अर्थव्यवस्था के सिकुड़ते समय शेयर बाजार में तेजी)?

- दुनिया भर में स्टिमुलस पैकेज: महामारी की शुरुआत ने भारत सहित दुनिया भर में मौद्रिक और राजकोषीय अधिकारियों को देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह आर्थिक गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं और घरेलू आय को पूरी तरह से नष्ट नहीं करता है, समर्थन उपायों का एक नमूना पेश करता है।
- वित्तीय प्रणाली में आसान पैसा: प्रोत्साहन के उपायों, जिसमें ब्याज दर में कटौती और तरलता का जलसेक शामिल था, ने वित्तीय प्रणाली में धन में पर्याप्त वृद्धि की है, जिसमें भारत के विदेशी निवेशकों के मामले भी शामिल हैं। कम लागत वाली उधार की उपलब्धता भी लोगों को शेयरों में निवेश करने के लिए पैसे उधार लेने के लिए प्रेरित करती है।
- भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) का पुनरुत्थान: एनएसडीएल का नवीनतम डेटा। दिखाते हैं कि चालू वित्त वर्ष में इक्विटी में शुद्ध एफपीआई 38.1 गुना बढ़कर, 2,36,781 करोड़ (16 जनवरी को) के रूप में हुई, जो पिछले वर्ष में अल्पावधि 6,153 करोड़ से अधिक थी।
- उच्च रिटर्न के लिए विकल्पों की कमी: दुनिया भर में, आसान पैसे की स्थिति में अतीत में स्टॉक मार्केट की रैलियों में तेजी आई है क्योंकि निवेशक ऐसे समय में उच्च रिटर्न चाहते हैं जब जमा और बॉन्ड में गिरावट से फिक्स्ड आय परिसंपत्तियों पर ब्याज दर कम हो जाती है।

क्यों चिंतित है आरबीआई?

- एसेट बुलबुले का निर्माण: आसान पैसा अक्सर संपत्ति बुलबुले बनाता है। एसेट बबल तब होता है जब आवास, स्टॉक या सोने जैसी परिसंपत्तियां नाटकीय रूप से कम अवधि में बढ़ जाती हैं जो उत्पाद के मूल्य द्वारा समर्थित नहीं होती हैं। एक बुलबुले की पहचान तर्कहीन विपुलता है - एक घटना जब हर कोई एक विशेष संपत्ति खरीद रहा है।
- ऐसे बुलबुले के फटने से होने वाली आर्थिक संकट की संभावना: RBI जोखिम से सावधान है कि प्रवृत्ति में अचानक तेज उलटफेर (शेयर बाजारों में बहने वाले आसान धन) के कारण परिसंपत्ति का बुलबुला फट सकता है, जिससे व्यापक संक्रमण हो सकता है।
- उदाहरण: एक आदमी की यात्रा कंपनी में अपनी बचत का निवेश करें क्योंकि स्टॉक इस उम्मीद में तेजी से बढ़ रहा है कि एक टीका उपलब्ध होने के साथ, यात्रा व्यवसाय बंद हो जाएगा। लेकिन अगर वायरस का दूसरा, अधिक संक्रामक तनाव होता है और यात्रा कंपनी बस्ट हो जाती है, तो इसका शेयर मूल्य गिर जाएगा और दर्द सभी शेयरधारकों के साथ साझा किया जाएगा।
- **प्रभाव:** यह परिसंपत्ति बुलबुला फटकर इसे बदतर बना देता है यह वित्तीय संस्थानों के बीच अंतर-संक्रमण का स्तर है। एक बेच संभावित रूप से वित्तीय प्रणाली (पूर्व म्युचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बैंक और NBFC, HFC, NABARD, EXIM, NHB, SIDBI आदि) में परिसंपत्ति बाजार के झटके प्रेषित कर सकता है।

- **विश्वव्यापी अनुभव:** उदाहरण के लिए, अमेरिका में **2001** की मंदी, डॉटकॉम बबल के फूटने (टेक कंपनियों के ओवरवैल्यूएशन) द्वारा उछाली गई थी, जो **11** सितंबर के आतंकवादी हमलों और प्रमुख कंपनियों के लेखांकन घोटालों की एक श्रृंखला के साथ मिलकर कार्य कर रही थी।

निष्कर्ष

- केंद्रीय बैंकों और राजकोषीय अधिकारियों द्वारा सक्रिय हस्तक्षेप को प्रणाली के स्थूल-वित्तीय स्थिरता के लिए किसी भी जोखिम को कम करने में सक्षम होना चाहिए।

ओपन स्काई संधि से अलग हुआ रूस

संदर्भ: अमेरिका के 'ओपन स्काई संधि' **(OST)** से अलग होने की घोषणा के बाद रूस ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है।। नवंबर **2020** में, रूस पर इसके उल्लंघन का आरोप लगाकर यूएसए ने ओएसटी छोड़ दिया था। मॉस्को ने अब संधि छोड़ने के अपने फैसले के लिए वाशिंगटन को दोषी ठहराया है।

ओपन स्काई संधि क्या है?

- यह एक ऐसा समझौता है जो प्रतिभागियों को अपने साथी सदस्य राज्यों के किसी भी हिस्से में निहत्थे टोही उड़ानों को उड़ाने की अनुमति देता है
- **1955** में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर द्वारा शीत युद्ध के दौरान तनाव को कम करने के साधन के रूप में इसे प्रस्तावित किया गया था। यह दावा करते हुए कि व्यापक जासूसी के लिए पहल का उपयोग किया जाएगा, मास्को ने आइजनहावर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
- हालांकि, यूएसएसआर के विघटन के बाद नाटो सदस्यों और पूर्व वारसा पैक्ट देशों के बीच **1992** में ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- यह **2002** में प्रभावी हुआ और इसमें **35** हस्ताक्षरकर्ता थे, जिनमें प्रमुख खिलाड़ी अमेरिका और रूस के साथ-साथ एक गैर-अनुसन्धान सदस्य (किर्गिस्तान) भी थे।
- **OST** का उद्देश्य सदस्यों के बीच आपसी खुलेपन के माध्यम से विश्वास पैदा करना है, जिससे आकस्मिक युद्ध की संभावना कम हो जाती है।
- इस संधि में 35 हस्ताक्षरकर्त्ता देशों (अमेरिका और रूस सहित) को संधि में शामिल अन्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जाँच के लिये गैर-हथियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमति है। इस निगरानी के दौरान केवल इमेजिंग उपकरणों की ही अनुमति दी जाती है। इस निगरानी के दौरान उस देश के सदस्य भी निगरानी प्रकिया में हिस्सा ले सकते हैं, जिसकी निगरानी की जा रही है।
- सेना की गतिविधियों, सैन्य अभ्यास और मिसाइल तैनाती पर एकत्रित जानकारी को सभी सदस्य राज्यों के साथ साझा करना होगा।

- निगरानी उड़ानों पर एकमात्र इमेजिंग उपकरणों की अनुमति है, और मेजबान राज्य के अधिकारी भी योजनाबद्ध यात्रा के दौरान बोर्ड पर रह सकते हैं।

हस्ताक्षरकर्ता

- 35 **राज्य** - बेलारूस, बेल्जियम, बोस्निया-हर्ज़ेगोविना, बुल्गारिया, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, किर्गिस्तान, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स , नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

ओपन स्काई संधि का महत्व

- इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए महत्व: उन्नत उपग्रह इमेजिंग तकनीक के आगमन से बहुत पहले 1992 में OST पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो वर्तमान में खुफिया जानकारी के लिए पसंदीदा तरीका है। फिर भी, निगरानी विमान महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं जो अभी भी उपग्रह सेंसर द्वारा एकत्रित नहीं की जा सकती हैं, जैसे कि थर्मल इमेजिंग डेटा।
- संधि के लिए छोटे देशों की पार्टी की मदद करता है: हालांकि उपग्रह एक ही प्रदान कर सकते हैं, और इससे भी अधिक विस्तृत, जानकारी, सभी संधि राज्यों-पार्टियों में ऐसी क्षमताएं नहीं हैं।
- **कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टूल:** संधि का उद्देश्य राज्यों-पार्टियों के बीच अति विश्वास में उनकी भागीदारी के माध्यम से विश्वास को बढ़ाना है।
- यूएसए ने रूस से अधिक इस संधि का उपयोग किया है: 2002 और 2016 के बीच, अमेरिका ने रूस द्वारा चलाई गई 71 उड़ानों की तुलना में रूस के ऊपर 196 उड़ानें भरीं। ट्रम्प के एक पूर्व अधिकारी ने 2014 के रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान एकत्र किए गए OST डेटा की भी प्रशंसा की थी।

अमेरिका ने ओपन स्काई संधि' क्यों छोड़ दी?

- जब इसे एक प्रमुख हथियार नियंत्रण समझौते के रूप में परिकल्पित किया गया था, तो अमेरिका में कई लोगों ने एक दशक से अधिक समय तक रूस पर **OST** प्रोटोकॉल का पालन न करने का आरोप लगाया, मॉस्को को अपने क्षेत्र पर निगरानी उड़ानों में बाधा डालने के लिए दोषी ठहराया, जबकि प्रमुख सामरिक डेटा एकत्र करने के लिए अपने स्वयं के मिशन का दुरुपयोग किया। ।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी इससे नाखुश थे, जब एक रूसी टोही ने **2017** में न्यू जर्सी राज्य में उनके गोल्फ कोर्स पर उड़ान भरी।
- मई **2020** में, ट्रम्प प्रशासन ने **OST** से हटने के अपने इरादे की घोषणा की, जिसमें रूस पर "वर्षों से विभिन्न तरीकों से संधि का लगातार उल्लंघन करने " का आरोप लगाया और नवंबर **2020** में इसे अलग हो गया।

रूस ने अमेरिका के बाद इसे क्यों छोड़ दिया?

- ओटीएस के साथ रूस के अनुपालन के संबंध में एक विवादास्पद मुद्दा कालिनिनग्राद पर उड़ानों की अनुमति देने के लिए इसकी कथित अनिच्छा थी, पूर्वी यूरोप में इसका बहिष्कार जो नाटो सहयोगी लिथुआनिया और पोलैंड के बीच स्थित है।
- रूस ने यह कहते हुए अपनी स्थिति का बचाव किया कि प्रतिबंध संधि नियमों के तहत स्वीकार्य थे, और अमेरिका ने अलास्का पर उड़ानों पर समान सीमाएं लागू करने का उदाहरण दिया।
- अमेरिका द्वारा **OST** छोड़ने के बाद, रूस ने नाटो सहयोगियों से आश्वासन मांगा जो इस संधि पर बने रहे कि वे रूस से वाशिंगटन के लिए अपनी उड़ानों द्वारा एकत्र किए गए डेटा को स्थानांतरित नहीं करेंगे। अपने बयान में, रूस ने कहा कि ये अनुरोध नाटो सदस्यों द्वारा समर्थित नहीं थे, इसे संधि छोड़ने के लिए प्रेरित किया।

हालिया विकास का गंभीर विश्लेषण (रूस का OST से हटना)

- वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ती अविश्वास: ओपन स्काई संधि की विफलता के बाद एक और महत्वपूर्ण हथियार नियंत्रण समझौता इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (INF) संधि, जिसे अमेरिका और रूस दोनों ने इसे 2019 में छोड़ दिया।
- **रूस को ट्रैक करने के लिए यूरोपीय संघ की क्षमताएं कमजोर हैं:** रूस के प्रस्थान वाशिंगटन के यूरोपीय सहयोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, जो बाल्टिक क्षेत्र में रूसी टुकड़ी आंदोलनों को ट्रैक करने के लिए OST डेटा पर भरोसा करते हैं।
- परमाणु हथियार नियंत्रण संधि: विशेषज्ञ अब यूएस-रूस 'न्यू START' परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते के भाग्य पर विचार कर रहे हैं, जिसे फरवरी 2021 में समाप्त होने की उम्मीद है। ट्रम्प पहले ही कह चुके हैं कि उनका प्रशासन इसे नवीनीकृत नहीं

करेगा जब तक चीन इसमें शामिल नहीं होता। नए राष्ट्रपति जो बेडन की पुनर्विचार की इच्छा के बावजूद, ऐसी आशंकाएं हैं कि इसे फ़रवरी की समयसीमा से पहले पूरा नहीं किया जाएगा।

फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- सेबी ने हाल ही में फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) के लिए ढाँचे में ढील दी है।
- इस कदम से कंपनियों के प्रमोटरों को इस मार्ग से आसानी से धन जुटाने में मदद मिलेगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- न्यूनतम प्रमोटरों के योगदान मानदंड और एफपीओ बनाने वाले जारीकर्ताओं के लिए लॉक-इन आवश्यकताओं की प्रयोज्यता को हटा दिया गया है।
- इससे पहले, प्रमोटरों को एक एफपीओ की ओर 20% योगदान करने के लिए अनिवार्य किया गया था।
- इसके अलावा, जनता को पूंजी के किसी भी मुद्दे के मामले में, न्यूनतम प्रमोटरों के योगदान को तीन साल के लिए लॉक-इन करने की आवश्यकता थी।
- छूट उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो कम से कम तीन साल के लिए स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करती हैं।
- साथ ही, ऐसी कंपनियों को 95% निवेशकों की शिकायतों का निवारण करना चाहिए।

महत्वपूर्ण तथ्य

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

- यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार का नियामक है।
- इसे **1988** में स्थापित किया गया था और सेबी अधिनियम, **1992** के माध्यम से वैधानिक दर्जा दिया गया था।
- सेबी तीन समूहों की जरूरतों के लिए जिम्मेदार है:
  - प्रतिभूतियों के जारीकर्ता
  - निवेश
  - बाजार के लिए मध्यस्थता

कार्य:

- अर्ध-विधायी - ड्राफ्ट नियम
- अर्ध-न्यायिक - नियम और आदेश पारित करता है
- अर्ध-कार्यकारी - जांच और प्रवर्तन कार्रवाई करता है

शक्तियां:

- प्रतिभूति एक्सचेंजों के कानूनों द्वारा अनुमोदित करना।
- कानूनों द्वारा संशोधन करने के लिए प्रतिभूति विनिमय की आवश्यकता होती है।
- खातों का निरीक्षण करें और मान्यता प्राप्त प्रतिभूति एक्सचेंजों से आवधिक रिटर्न के लिए कॉल करें।
- वित्तीय मध्यस्थों के खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करें।
- कुछ कंपनियों को अपने शेयरों को एक या अधिक प्रतिभूति एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने के लिए मजबूर करें।
- दलालों और उप-दलालों का पंजीकरण

Related articles:

- Mutual Funds (MF) Risk-o-meter becomes effective: Click here
- SEBI eases Fund-raising norms for firms: Click here

एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, विश्व की खाद्य कीमतें दिसंबर में लगातार सातवें महीने बढ़ीं, सभी प्रमुख श्रेणियों के साथ, चीनी को वर्जित करते हुए, पिछले महीने लाभ प्राप्त किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) खाद्य मूल्य सूचकांक खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में मासिक परिवर्तन का एक उपाय है।
- इसमें औसत निर्यात शेयरों के साथ भारित पांच कमोडिटी ग्रुप प्राइस इंडेक्स [अनाज, सब्जी, डेयरी, मांस और चीनी] का औसत होता है।
- यह दिसंबर में 107.5 अंक औसतन नवंबर में 105.2 था।
- पूरे 2020 के लिए, बेंचमार्क इंडेक्स में 97.9 अंक, तीन साल का उच्च और 2019 से 3.1% की वृद्धि हुई।

महत्वपूर्ण तथ्य

एफएओ

- संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की ओर ले जाटी है।
- मुख्यालय: रोम, इटली
- स्थापित: 16 अक्टूबर 1945, क्यूबेक सिटी, कनाडा
- अभिभावक संगठन: संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद

मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (MII)

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी स्थापित करने के लिए नए प्रवेशकर्ताओं की सुविधा के लिए स्वामित्व और शासन मानदंडों की समीक्षा पर एक चर्चा पत्र जारी किया है, अन्यथा इसे बाजार बुनियादी ढाँचा संस्थान **(MII)** कहा जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- MII के स्वामित्व का कम से कम 50% पूंजीगत बाजारों या वित्तीय सेवाओं से संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में पांच साल या उससे अधिक के अनुभव वाले व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है।
- सेबी ने डिपॉजिटरी या स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए नए प्रवेशकर्ताओं की सुविधा के लिए शासन और स्वामित्व मानदंडों की समीक्षा करने के लिए एक चर्चा पत्र पेश किया है।
- प्रस्ताव के अनुसार, MII (Market Infrastructure Institutions or Intermediaries) स्थापित करने के इच्छुक निवासी प्रमोटर 100% शेयर अपने पास रख सकते हैं।
- एफएटीएफ (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) के एक विदेशी प्रमोटर सदस्य MII में 49% शेयर अपने पास रख सकते हैं।
- एफएटीएफ सदस्य क्षेत्राधिकार के अलावा अन्य विदेशी संस्थाएं या व्यक्ति MII में 10% तक हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं। प्रमोटर के अलावा कोई भी व्यक्ति 25% से कम हिस्सेदारी का अधिग्रहण या अधिग्रहण कर सकता है।

रसद पर राज्यों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने हाल ही में रसद पर राज्यों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- राष्ट्रीय रसद नीति, जो राष्ट्रीय रसद परिषद और राज्य रसद समन्वय समिति के साथ परामर्श के अधीन है, रसद केंद्र के लिए बेहतर समन्वय और एकीकृत विकास के लिए एक टेम्पलेट के रूप में काम करेगी।
- लॉजिस्टिक्स में **5** आर(R) शामिल हैं: सही उत्पाद प्राप्त करना - सही स्थिति में - सही जगह पर - सही समय पर - सही ग्राहक के लिए।

क्या आपको पता है?

- भारत में **200** बिलियन **$** का लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है।
- इसका एक अच्छा हिस्सा भारतीय रेलवे द्वारा समर्थित है।
- एक उत्पाद की लगभग **13-14%** लागत रसद है, और मंत्रालय इसे लगभग **8%** तक लाने की दिशा में काम करेगा।

SBI ने विदेश में बॉन्ड बिक्री से जुटाए 60 करोड़ डॉलर

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - बैंकिंग; अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (**SBI**) ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को 1.80 प्रतिशत के कूपन पर बॉन्ड बेचकर 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं.

महत्वपूर्ण बिंदु

- बॉन्ड की कीमत **5**-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी दर से **140** आधार अंकों तक फैली हुई है और इसे सिंगापुर एक्सचेंज सिक्योरिटीज ट्रेडिंग लिमिटेड (एसजीएक्स-एसटी) और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड (इंडिया आईएनएक्स) में सूचीबद्ध किया जाएगा।
- सालों के अंतराल के बाद एसबीआई की अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक बॉन्ड ने बाजारों में वापसी का प्रतिनिधित्व किया है।
- विनियमन को आम तौर पर "ऑफशोर ऑफरिंग" के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि उन्हें मुख्य रूप से या तो एक विदेशी कंपनी के साथ एक प्रस्ताव बनाना होता है, या एक अमेरिकी कंपनी जो अपने ऋण या इक्विटी को विदेशों में, अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर की पेशकश कर रही है।
- एक विनियमन एस की पेशकश कई यूरोपीय प्रसादों और यूरोप में बड़ी समाशोधन फर्मों के लिए विशिष्ट है, अक्सर एक विनियमन के माध्यम से अपने सिस्टम तक पहुंच प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - स्टार्ट-अप; उद्यमिता; नवाचार

समाचार में-

- हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद में 28 गैर-आधिकारिक सदस्यों को नामांकित किया है, जिसमें बायजू के संस्थापक बायजू रविंद्रन, ज़ेस्टमनी (ZestMoney) के सह-संस्थापक लिज़ी चैपमैन और एक्सिलर वेंचर्स के अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन समेत कई अन्य स्टार्टअप्स के संस्थापक और निवेशक शामिल हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग **(DPIIT)** ने **21** जनवरी, **2020** को परिषद का गठन किया था, जो देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह दे।
- इस परिषद के गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल दो साल के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक होगा।

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन

परिषद की संरचना

- अध्यक्ष: वाणिज्य और उद्योग मंत्री।
- परिषद के संयोजक: संयुक्त सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग।
- पदेन सदस्य: संबंधित मंत्रालयों / विभागों / संगठनों के नाम संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं।
- गैर-सरकारी सदस्य, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाना है।
- इन सदस्यों को विभिन्न श्रेणियों से नामांकित किया जाएगा जैसे कि सफल स्टार्टअप के संस्थापक, दिग्गज जो भारत में बड़े और बढ़े हुए कंपनियां हैं, ऐसे व्यक्ति जो स्टार्टअप में निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं, आदि।
- गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल दो साल की अवधि के लिए होगा।

कार्य

- परिषद नागरिकों और छात्रों के बीच नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के उपाय सुझाएगी, विशेष रूप से, देश भर में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगी।
- यह सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार, सृजन, संरक्षण को बढ़ावा देने और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्वजनिक संगठनों को नवाचार को सुविधाजनक बनाने के लिए उपाय सुझाएगा।

- इसके अलावा, यह विनियामक अनुपालन और लागतों को कम करके व्यवसायों को शुरू करने, संचालित करने, बढ़ने और बाहर निकलने के लिए आसान बनाने के उपायों का सुझाव देगा, स्टार्टअप के लिए पूंजी तक पहुंच में आसानी को बढ़ावा देगा।

भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - स्टार्ट-अप; उद्यमिता; नवाचार

समाचार में-

- नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान के साथ भारत नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया।
- सूचकांक का पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन की जांच की जाती है।
- 'प्रमुख राज्यों की श्रेणी में टॉपर्स: (1) कर्नाटक; (2) महाराष्ट्र; (3) तमिलनाडु
- चार दक्षिणी राज्यों- कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल ने इस साल कर्नाटक प्रमुख राज्यों की श्रेणी के तहत शीर्ष पांच स्थानों पर कब्जा कर लिया।
- कुल मिलाकर, दिल्ली ने अपनी पहली रैंक बरकरार रखी, जबकि चंडीगढ़ इस साल दूसरे स्थान पर रहा।
- **उत्तर-पूर्वी / पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के तहत:** हिमाचल प्रदेश इस वर्ष शीर्ष रैंकर के रूप में उभरने के लिए दूसरे स्थान से ऊपर चला गया।

पैरामीटर:

- नवाचार आदानों को पांच एनबलर मापदंडों और आउटपुट के माध्यम से दो प्रदर्शन मापदंडों के माध्यम से मापा गया।
- एनबलर पैरामीटर्स: ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट '
- प्रदर्शन पैरामीटर: नॉलेज आउटपुट 'और नॉलेज डिफ्यूजन'

क्या आपको पता है?

कर्नाटक की रैंक का कारण:

- कर्नाटक की रैंकिंग उद्यम पूंजी सौदों, पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी निर्यात की अपनी पर्याप्त संख्या के कारण है।
- कर्नाटक के उच्च एफडीआई प्रवाह ने राज्य की नवाचार क्षमताओं को भी बढ़ाया है।

Related article:

- National Innovation Portal (NIP) launched: Click here

पावर सब्सिडी

संदर्भ: सीईई और आईआईएसडी के एक अध्ययन के अनुसार, ऊर्जा उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए भारत सालाना लगभग 2.89 लाख करोड़ रुपये (~ $ 39.5 बिलियन) खर्च करता है। इसमें बिजली, गैस, एलपीजी, केरोसिन और उर्वरक शामिल हैं। सब्सिडी की आवश्यकता उन वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए होती है जिनके पास अधिक सामाजिक / पर्यावरण कल्याण है या जो उन लोगों के लिए उपभोग के बुनियादी स्तरों तक पहुंच को कम कर सकते हैं जो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

मुद्दे

- सब्सिडी में सुधार करना: यदि लक्षित लाभार्थियों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तो सब्सिडी समाप्त हो जाती है, जिससे वे बहुत ही सामाजिक कल्याण को बिगाड़ते हैं जिसे वे ठीक करना चाहते थे।
- उच्च शुल्कों की निरंतरता: पूरी तरह से लक्षित बिजली सब्सिडी (63,778 करोड़ रुपये में) सभी ऊर्जा सब्सिडी के पांचवें से अधिक का गठन। फिर भी, भारत के पास क्रय शक्ति समता के आधार पर सबसे अधिक बिजली शुल्क है।
- भारत की नीतियों के साथ गठबंधन नहीं किया गया है: सरकार के कार्यक्रमों से संकेत मिलता है कि भारत सही मायने में दो ऊर्जा संक्रमणों से गुजर रहा है: एक सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच की ओर और दूसरा क्लीनर ऊर्जा की ओर। लेकिन इसकी सब्सिडी संरचना दोनों उद्देश्यों के खिलाफ है, गंदे ईंधन के लिए विकृत कीमतों को बनाए रखने और समर्थन की जरूरत के लिए उपलब्ध संसाधनों को सीमित करने के लिए।

आगे की राह

- डेटा आधारित सब्सिडी संरचना: बेहतर सब्सिडी वितरण डेटा उन समूहों की पहचान करने में मदद करता है जो लाभान्वित होते हैं, और अमीर उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों को संशोधित करने के लिए राजनीतिक स्थान बनाते हैं। एलपीजी सब्सिडी के लिए गिव-इट-अप अभियान ने इस सिद्धांत का पालन किया।
- समुचित लक्ष्यीकरण के लिए जनगणना का उपयोग करें: जनसंख्या को धन / आय के आधार पर बेहतर वर्गीकृत करने की आवश्यकता है ताकि बेहतर लक्षित बिजली सब्सिडी हो। जनगणना ऐसे उद्देश्यों के लिए आवश्यक डेटा प्रदान कर सकती है। आय की आत्म-रिपोर्टिंग की सीमाओं को दूर करने के लिए, घरों को ठीक से वर्गीकृत करने के लिए धन और सामाजिक संकेतकों की भी आवश्यकता होगी।
- सब्सिडियों के लिए DBT विकल्प: एक अच्छी तरह से लक्षित प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण सभी या नाममात्र बिजली की खपत के एक हिस्से को कवर कर सकता है। इस तरह के बिजली पहुंच सुरक्षा जाल, तनावपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों के दौरान, तीन महीनों के लिए 3,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, पूरे राज्य में वार्षिक बिजली सब्सिडी का 5% से भी कम।
- आनुपातिक कृषि-बिजली सब्सिडी: बिजली और उर्वरक के कृषि उपयोग के लिए सब्सिडी को खेत के आकार से जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, प्राकृतिक खेती उर्वरक पर सब्सिडी को बचा सकती है, और इसके बजाय किसानों को अधिक टिकाऊ खेती के तरीकों में बदलाव करने की लागत (एक दशक के भीतर) को कवर कर सकती है।
- अंतर-विभागीय सहयोग: बिजली के लिए लक्षित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को गैर-ऊर्जा सामाजिक कल्याण योजनाओं को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार विभागों के सहयोग से डिजाइन किया जा सकता है।

- बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सब्सिडी: नवीकरण के लिए सब्सिडी ग्रिड बैलेंसिंग और ऊर्जा भंडारण में निवेश करने की आवश्यकता होती है ताकि कई अन्य क्षेत्रों (परिवहन, खाना पकाने, छोटे उद्योगों) का व्यापक विद्युतीकरण संभव हो सके।
- शहरी क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस: यह अनुमान है कि 2025 तक शहरी क्षेत्रों में पाइप्ड प्राकृतिक गैस के तेजी से रोलआउट से एलपीजी सब्सिडी पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत हो सकती है।
- सब्सिडी संरचना का पुनर्गठन: खराब डिजाइन वाले क्रॉस-सब्सिडी के लिए सब्सिडी सुधार (जैसे कि गरीब उपभोक्ताओं के लिए एक सीधा लाभ हस्तांतरण) को प्रतिस्थापित करना न केवल सब्सिडी पर खर्च किए गए धन को कम कर सकता है, बल्कि औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता में भी सुधार करेगा।
- समग्र दृष्टिकोण: सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता और नए आर्थिक अवसर के अनुरूप सिद्धांतों को अपनाना।

निष्कर्ष

- अच्छी और बुरी सब्सिडी के बीच अंतर सामाजिक कल्याण और राजनीतिक संरक्षण के बीच संतुलन में है।
- महामारी से प्रेरित आर्थिक संकट विकृतियों को ठीक करने का एक और मौका देता है, जरूरतमंद लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा जाल बढ़ाता है, स्वच्छ बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए संसाधनों को मुक्त करता है, अधिक नौकरियां पैदा करता है और नए निवेश में अरबों को आकर्षित करता है।

RBI SBI, ICICI और HDFC बैंकों को 'TO BIG TO FAIL' बैंकों के रूप में बरकरार रखता है

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - बैंकिंग

समाचार में-

- **RBI** ने भारतीय स्टेट बैंक, **ICICI** बैंक और **HDFC** बैंक को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक **(D-SIB)** या ऐसे बैंकों के रूप में बरकरार रखा है जिन्हें "विफल होने के लिए बहुत बड़ा" माना जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- **SBI** ने कहा कि ये तीनों बैंक इतने बड़े हैं कि कभी डूब **(Too Big To Fail)** नहीं सकते। केंद्रीय बैंक ने **D-SIB (Domestic Systemically Important Banks)** की 2020 लिस्ट की घोषणा करते हुए यह बात कही।
- आरबीआई ने **22** जुलाई **2014** को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों से निपटने के लिए रूपरेखा जारी की थी।
- **D-SIB** ढांचे के लिए आरबीआई के लिए आवश्यक है कि वह **2015** से शुरू होने वाले **D-SIB** के रूप में नामित बैंकों के नामों का खुलासा करे और इन बैंकों को उनके प्रणालीगत महत्व के स्कोर (एसआईएस) के आधार पर उपयुक्त बाल्टियों में रखे।
- इस लिस्ट में शामिल होने वाले बैंकों पर **RBI** कड़ी नजर रखता है। इसका मकसद वित्तीय तंत्र को ढहने से बचाना है। रिजर्व बैंक साल 2015 से हर अगस्त में इस श्रेणी में आने वाले बैंक के नाम जारी करता है। केंद्रीय बैंक हर बैंक को सिस्टमेटिक इमर्पोटेंट स्कोर (**Systemic Importance Scores, SIC**) देता है, जिसके आधार पर ऐसे बैंक को छांटा जाता है।

- शुरूआत के दौरान रिजर्व बैंक ने कहा था है कि इन बैंकों को अपनी कॉमन इक्विटी टायर-1 (**Common Equity Tier 1, CET**1) को बढ़ाना होगा। इसकी शुरुआत एक अप्रैल 2016 से हो गई है, जो 2019 से पूरी तरह लागू हुई। केंद्रीय बैंक ने इस श्रेणी के बैंकों के लिए एक फ्रेमवर्क जुलाई 2014 में तैयार किया था। रिजर्व बैंक बड़े बैंकों को अपनी डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट (**D-SIB)** श्रेणी में रखता है।
- **RBI** के इस लिस्ट में **SBI** और **ICICI** बैंक सबसे पहले से शामिल हैं। इन दोनों बैंकों को इस लिस्ट में 2015 में शामिल किया गया था। फिलहाल इस लिस्ट में सिर्फ तीन बैंक शामिल हैं। **HDFC** बैंक का नाम बाद में सितंबर 2017 में शामिल किया गया था। **RBI** ने **SBI** और **ICICI** बैंक के साथ 2015 में पहली बार **D-SIB** लिस्ट जारी की थी। वर्तमान अपडेट 31 मार्च, 2020 तक बैंकों से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है।

RBI ने NBFC के लिए एक कठिन नियामक ढांचा सुझाया है

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - बैंकिंग; अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- **RBI** ने देश की वित्तीय प्रणाली में किसी भी प्रणालीगत जोखिम की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों **(NBFC)** क्षेत्र के लिए एक कठिन नियामक ढांचा सुझाया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- आरबीआई ने संशोधित नियामक ढांचे पर एक चर्चा पत्र जारी किया, जो एक बड़े पैमाने पर आधारित दृष्टिकोण पर तैयार किया गया है, और एक महीने के भीतर टिप्पणियां मांगी गई हैं।
- रिजर्व बैंक ने अपने डिस्कशन पेपर में कहा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के स्ट्रक्चर में बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर होना चाहिए। बेस लेयर ने वैसे **NBFCs** को रखने का सुझाव दिया गया जो नॉन-डिपोजिट **NBFCs** हैं, यानी जिनमें लोग पैसे जमा नहीं करते हैं। वहीं, मिडिल लेयर में वैसै नॉन-डिपोजिट **NBFCs** जो फाइनेंशियल सिस्टम के लिए जरूरी हैं, उन्हें रखने की बात कही गई है। इनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ दूसरे **NBFCs** को रखने का सुझाव दिया गया है और कहा गया है कि इनके लिए जो नियम बनें, वे बेस लेयर से कड़े होने चाहिए।
- एनबीएफसी-एनडी के लिए मौजूदा नियामक ढांचा अब आधार परत एनबीएफसी पर लागू होगा।
- **NBFC-NDSI** के लिए लागू मौजूदा विनियामक ढांचा मध्य परत **NBFC** पर लागू होगा।
- ऊपरी परत में रहने वाले **NBFC** एक नई श्रेणी का गठन करेंगे।
- प्रणालीगत महत्व के लिए वर्तमान सीमा, जो अभी **500** करोड़ है, को संशोधित कर **1,000** करोड़ करने का प्रस्ताव है।
- प्रस्तावों के अनुसार, **180** दिनों का मौजूदा एनपीए वर्गीकरण मान **90** दिनों तक कम हो जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

- यह एक वित्तीय संस्थान है जिसके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं है या इसकी निगरानी किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियामक एजेंसी द्वारा नहीं की जाती है।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बैंकों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि NBFCs डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते हैं।

Related articles:

- RBI introduces risk-based internal audit norms for NBFCs, UCBs: Click here
- Structured Finance and Partial Guarantee Programme to NBFC-MFIs launched: Click here
- Special liquidity scheme for NBFCs/HFCs approved: Click here

---

ग्रीन बांड जारी करने की लागत अन्य बांडों की तुलना में अधिक होती है

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- RBI द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि ग्रीन बांड जारी करने की लागत आम तौर पर भारत में अन्य बॉन्ड की तुलना में अधिक रही है, बड़े पैमाने पर असममित जानकारी के कारण।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 2015 से 5 से 10 वर्षों के बीच परिपक्वता के साथ जारी किए गए हरे बांड के लिए औसत कूपन दर आमतौर पर इसी तरह के कार्यकाल के साथ कॉर्पोरेट और सरकारी बांड से अधिक बनी हुई है।
- 10 डॉलर से अधिक या उससे अधिक के कार्यकाल वाले अमेरिकी डॉलर-मूल्य वाले हरे बांड के लिए, कूपन दर कॉर्पोरेट बॉन्ड की तुलना में कम थी।
- भारत में ज्यादातर ग्रीन बॉन्ड सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों या कॉर्पोरेट्स द्वारा बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य के साथ जारी किए जाते हैं।
- 2018 के बाद से भारत में जारी किए गए सभी बांडों में से केवल 0.7% ग्रीन बॉन्ड का गठन किया गया,
- भारत में एक बेहतर सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करने से परिपक्वता बेमेल को कम करने, लागत उधार लेने और इस सेगमेंट में कुशल संसाधन आवंटन करने में मदद मिल सकती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ग्रीन बांड एक निश्चित आय वाला साधन है जिसे विशेष रूप से विशिष्ट जलवायु-संबंधित या पर्यावरणीय परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ग्रीन बॉन्ड आम तौर पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कर प्रोत्साहन के साथ आते हैं।
- विश्व बैंक ने 2009 में पहला आधिकारिक ग्रीन बांड जारी किया।
- 2019 में लगभग $ 157 बिलियन के ग्रीन बांड जारी किए गए।

संकट के समय में बजट

संदर्भ: जीवन की सामान्य कार्यप्रणाली को बाधित करने वाले COVID-19 महामारी के मद्देनजर विश्व की अर्थव्यवस्थाएं संकट में हैं।

अमेरिका किस प्रकार से इस आर्थिक संकट से निपटने की कोशिश कर रहा है?

- आज अमेरिका महामंदी के बाद से अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। रूजवेल्ट की तरह, राष्ट्रपति जो बिडेन अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिकी बचाव योजना शुरू कर रहे हैं।
- $ 1.9 ट्रिलियन योजना का प्रस्ताव है
- $ 1,400 प्रति व्यक्ति भुगतान
- बेरोजगारी लाभ में वृद्धि
- स्थानीय सरकारों को सहायता
- त्वरित वैक्सीन रोलआउट के लिए समर्थन
- बच्चों को स्कूल में वापस लाने के लिए निवेश
- न्यूनतम वेतन $ 15 प्रति घंटा।

आर्थिक संकट से निपटने के लिए पॉल क्रुगमैन सिद्धांत क्या हैं?

- नोबल लॉरेट पॉल क्रुगमैन ने आर्थिक गड़बड़ी से निपटने में बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने बजट बनाने के नियमों को आधार बनाया है।
- **बढ़ी हुई सरकारी खर्च:** पहला नियम सरकार की मदद करने की शक्ति पर संदेह नहीं करना है। सरकारी खर्च बेहद फायदेमंद हो सकता है। उदाहरण के लिए, सस्ती देखभाल अधिनियम, स्वास्थ्य बीमा के बिना अमेरिकियों की संख्या में गिरावट का कारण बना, और लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया।
- **दोषों में ढील:** दूसरा ऋण से ग्रस्त नहीं होना है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पारंपरिक ज्ञान की तुलना में कर्ज बहुत कम समस्या है। ऐतिहासिक मानकों से ब्याज दरें कम हैं। ऋण की सेवा का बोझ कम है।
- **मुद्रास्फीति की चिंताएं खत्म हो गई हैं:** तीसरा नियम मुद्रास्फीति के बारे में चिंता नहीं करना है। कम आय वाले बेरोजगारी और बड़े बजट घाटे के साथ मुद्रास्फीति हॉट इकोनॉमी चला सकते हैं।

- **आम सहमति मुश्किल है:** चौथा द्विदलीय समर्थन पर भरोसा नहीं करना है। सरकारी अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की योजना के संबंध में कुछ विरोध होगा जो संकीर्ण उद्देश्यों के लिए हो सकता है। फिर भी, सरकार को अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

भारतीय संदर्भ - आगामी बजट में क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **वित्तीय वर्ष की चुनौती** - वित्तीय जीडीपी का अनुमान 200 लाख करोड़ है। सरकार को 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करने की जल्दी थी। राजकोषीय घाटा FRBM अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य का निरीक्षण कर सकता है। ज्यादा खर्च करना मुश्किल हो रहा है।
- **स्वास्थ्य व्यय को प्राथमिकता देना:** भारत में **10,000** भारतीयों के लिए केवल पांच बेड हैं और **2020** की मानव विकास रिपोर्ट में बेड की उपलब्धता पर 155 वें स्थान पर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को जीडीपी के 1.5% से स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2.5% तक बढ़ाना चाहिए।
- **इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाना क्योंकि इसमें गुणक है:** नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का लक्ष्य **6,25** से अधिक परियोजनाओं में **2025** तक **25 111** लाख करोड़ का निवेश करना है। एक विकास वित्त संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव अभी भी हासिये पर है। चीनी सरकार ने सामाजिक आवास परियोजनाओं के निर्माण में प्रवेश किया है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना। यह प्रत्यक्ष -नकद हस्तांतरण से कहीं बेहतर होगा।
- कराधान में परिवर्तन: ईंधन की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट के बावजूद, सरकार ने ईंधन की कीमतों को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ाने के लिए चुना। GST राजस्व का बड़ा स्रोत रहा है। GST टैरिफ को कम करने के लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता है। सुपर-रिच पर उपकर या अधिभार लगाया जा सकता है। प्रोफेसर अरविंद पनागरिया द्वारा सुझाए गए औसत टैरिफ को 2024 तक 14% के अपने मौजूदा स्तर से 10% तक नीचे आना चाहिए।
- व्यापार उदारीकरण और निजीकरण: कई प्रमुख सुधारों के साथ - नए श्रम कोड, नए खेत कानून, एकल राष्ट्रव्यापी GST, इन्सॉल्वेंसी कोड, कम कॉर्पोरेट लाभ कर - निजीकरण और व्यापार उदारीकरण के अलावा लगभग दोहरे अंक के विकास की गारंटी होगी।

निष्कर्ष

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, ग्रामीण और शहरी दोनों तरह की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा बजट बढ़ रहा है। इसलिए सरकार को बजट के साथ आना होगा जो अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करे।

कृषि

मंत्रिमंडल ने इथेनॉल आसवन क्षमता को बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दी

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -इन्फ्रास्ट्रक्चर; वातावरण; कृषि

समाचार में- मंत्रिमंडल ने इथेनॉल आसवन क्षमता को बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दी

पृष्ठभूमि

- **2010-11** के बाद से देश में चीनी का अधिशेष उत्पादन हुआ है।
- गन्ने की उन्नत किस्मों की शुरुआत के कारण आने वाले वर्षों में भारत में चीनी उत्पादन अधिशेष रहने की संभावना है।
- चीनी के अधिशेष स्टॉक से निपटने के लिए, चीनी मिलें चीनी का निर्यात करती रही हैं, जिसके लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है।
- भारत विकासशील देश होने के नाते विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के अनुसार वर्ष **2023** तक वित्तीय सहायता प्रदान करके चीनी का निर्यात कर सकता है।
- इसलिए, अतिरिक्त गन्ने और शक्कर से इथेनॉल को डायवर्ट करना सरप्लस शेयरों से निपटने का एक सही तरीका है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस प्रकार, हाल ही में कैबिनेट ने इथेनॉल आसवन क्षमता को बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दी है।
- अतिरिक्त चीनी से घरेलू रूप से चीनी की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी।
- यह चीनी मिलों को भंडारण समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद करेगा।
- यह उनके नकदी प्रवाह में सुधार करेगा और किसानों के गन्ना मूल्य बकाया की निकासी में उन्हें सुविधा प्रदान करेगा।
- सरकार ने **2022** तक पेट्रोल के साथ ईंधन ग्रेड इथेनॉल के **10%, 2026** तक **15%** और **2030** तक **20%** सम्मिश्रण का लक्ष्य तय किया है।
- चीनी क्षेत्र का समर्थन करने और गन्ना किसानों के हित में, सरकार ने बी-हैवी मोलासेस, गन्ने के रस, चीनी सिरप और चीनी से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है।
- ईंधन ग्रेड इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, सरकार मक्का से इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए भट्टियों को भी प्रोत्साहित कर रहा है; और चावल एफसीआई के पास उपलब्ध है।
- सरकार ने मक्का और चावल से इथेनॉल की पारिश्रमिक कीमत तय की है।
- सरकार वर्ष **2025** तक और उसके बाद **20%** सम्मिश्रण लक्ष्य की उपलब्धि को प्राप्त करने की योजना बना रही है।
- मिश्रित स्तर में वृद्धि के साथ, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाएगी और वायु प्रदूषण भी कम होगा।

इसके अलावा, सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:

- इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ब्याज सबवेंशन बढ़ाने के लिए एक संशोधित योजना लाना।
- सरकार परियोजना के समर्थकों द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण के विरुद्ध एक वर्ष की मोहलत सहित पाँच वर्ष के लिए ब्याज उपकर का वहन करेगी, जो प्रतिवर्ष **6%** या बैंकों द्वारा लगाए गए ब्याज की दर का **50%** कम है।

- ब्याज सबवेंशन केवल उन्हीं भट्टियों को मिलेगा जो पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए ऑपरेशन्स मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम **(OMCs)** को उत्पादित इथेनॉल का कम से कम **75%** आपूर्ति करेगी।

क्या आपको पता है?

- प्रस्तावित हस्तक्षेप विभिन्न फीड स्टॉक से **1G** इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाएगा, जिससे पेट्रोल के साथ इथेनॉल के मिश्रित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुविधा होगी।
- यह इथेनॉल को एक ईंधन के रूप में बढ़ावा देगा जो कि स्वदेशी, गैर-प्रदूषणकारी और वस्तुतः अटूट है।
- इससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार होगा और तेल आयात बिल पर बचत होगी।
- यह किसानों को बकाया का समय पर भुगतान भी सुनिश्चित करेगा।

मेघालय में नॉर्थ ईस्ट का पहला विशिष्ट "जिंजर" प्रोसेसिंग प्लांट को पुनर्जीवित किया जा रहा है

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - पॉलिमिट्री और इंटरवेंशन

समाचार में-

- मेघालय में जिला री-भूई में उत्तर पूर्व का पहला विशेषीकृत "जिंजर" प्रसंस्करण संयंत्र पुनर्जीवित किया जा रहा है और **2021** की शुरुआत में इसके कार्यशील होने की संभावना है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह प्लांट एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क **(ईपीआईपी),** राजा भागन, बरनिहाट हाट में स्थित है।
- यह अदरक को संसाधित करेगा और मोम वाले अदरक, अदरक का पेस्ट, अदरक पाउडर, अदरक के गुच्छे, अदरक के तेल आदि जैसे उत्पादों को तैयार करने में मदद करेगा।
- हाल ही के महीनों में **COVID-19** वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में रिपोर्ट किए गए गुणों के कारण अदरक को प्रमुखता का स्थान प्राप्त हुआ है।
- इस संयंत्र से तैयार किए जा रहे अदरक उत्पाद घरेलू खपत के लिए उपलब्ध होंगे और साथ ही वैश्विक मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे।
- यह प्रधान मंत्री मोदी की **"Vocal for Local"** को भी पूरा करेगा।
- पीपीपी मोड के लिए, एक संचालन और रखरखाव ऑपरेटर को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था और संयंत्र की स्थापना और पुनर्जीवित करने पर काम चल रहा है।

क्या आपको पता है?

- भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र हर साल लगभग 450,000 मीट्रिक टन उच्च-गुणवत्ता वाला अदरक का उत्पादन करता है, लेकिन प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की कमी के कारण इसका अधिकांश हिस्सा कम कीमत पर बेचा जाता है।
- मेघालय में संयंत्र अदरक उत्पादकों को बहुत आवश्यक सुविधा देगा।
- वे अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करेंगे।

- गुवाहाटी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य प्रमुख शहरों में पूर्वोत्तर और फल कियोस्क में 100 नए नए रीटेल पॉइंट स्थापित करने की भी योजना है।
- इनमें से अधिकांश पीपीपी मोड में होंगे।

किसानों की मदद के लिए, सही दृष्टिकोण एफपीओ के माध्यम से है, एपीएमसी मंडियों के माध्यम से नहीं

संदर्भ: नए अधिनियमित कृषि बिल के खिलाफ किसानों द्वारा विरोध और इन कानूनों को निरस्त करने की उनकी मांग। हालांकि, सरकार आंदोलनकारी किसानों के साथ बातचीत करने और एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है

- भारतीय कृषि के बारे में बुनियादी तथ्य, जो किसान समुदाय के बड़े हित को लाभ पहुंचाने के एक सामान्य उद्देश्य के साथ दोनों पक्षों के वार्ताकारों की मदद कर सकते हैं।
- **निहित कराधान:** ICRIER के शोध के अनुसार, भारतीय कृषि पर इसके मूल्य का लगभग 14% लगाया गया। यह मुख्य रूप से प्रतिबंधात्मक व्यापार और विपणन नीतियों के कारण था, यह निर्यात नियंत्रण और स्टॉकिंग सीमा से लेकर प्रतिबंधात्मक मंडी प्रणाली तक पहुचेगा।
- **गलत आशंका:** इसके द्वारा किसानों की कीमत वसूली में सुधार करना था, इसलिए, इकृषि को विभिन्न नियंत्रणों से मुक्त करना था। लेकिन किसी भी तरह, एक डर पैदा हो गया है कि ये कृषि कानून एपीएमसी बाजारों, एमएसपी के किसानों को लूट लेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बड़े कॉरपोरेट घरानों उनकी जमीनें हड़प लेंगे।

प्राइवेट प्लेयर्स की भूमिका?

- इसमें कोई संदेह नहीं है कि एपीएमसी बाजार और एमएसपी का सामना निजी बाजारों और मंडी के एपीएमसी के लेनदेन से होगा।
- लेकिन अशोक गुलाटी जैसे कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतियोगिता से किसानों को बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी, खासकर छोटे और सीमांत लोग। अतिरिक्त 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और एक लाख करोड़ रुपये के एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के निर्माण से इस प्रक्रिया में मदद मिलेगी।
- लेकिन आंदोलनकारी किसानों में से कई को पंजाब और हरियाणा में गेहूं और धान पर मिलने वाले एमएसपी खोने का डर है।
- हालांकि, इन सभी वर्षों में 1965 में एमएसपी को केवल 6 प्रतिशत किसानों को दिया गया था और मोटे तौर पर कृषि उत्पादन के मूल्य का 6 प्रतिशत इस प्रणाली से लाभान्वित हुआ है
- एमएसपी और एपीएमसी प्रणाली मुख्य रूप से उन लोगों की मदद करती है जिनके पास बड़े अधिभार हैं, मुख्यतः बड़े किसान।
- यदि कोई वास्तव में छोटे और सीमांत किसानों की मदद करना चाहता है, तो सही दृष्टिकोण ग्रामीण स्तर पर एफपीओ के माध्यम से है, एपीएमसी मंडियों में नहीं। लगभग 86 प्रतिशत भारतीय किसान छोटे और सीमांत (2 हेक्टेयर से कम) हैं, जो देश में कुल संचालित क्षेत्र का लगभग 47 प्रतिशत है।

एमएसपी वैधानिक अधिकार और कानूनों को निरस्त करने की मांग करने वालों के बारे में क्या?

- निजी क्षेत्र पर भी MSP को वैधानिक रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए कहने से किसान विरोधी हो जाएगा क्योंकि निजी व्यापार इस तरह की व्यवस्था को खत्म कर देगा, जिससे अराजकता पैदा होगी। यह इन कानूनों को रद्द करने से भी बदतर होगा।

- इन कृषि कानूनों को निरस्त करना 90 प्रतिशत से अधिक किसानों को लूटने जैसा होगा - जिन्होंने कभी एमएसपी प्रणाली से लाभ नहीं लिया और जो बड़े पैमाने पर छोटे और सीमांत हैं - उनके अधिकारों का क्या?

इन बुनियादी तथ्यों को देखते हुए, हम आंदोलनकारी किसानों के डर को कैसे दूर करेंगे?

- सबसे पहले, सरकार को लिखित में देने के लिए तैयार होना चाहिए कि एपीएमसी बाजारों और एमएसपी की मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी और मजबूत होगी।
- दूसरा, सरकार यह भी लिखित में दे सकती है कि अनुबंध उपज के लिए होगा, भूमि के लिए नहीं।
- तीसरा, किसान विवादों को जिला अदालतों में ले जा सकते हैं, यदि वे चाहें।
- चौथा, इन लिखित आश्वासनों को जोड़ने के लिए, सरकार मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत 25,000 करोड़ रुपये का एक कोष बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध हो सकती है, जिसका उपयोग MSP के नीचे10 प्रतिशत से अधिक की कमी होने पर निर्दिष्ट वस्तुओं के बाजार मूल्यों का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है।
- यह दालों और तिलहनों के बाजार मूल्य, या कपास की कीमतों के लिए भारतीय कपास निगम (CCI) का समर्थन करने के लिए NAFED के संचालन के समान है, और इसे मक्का, मोती बाजरा, आदि तक बढ़ाया जा सकता है।
- पांचवां, अगर स्टॉक में बढ़ोतरी जारी रहती है, जैसा कि आज गेहूं और चावल के मामले में है, तो मांग और आपूर्ति में असंतुलन को ठीक करने के लिए, सरकार को या तो खरीद के आकार को सीमित करना चाहिए या कीमत की कमी के भुगतान के लिए जाना चाहिए। एक और सकारात्मक कदम पंजाब-हरियाणा बेल्ट के लिए विविधीकरण पैकेज की घोषणा करना होगा।

निष्कर्ष

- किसी को भी यह याद रखना चाहिए कि किसान हमेशा अपनी उपज के लिए अधिक मूल्य चाहते हैं, लेकिन उच्च खाद्य मूल्य भी गरीब उपभोक्ताओं को पीड़ा पहुंचा सकते हैं। नीति निर्धारण की कला उचित वित्तीय संसाधनों के भीतर उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित को संतुलित करना है।

कृषि के लिए सरकार के समर्थन की तुलना

संदर्भ: किसान विरोध पर जा रहा है, जबकि सरकार का तर्क है कि तीनों कृषि कानून भारत के कृषि क्षेत्र में बाजार सुधारों का एक तार्किक विस्तार हैं।

नए अधिनियमित कृषि बिल के खिलाफ किसानों का तर्क क्या हैं?

- **सामाजिक सुरक्षा खोने का डर:** विरोध करने वाले किसानों मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा से संबंधितउनमें एक डर है कि नए कृषि कानून और एमएसपी प्रणाली के कमजोर होने के आरोपों से किसानों को उनके पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा जाल को टूट जाएगा।
- **खेती को गिरावट के विकल्प के रूप में देखा जाता है:** किसान खेती को केवल एक "नौकरी" के रूप में नहीं देखते हैं, हम में से कई जो आधुनिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं उनके लिए, खेती भी गिरावट का विकल्प है जबकि अन्य उद्यम भी विफल होते हैं।
- **केवल आजीविका के रूप में खेती करना:** किसानों के लिए, खेती केवल उत्पादकता मेट्रिक्स के बारे में नहीं है; यह उनके लिए एक विकल्प के बारे में भी है कि वे एक जीवित, लेकिन अल्पाहार को बाहर निकाल सकते हैं, जब वे खुद को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों - उद्योग और सेवा क्षेत्र में भाग लेने में असमर्थ पाते हैं।

- शायद यह समझा जाता है कि दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश का दो-तिहाई हिस्सा ग्रामीण इलाकों में क्यों रहता है या भारत के सकल घरेलू उत्पाद में **15%** से कम योगदान देने के बावजूद कृषि भारत के लगभग आधे हिस्से **(44%)** को रोजगार देती है।

India

Indicator	2015	2016	2017	2018	2019	1986 - 2019
Total Support Estimate, % of GDP	1.10	0.11	0.66	0.15	0.39	
Producer Support Estimate, % of GFR	-3.6	-7.0	-3.3	-6.7	-5.0	
Nominal Protection Coefficient, Ratio	0.91	0.88	0.90	0.87	0.87	
Agriculture in GDP, %	16.2	16.2	15.6	14.6	—	
Agricultural employment, %	45.56	45.12	44.52	43.86	—	

क्या भारत सरकार अपने किसानों को अन्य देशों की तरह समर्थन प्रदान करती है?

- ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (या **OECD**) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, भारतीय किसानों को वास्तविक नुकसान होता है।
- सकल देशों में, **OECD** कृषि समर्थन के मुद्दे पर पांच सेट डेटा प्रदान करता है और यह भारत के लिए सबसे अधिक मायने रखता है।

निष्कर्ष

- पीएसई का नकारात्मक मूल्य दर्शाता है कि घरेलू उत्पादकों, कुल मिलाकर, अनुमानित रूप से कर लगाए जाते हैं, क्योंकि किसानों को बजटीय भुगतान जटिल घरेलू नियमों और व्यापार नीति उपायों के मूल्य में निराशाजनक प्रभाव को ऑफसेट नहीं करते हैं।
- उत्पादकों पर कृषि मूल्य-निराशाजनक प्रभाव को प्रतिबिंबित करते हुए, नीतियां उपभोक्ताओं को अंतर्निहित समर्थन प्रदान करती हैं।
- दूसरे शब्दों में, कई लोगों के बीच धारणा के विपरीत, सरकार ने भारतीय किसानों के ऊपर भारतीय उपभोक्ताओं के कल्याण को प्राथमिकता दी है।

गुणवत्तायुक्त धनिये के उत्पादन एवं इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ऑफ कोरिऐन्डर वेबिनार आयोजित

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -कृषि

समाचार में-

- भारतीय मसाला बोर्ड तथा डीबीटी-एसएबीसी बायोटेक किसान हब ने आईसीएआर-एनआरसीएसएस, आरएसएएमबी और कोटा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से गुणवत्तायुक्तधनिये केउत्पादन,फसल कटाई के बाद, मूल्य संवर्धन तथा भारत से

धनिये का निर्यात बढ़ाने पर वर्ल्ड ऑफ कोरिऐन्डर वेबिनार 4 जनवरी 2021 को आयोजित किया। इसमें विभिन्न राज्यों के एक सौ से अधिक महत्वपूर्ण हितधारकों ने भाग लिया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- दक्षिण पूर्व राजस्थान का हदोती क्षेत्र तथा मध्यप्रदेश का गुना जिला धनिया उत्पादन के लिए जाना जाता है और देश से धनिया के निर्यात में इनका महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- कोटा जिला की रामगंज एपीएमसी मंडी एशिया में धनिया की सबसे बड़ी मंडी है और इसे कोरिऐन्डर सिटी के रूप में जाना जाता है।
- हाल में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) की सूची में धनिया को कोटा जिले का उत्पाद माना है।

क्या आपको पता है?

- सामान्यतः इसके पत्तो का उपयोग सब्ज़ी की सजावट और ताज़े मसाले के रूप में किया जाता है।
- इसके बीज को सुखाकर सूखे मसाले की तरह प्रयोग किया जाता है।

छोटे किसानों को आय का दूसरा स्रोत

मुद्दे

- **किसानों की अधिकांश संख्या सीमांत है:** भारत के 70% किसानों के पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है और सीमांत भूमि जोत कम है।
- **अप्रतिबंधित आजीविका:** औसतन, छोटी जोत के पैसे कम हो जाते हैं क्योंकि उनकी घरेलू लागत उनकी कमाई से अधिक होती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के अनुसार, दो हेक्टेयर तक के किसानों की औसत आय 5,240 रुपये प्रति माह है
- **सीमान्त कृषि :** सबसे छोटे खेत तब से हैं जब तक वे श्रम के लिए भुगतान नहीं करते हैं, यह पूरी तरह से परिवार पर निर्भर हैं, और वे उत्पादित चीजों का अधिक उपभोग करते हैं।
- **अनियमित आय:** खेती एक मौसमी मामला है, न कि पूर्णकालिक नौकरी

खेत से लेकर कारखाने तक समय की जरूरत है

- **औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करना:** विशेष प्रोत्साहन प्रदान करके ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह एकमात्र कृषि-आधारित आय पर निर्भरता को कम करने के लिए एक अतिरिक्त आय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **अनकैप्ड पोटेंशियल:** अंशकालिक मौसमी खेती के अलावा, एक छोटे किसान और खेत मजदूर के पास काम करने के लिए पर्याप्त समय होता है और पास के एक कारखाने में आठ घंटे के श्रम के बाद आसानी से 12,000-15,000 रुपये प्रति माह कमा सकते हैं।

अध्ययन

- होशियारपुर के सोनालिका संयंत्र में 8,000 श्रमिकों में से 90% सीमांत किसान और आस-पास के गाँव के खेत मजदूर हैं।

- सीमांत किसानों और खेत मजदूरों के लिए रोजगार के साथ उद्योग को जोड़ने का इस मॉडल को पैन-इंडिया को प्रवर्तित किया जा सकता है, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में।

आगे की राह

- **निर्यात को बढ़ावा देना:** इन क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाने के लिए, रेलवे भाड़े में 50% की छूट प्रदान की जाती है क्योंकि ड्राई पोर्ट से माल ढुलाई सब्सिडी दी जा सकती है।
- **क्लस्टर दृष्टिकोण:** औद्योगिक गलियारों और समूहों को विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन की पेशकश की जा रही है, लेकिन इस मॉडल को ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में पास के छोटे और सीमांत किसानों और खेत मजदूरों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए दोहराया जाना चाहिए।
- **विकेंद्रीकृत माइक्रोएंटरप्राइज़ इकोसिस्टम:** एक वितरित, माइक्रो-लेवल फैक्ट्री जो सोलोप्रीनर्स और माइक्रो-एंटरप्राइजेज का उत्पादन कर सकती है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया और समर्थित किया जाना है। उदाहरण के लिए, शहरी मॉल में बिक्री के लिए सब्जियों का प्रसंस्करण और पैकेजिंग एक ऐसा सूक्ष्म उद्यम हो सकता है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश:** ग्रामीण भारत में नई नौकरियां प्रदान करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन के साथ नए औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना। छोटे, सीमांत किसानों और खेत मजदूरों को आस-पास के क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना ग्रामीण-से-शहरी प्रवास को कम करेगा

निष्कर्ष

- केंद्रीय संशोधित कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में जमीनी सुधारों में अधिक समय लगेगा लेकिन यह ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में छोटे, सीमांत किसानों और खेत मजदूरों के लिए एक नौकरी के इंजन के रूप में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नीति और रूपरेखा का समय है।
- यह ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में निवास करने वाली देश की 60% से अधिक आबादी को कवर करने, सब का विकास (सब के लिए प्रगति) का वास्तविक निष्पादन होगा।

Connecting the dots

- New Farms Laws and Opposition to it: Click Here

असम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एरी सिल्क प्रदान किया जाएगा

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I - भूगोल और GS- III - कृषि

समाचार में-

- असम में उत्पादित सिल्क की एक किस्म 'एरी' से बने खादी शर्ट, और शॉल और स्टोल इस महीने से चरणबद्ध तरीके से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रदान करने का फैसला किया

महत्वपूर्ण तथ्य

- एरी रेशम सामिया रिकिनी के कैटरपिलर से आता है।
- यह पूर्वोत्तर भारत और चीन, जापान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।

- "एरी" नाम असमिया शब्द "एरा" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "अरंडी", जैसा कि रेशम के कीड़े अरंडी के पौधों पर पाए जाते हैं।
- एरी सिल्क को भारत में एंडी या इरंडी के रूप में भी जाना जाता है।
- ऊनी सफेद रेशम को अक्सर शांति के कपड़े के रूप में जाना जाता है जब इसे रेशमकीट को मारे के बिना संसाधित किया जाता है।
- इस प्रक्रिया से अहिंसा रेशम नामक रेशम निकलता है।
- पतंगे कोकून छोड़ देते हैं और फिर कोकून को काता जाता है।
- एर्बी रेशमकीट, बॉम्बेक्स मोरी के अलावा एकमात्र पूरी तरह से घरेलू रेशम कीट है।

क्या आपको पता है?

- भारत को दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होने का गौरव प्राप्त है जो सभी पाँच प्रमुख प्रकार के रेशम को दो श्रेणियों में विभाजित करता है:
- **शहतूत रेशम**: मुख्य रूप से कर्नाटक में
- **गैर-शहतूत रेशम**: महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश में शीतोष्ण तुषार रेशम; उप-हिमालयी बेल्ट (मणिपुर, असम, मेघालय, आदि) में उष्णकटिबंधीय तुषार रेशम; असम में मुगा सिल्क और असम, ओडिशा, बिहार में एरी सिल्क

Related articles:

- Types of silk and challenges of India's silk industry: Click here

---

कृषि कानून, उनकी संवैधानिक वैधता, और उम्मीद

संदर्भ: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नए कृषि कानूनों के संचालन और सरकार और किसानों के साथ बातचीत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया।

Why farmers are protesting against farm laws: Click here and here

Why earlier government negotiations have failed: Click here

What is the long term solution advocated by experts: Click here

समिति गठित करने के SC के निर्णय से किसानों की क्या प्रतिक्रिया रही है?

- किसानों की यूनियनों ने विशेषज्ञों की समिति के गठन के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी है।
- उनका आरोप है कि समिति में पूरी तरह से निष्पक्ष विशेषज्ञ शामिल नहीं हैं। उनमें से ज्यादातर कृषि कानूनों के जाने-माने और मजबूत रक्षक हैं, और आंदोलन के आलोचक हैं।
- इस प्रकार, किसानों द्वारा किया जा रहा आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है।

SC के निर्णय का महत्वपूर्ण विश्लेषण

- **पार्टियों का विश्वास हासिल करना समिति के लिए चुनौती:** सरकार और किसानों दोनों के साथ बातचीत करने के लिए, समिति के सदस्यों को मुख्य मुद्दों पर खुले दिमाग से विचार करना चाहिए, जो अकेले ही संबंधित पक्षों में एक आवश्यक विश्वास पैदा करेगा।
- **किसानों की स्थिति:** किसानों ने यह स्पष्ट किया है कि वे इन कानूनों के निरसन से कम पर सहमत नहीं होंगे। इसका मतलब यह होगा कि वर्तमान आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना है।
- **SC का निर्णय अस्पष्ट है:** यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इस समिति की रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए विशेषज्ञों की समिति जो भी सिफारिश करती है, कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता का सवाल न्यायालय के समक्ष मामले की उचित सुनवाई के बाद ही तय किया जा सकता है।
- **सत्तारूढ़ दल द्वारा राजनीतिक निवेश:** जबकि एक कानून का निरसन एक साधारण विधायी कार्य है, एक कानून को निरस्त करना जिसमें सरकार ने अपनी प्रतिष्ठा का बहुत अधिक निवेश किया है, इतना आसान नहीं है।

किस आधार पर कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है?

1. संघवाद का उल्लंघन

- कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि संसद के पास इन कानूनों को लागू करने के लिए कोई विधायी क्षमता नहीं है, जिसका विषय अनिवार्य रूप से राज्य सूची में है।

2. सदन के नियमों का उल्लंघन

- यह सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि राज्य सभा में कृषि विधेयकों पर मतदान सदन के नियमों के अनुसार नहीं किया गया था।
- इन नियमों के लिए अध्यक्ष को सदस्यों द्वारा वोट (विभाजन) की रिकॉर्डिंग का आदेश देने की आवश्यकता होती है, यदि कोई सदस्य इसकी मांग करता है।
- सदन के उपाध्यक्ष, जो उस समय कार्यवाही का संचालन कर रहे थे, ने विभाजन का आदेश नहीं दिया, हालांकि कुछ सदस्यों ने खुले तौर पर और जोर से इसकी मांग की।
- इस प्रकार, विभाजन की मांग होने पर ध्वनि मत से विधेयकों को पारित करने में सदन के नियमों का उल्लंघन हुआ।

3. विधेयक पारित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं के संबंध में संविधान का उल्लंघन

- अनुच्छेद 100 कहता है कि किसी भी सदन के किसी भी बैठक में सभी प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्धारित किए जाएंगे।
- बहुमत केवल संख्या के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है, और इसलिए इस अनुच्छेद की आवश्यकता है कि सदन में सभी प्रश्न उपस्थित सदस्यों के वोट रिकॉर्ड करके और मतदान करके निर्धारित किए जाएं।
- ध्वनि मत के माध्यम से बहुमत निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, संविधान एक विधायिका में बहुमत निर्धारित करने के लिए ध्वनि मत को मान्यता नहीं देता है।
- हालांकि, ध्वनि मत द्वारा प्रश्न तय करना सभी विधानसभाओं में प्रचलित है। यह सुविधा के लिए तैयार किया गया था और हमेशा एक धारणा है कि चूंकि सरकार के पास बहुमत है, इसलिए सदन के समक्ष किसी भी प्रस्ताव को बहुमत का समर्थन प्राप्त है।

- लेकिन यह धारणा तब चलती है जब कोई सदस्य सदन में मतदान की मांग करता है और अध्यक्ष के पास वास्तविक मतदान का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। चूंकि यह नहीं किया गया था और बिलों को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था, इसलिए नियमों के साथ-साथ यह संविधान का भी उल्लंघन है (अनुच्छेद **100**)

उच्चतम न्यायालय के समक्ष क्या विकल्प हैं?

1. अनुच्छेद 100 और 107 के उल्लंघन पर कानूनों को कम करना

- न्यायालय पूरे कानूनों को रद्द कर सकता है क्योंकि अनुच्छेद **107** की आवश्यकता पूरी नहीं हुई है। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी विधेयक को तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि दोनों सदनों द्वारा इस पर सहमति नहीं बन जाती।
- जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, विधेयकों को वास्तव में राज्य सभा द्वारा पारित नहीं किया गया है क्योंकि अनुच्छेद **100** के अनुसार बहुमत निर्धारित नहीं किया गया था।

2. राज्यसभा की कार्यवाही को अमान्य करना

- न्यायालय राज्य सभा की कार्यवाही को भी अमान्य कर सकता है और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए तीन अधिनियमों को उस सदन में वापस भेज सकता है।
- यदि ऐसा होता है, तो यह सरकार को इन कानूनों को फिर से प्रस्तुत करने का एक अच्छा अवसर प्रदान कर सकता है।
- इन्हें फिर राज्य सभा की एक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है जो किसानों और अन्य सभी हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है और अंत में बेहतर बिल का निर्माण कर सकती है।

निष्कर्ष

- शीर्ष अदालत द्वारा जिस मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए वह कानूनों की संवैधानिक वैधता है और कानून और संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का पालन है।

ज्वार निर्यातकों के साथ वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - कृषि

समाचार में-

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण **(APEDA),** आंध्र प्रदेश सूखा शमन परियोजना **(APDMP)** के सहयोग से ज्वार निर्यातकों तथा ज्वार के एफपीओ के साथ मिलकर मार्केटिंग संपर्क स्थापित करने के लिए वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया।
- ज्वार तथा ज्वार उत्पाद निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार करते हुए और पौष्टिक अनाजों में ज्वार के विकास पर सरकार के फोकस को देखते हुए एपीईडीए **5** वर्षों के लिए ज्वार तथा ज्वार उत्पादों के प्रोत्साहन के उद्देश्य से भारतीय ज्वार अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) तथा राष्ट्रीय पौष्टिकता संस्थान, सीएफटीआरआई तथा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) जैसे अन्य हितधारकों के साथ घनिष्ठता से काम कर रहा है।
- इस प्लेटफार्म ने निर्यातकों और एफपीओ को उत्पादों की सप्लाई और प्राप्ति के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने का अवसर प्रदान किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ज्वार पौष्टिक अनाज है और इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी, छोटा ज्वार, कंगनी, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोदो तथा अन्य ज्वार आते हैं और इनका पौष्टिक महत्व अधिक होता है।
- ये उच्च पोषक मूल्य के लिए जाने जाते हैं।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिल्ट्स रिसर्च (IIMR)

- यह एक कृषि अनुसंधान संस्थान है जो बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान में लगा हुआ है।
- यह राजेंद्रनगर (हैदराबाद, तेलंगाना) में स्थित है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तत्वावधान में आईआईएमआर संचालित होता है।
- इसकी स्थापना **1958** में कपास, तिलहन और बाजरा **(PIRCOM)** पर गहन अनुसंधान परियोजना के तहत की गई थी।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

- यह कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, यह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक सर्वोच्च निकाय है।
- **APEDA** की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत दिसंबर **1985** में संसद द्वारा पारित की गई थी।

एपीडा के कुछ कार्य इस प्रकार हैं:

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। अनुसूचित उत्पादों के निर्यात उन्मुख उत्पादन और विकास को बढ़ावा देना।
- भारत के बाहर अनुसूचित उत्पादों के लिए पैकेजिंग, विपणन जैसे कई क्षेत्रों में सुधार करना।
- निर्यात के उद्देश्य से अनुसूचित उत्पादों के लिए मानक और विनिर्देश स्थापित करना।
- संबंधित उद्योगों को वित्तीय सहायता, राहत और सब्सिडी।
- संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए

Related articles:

- Export of Moringa powder: Click here
- Kiwis of Ziro Valley: Click here

केन्या के कृषि प्रयोग से सबक

संदर्भ: नए कृषि कानूनों पर बहस में, ऐसी चिंता व्यक्त की गयी है कि छोटे किसानों को बड़े कृषि-व्यवसायों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है।

Why farmers are protesting against farm laws: Click here and here
Why earlier government negotiations have failed: Click here
What is the long term solution advocated by experts: Click here

वाद-विवाद में कमी

- **प्रेडिक्टिबिलिटी फैक्टर:** नए कानूनों में ज्यादातर अप्रयुक्त नीतियां शामिल हैं और यह लागू करना मुश्किल है कि जब वे लागू हों तो क्या हो सकता है
- **अंतर्राष्ट्रीय मॉडल:** आश्चर्य की बात यह है कि कृषि-व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर नीतियों को लागू करने वाले देशों से सीखे गए पाठों पर बहुत कम चर्चा हुई है।
- **आंकड़ों की कमी:** 1980 और 1990 के दशक में बाजार उन्मुख नीतियों के आगमन के बाद से, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कई सरकारें निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि बाजारों को नियंत्रित करने से दूर चली गईं। किसान-खरीदार रिश्तों पर डेटा की कमी और कृषि नीतियों में जाने वाले कई खंडों को निर्धारित करने की जटिलता के कारण उन नीतियों का मूल्यांकन मुश्किल हो गया है।
- लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) के हालिया शोध ने केन्या से उच्च-गुणवत्ता वाले किसान-खरीदार डेटा के एक दशक की अवधि में इन बाधाओं को दूर किया, जब इसने कृषि-व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए कट्टरपंथी कृषि कानूनों की शुरुआत की।

केन्या का कृषि-प्रयोग

- बहुत कुछ उसी तरह जैसे कि भारतवासी अब कर रहे हैं, केन्याई सरकार ने इस अपेक्षा के साथ नए कानून पेश किए कि इस तरह के व्यवसायों के उदय से छोटे धारक कृषि बेहतर बनेंगे।
- फसल बाजारों में कृषि-व्यवसाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कानून के **20** से अधिक टुकड़ों को निरस्त किया गया, जो कि छोटे कृषि आय का **70%** से अधिक था।
- कृषि-व्यवसायों के उदय पर इसका अपेक्षित प्रभाव पड़ा। खेत के खरीदारों के रूप में उनके (निजी खिलाड़ियों) समग्र बाजार में हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो गई, जो **2010** तक **38%** तक पहुंच गई।

क्या केन्या का प्रयोग बिना किसी दोष के था?

- **लंबे समय का अनुभव कड़वा था:** नीति के लागू होने के तुरंत बाद, छोटे किसानों को इन फसलों को कृषि-व्यवसायों को बेचने की अधिक संभावना हो गई, खासकर उन क्षेत्रों में जो कृषि-पारिस्थितिक स्थितियों के कारण इन फसलों पर अधिक निर्भर थे। लेकिन, पांच साल बाद, कई ने इन व्यवसायों को बेचना बंद कर दिया था।
- इन फसलों से कृषि आय में गिरावट आई थी। कृषि व्यवसाय पर भरोसा करने वाले किसानों ने अपनी आय में औसतन 6% की गिरावट देखी। उन्होंने अपने दैनिक उपभोग को बनाए रखने के लिए घरेलू संपत्ति बेचनी पड़ी

केन्या में कृषि-व्यवसायों ने लंबे समय में अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं दिए?

- **कीमत पर बाजार में हिस्सेदारी का प्रारंभिक लाभ:** केन्याई किसानों को कृषि-व्यवसायों को बेचने से उत्पादकता लाभ देखने की उम्मीद थी, जिसने शुरुआत में अन्य खरीदारों की कीमत पर बाजार हिस्सेदारी हासिल की। व्यापार करने में आसानी खरीद और विपणन में वृद्धि हुई। हालांकि, लंबे समय में, उत्पादकता में बहुत वृद्धि नहीं हुई और फलस्वरूप किसानों की आय भी गिर गई।
- **कृषि-व्यवसायों को अधिक लाभ की आवश्यकता थी:** जैसे-जैसे कृषि-व्यवसाय इन नई गतिविधियों में आगे बढ़े, निवेश की अधिकता बढ़ेगी और इसलिए उन्हें वित्त देने के लिए अधिक लाभप्रदता की आवश्यकता थी। इससे छोटे किसानों को किए गए भुगतान और इस तरह उनकी आय पर असर पड़ा।

- **समय के साथ कम खरीदार:** किसानों को बड़े कृषि-व्यवसायों का सामना करना शुरू हुआ, जिन्होंने औसतन, अपने लाभ मार्जिन में **5%** की वृद्धि देखी। जबकि कुछ किसान अपने कृषि-व्यवसाय संबंधों को छोड़ने में सक्षम थे, कई फसल बाजारों में बड़े और कम खरीदारों का सामना कर रहे थे।
- **केन्याई सरकार द्वारा सीखे गए प्रमुख सबक: 2010** में अपनी संशोधित कृषि रणनीति में, केन्याई नीति निर्माताओं ने इस बात पर विचार किया कि छोटे किसानों को कैसे नुकसान हो सकता है जब व्यापार करने में आसानी उन बाजारों में होती है, जहां "कोई महत्वपूर्ण द्रव्यमान नहीं है और निजी क्षेत्र के बढ़ने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है"।

निष्कर्ष

- केन्याई अनुभव बताता है कि बड़े पैमाने पर अप्रशिक्षित नीतियों के साथ क्या गलत हो सकता है और कठिनाई से बचने के लिए किन प्रावधानों का होना आवश्यक है।
- बेशक, यह कहना नहीं है कि भारत के पास एक ही अनुभव होगा। केन्या की तुलना में भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में निश्चित रूप से एक बेहतर आर्थिक स्थिति में है।
- लेकिन छोटे उत्पादकों की कृषि में कई सामान्य समस्याएं हैं, जैसे कम उत्पादकता, निवेश और बाजार पहुंच, जो पूरे भारत में कृषि आय को कम रखते हैं।

राजस्थान में पोटाश के समाधान खनन की व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - विज्ञान और तकनीक; कृषि

समाचार में-

- खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड **(MECL),** राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड **(RSMML)** और खान एवं भूविज्ञान विभाग **(DMG),** सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

महत्वपूर्ण बिंदु

- राजस्थान के नागौर और उत्तर पश्चिम में गंगानगर बेसिन में **50,000** वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विशाल पोटाश और हैलाइट संसाधन प्राप्त हुए हैं-
- भूमिगत नमक भंडारण, हाइड्रोजन, अमोनिया और हीलियम गैस के लिए रिपोजिटरी, कम्प्रेसर गैस और परमाणु कचरे के भंडारण के लिए बेडल्ड साल्ट फॉर्मेशन रणनीतिक रूप से बहुत उपयोगी हैं।
- पोटाश और सोडियम क्लोराइड क्रमशः उर्वरक उद्योग और रासायनिक उद्योग में बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं।
- देश में पहली समाधान खनन परियोजना का मार्ग प्रशस्त होने से यह परियोजना रोजगार उत्पन्नकरेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- पोटाश में विभिन्न खनन और निर्मित लवण शामिल होते हैं जिनमें पानी में घुलनशील रूप में पोटेशियम होता है।
- यह नाम पॉट की राख से निकला है, जो एक बर्तन में पानी में भिगोए गए राख या लकड़ी के बुरादे को संदर्भित करता है, जो औद्योगिक युग से पहले उत्पाद के निर्माण का प्राथमिक साधन था।
- पोटाश का उत्पादन दुनिया भर में ज्यादातर उर्वरक में उपयोग के लिए किया जाता है।

सीसीईए वर्ष 2021 के लिए कोपरा के एमएसपी के लिए अपनी मंजूरी देता है

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -कृषि

समाचार में-

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने **2021** के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य **(MSP)** के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- नारियल का उत्पादन करने वाले राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघलिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारीउपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) एमएसपीक्रियान्वन के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करते रहेंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED)

- यह भारत में कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों का एक सर्वोच्च संगठन है।
- इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी।
- यह बहु-राज्य सहकारी समितियों अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत है।
- NAFED अब भारत में कृषि उत्पादों के लिए सबसे बड़ी खरीद के साथ-साथ विपणन एजेंसियों में से एक है।
- उद्देश्य: (1) कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को व्यवस्थित, बढ़ावा और विकसित करना; (2) कृषि मशीनरी, औजार और अन्य इनपुट वितरित करने के लिए; (3) कृषि उत्पादन में तकनीकी सलाह के लिए कार्य करना और सहायता करना

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21: कृषि

- आर्थिक सर्वेक्षण, **2020-21** के अनुसार, कृषि और संबद्ध गतिविधियों ने **2020-21** के दौरान निरंतर कीमतों पर **3.4%** की वृद्धि दर्ज की।

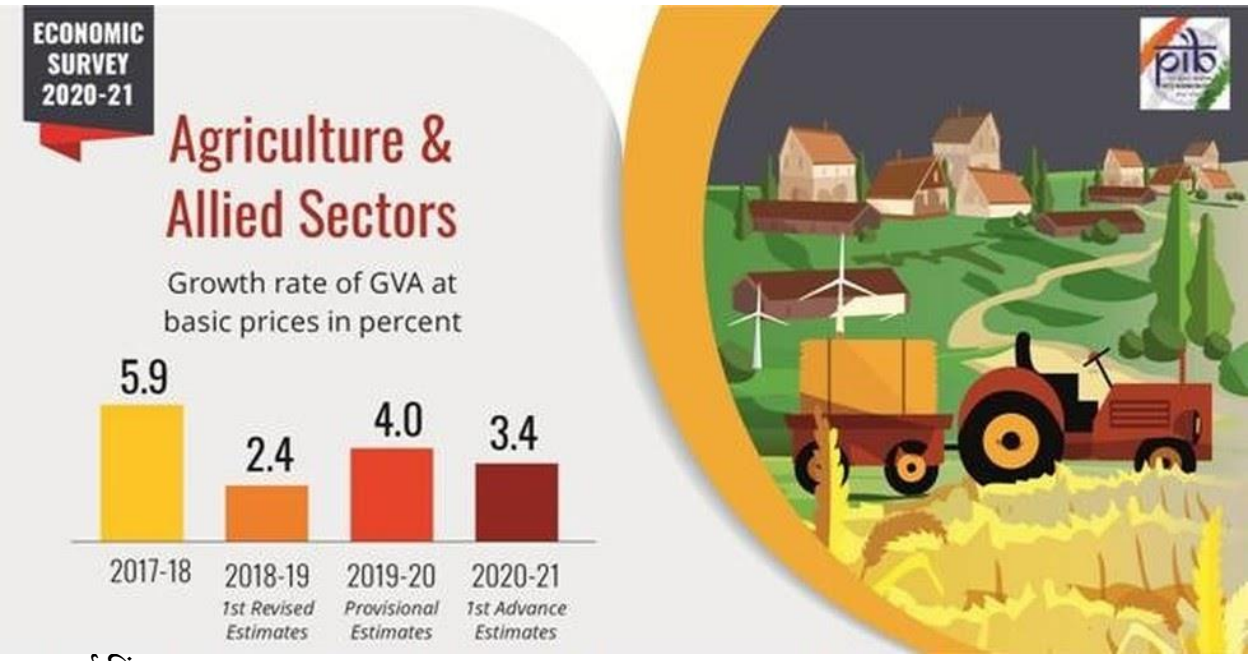

महत्वपूर्ण बिंदु

- 29 मई, 2020 को CSO द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वर्तमान मूल्य पर देश के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्ष 201-20-20 के लिए 17.8% है।
- कृषि वर्ष 2019-20 (चौथा अग्रिम अनुमान के अनुसार), देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 296.65 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2018 के दौरान प्राप्त 285.21 मिलियन टन के खाद्यान्न के उत्पादन की तुलना में 11.44 मिलियन टन अधिक है।
- 2019-20 में, प्रमुख कृषि और संबद्ध निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश थे।
- भारत से निर्यात किए जाने वाले शीर्ष कृषि और संबंधित उत्पाद समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसाले, गैर-बासमती चावल, कपास कच्चे, तेल भोजन, चीनी, अरंडी का तेल और चाय थे।
- पशुधन क्षेत्र ने 2018-19 में कुल जीवीए का 4.19% योगदान दिया।
- 2018-19 के अंत में पिछले 5 वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (FPI) क्षेत्र लगभग 9.99% की औसत वार्षिक विकास दर (AAGR) से बढ़ रहा है, जबकि कृषि में लगभग 3.12% और 2011 में विनिर्माण में 8.25% था।

पर्यावरण/प्रदूषण

अपशिष्ट प्रबंधन: भारत के उत्तर पूर्व में शासन में सुधार

संदर्भ: उत्तर पूर्व भारत उगते सूरज की भूमि है और इसमें ताजे जल स्रोतों की प्रचुरता है। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं रह सकता है।

उत्तर पूर्व भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे

- **पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का अभाव:** विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है, यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट और नागांव को भी स्पर्श है। फिर भी, इनमें से किसी भी स्थान पर अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली या अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र नहीं है।
- **नदी का प्रदूषण**: उत्तर पूर्व में कम से कम 85 प्रतिशत कचरा बिना प्रसंस्करण उपचार के बिना डंप किया जाता है। भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में कई डंपसाइट आर्द्रभूमि या नदी के किनारे स्थित हैं।
- **अप्रयुक्त रोजगार सृजन क्षमता:** यदि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को लागू करता है, तो इन शहरों में 12,000 से अधिक रोजगार सृजित किये जा सकते हैं। यदि सभी गाँवों तक विस्तारित किया जाए, तो डोर-टू-डोर संग्रह, खाद और पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला से संबंधित लगभग 40,000 नौकरियों का सृजन किया जा सकता है।
- अपर्याप्त क्षमताएं: उत्तर पूर्व में नगरपालिकाओं में तकनीकी जानकारी का अभाव है। स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों से राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी भी है। कुछ कर्मचारियों के सदस्यों के पास पर्याप्त प्रशिक्षण और जोखिम की कमी होती है। अधिकांश प्रशिक्षण आयुक्तों और इंजीनियरों के लिए आयोजित किए जाते हैं, लेकिन संग्रह कर्मचारियों या सैनिटरी पर्यवेक्षकों के लिए शायद ही कभी।

आगे की राह

- **मजबूत प्रतिबद्धता:** यदि हम भारत के शीर्ष पांच सबसे स्वच्छ शहरों को देखते हैं, तो क्या उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें धन प्राप्त हुआ बल्कि इसलिए कि संबंधित लोगों और अधिकारियों द्वारा मजबूत प्रतिबद्धता थी।
- **प्रौद्योगिकी का बड़ा खर्च करने के बजाय समुदाय को शामिल करना:** भारत के लिए समाधान मौजूदा प्रणाली को मजबूत करने और संग्रह एवंम रीसाइक्लिंग में अनौपचारिक क्षेत्र को एकीकृत करने में निहित है। अनौपचारिक क्षेत्र थोड़े से निवेश के साथ **60** प्रतिशत से अधिक अकार्बनिक कचरे को डंपसाइट से निकाल सकता है और रीसाइक्लिंग के माध्यम से अधिक ऊर्जा बचा सकता है।
- **छोटी कंपनियों को प्रोत्साहित करना:** देश के सबसे स्वच्छ शहरों मे से कोई भी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बड़ी कंपनियों को नियुक्त नहीं करता है। बल्कि, वे अच्छे स्थानीय खिलाड़ियों पर निर्भर थे, जिनमें महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह, अपशिष्ट बीनने वाली सहकारी समितियाँ या स्थानीय गैर-लाभकारी और छोटे ठेकेदार भी शामिल थे।
- **अपशिष्ट अलगाव कानूनों का प्रवर्तन:** नगरपालिका के उपनियमों की कमी या कूड़े और गैर-अलगाव के संबंध में दंड का प्रवर्तन अपशिष्ट शासन घाटे के दो सबसे खराब रूप हैं। यदि अधिकारी इसे लागू नहीं करते हैं, तो शहरों को लंबे समय तक साफ नहीं रखा जा सकता है।
- **प्रदान की गई सेवाओं के लिए फीस जमा करना:** यह महत्वपूर्ण है कि लोगों को सेवाओं के लिए भुगतान करना सीखना चाहिए। अपशिष्ट सेवाओं के लिए भुगतान का प्रावधान कानूनों में है, लेकिन नेताओं द्वारा आपत्तियों के कारण इसे लागू नहीं किया जाता है। सर्वेक्षण का सुझाव है कि अगर प्रणाली सही हैं तो लोग अपने कचरे को अलग कर देंगे

- **प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम करना:** स्वच्छ शहरों और भ्रष्टाचार मुक्त शहरों के बीच एक सीधा संबंध है। जैसे: दुनिया के शीर्ष **10** सबसे स्वच्छ शहरों: कैलगरी, होनुलुलु, हेलसिंकी, कोबे, ओस्लो, एडिलेड, ब्रिसबेन, वेलिंगटन आदि भ्रष्टाचार सूचकांक में निम्न स्तर पर है।

निष्कर्ष

- उत्तर पूर्व भारत को नगरपालिका प्रणालियों के निचले कर्मचारियों की निर्माण क्षमता के साथ-साथ अपने नगरपालिका शासन में सुधार करने की आवश्यकता है। स्वच्छ भारत मिशन तब तक सफल नहीं होगा जब तक हमें प्रशासन से प्रतिबद्धता दिखाई नहीं देती।

2021 में जलवायु परिवर्तन और भारत

मुद्दे

- **जलवायु जोखिमों के लिए उच्च भेद्यता:** भारत में 75% जिले, आधी से अधिक आबादी के लिए घर, अत्यधिक जलवायु जोखिमों की चपेट में थे। पिछले दो दशकों में सूखा प्रभावित जिले औसतन 13 गुना बढ़े हैं। चक्रवातों की आवृत्ति भी दोगुनी हो गई है।
- **चरम जलवायु घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि:** जबकि भारत ने 1970 और 2005 के बीच 250 चरम जलवायु घटनाओं को देखा, देश ने अकेले 2005 तक 310 चरम जलवायु घटनाओं को दर्ज किया।
- **वित्तीय घाटा:** 1990 और 2019 के बीच, भारत ने100 बिलियन $ से अधिक का नुकसान उठाया।
- चरम जलवायु घटनाओं की बढ़ी हुई तीव्रता: बाढ़ की तीव्रता में आठ गुना वृद्धि हुई और इससे जुड़ी घटनाओं जैसे कि भूस्खलन और भारी वर्षा में 1970 के बाद से 20 गुना की वृद्धि हुई।
- **स्वैपिंग ट्रेंड:** 40% से अधिक भारतीय जिले अब एक अदला-बदली की प्रवृत्ति दिखाते हैं: बाढ़-प्रवण क्षेत्र सूखाग्रस्त होते जा रहे हैं। भारत को चरम जलवायु घटनाओं के खिलाफ अपनी लचीलापन और अनुकूली क्षमता बढ़ाने के लिए 2021 में कदम उठाने चाहिए
- **केंद्रित मिशन:** भारत को आपातकालीन तैयारियों को बढ़ाने, महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित करने और अत्यधिक जलवायु घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता का मुकाबला करने के लिए लचीला बुनियादी ढांचे और शासन प्रणालियों का निर्माण करने के लिए एक पर्यावरण और स्वास्थ्य डी-रिस्किंग मिशन बनाना चाहिए।
- **विकेंद्रीकरण:** राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय और जिला आपदा और जलवायु योजनाओं में जोखिम अनुमानों को एकीकृत करने के साथ स्थानीय जलवायु-संबंधी और मौसम संबंधी आंकड़ों के लोकतंत्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करना।
- **स्वदेशी समुदायों पर ध्यान दें:** पुनर्स्थापना, पुनरुद्धार, और पारंपरिक जलवायु-लचीली प्रथाओं का पुनर्मिलन, स्वदेशी समुदायों पर विशेष ध्यान देने के साथ, अक्सर पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण की अग्रिम पंक्तियों पर है।

- **व्यापक जलवायु जोखिम एटलस का निर्माण:** इस एटलस के माध्यम से चरम जलवायु घटनाओं के खिलाफ बेहतर तैयारी के लिए पुरानी और तीव्र जोखिमों की पहचान, आकलन और परियोजना का निर्माण करना चाहिए। एटलस समुदायों और व्यापार की लचीलापन और अनुकूलन क्षमताओं का आकलन करने और नीति-निर्माताओं के लिए जोखिम-सूचित निर्णय लेने वाले टूलकिट के रूप में कार्य करने में भी मदद करेगा। यह जलवायु-प्रूफिंग महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में मदद करेगा।
- **वित्तपोषण उपकरण :** पैमाने पर जलवायु कार्रवाई को वित्त करने के लिए, जोखिम वित्तपोषण उपकरण और जोखिम प्रतिधारण और पहचान उपकरण को ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे आकस्मिकता और अनुकूलन निधि द्वारा पूरक होना चाहिए। यह सार्वजनिक वित्त पूल को बढ़ाएगा और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं और लचीले सामुदायिक कार्यों पर निवेश जुटाने से जोखिम वाले क्षेत्रों में कुशल आवंटन को बढ़ाएगा।

Connecting the dots

- Paris Climate Deal
- Do you think COVID-19 has enhanced environmental consciousness of the world?

दीपोर बील में सामुदायिक मछली पकड़ने की मनाही

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - पर्यावरण; जैव विविधता

समाचार में-

- कामरूप (महानगर) जिला प्रशासन ने दीपोर बील में सामुदायिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- यह गुवाहाटी के दक्षिण-पश्चिमी किनारे पर स्थित एक आर्द्रभूमि है।
- यह असम का एकमात्र रामसर साइट है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- वेटलैंड में और उसके आसपास मछली पकड़ने, खुदाई और निर्माण को रोकने के लिए यह आदेश आवश्यक था जो वर्षों से सिकुड़ रहा है।
- दीपोर बील को **2002** में पक्षियों की **219** प्रजातियों के अलावा जलीय जीवन रूपों की एक श्रृंखला को बनाए रखने के लिए रामसर साइट नामित किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य

रामसर कन्वेंशन

- यह **2** फरवरी, **1971** को हस्ताक्षरित किया गया था।
- यह सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित सबसे पुराने अंतर-सरकारी समझौते में से एक है।
- उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उनके आर्द्र क्षेत्रों के पारिस्थितिक चरित्र को संरक्षित करना।
- इसका नाम ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, जहां संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- इसके अंतर्गत संरक्षण के लिए चुनी गई जगहों को 'रामसर साइट' का टैग दिया गया है।

- **रामसर सूची का उद्देश्य:** आर्द्रभूमि के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और बनाए रखना जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और उनके पारिस्थितिक तंत्र के घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Related articles:

- Other recently added Ramsar sites: Click here

1901 से 2020 तक यह 8 वां सबसे गर्म वर्ष था

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - जलवायु

समाचार में-

- भारत की जलवायु पर हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग **(IMD)** द्वारा एक बयान जारी किया गया था।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि 1901 के बाद से 2020 आठवां सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा लेकिन 2016 की सबसे अधिक गर्मी की तुलना में यह "काफी कम" रहा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 1901-2020 के दौरान देश में औसत वार्षिक तापमान सामान्य में 0.62 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई। विभाग ने 2020 के दौरान भारत की जलवायु संबंधी एक बयान में कहा कि वर्ष के दौरान देश में औसत वार्षिक तापमान सामान्य से 0.29 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यह आंकड़ा 1981-2010 के आंकड़ों पर आधारित है।
- आईएमडी के अनुसार रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा गर्म पांच वर्षों का क्रम इस प्रकार रहा- 2016, 2009, 2017, 2010 और 2015।
- हालांकि 2020 के सबसे गर्म साल होने पर अलग-अलग संस्थाओं की अलग-अलग राय है। कैलीफोर्निया के ब्रेकथ्रू इंस्टीट्यूट के क्लाइमेट साइंटिस्ट जेके हॉसफादर का कहना है कि यह एक मामले में उल्लेखनीय है कि साल 2020 के ली नीना साल और 2016 सुपर इल नीनो घटना थी।
- उनका कहना है कि 2016 वाला साल 2.22 डिग्री फॉरेन्हाइट ज्यादा था। जबकि दूसरा गर्म साल 2019, 2.16 डिग्री गर्म था। अभी तक सबसे ज्यादा गर्म साल 2016 बताया जाता है और वातावरण में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता अभी और बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि 2020 जैसे आगे भी खतरनाक तूफान, जंगलों में आग, कम ठंडी और ज्यादा गर्मी जैसी घटनाएं होती रहेंगी।

यमुना नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का किया गया गठन

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - पर्यावरण; प्रदूषण

समाचार में-

- हाल ही में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने यमुना नदी में बार-बार अमोनिया नाइट्रोजन में बढ़ोतरी के मुद्दे और अल्पकालिक व दीर्घकालिक सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की।
- उद्देश्य: यमुना नदी में अमोनिया नाइट्रोजन में वृद्धि के आवर्ती मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और छोटी एवं लंबी अवधि के उपचारात्मक कार्यों की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, डेजेबी, डीपीसीसी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली, एचएसपीसीबी और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा की भागीदारी वाले एक संयुक्त निगरानी समूह के गठन पर भी सहमति बन गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पहचान किए गए मुद्दे पर लंबे विचार-विमर्श और संभव कारणों से सहमत हो सकते हैं: (1) हरियाणा के नदी किनारे के शहरों से बिना शोधित किए दूषित जल का उत्सर्जन; (2) औद्योगिक इकाइयों, सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) और सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) से उत्सर्जन; (3) बाहरी दिल्ली में टैंकरों के माध्यम से बिना सीवर वाली कॉलोनियों से सीवेज का अवैध उत्सर्जन; (4) यमुना नदी के प्रवाह में कमी और नदी के तल पर जमा कीचड़ का अवायवीय अपघटन।
- अध्ययन करने वाले समूह में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली को शामिल किया गया है।
- यह समूह निगरानी व्यवस्था की एक समान समीक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता, पुराने आंकड़ों के विश्लेषण और प्रमुख स्थलों के साथ साथ ज्यादा अमोनिया के स्तर की अवधि की पहचान के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण का काम करेगा।
- समूह से टिकाऊ समाधान के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय सुझाने और एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया है।

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन

- अमोनियाकल नाइट्रोजन **(NH3-N)** अमोनिया की मात्रा के लिए एक उपाय है, जो एक विषैला प्रदूषक है जो अक्सर लैंडफिल लीचेट और अपशिष्ट उत्पादों, जैसे कि सीवेज, तरल खाद और अन्य तरल कार्बनिक अपशिष्ट उत्पादों में पाया जाता है।

सरकारने देश भर में मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए परामर्श को मंजूरी दी

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - पर्यावरण

समाचार में-

- नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ **(SC-NBWL)** की स्थायी समिति ने देश में मानव-वन्यजीव संघर्ष **(HWC)** के प्रबंधन के लिए परामर्श को मंजूरी दी है।

- सलाहकार मानव/ वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए महत्वपूर्ण नुस्खे बनाता है और शीघ्र अंतर-विभागीय समन्वित और प्रभावी कार्यों की तलाश करता है।

प्रमुख उपायों को मंजूरी दी

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, **1972** की धारा **11 (1) (B)** के अनुसार समस्याग्रस्त जंगली जानवरों से निपटने के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना।
- एचडब्ल्यूसी के कारण फसल क्षति के लिए फसल क्षतिपूर्ति के लिए प्रधान मंत्री बीमा योजना के तहत एड-ऑन कवरेज का उपयोग।
- वन क्षेत्रों के भीतर चारा और जल स्रोतों को संवर्धित करना।
- पीड़ित / परिवार को घटना के **24** घंटे के भीतर अंतरिम राहत के रूप में भूतपूर्व हिस्से के भुगतान।
- स्थानीय / राज्य स्तर पर अंतर-विभागीय समितियों का निर्धारण।
- पूर्व चेतावनी प्रणाली को अपनाना
- बाधाओं का निर्माण
- टोल फ्री हॉटलाइन नंबरों के साथ समर्पित सर्कल वार कंट्रोल रूम जो **24X7** आधार पर संचालित किए जा सकते हैं।
- हॉटस्पॉट्स की पहचान और बेहतर स्टाल-फेड फार्म जानवरों आदि के लिए विशेष योजनाओं के कार्यान्वयन और कार्यान्वयन।
- राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली मध्यम आकार की जंगली बिल्ली को गंभीर रूप से खतरनाक प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है
- परामर्श में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, **1972** के खण्ड **11 (1)** (बी) के अनुसार, संकटग्रस्त वन्य जीवों से निपटने में ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की परिकल्पना की गई है।
- मानव और वन्यजीव संघर्ष के कारण फसलों के नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति और वन्य क्षेत्रों के भीतर चारे और पानी के स्रोतों को बढ़ाना जैसे कुछ महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं।
- संघर्ष की स्थिति में पीड़ित परिवार को अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि के एक हिस्से का भुगतान **24** घंटे की भीतर किया जाये।
- परामर्श में स्थानीय/राज्य स्तर पर अंतर-विभागीय समितियों को निर्धारित करने, पूर्व चेतावनी प्रणालियों को अपनाने, अवरोधों के निर्माण, **24X7** आधार पर संचालित होने वाले निःशुल्क हॉटलाइन नंबरों के साथ समर्पित क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष,हॉटस्पॉट की पहचान और उन्नत स्टाल-फ़ेड फ़ार्म पशु आदि के लिए विशेष योजनाओं को बनाने और उनके कार्यान्वयन को अपनाने की अवधारणा भी की गई हैं।
- बैठक के दौरान हुई कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियों में राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली कैराकल को केंद्र प्रायोजित योजना वन्यजीव निवास स्थलों का विकास के तहत वित्तीय सहायता के साथ संरक्षण के प्रयासों के अंतर्गत लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में जोड़ना भी शामिल है।
- अब, महत्वपूर्ण रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की पुनः वृद्धि के कार्यक्रम के तहत **22** वन्यजीव प्रजातियां हैं।
- स्थायी समिति ने कुछ राहत उपायों के साथ तेलंगाना के मुलुगु जिले में जम्पन्नवगू के मुथापुर और जम्पन्नवगु के बीच मोतलगुडेम के बीच सेतु के निर्माण की भी सिफारिश की।
- इसने भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा दी गई सलाह के अनुरूप कुछ राहत उपायों के साथ दक्षिण पश्चिम रेलवे, कर्नाटक के टीनाघाट-कैस्टलरॉक-कैरनज़ोल रेलवे लाईन के दोहरीकरण के प्रस्ताव की भी सिफारिश की।

- उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के गांवों माधरवा, ठाकुरपुर, जमधरा और सुगांव में पानी की आपूर्ति और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक पुल और नहर का निर्माणऔर ठाणे जिले में नवी मुंबई के वाशी इलाके में एकीकृत बस टर्मिनल और वाणिज्यिक परिसर का निर्माण शामिल है।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, **1972** (डब्ल्यूएलपीए) की धारा **5**ए के तहत किया है।
- एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति कई स्तरों पर जांच के बाद प्रस्तावों पर विचार करती है और इसमें राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन, राज्य सरकार और राज्य वन्यजीव बोर्ड की सिफारिशें शामिल होती हैं।
- एससी-एनबीडब्ल्यूएलकी बैठकों के दौरान, निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ सदस्यों के विचारों पर भी पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है।

क्या आपको पता है?

- वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के 5 ए के तहत केंद्र सरकार द्वारा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ **(NBWL)** का गठन किया जाता है।
- एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति कई स्तरों पर जांच के बाद प्रस्तावों पर विचार करती है और इसमें राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन, राज्य सरकार और राज्य वन्यजीव बोर्ड की सिफारिशें होती हैं।
- **SC-NBWL** की बैठकों के दौरान, निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ सदस्यों के विचारों पर ध्यान दिया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

कैराकल

- यह एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है जो अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य एशिया और भारत की मूल निवासी है।
- यह आमतौर पर निशाचर होता है।
- यह क्षेत्रीय है।
- यह मुख्य रूप से अकेले या जोड़े में रहता है।
- यह मांसाहारी है
- प्राचीन मिस्र में शिकार के लिए कैराकल का इस्तेमाल किया गया था।
- भारत में, कैराकल सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पायी जाती है।
- आईयूसीएन रेड लिस्ट: 2002 से सुभेध
- खतरा: कृषि विस्तार, सड़कों और बस्तियों के निर्माण के कारण आवास की हानि
- CITES स्थिति: (1) अफ्रीकी कैराकल आबादी - परिशिष्ट II; (2) एशियाई आबादी - परिशिष्ट I

NCAVES इंडिया फोरम 2021 का आयोजन

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - पर्यावरण; पारिस्थितिकी; अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन (Natural Capital Accounting and Valuation of the Ecosystem Services) इंडिया फोरम -2021 का आयोजन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) द्वारा किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यूरोपीय संघ (European Union) द्वारा वित्तपोषित NCAVES परियोजना को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (United Nations Statistics Division), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme) और जैव विविधता सम्मेलन (Convention of Biological Diversity) के सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है।
- भारत इस परियोजना में भाग लेने वाले पाँच देशों (ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको) में शामिल है।
- भारत में NCAVES परियोजना को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (National Remote Sensing Centre) के सहयोग से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस परियोजना में भागीदारी से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को **UN-SEEA** फ्रेमवर्क के अनुरूप पर्यावरणीय खातों के संकलन और वर्ष 2018 से वार्षिक आधार पर अपने प्रकाशन "एनवीस्टैट्स इंडिया" (**EnviStats India)** में पर्यावरणीय खातों को जारी करने में मदद मिली है।
- इनमें से कई खाते सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं से निकटता से जुड़े हैं, जो कि उन्हें इस नीति का एक उपयोगी उपकरण बनाते हैं।
- **NCAVES** परियोजना के तहत एक अन्य उपलब्धि भारत–**EVL** उपकरण का विकास है, जो कि अनिवार्य रूप से देश भर में किये गए लगभग 80 अध्ययनों पर आधारित देश के विभिन्न राज्यों में अनेक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यों की तस्वीर पेश करने वाला एक उपकरण है।

इलेक्ट्रिक वाहन: नॉर्वे केस स्टडी

संदर्भ: **2020** में, नॉर्वे ने नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों में एक विश्व नेता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया, क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन **(BEV)** ने वर्ष के दौरान देश में बेचे जाने वाले सभी वाहनों के आधे से अधिक है।

नॉर्वे में ऑटो बाजार के आंकड़े

- **2020** में, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों **(BEV)** का बाजार हिस्सा **2019** में **42%** से बढ़कर **54%** हो गया।
- केवल एक दशक पहले, **BEVs** ने समग्र बाजार का सिर्फ **1** प्रतिशत बनाया था।
- यदि हाइब्रिड वाहनों को शामिल किया जाता है, तो **2020** में बेचे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 83 प्रतिशत है।
- बिकने वाली पेट्रोल और डीजल कारें, जिनकी **2015** में बाजार हिस्सेदारी **71** प्रतिशत थी, अब **17** प्रतिशत है।
- नॉर्वे की सड़कों पर **2.8m** वाहन हैं और **260,000** से अधिक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैं, कुल कार स्टॉक का लगभग **9%**।

नॉर्वे एक इलेक्ट्रिक वाहन अग्रणी कैसे बना?

- विरोधाभास: नॉर्वे, जो पश्चिमी यूरोप में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ने हाल ही में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से नवीकरणीय ऊर्जा में बदलाव किया है।
- 1990 के दशक की शुरुआत : यह देश क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र के आकार का था, इसने 1990 के दशक में शहरी केंद्रों में प्रदूषण, भीड़ और शोर को कम करने के प्रयास में विधुत के प्रयोग को प्रोत्साहित किया।
- **महत्वाकांक्षी लक्ष्य:** 2017 में, नॉर्वे की संसद ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक गैर-बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया कि 2025 तक बेची जाने वाली सभी कारों से शून्य उत्सर्जन होना चाहिए। ब्रिटेन और जर्मनी ने 2030 तक और फ्रांस ने 2040 तक ऐसा करने की योजना बनाई है। भारत में, सरकार ने 2030 तक ईवी बनने वाले 30 प्रतिशत वाहनों के लिये यह लक्ष्य निर्धारित किया है।
- **कम कर:** नॉर्वे में करों को लक्जरी वस्तु के रूप में मान्यता दी गयी हैं। कई प्रोत्साहन के साथ, इलेक्ट्रिक वाहनों पर करों में कमी, कार खरीदारों को लुभाने के लिए बाध्य करता है।
- **प्रोत्साहन:** सरकार इलेक्ट्रिक कारों को बस लेन पर चलने देती है, जबकि टोल सड़कें उनके लिए मुफ्त हैं। इसके अलावा, पार्किंग स्थल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मुफ्त पार्किंग शुल्क का भी प्रावधान हैं।
- **चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर:** देश के राजमार्गों पर नए चार्जिंग स्टेशन लगातार बनाए जा रहे हैं – यह नियमित चार्जिंग स्टेशनों और फास्ट-चार्जर्स का मिश्रण है। फिलहाल, नॉर्वे में सार्वजनिक रूप से 10,000 चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध हैं।
- **नीतिगत मोड़:** देश की नीतियों ने भी कार निर्माताओं को नॉर्वे को एक परीक्षण मैदान के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार, वोक्सवैगन का लक्ज़री ब्रांड ऑडी 2020 में मार्केट लीडर था, जिसने अपने ई-ट्रॉन मॉडल की 9,227 यूनिट बेचीं, इसके बाद टेस्ला का मॉडल 3 था, जिसकी बिक्री 7,77o यूनिट थी।
- **प्राकृतिक संसाधन के साथ धन्य:** जबकि नॉर्वे अभी भी दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में से एक है, उसे अपनी शक्ति का 90% से अधिक जलविद्युत स्रोतों से प्राप्त होता है। यह समझाने का कोई तरीका है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का परिचय ऐसा विजेता क्यों रहा है: जब तक नदियां और झरने सूख नहीं जाते हैं, यह शक्ति का एक अनंत स्रोत है जो वाहनों पर भी लागू किया जा सकता है।

आगे की चुनौतियां

- **आयात पर निर्भरता:** देश कारों का निर्माण नहीं करता है (एक नार्वेजियन शहर इलेक्ट्रिक कार के लिए अपवाद है, जिसे एक होमग्रोन फर्म की बडी इलेक्ट्रिक द्वारा निर्मित किया गया है) और इसके अधिकांश वाहन बेड़े का आयात किया जाता है।
- **जलवायु पदचिह्न:** हालांकि बीईवी एक स्थानीय संदर्भ में पर्यावरण के अनुकूल हैं, विश्व स्तर पर वे अभी भी बड़े जलवायु पदचिह्न छोड़ते हैं। बीईवी बैटरी के निर्माण के लिए महंगी और दुर्लभ धातुओं की आवश्यकता होती है, जबकि उपयोग की गई और टूटी हुई बैटरी का सुरक्षित रूप से निपटान एक समस्या है।
- **विकासशील देशों पर बोझ:** प्रयुक्त और टूटी हुई बैटरी के निपटान की चिंताएं गरीब, कमजोर देशों - जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के लिए एक समस्या हैं, यह दुनिया के 60% कोबाल्ट का उत्पादन करता है - जिससे निपटने के लिए कानून का अभाव है।
- **पुनरावृत्ति करने में मुश्किल:** दुनिया के अन्य हिस्सों में नॉर्वे की नीतियों को दोहराना मुश्किल है, मुख्य रूप से क्योंकि देश तेल और गैस उत्पादन से अपने राजस्व के लिए उदार सब्सिडी की पेशकश को प्रस्तुत कर सकता है।

---

30 वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) समारोह आयोजित किया गया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - ऊर्जा संसाधन; संरक्षण

समाचार में-

- ऊर्जा मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) के सहयोग से 30 वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (NECA) समारोह का आयोजन किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- घटना के दौरान, एयर कंप्रेशर्स और अल्ट्रा हाई डेफिनिशन (यूएचडी) टीवी के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर शुरू किया गया था।
- ऊर्जा खपत मानक 01 जनवरी 2021 से प्रभावी होंगे।
- इस पहल से 2030 तक एयर कंप्रेशर्स के लिए लगभग 8.41 बिलियन यूनिट और यूएचडी टीवी के लिए 9.75 बिलियन यूनिट बिजली की बचत होने की उम्मीद है।
- SAATHEE (ऊर्जा दक्षता पर वार्षिक लक्ष्य और हेडवे पर राज्यवार कार्रवाई) - राज्य स्तर की गतिविधियों के लिए राज्य नामित एजेंसी के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था।
- बीईई ने इस पोर्टल को विकसित किया है।
- यह राज्य स्तर पर विभिन्न ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के कार्यान्वयन की प्रगति की वास्तविक समय की निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

- यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
- यह विकासशील नीतियों और रणनीतियों में सहायता करता है।

- उद्देश्य: भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना।

Related articles:

- (DISCOMs) to be covered under the Energy Conservation (EC) Act, 2001: Click here

भारतीय चिड़ियाघरों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई-ज़ू) फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - पर्यावरण; जैव विविधता

समाचार में-

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भारतीय चिड़ियाघरों (MEE-ZOO) के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- रूपरेखा भारत के चिड़ियाघरों के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश, मानदंड और संकेतक का प्रस्ताव करती है, जो असतत, समग्र और स्वतंत्र है।
- मूल्यांकन मानदंड और संकेतक पारंपरिक अवधारणाओं से परे दिखते हैं और इसमें पशु कल्याण, पति और संसाधनों और वित्त की स्थिरता शामिल हैं।
- एमईई-ज़ू व्यायाम पूरे भारत में चिड़ियाघर में उच्चतम मानकों को विकसित करने की ओर बढ़ रहा है।
- यह लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के जनादेश को प्राप्त करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता, नवाचार, प्रौद्योगिकी के उपयोग, सहयोग और अखंडता के मुख्य मूल्यों का पालन करने में मदद करेगा।

मीलवॉर्म (येलो ग्रब) यूरोप का पहला कीट खाद्य बन जाता है

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - पारिस्थितिकी; जैव विविधता

समाचार में-

- मीलवॉर्म (येलो ग्रब) मानव भोजन के रूप में यूरोप में अनुमोदित होने वाला पहला कीट बन गया है।
- मीलवॉर्म (येलो ग्रब) यूरोप का पहला कीट खाद्य बन जाता है

महत्वपूर्ण बिंदु

- यूरोपीय खाद्य सुरक्षा एजेंसी (ईएफएसए) द्वारा निर्णय लिया गया कि मीलवॉर्म (येलो ग्रब) का उपयोग संपूर्ण और करी एवं अन्य व्यंजनों में सूखे और बिस्कुट, पास्ता और ब्रेड बनाने के लिए आटा के रूप में किया जाए।
- प्रोटीन, वसा और फाइबर में समृद्ध, वे आने वाले वर्षों में यूरोपीय प्लेटों पर कई कीड़े होने की संभावना रखते हैं।

म्यूचुअल फंड (एमएफ) के लिए जोखिम-ओ-मीटर जनवरी से प्रारंभ

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III- पारिस्थितिकी; जैव विविधता

समाचार में-

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(SEBI)** के लिए "जोखिम-ओ-मीटर" पर निर्णय **1** जनवरी को लागू होगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउस के लिए अपनी योजनाओं के जोखिम स्तर को छह-स्तरीय पैमाने पर "निम्न" से "बहुत उच्च" करने के लिए अनिवार्य कर दिया है।
- **1** जनवरी से शुरू होने वाले सभी म्यूचुअल फंड स्कीम की विशेषताओं के आधार पर लॉन्च के समय उनकी योजनाओं के लिए एक जोखिम स्तर प्रदान करते हैं।
- जोखिम-ओ-मीटर का मासिक आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- फंड हाउसों को अपनी सभी वेबसाइटों पर अपनी सभी योजनाओं के साथ-साथ एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया **(AMFI)** की वेबसाइट के बंद होने के **10** दिनों के भीतर जोखिम-ओ-मीटर जोखिम स्तर का खुलासा करना आवश्यक है।
- किसी योजना के संबंध में जोखिम-ओ-मीटर रीडिंग में कोई भी परिवर्तन उस योजना के इकाई-धारकों को सूचित किया जाएगा।
- यह कदम निवेशकों को अधिक सूचित निवेश निर्णय लेने में मदद करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

- यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार का नियामक है।
- इसे 1988 में स्थापित किया गया था और सेबी अधिनियम, **1992** के माध्यम से वैधानिक दर्जा दिया गया था।
- सेबी तीन समूहों की जरूरतों के लिए जिम्मेदार है:
    - प्रतिभूतियों के जारीकर्ता
    - निवेशक
    - बाजार मध्यस्थ
- **कार्य:**

- अर्ध-विधायी - ड्राफ्ट नियम
- अर्ध-न्यायिक - नियम और आदेश पारित करता है
- अर्ध-कार्यकारी - जांच और प्रवर्तन कार्रवाई करता है

- **शक्तियां:**
  - प्रतिभूति एक्सचेंजों के कानूनों द्वारा अनुमोदित करना।
  - कानूनों द्वारा संशोधन करने के लिए प्रतिभूति विनिमय की आवश्यकता होती है।
  - खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करें और मान्यता प्राप्त प्रतिभूति एक्सचेंजों से आवधिक रिटर्न के लिए कॉल करें।
  - वित्तीय मध्यस्थों के खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करें।
  - कुछ कंपनियों को अपने शेयरों को एक या अधिक प्रतिभूति एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने के लिए मजबूर करें।
  - दलालों और उप-दलालों का पंजीकरण

Related articles:

- SEBI eases Fund-raising norms for firms: Click here
- Participatory notes: Click here

सक्षम: जीवाश्म ईंधन के उपभोक्ताओं के लिए एक महीने का लंबा अभियान

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - पर्यावरण

समाचार में-

- जीवाश्म ईंधनों के उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन (पीसीआरए) ने बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट के प्रतिकूल स्वास्थ्य और पर्यावरणगत प्रभावों को रेखांकित करते हुए महीने भर चलने वाला अभियान लांच किया।
- लॉन्च: पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- अभियान बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट्स के प्रतिकूल स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों को उजागर करेगा।
- सक्षम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को क्लीनर ईंधन पर स्विच करने और जीवाश्म ईंधन का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए व्यवहार परिवर्तन में लाने के लिए राजी करना है।
- इस अभियान से 7 प्रमुख कारकों के बारे में जागरूकता फैलेगी, जिनका प्रधानमंत्री ने हाल ही में उल्लेख किया है, जो भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने में मदद करेंगे।
- प्रमुख चालकों में शामिल हैं: **(1)** गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना; **(2)** जीवाश्म ईंधन का स्वच्छ उपयोग; **(3)** जैव ईंधन को चलाने के लिए घरेलू स्रोतों पर अधिक निर्भरता; **(4)** निर्धारित समयसीमा के साथ अक्षय लक्ष्यों को प्राप्त करना; **(5)** गतिशीलता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता उपयोग; **(6)** हाइड्रोजन जैसे क्लीनर ईंधन का बढ़ता उपयोग; **(7)** सभी ऊर्जा प्रणालियों में डिजिटल नवाचार।

वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार सार्वजनिक खरीद के लिए मॉडल निविदा

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- वित्त मंत्रालय ने सभी केंद्र सरकार के विभागों द्वारा सार्वजनिक खरीद के लिए एक मॉडल निविदा दस्तावेज का मसौदा तैयार किया है, जिसमें भाषा और खंड शामिल करने और अनुबंध संबंधी विवादों से बचने के लिए बोली लगाई गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सार्वजनिक खरीद से तात्पर्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, वैश्विक स्तर पर जीडीपी के औसत **15%** के लिए लेखांकन।
- सार्वजनिक खरीद से तात्पर्य वैश्विक स्तर पर जीडीपी के औसत 15% के हिसाब से सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से है।
- भारत में, सरकारी खरीद का अनुमान है कि जीडीपी का लगभग 30% केंद्र सरकार के पास होगा।
- भारत में सार्वजनिक खरीद में कोई मानकीकृत नामकरण नहीं है और अमेरिकी, यूरोपीय और भारतीय नामकरण का मिश्रण सामान्य हो गया है। जैसे निविदा में भाग लेने वालों को निविदाकार और बोलीदाता कहा जाता है।
- अब विकसित मानक बोली दस्तावेज, इस द्वंद्व को कम करने के लिए यह ढील देना चाहता है कि 'निविदा' को निविदा दस्तावेज और प्रक्रिया को संदर्भित करना चाहिए, जबकि 'बोली' शब्द बोलीदाताओं को संदर्भित करेगा;
- संभावित आपूर्तिकर्ताओं को संदर्भित करने के लिए 'टेंडरर' के बजाय 'बिडर' का उपयोग किया जाना है और प्रस्तावित मॉडल के अनुसार बोली दस्तावेज का उपयोग किया जाना चाहिए।

अनुपचारित अप्रयुक्त औद्योगिक प्रवाह के अनियंत्रित वृद्धि से गुजरात की नदियों में प्रदूषण बढ़ गया है

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - पर्यावरण; प्रदूषण

समाचार में-

- अनुपचारित औद्योगिक प्रवाह के अनियंत्रित वृद्धि से गुजरात में नदियों साबरमती, महिसागर, नर्मदा, विश्वामित्र और भादर में प्रदूषण बढ़ गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पर्यावरण और वन मंत्रालय **(MoEF)** के आंकड़ों के अनुसार, साबरमती देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है।
- गुजरात अत्यधिक प्रदूषित नदियों के साथ शीर्ष पांच राज्यों में चौथे स्थान पर है।
- आधिकारिक मापदंडों के अनुसार, यदि रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी), जो कार्बनिक प्रदूषक भार को इंगित करता है, **250** मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है, तो औद्योगिक प्रवाह को इन नदियों में प्रावाहित नहीं किया जाना चाहिए।
- गुजरात की अधिकांश नदियों में अपशिष्टों को डंप किया जाता है, **COD** स्तर **700** से **1000** मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा तक है।
- जबकि महिसगर जैसी बारहमासी नदियों में विघटित ऑक्सीजन (डीओ) स्तर (एक नदी के स्वास्थ्य का संकेत) 6 से 8 मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा में होना चाहिए, यह वास्तव में 2.9 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे है।

ड्रैगन फल

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - पारिस्थितिकी; जैव विविधता

समाचार में-

- ड्रैगन फल हाल ही में खबरों में था क्योंकि गुजरात सरकार ने इसका नाम बदलकर 'कमलम' रखने का फैसला किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ड्रैगन फल दक्षिण और मध्य अमेरिका के लिए स्वदेशी जंगली कैक्टस की एक प्रजाति का फल है, जहां इसे पिटया या पिथैया कहा जाता है।
- फल का आंतरिक भाग (गुदा) आमतौर पर सफेद या लाल रंग का होता है - हालाँकि इसमें पीला आम भी कम होता है - और इसमें किवीफ्रूट की तरह छोटे बीज होते है।
- सबसे बड़ा ड्रैगन फल उत्पादक और निर्यातक: वियतनाम
- ड्रैगन फ्रूट की खेती थाईलैंड, ताइवान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल और श्रीलंका में भी की जाती है।
- यह 1990 के दशक में इसे भारत में लाया गया था, और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में इसे उगाया जाता है।
- यह सभी प्रकार की मिट्टी में उगता है, और इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है।

CSIR-CMERI ने भारत के पहले एक्वा कायाकल्प संयंत्र का अनावरण किया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -इन्फ्रास्ट्रक्चर; वातावरण

समाचार में-

- सीएसआईआर और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) ने पहली बार अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकी मॉडल का अनावरण किया जो सिंचाई / खेती के उद्देश्यों के लिए अपशिष्ट जल को शुद्ध करता है।
- यह उपचारित अपशिष्ट जल के माध्यम से एक जैविक खेती मॉडल की सुविधा प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- एक्वा कायाकल्प प्लांट (ARP) एक एकीकृत अपशिष्ट जल कायाकल्प मॉडल है जिसमें विभिन्न शुद्धि मापदंडों के आधार पर अपशिष्ट जल के व्यापक उपचार के लिए छह-चरण शुद्धि प्रोफ़ाइल है।
- एआरपी का उपयोग करके 24,000 लीटर पानी का कायाकल्प किया जा सकता है जो लगभग 4 एकड़ कृषि भूमि (पानी की आवश्यकताओं में मौसमी बदलाव को रोकना) के लिए पर्याप्त होगा।
- उपयोग किए गए निस्पंदन मीडिया को विशेष रूप से भारतीय सीवेज जल पैरामीटर को संभालने के लिए विकसित किया गया है और भौगोलिक विविधता के आधार पर उन्हें संशोधित किया जा सकता है।
- सिस्टम का दोहरा लाभ है। जबकि उपचारित पानी का उपयोग सिंचाई के उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, उत्पन्न फ़िल्टर किए गए कीचड़ को खाद / उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है।
- पतझड़ के मौसम में गिरने वाले सूखे पत्तों से तैयार बायो चार्ट का उपयोग मिट्टी में मिलाने के लिए भी किया जाता है क्योंकि यह सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता को कम करता है जिससे कीमती पानी की बचत होती है।

भारत में दुर्लभ चींटी वंश की दो नई प्रजातियों की खोज की गई है।

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - जैव विविधता; वातावरण

समाचार में-

- भारत में एक दुर्लभ चींटी जीनस की दो नई प्रजातियों की खोज की गई है।
- केरल और तमिलनाडु में पाई गई चींटी 'उकेरिया' वंश की प्रजातियाँ, इस दुर्लभ वंश की विविधता को बढ़ाती हैं। ये एंटेनल खंडों (Antennal Segments) की संख्या के आधार पर अपने वंश की अन्य प्रजातियों से अलग हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इनमें से एक केरल के पेरियार बाघ अभयारण्य में पाई गई है जिसका नाम प्रख्यात विकासमूलक जीवविज्ञानी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के सम्मान में 'उकेरिया जोशी' (Ooceraea Joshii) रखा गया है।
- मदुरै (केरल) के अलागरकोईल में खोजी गई दूसरी प्रजाति उकेरिया डीकैमरा (Ooceraea Decamera) है, डीकैमरा दस खंडों वाले एंटेनल को संदर्भित करती है।

आर्कटिक नीति मसौदा

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - पर्यावरण

समाचार में-

- हाल ही में भारत ने एक नया आर्कटिक नीति मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, स्थायी पर्यटन और खनिज तेल एवं गैस की खोज को बढ़ावा देना है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत को उम्मीद है कि गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च वैज्ञानिक अनुसंधान का नेतृत्व करेगा और इसके तहत गतिविधियों के समन्वय के लिए एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करेगा।
- उद्देश्य: (1) पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थानों में खनिज / तेल और गैस की खोज के लिए आर्कटिक से संबंधित कार्यक्रमों को रखना; (2) आर्कटिक उद्यमों के साथ संलग्न करने के लिए विशेष क्षमता और जागरूकता के निर्माण में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना।
- आर्कटिक अनुसंधान से भारत के वैज्ञानिक समुदाय को तीसरे ध्रुव - हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने की दर का अध्ययन करने में मदद मिलेगी, जो भौगोलिक ध्रुवों के बाहर दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के भंडार से संपन्न हैं।

क्या आपको पता है?

- भारत ने 2007 में आर्कटिक में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया।
- हिमाद्री भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है जो स्पिट्सबर्गेन, स्वालबार्ड, नॉर्वे में स्थित है।
- इसे 2008 में भारत के दूसरे आर्कटिक अभियान के दौरान स्थापित किया गया था।

यूएसए का नये राष्ट्रपति ने पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका की भागीदारी को पुनर्स्थापित किया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - पर्यावरण

समाचार में-

- जो बिडेन ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया।
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र पेरिस समझौते में अमेरिका की भागीदारी को बहाल करना, उनके पहले आदेशों में से एक था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस समझौते में अमेरिका की वापसी 19 फरवरी को प्रभावी होगी।
- यूएसए ने 2050 से बाद में नेट-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रवर्तन तंत्र का वादा किया है, जिसमें 2025 में अपने कार्यकाल के अंत की तुलना में कोई लक्ष्य नहीं है, एक नियोजित संघीय निवेश द्वारा सहायता प्राप्त है जो निजी निवेशों के अलावा दस वर्षों में $ 1.7 ट्रिलियन होगा।
- यह योजना सौर और पवन ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ लगभग 10 मिलियन अच्छी तरह से भुगतान करने वाली स्वच्छ ऊर्जा नौकरियों का सर्जन करेगी।
- ग्लासगो में इस साल के संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में नए प्रशासन को UNFCCC के सदस्य-राष्ट्रों को वैश्विक महत्वाकांक्षा को पूरा करते हुए देखा जाएगा।

क्या आपको पता है?

- पेरिस समझौते से वापसी का मतलब था कि अमेरिका अब संधि के तहत की गई अपनी राष्ट्रीय प्रतिज्ञा से बाध्य नहीं था: गौरतलब है कि इस समझौते के तहत अमेरिका द्वारा वर्ष 2025 तक अपने उत्सर्जन में वर्ष 2005 की तुलना में 26-28% तक की कटौती करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी
- अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के ग्रीन क्लाइमेट फंड में अपना योगदान भी रोक दिया, जिसमें अनुमानित 1 बिलियन के हस्तांतरण के बाद उसने 3 बिलियन $ का वादा किया था।
- अतीत में, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के तहत, यू.एस. ने, पिछले संधि, क्योटो प्रोटोकॉल, 2001 में खींच लिया था।

महत्वपूर्ण तथ्य

क्या है पेरिस समझौता?

- दिसंबर 2015 में, 195 देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के भीतर एक समझौते (नवंबर 2016 में लागू हुआ) को ग्रीनहाउस-गैस-उत्सर्जन शमन, अनुकूलन और वित्त के साथ समझौता किया
- उद्देश्य: दिसंबर 2015 में विश्व के 195 देशों ने 'वैश्विक स्तर पर तापमान में हो रही औसत वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C तक सीमित रखने और इस वृद्धि को 1.5°C तक नियंत्रित करने के प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- साथ ही इस समझौते में शामिल सभी सदस्यों ने 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (Nationally Determined Contribution- NDC) के माध्यम से अपने सर्वोत्तम प्रयासों को आगे बढ़ाने तथा आने वाले वर्षों में इसे और अधिक मज़बूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- इस समझौते में एक और महत्वपूर्ण बिंदु 2050 और 2100 के बीच "शुद्ध शून्य उत्सर्जन" प्राप्त करना था। राष्ट्रों ने "इस सदी के उत्तरार्ध में ग्रीनहाउस गैसों के स्रोत और निष्कासन द्वारा मानवजनित उत्सर्जन के बीच संतुलन हासिल करने का संकल्प लिया है"।
- विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूलन उपायों के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए भी कहा गया था।
- एक समीक्षा तंत्र के हिस्से के रूप में, विकसित देशों को हर दो साल में "सांकेतिक" राशि का संचार करने के लिए कहा गया था जो वे अगले दो वर्षों में उठा पाएंगे, और इस बात की जानकारी सार्वजनिक वित्तीय स्रोतों में से कितनी होगी। ।
- इसके विपरीत, विकासशील देशों को स्वैच्छिक आधार पर हर दो साल में ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए "प्रोत्साहित" किया जाता है।
- इस समझौते में सूखे, बाढ़ आदि जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण कम विकसित राष्ट्रों द्वारा सामना किए गए वित्तीय घाटे को संबोधित करने के लिए एक तंत्र भी शामिल है। हालांकि, विकसित राष्ट्रों को वित्तीय दावों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वह इसमें शामिल नहीं है या किसी भी दायित्व के लिए यह उन्हें कोई आधार प्रदान नहीं करता है।

Related articles:

- US and Paris Agreement: Click here
- Paris Climate Deal: India's Progress, Pandemic and Challenges: Click here

कृषि-ऋण में, छोटे किसान अभी भी बाड़ के बाहर हैं

प्रसंग: भारत में छोटे किसानों को तकनीकी, वित्तीय और संस्थागत सहायता हासिल करने के मार्ग में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: औपचारिक ऋण एवं बीमा तक सीमित पहुंच; उन्हें आधुनिक कृषि उपकरणों एवं तौर-तरीकों का समुचित प्रशिक्षण देने वाले क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का अभाव; सिंचाई के लिए अपर्याप्त पानी की आपूर्ति; फसल विविधीकरण के लिए बेहद कम या कोई गुंजाइश नहीं; और विपणन सुविधाओं का अभाव।

Why farmers are protesting against farm laws: Click here and here
Why earlier government negotiations have failed: Click here
What is the long term solution advocated by experts: Click here

क्या आपको पता है?

- कृषि जनगणना, 2015-16 में, देश में छोटे और सीमांत किसानों के घरों की कुल संख्या 12.55 करोड़ थी। इनकी छोटी और सीमांत होल्डिंग कुल होल्डिंग का 86.1% बनाते हैं।
- RBI ने एक कैप सेट किया है जो बैंक के समग्र समायोजित नेट बैंक क्रेडिट में से 18% कृषि क्षेत्र में दिया जाना चाहिए, और इसके भीतर 8% छोटे और सीमांत किसानों और 4.5% अप्रत्यक्ष ऋण के रूप में दिया जाना चाहिए

फार्म क्रेडिट और छोटे किसान

- **संस्थागत ऋण**: छोटे किसानों को अपनी फसलों में विविधता लाने या अपनी आय में सुधार करने में सक्षम बनाने के लिए उनके पास ब्याज की उचित दरों पर ऋण तक पहुंच होनी चाहिए। यह उन्हें निजी साहूकार के पास जाने से रोकता है जो कर्ज के जाल में फंसने के लिए अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं
- **प्रत्येक वर्ष बढ़ता हुआ कृषि**-ऋण: केंद्र सरकार हर साल सब्सिडी वाली कृषि ऋण सीमा के लक्ष्य में वृद्धि की घोषणा करती है और बैंक ऋण लक्ष्य से अधिक हो जाते हैं। 2011-12 में, लक्ष्य 754.75 लाख करोड़ था;वर्तमान में, कृषि-ऋण 2020-21 में 21,1,000 करोड़ की आवंटित सब्सिडी के साथ 15 लाख करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच गया है।
- **कृषि विकास प्रदान करने में कृषि-ऋण कम कुशल हो गया है:** दुर्भाग्य से, जबकि दशकों में ऋण की मात्रा में सुधार हुआ है, इसकी गुणवत्ता और कृषि पर प्रभाव केवल बिगड़ गया है। 85% से अधिक किसानों की आय वर्षों से स्थिर है।
- **एग्री-क्रेडिट छोटे किसानों तक नहीं पहुंच रहा है:** पिछले 10 वर्षों में, कृषि ऋण में 500% की वृद्धि हुई है लेकिन 12.56 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के 20% तक भी नहीं पहुंची है। सबसे कम भूमि रखने वाले परिवारों (दो हेक्टेयर तक) को संस्थागत स्रोतों (बैंक, सहकारी समिति) से सब्सिडी वाले बकाया ऋण का लगभग 15% ही मिल रहा है। दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवारों के लिए यह हिस्सा 79% है।
- **कृषि यंत्र अभी भी गैर-अनुदानित ऋण द्वारा वित्तपोषित है:** कृषि-ऋण में वृद्धि के बावजूद, आज भी, देश में बेचे जाने वाले 95% ट्रैक्टर और अन्य कृषि-उपकरणों पर NBFCs द्वारा 18% की दर से बैंकों द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।
- **सब्सिडी वाले एग्री-क्रेडिट के थोक को बड़े किसानों और कृषि-व्यवसाय कंपनियों द्वारा हड़प लिया जाता है**: एग्री-क्रेडिट की ढीली परिभाषा के कारण एग्री-बिजनेस में बड़ी कंपनियों को सब्सिडी दरों पर ऋण का रिसाव हुआ है। 2017 में, नाबार्ड द्वारा महाराष्ट्र को प्रदान किए गए कृषि ऋण का 53% मुंबई शहर और उपनगरों को आवंटित किया गया था, जहां कोई किसान नहीं हैं, केवल कृषि-व्यवसाय है।

- **संस्थागत ऋण असमान रूप से वितरित है:** 2019 में आरबीआई के आंतरिक कार्य समूह ने पाया कि कुछ राज्यों में, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण वितरण उनके कृषि सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में अधिक था और इनपुट आवश्यकता के हिसाब से फसली ऋण का अनुपात बहुत असमान रूप से वितरित किया गया था। उदाहरण केरल (326%), आंध्र प्रदेश (254%), तमिलनाडु (245%), पंजाब (231%) और तेलंगाना (210%) में हैं।
- **गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण का मोड़**: 4% -7% की ब्याज दर पर रियायती ऋण प्रणाली में भ्रष्टाचार और खामियों के कारण अन्य उद्देश्यों के लिए वितरित किया जा रहा है। कई बार ये ऋण खुले बाजार में 36% तक की ब्याज दर पर छोटे किसानों को दिए जाते हैं।
- नए कृषि कानूनों की अनदेखी: यहां तक कि नए कृषि कानूनों ने कृषि ऋण प्रणाली में सुधार को संबोधित नहीं किया है

आगे का रास्ता

- प्रत्यक्ष आय सहायता: लघु और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने का एक तरीका यह है कि उन्हें ऋण सब्सिडी के बजाय प्रति हेक्टेयर के आधार पर प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाए।
- किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना: किसान उत्पादक संगठनों को उच्च फसल ऋण की सुविधा के लिए कृषि-ऋण प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, या कमोडिटी स्टॉक के विरुद्ध छोटे किसानों की एफपीओ कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मॉडल हो सकता है।
- प्रौद्योगिकी: भारत में कृषि परिवारों के बीच मोबाइल फोन की पहुंच 89.1% से अधिक होने के कारण, प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों के माध्यम से संस्थागत ऋण वितरण में सुधार के लिए प्रयास की संभावनाएं कृषि परिवारों के वित्तीय बहिष्करण की सीमा को कम कर सकती हैं।
- **नए युग के कृषि-उद्यमियों को बढ़ावा देना:** ऐसी खबरें हैं कि किसान मोबाइल फोन एप्लिकेशन के माध्यम से ऋण लेने में सक्षम हैं। ये ऐप उन सैटेलाइट इमेजरी रिपोर्टों का उपयोग करते हैं, जो राज्यों में किसानों के स्वामित्व वाली भूमि की सीमा पर कब्जा करते हैं, जहां भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप दिया जाता है और वे किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का डिजिटल रूप से विस्तार करने के लिए फसल उगाते हैं।
- **सहकारी संघवाद:** आवश्यक अन्य कदम भूमि पट्टे के ढांचे में सुधार कर रहे हैं और इस अंतर को भरने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच आम सहमति बनाने के लिए एक राष्ट्रीय-स्तर की एजेंसी का निर्माण कर रहे हैं ताकि अंतर को भरने और छोटे और सीमांत किसानों की संख्या तक पहुंच सके।

यूएसए पेरिस समझौते में फिर से शामिल हो रहा है

संदर्भ: जो बिडेन ने **20** जनवरी**, 2021** को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला**,** और उन्होंने जो पहले आदेश दिए**,** उनमें से एक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र पेरिस समझौते में अमेरिका की भागीदारी को बहाल करने के लिए था**,** जो राष्ट्रीय उत्सर्जन कटौती के स्वैच्छिक लक्ष्यों पर आधारित था।

- अमेरिका की वापसी पर उनका निर्णय **19** फरवरी को प्रभावी होगा**,** जो डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के तहत अपनी वापसी के **107** दिनों के बाद **4** नवंबर**, 2020** को औपचारिक हो गया।

अमेरिका और प्रदूषण

- ग्लोबल जीएचजी उत्सर्जन में हिस्सेदारी: अमेरिकी वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन का 15% हिस्सा उत्सर्जित करता है, लेकिन यह वायुमंडलीय गैसों का सबसे बड़ा विरासत योगदानकर्ता है।

- जीएचजी उत्सर्जन के लिए क्षेत्रीय योगदान: परिवहन (28%) और बिजली (27%) जीएचजी उत्सर्जन में योगदान करने वाले दो सबसे बड़े राष्ट्रीय क्षेत्र हैं, इसके बाद उद्योग (22%), कृषि (10%) और वाणिज्यिक और आवासीय उत्सर्जन आते हैं।
- मीथेन प्रदूषण के प्रमुख योगदानकर्ता: उल्लेखनीय रूप से, अमेरिकी उत्सर्जन का 10% मीथेन है, जिसका CO2 से अधिक वार्मिंग प्रभाव होता है, और इसमें 81% कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोराइड युक्त गैसों से बना है।

क्या आपको पता है?

- **2001** में जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के अधीन**,** यू.एस**.** ने क्योटो प्रोटोकॉल से खुद को बाहर कर लिया था।
- ट्रम्प प्रेसीडेंसी **(2016** के बाद**)** के बाद से**,** यूएस ने निम्नलिखित संधियों से खुद को बहरा किया है
  - यू.एन**.** मानवाधिकार परिषद और यू.एन**.** सांस्कृतिक निकाय यूनेस्को से
  - ईरान परमाणु समझौते से
  - अमेरिकी जनसंख्या कोष **(UNFPA)** और **U.N** एजेंसी के लिए धन की कटौती**,** जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों **(UNRWA)** को मदद करती है
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन **(WHO)** से यू.एस को अलग करना

ट्रम्प प्रशासन ने जलवायु पर क्या बदलाव किए थे ?

- **प्रतिज्ञाओं के बाध्य नहीं**: पेरिस समझौते से वापसी का मतलब था कि अमेरिका अब संधि के तहत किए गए अपने राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के लिए बाध्य नहीं था, इस समझौते के तहत अमेरिका द्वारा वर्ष 2025 तक अपने उत्सर्जन में वर्ष 2005 की तुलना में 26-28% तक की कटौती करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी
- **ग्लोबल फंडिंग पर रोक :** अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के ग्रीन क्लाइमेट फंड में अपना योगदान भी रोक दिया, जिसमें अनुमानित $ 1 बिलियन के हस्तांतरण के बाद उसने $ 3 बिलियन देने का वादा किया था।
- **जीवाश्म ईंधन आधारित उद्योग को समर्थन**: इसके विपरीत, ट्रम्प शासन ने जीवाश्म ईंधन आधारित उद्योगों से उत्सर्जन पर नियंत्रण, वायु गुणवत्ता पर मानकों को कमजोर करने और एयर कंडीशनिंग प्रणाली से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लीक करने और वेंटिलेशन पर ध्यान केंद्रित किया था।
- **पर्यावरण की कमजोर विधियां:** प्रशासन द्वारा 100 से अधिक पर्यावरण नियमों के साथ छेड़छाड़ की गई, कुछ नियम उलट प्रक्रिया में शेष रहे जब राष्ट्रपति चुनाव हुए, और अन्य को अदालत में ले जाया गया।

उत्सर्जन में कटौती के लिए बिडेन किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे?

- **समर्पित टीम:** बिडेन, ने जलवायु के लिए विशेष राष्ट्रपति दूत, जॉन केरी सहित एक उच्चस्तरीय टीम का गठन किया है, यह स्वच्छ विकास का नेतृत्व करने के लिए, अपनी प्राथमिकताओं के बीच जलवायु परिवर्तन के मोर्चे और केंद्र को रखा है।
- **कार्बन तटस्थता:** नए राष्ट्रपति बिडेन ने 2050 के बाद "नेट-शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए प्रवर्तन तंत्र" का वादा किया है, जिसमें 2025 में उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद का कोई भी लक्ष्य शामिल नहीं है।
- **उन्नत वित्त पोषण:** कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की योजना एक नियोजित संघीय निवेश द्वारा सहायता प्राप्त की जा रही है जो निजी निवेशों के अलावा दस वर्षों में कुल 1.7 ट्रिलियन $ होगी।
- **बहुपक्षीयता और जवाबदेही:** चुनाव से पहले जारी उनकी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण न्याय की योजना में, बिडेन का कहना है कि अमेरिका फिर से बहुपक्षवाद का जोरदार समर्थन करेगा, लेकिन जीएचजी उत्सर्जन पर शीर्ष उत्सर्जक, चीन सहित अन्य देशों से जवाबदेही का भी आह्वान करेगा।

अन्य देशों के लिए श्री बिडेन की नीति का क्या अर्थ है?

- अंतर्राष्ट्रीय मंचों में अमेरिका से भागीदारी बढ़ाने और दूसरों से जवाबदेही की मांग करने का मतलब है कि जो राष्ट्र डिफ़ॉल्ट रूप से कार्बन समायोजन शुल्क या कोटा का सामना कर सकते हैं।
- ग्लासगो में इस साल के संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में नए प्रशासन को UNFCCC के सदस्य-राष्ट्रों को वैश्विक महत्वाकांक्षा को पूरा करते हुए देखा जाएगा।
- इसका मतलब यह भी है कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए उम्मीदें हैं जो ग्रीन क्लाइमेट फंड के माध्यम से वह सहायता प्राप्त कर सकते हैं जो विकसित देशों से क्लीनर महंगी प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने में मदद करेंगे।

जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - अंतर्राष्ट्रीय संबंध और GS- III - जलवायु परिवर्तन

समाचार में-

- भारतीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन **2021** को संबोधित किया।
- आयोजन: नीदरलैंड

महत्वपूर्ण बिंदु

- शिखर सम्मेलन में नए निवेश हासिल करने पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाखों छोटे-छोटे किसान खाद्य उत्पादन के लिए जलवायु के तनाव के अनुकूल हो सकें।
- शिखर सम्मेलन के दौरान, यह कहा गया कि भारत **2030** तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के **450** गीगावाट को लक्षित कर रहा है।
- यह एलईडी रोशनी को भी बढ़ावा दे रहा है और सालाना **38** मिलियन टन कार्बन-डाय-ऑक्साइड उत्सर्जन को बचा रहा है।
- भारत **2030** तक **26** मिलियन हेक्टेयर अवसादित भूमि को पुनर्स्थापित करने जा रहा है।
- **80** मिलियन ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने वाला ईंधन प्रदान किया जा रहा है।
- **64** मिलियन घरों को पाइप जलापूर्ति से जोड़ा जा रहा है।

समाचार में जगह: सिंगुर पठार

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - पर्यावरण

समाचार में-

- सुप्रीम कोर्ट ने **14** अक्टूबर, **2020** को गठित एक तकनीकी समिति के सदस्य के रूप में संरक्षणवादी नंदिता हजारिका को नियुक्त किया था, जो नीलगिरी कलेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ भूमि मालिकों द्वारा शिकायतें सुनने के लिए नियुक्त की गयी थे, जिसमें "हाथी गलियारे के एक हिस्से में मनमाना विचरण" भी शामिल था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- **14** अक्टूबर को, **SC** ने 'हाथी कॉरिडोर' को अधिसूचित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के अधिकार को बरकरार रखा और नीलगिरि जीवमंडल रिजर्व के माध्यम से जानवरों के प्रवासी पथ की रक्षा की।
- गलियारा पारिस्थितिक रूप से नाजुक सिगुर पठार में स्थित है।

क्या आपको पता है?

- सिगुर पठार तमिलनाडु के नीलगिरि पहाड़ियों में नीलगिरि जिले के उत्तर और पूर्व में स्थित एक पठार है।
- यह पश्चिमी और पूर्वी घाटों को जोड़ता है और हाथी आबादी और उनकी आनुवंशिक विविधता को बनाए रखता है।
- इसके दक्षिण-पश्चिम की ओर नीलगिरि पहाड़ियाँ और इसके उत्तर-पूर्वी किनारे पर मोयार नदी घाटी है।
- हाथी भोजन और पानी की तलाश में पठार को पार करते हैं।

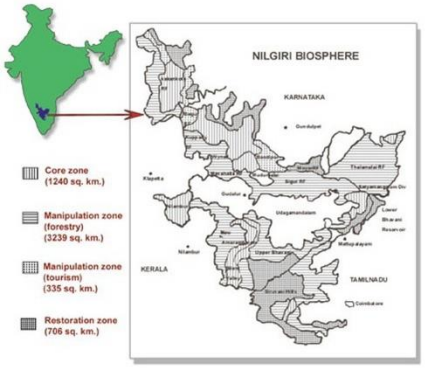

- Image source: Click here

राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - पर्यावरण; जैव विविधता

समाचार में-

- विशाल समुद्री जीवों और कछुओं के संरक्षण के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी, 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021-2026 (National Marine Turtle Action Plan 2021-2026) पर दिशा-निर्देश जारी किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- समुद्री कछुओं के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित और भागीदारी तंत्र के माध्यम से समुद्री कछुओं और संबद्ध प्रजातियों के लिए एक व्यवहार्य और स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना।
- महत्वपूर्ण तथ्य: समुद्री कछुओं का समुद्री जैव विविधता की संरचना और क्रियाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव है। समुद्री कछुए स्वस्थ समुद्री पर्यावास को बनाए रखने के लिए कई तरह की पारिस्थितिक भूमिकाएँ निभाते हैं।
- समुद्री कछुओं की प्रजातियों, उनके आवास का संरक्षण करना और उन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करना।
- एक समन्वित तंत्र के माध्यम से समुद्री कछुए और उनके आवास की समझ में सुधार करना।

- समुद्री कछुए और उनके निवास स्थान के संरक्षण पर जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना।
- सतत इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के माध्यम से तटीय समुदायों की आजीविका में वृद्धि करना।
- समुद्री कछुआ संरक्षण के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने समुद्री मेगा फॉना स्ट्रैंडिंग दिशानिर्देश'और 'राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना' जारी की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

भारत में कछुओं की स्थिति

भारतीय कछुओं की पांच प्रजातियां IUCN की स्थिति के साथ इस प्रकार हैं:

1. जैतून रिडले () - कमजोर
2. ग्रीन कछुआ - लुप्तप्राय
3. लोगर हेड - कमजोर
4. हॉक्सबिल - गंभीर रूप से लुप्तप्राय
5. लेदर बैक - कमजोर

- वे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची I के तहत संरक्षित हैं।
- वे जैव विविधता संरक्षण और गंगा कायाकल्प कार्यक्रम के तहत भी संरक्षित हैं।

Related articles:

- World Turtle Day 2020: Click here

समाचारों में प्रजातीयां / राष्ट्रिय उद्यान

खबरों में प्रजाति: कोला कोलार लीफ-नोज़्ड बैट (Kolar Leaf-Nosed Bat)

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - जैव विविधता

समाचार में-

- कर्नाटक वन विभाग, बैट कंजर्वेशन इंडिया ट्रस्ट (बीसीआईटी) के साथ, कोलार लीफ-नोज़्ड बैट (**Kolar Leaf-Nosed Bat**) को विलुप्त होने से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है।

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन

- सामान्य नाम: कोलार लीफ-नोज़्ड बैट (**Kolar Leaf-Nosed Bat)** या लीफलेटेड लीफ- नोज़्ड बैट।
- वैज्ञानिक नाम: **हिप्पोसाइडरोस हाइपोफिलस (**Hipposideros hypophyllus)
- यह हिप्पोसाइडरोस परिवार के बैट या चमगादड़ की एक प्रजाति है।
- निवास स्थान: इसके प्राकृतिक आवास उपोष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय शुष्क जंगल और गुफाएं हैं।
- यह भारत के लिए स्थानिक है।
- यह कर्नाटक के कोलार जिले में हनुमानहल्ली गाँव में केवल एक गुफा में पाया जाता है।
- इसकी जनसंख्या **200** व्यक्तियों से कम है।
- **IUCN** लाल सूची: गंभीर रूप से संकटग्रस्त

गंगा नदी डॉल्फिन

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में-

- उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हाल ही में सोशल मीडिया पर एक गंगा डॉल्फिन को पीट-पीट कर मार डाला गया।
- लुप्तप्राय प्रजाति, गंगा नदी डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय जलीय जानवर के रूप में मान्यता प्राप्त है।

महत्वपूर्ण तथ्य

गंगा डॉल्फिन

- वैज्ञानिक नाम: प्लैटनिस्टा गैंगेटिका (**Platanista gangetica)**
- यह आमतौर पर अंधे होते हैं।

- यह एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उत्सर्जन करके अपने शिकार को पकड़ते हैं जो शिकार तक पहुँचती है।
- इन्हें सुसु भी कहा जाता है।
- यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, विशेष रूप से गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली-सांगु नदी प्रणालियों में और गंगा की सहायक नदियों में।
- खतरा: बांध, प्रदूषण, अत्यधिक सिल्टिंग और रेत खनन का निर्माण।
- इसे भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मान्यता दी है
- यह गुवाहाटी, असम का आधिकारिक पशु है।
- आईयूसीएन स्थिति: लुप्तप्राय

क्या आपको पता है?

- यह **CITES** के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है तथा **IUCN** की लुप्तप्राय **(Endangered)** सूची में शामिल है।
- यह प्रवासी प्रजाति **(**सीएमएस**)** पर कन्वेंशन के परिशिष्ट **II** में भी शामिल हैं।
- स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन **5** अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

Related articles:

- Project Dolphin announced: Click here
- Project Lion and Project Dolphin: Click here

लाल पांडा की दोनों प्रजातियों के लिए भारत आवास है: ZSI

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - पारिस्थितिकी और जैव विविधता
समाचार में-

- **जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि भारत दोनों (उप) प्रजातियों - हिमालयन रेड पांडा** (Ailurus fulgens) **और चीनी लाल पांडा** (Ailurus styani) **का घर है**
- **लाल** पांडा की दो अलग-अलग प्रजातियां हैं, इसमें पहली **Ailurus fulgens** जिसे आमतौर पर हिमालयन रेड पांडा के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी **Ailurus fulgens styani** है, जिसे आमतौर पर चाइनीज रेड पांडा के नाम से जाना जाता है, •जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि भारत इन दोनों प्रजातियों के लिए आवस हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी इन दो फ़ाइलोजेनेटिक प्रजातियों को विभाजित करती है।
- लाल पांडा को **2020** तक एक मोनोटाइपिक प्रजाति माना गया था जब तक कि वैज्ञानिकों ने भौगोलिक वितरण के संबंध में आनुवंशिक अध्ययन नहीं किया और दोनों प्रजातियों की घटना का वर्णन किया।
- हिमालयी लाल पांडा के जनसंख्या आकार में कमी का कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी दोलनों है क्योंकि पिछले ग्लेशियल मैक्सिमा और प्लेइस्टोसिन के दौरान आद्र और शुष्क काल के दोहराया चक्रों के माध्यम से यह भारी भौगोलिक और भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के संपर्क में था।
- इसे पारिस्थितिक परिवर्तन के लिए एक संकेतक प्रजाति माना जाता है, लाल पांडा शर्मीली, एकान्त और जंगली जानवर है। यह मुख्य रूप से बांस पर फ़ीड करता है और मानव उपस्थिति से बचा जाता है।
- **ZSI** के निदेशक ने कहा कि इस पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील प्रजातियों के समग्र संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हितधारकों के प्रयास और स्थानीय समुदायों के बीच पर्याप्त जागरूकता की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- लाल पांडा **(Ailurus fulgens)** एक स्तनपायी प्रजाति है जो पूर्वी हिमालय और दक्षिण-पश्चिमी चीन में स्थित है।
- इसे **IUCN** रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है
- खतरा**:** निवास हानि और विखंडन**,** अवैध शिकार और अंतर्ग्रहण अवसाद।
- अपने नाम के बावजूद**,** यह विशाल पांडा से निकटता से संबंधित नहीं है

Related articles:

- Zoological Survey of India lists 62 species of Skinks: Click here
- Malayan Giant Squirrel could decline by 90% in India by 2050: Zoological Survey of India (ZSI): Click here
- Red Panda: Click here

सुंदरबन पक्षियों की 428 प्रजातियों का घर है: ZSI

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - जैव विविधता; वातावरण

समाचार में-

- जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) के "Birds of the Sundarban Biosphere Reserve" नाम के एक हालिया प्रकाशन के अनुसार, यह क्षेत्र पक्षियों की 428 प्रजातियों का घर है। भारतीय सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक है, जिसमें सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी शामिल है।
- कुछ पक्षी जैसे मास्क्ड फिनफुट और बफी फिश उल्लू केवल सुंदरबन में पाए जाते हैं।

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन

- भारतीय सुंदरबन में सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी शामिल है।
- 2020 में अंतिम जनगणना के अनुसार लगभग 96 शाही बंगाल बाघों का घर है।
- यह एक विश्व धरोहर स्थल और रामसर स्थल है।

मास्क्ड फिनफुट

- नकाबपोश फिनफुट या एशियाई फ़िनफ़ुट पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप, इंडोचाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया की ताज़ा और खारा आर्द्रभूमि से एक जलीय पक्षी है।

बफी फिश उल्लू

- बफी फिश उल्लू, जिसे फिश मछली उल्लू के रूप में भी जाना जाता है, परिवार स्ट्रिगिडी में एक मछली उल्लू है।
- यह दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है और उष्णकटिबंधीय जंगलों और आर्द्रभूमि में सबसे आगे रहता है।
- इसके व्यापक वितरण और ग्रहण की गई स्थिर आबादी के कारण, इसे **2004** से **IUCN** रेड लिस्ट में संकटमुक्त (**Least Concern** या **LC**) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है

इन्फ्रास्ट्रक्चर / ऊर्जा

कैबिनेट ने पारादीप पोर्ट पर इनर हार्बर फैसिलिटीज के डीपनिंग और ऑप्टिमाइजेशन को मंजूरी दी

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- 'पारादीप बंदरगाह में केप आकार के जहाजों के आवागमन के लिए सार्वजानिक – निजी साझेदारी (पीपीपी मोड) के तहत निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) के आधार पर पश्चिमी गोदी के विकास समेत आंतरिक बंदरगाह से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत और उन्नत बनाने' से जुड़ी परियोजना को मंजूरी दी है।
- **अनुमोदित**: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए)

महत्वपूर्ण बिंदु

- चालू होने के बाद, यह परियोजना कोयले और चूना पत्थर के आयात के अलावा पारादीप बंदरगाह के इर्द – गिर्द बड़ी संख्या में स्थापित इस्पात संयंत्रों की मौजूदगी को देखते हुए दानेदार स्लैग और स्टील के तैयार उत्पादों के निर्यात संबंधी जरूरतों को पूरा करेगी।
- यह परियोजना **(i)** बंदरगाह पर भीड़ को कम करेगी, **(ii)** समुद्री मालभाड़ा में कमी कर कोयला के आयात को सस्ता बनायेगी, और **(iii)** बंदरगाह के इर्द – गिर्द के इलाकों की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों का सृजन भी करेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

पारादीप बंदरगाह

- **पारा**दीप पोर्ट ट्रस्ट **(PPT),** भारत सरकार के तहत एक प्रमुख बंदरगाह और मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स अधिनियम, **1963** के तहत प्रशासित है, **1966** में इसे लौह अयस्क के निर्यात के लिए मोनो कमोडिटी पोर्ट के रूप में कमीशन किया गया था।
- **स्थान**: ओडिशा

बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) अनुबंध

- एक बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) अनुबंध एक मॉडल है जिसका उपयोग बड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है, आमतौर पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं।
- बीओटी योजना एक सार्वजनिक संस्था द्वारा प्रारंभिक रियायत को संदर्भित करती है जैसे कि एक स्थानीय सरकार दोनों को एक निजी फर्म को परियोजना का निर्माण और संचालन करती है।
- एक निर्धारित समय सीमा के बाद, आमतौर पर दो या तीन दशकों के बाद, परियोजना पर नियंत्रण सार्वजनिक संस्था को वापस कर दिया जाता है।

भारतीय रेलवे ने नए विस्टाडोम कोचों की 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार का सफल परीक्षण किया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III –इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय आधुनिक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए, भारतीय रेलवे ने आंतरिक कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित नए डिज़ाइन किए गए विस्टाडोम पर्यटक कोच की गति परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इन लक्ज़री पर्यटक कोचों का निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा किया गया है।
- यूरोपीय शैली के डिज़ाइन के इन कोचों में बाहरी दृश्यों को देखने के लिए छतों को कांच से बनाया गया है, और खिड़कियां चौड़ी रखी गई हैं।
- वर्तमान में, नीलगिरि माउंटेन रेलवे लाइन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका-शिमला रेलवे, कांगड़ा वैली रेलवे, माथेरान हिल रेलवे, मुंबई में दादर और मडगांव की अरकू घाटी के बीच के साथ-साथ कश्मीर घाटी में 13 विस्टाडोम कोचों का परिचालन किया जा रहा है।

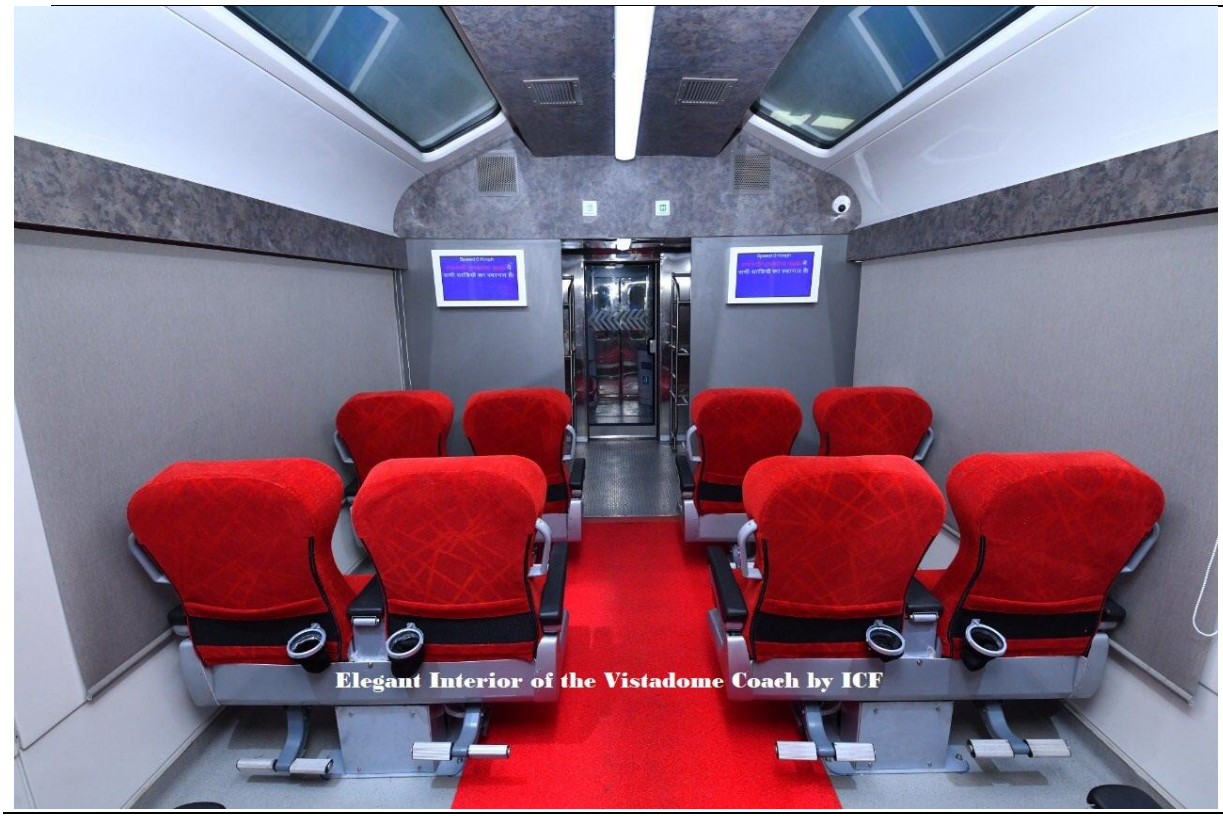

जम्मू-कश्मीर में रेलवे राष्ट्रीय परियोजना पर कार्य की प्रगति समीक्षा

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- जम्मू और कश्मीर में रेलवे राष्ट्रीय परियोजना पर कार्य की प्रगति की हाल ही में समीक्षा की गई।
- उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक **(USBRL)** परियोजना के शेष भाग पर कार्य मिशन मोड में पूरा किया जाना है।
- देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर क्षेत्र के लिए सभी मौसम की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर ध्यान दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **USBRL** भारतीय रेलवे द्वारा हिमालय के माध्यम से ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय परियोजना है।
- उद्देश्य**:** कश्मीर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना।
- सभी मौसम**,** आरामदायक**,** सुविधाजनक और लागत प्रभावी जन परिवहन प्रणाली क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उत्प्रेरक होगा।
- वर्तमान में**,** लाइन कश्मीर घाटी और जम्मू-उधमपुर-कटरा में बारामूला-बनिहाल के बीच चलने वाली ट्रेनों के परिचालन उपयोग में है।

एडीबी ने भारत असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 231 मिलियन $ ऋण पर हस्ताक्षर किया

भाग- GS **प्रीलिम्स और** GS- II - **अंतर्राष्ट्रीय संबंध और** GS- III - **इन्फ्रास्ट्रक्चर; ऊर्जा**

समाचार में-

- एशियाई विकास बैंक **(ADB)** और भारत सरकार ने **120** मेगावाट **(MW)** जलविद्युत संयंत्र के निर्माण के माध्यम से असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए **231** मिलियन **$** के ऋण पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह असम पावर सेक्टर निवेश कार्यक्रम के लिए तीसरा किश्त ऋण है जिसे जुलाई **2014** में एडीबी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- यह कार्यक्रम**,** अपने दो पिछले ट्रैन्च सहित**,** असम में ऊर्जा सेवा और वितरण प्रणालियों की क्षमता और दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है ताकि उपयोगकर्ताओं को समाप्त करने के लिए बिजली सेवा में सुधार किया जा सके।
- परियोजना के माध्यम से सुगम और स्वच्छ बिजली की आपूर्ति में वृद्धि से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ राज्य में रहने की स्थिति में सुधार**,** व्यापार विस्तार को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।
- यह परियोजना कोपिली नदी पर रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है जो **2025** तक **469** गीगावाटॉर **(GWh)** द्वारा स्वच्छ ऊर्जा से आपूर्ति की जाने वाली बिजली बढ़ाने में मदद करेगी और हर साल **360,000** टन कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगी।
- गरीबी में कमी **(JFPR)** के लिए जापान फंड से **2** मिलियन **$** का अनुदान भी इस परियोजना के साथ उपकरणों और परामर्श सेवाओं के वित्तपोषण के लिए जुड़ा हुआ है।

Related articles:

- ADB signs $500 million loan for Delhi-Meerut RRTS Corridor: Click here
- ADB and India sign $177 million loan for Maharashtra roads: Click here
- 15-billion ADB loan to India to fund COVID-19 emergency: Click here

---

कोच्चि-मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि-मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को **5** जनवरी को सुबह **11** बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- **450** किलोमीटर की पाइपलाइन गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा बनाई गई है
- इसमें प्रति दिन **12** मिलियन मानक क्यूबिक मीटर की परिवहन क्षमता है
- यह कोच्चि से मंगलुरु तक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) रेगेसिफिकेशन टर्मिनल से प्राकृतिक गैस ले जाएगा
- पाइपलाइन का बिछाना एक इंजीनियरिंग चुनौती थी क्योंकि पाइपलाइन के मार्ग ने **100** से अधिक स्थानों पर जल निकायों को पार करना था। यह एक विशेष तकनीक के माध्यम से किया गया था जिसे क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग विधि कहा जाता है।
- पाइपलाइन पर्यावरण के अनुकूल और किफायती ईंधन की आपूर्ति घरों, परिवहन क्षेत्र और जिलों में वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को करेगी।

सागरमाला विमान सेवा (एसएसपीएस)

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - नीतियां और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय सागरमाला सीप्लेन सर्विसेज (SSPS) की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत कर रहा है, जिसमें एयरलाइन ऑपरेटर शामिल हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

पोर्ट्स, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय संभावित एयरलाइन ऑपरेटरों के माध्यम से एक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) ढांचे के तहत, चुनिंदा मार्गों पर, सीप्लेन सेवाओं के संचालन शुरू कर रहा है।

- परियोजना का क्रियान्वयन और कार्यान्वयन सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड **(SDCL)** के माध्यम से होगा, जो मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- सीप्लेन संचालन के लिए कई स्थलों की परिकल्पना की गई है।
- हब और स्पोक मॉडल के तहत प्रस्तावित उत्पत्ति-गंतव्य जोड़े में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीप, असम में गुवाहाटी रिवरफ्रंट और उमरानो जलाशय, यमुना रिवरफ्रंट / दिल्ली (हब) के रूप में अयोध्या आदि शामिल हैं।
- ऐसी एक सीप्लेन सेवा अहमदाबाद में केवडिया और साबरमती रिवरफ्रंट के बीच पहले से ही चल रही है, जिसका उद्घाटन **31** अक्टूबर **2020** को प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था।

डबल स्टैक लॉन्ग हेल कंटेनर ट्रेन ऑपरेशन को हरी झंडी दिखाई गयी

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- **7** जनवरी **2021** को, भारतीय प्रधान मंत्री दुनिया के पहले डबल स्टैक लांग हाऊल **1.5** किमी लंबी कंटेनर ट्रेन को न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

महत्वपूर्ण बिंदु

- डबल स्टैक, लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन ऑपरेशन में **25** टन का बढ़ा हुआ एक्सल लोड होगा।
- डिजाइन क्षमता उपयोग और वर्दी वितरित और बिंदु लोडिंग को अधिकतम करेगा।
- ये वैगनों को भारतीय रेलवे पर वर्तमान यातायात की तुलना में कंटेनर इकाइयों के संदर्भ में चार गुना एक बार में ले जा सकता है।

रेवाड़ी-न्यू मदार फ्रेट कॉरिडोर देश को किया समर्पित

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- भारतीय प्रधान मंत्री देश को **306** किलोमीटर नई रेवाड़ी - पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) का नया मदार खंड **7** जनवरी **2021** को राष्ट्र को समर्पित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- द न्यू रेवाड़ी - वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नया मदार खंड हरियाणा और राजस्थान में स्थित है।
- इस खिंचाव के खुलने से राजस्थान और हरियाणा के विभिन्न उद्योगों को लाभ होगा।
- यह काठुवास में **CONCOR** के कंटेनर डिपो के बेहतर उपयोग को भी सक्षम करेगा।
- यह खंड गुजरात में स्थित कांडला, पिपावाव, मूंदड़ा और दाहेज के पश्चिमी बंदरगाहों के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा।
- इस खंड के उद्घाटन के साथ, डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी के बीच सहज संपर्क प्राप्त होगा।
- इससे पहले **351** किलोमीटर का न्यू भूपुर- ईडीएफसी का न्यू खुर्जा खंड **29** दिसंबर **2020** को प्रधान मंत्री द्वारा देश को समर्पित किया गया था।

विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में जलमार्ग में सुधार के लिए $ 105 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - अंतर्राष्ट्रीय संबंध और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 105 मिलियन $ की परियोजना पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पश्चिम बंगाल अंतर्देशीय जल परिवहन, रसद और स्थानिक विकास परियोजना की सुविधा होगी: (1) हुगली नदी के पार यात्री और माल ढुलाई ; (2) कोलकाता महानगर क्षेत्र में पहुंच में सुधार के लिए स्थानिक योजना को बनाना; (3) अपने निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना; (4) राज्य के रसद क्षेत्र की वृद्धि में योगदान।

- अंतर्देशीय जलमार्ग अब एक प्रभावी और यात्री और माल ढुलाई के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में उभर रहे हैं।
- यह परियोजना पश्चिम बंगाल में नदी परिवहन के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन एरिया में बाजारों और नौकरी केंद्रों के साथ हिंडलैंड को जोड़कर राज्य के आर्थिक विकास में मदद करेगी।
- यह परियोजना दक्षिणी पश्चिम बंगाल के पांच सबसे अधिक आबादी वाले जिलों को कवर करेगी, जिसमें इसके शहरी समूह - कोलकाता महानगर क्षेत्र (केएमए) शामिल हैं, जहां लगभग **30** मिलियन लोग या पश्चिम बंगाल की एक तिहाई आबादी रहती है।

क्या आपको पता है?

- **पहले चरण में:** परियोजना क्षमता को बढ़ाएगी और अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली की सुरक्षा में सुधार करेगी, जिसमें मौजूदा जेटी का पुनर्वास करना, बढ़ी हुई डिजाइन के साथ नए घाट खरीदना और 40 स्थानों पर इलेक्ट्रिक गेट स्थापित करना शामिल है।
- **दूसरे चरण में: यह समर्थन करेगा** - **(1)** यात्री आंदोलनों के लिए दीर्घकालिक निवेश, जिसमें टर्मिनल और जेटी शामिल हैं; **(2)** अंतर्देशीय जल परिवहन जहाजों के डिजाइन में सुधार; **(3)** सबसे खतरनाक और ट्रैफिक वाले मार्गों और क्रॉसिंग पॉइंट पर रात के नेविगेशन को सुनिश्चित करना; **(4)** निजी क्षेत्र को रो-रो जहाजों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना जो हुगली नदी के पार ट्रकों की आसान आवाजाही की अनुमति देगा।
- बढ़ी हुई वर्षा और बाढ़ से बेहतर सामना करने के लिए, जलवायु-स्मार्ट इंजीनियरिंग समाधान लागू किए जाएंगे।
- यह परियोजना विकलांग-अनुकूल सुविधाओं की सुविधा प्रदान करेगी, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- हुगली नदी कोलकाता में गंगा नदी की एक शाखा है।
- यह कोलकाता बंदरगाह को अपने बड़े खपत वाले केंद्रों से अलग करता है, जिसका विस्तार इसके थोक बाजार और इसकी विशाल पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिसमें पूरे उत्तर पूर्वी भारत और दो पड़ोसी देश नेपाल और भूटान शामिल हैं।
- वर्तमान में 80% से अधिक माल और यात्री यातायात कोलकाता के तीन पुलों के माध्यम से नदी को पार करते हैं।
- भीड़भाड़ को कम करने के लिए, शहर ने कुछ पुलों तक ट्रकों की आवाजाही को सीमित कर दिया है और केवल सीमित घंटों के दौरान, बंदरगाह तक पहुंच को कम करने और रसद की लागत को बढ़ाया है।

फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को हाल ही में माल ग्राहकों की सभी जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में लॉन्च किया गया था।
- मंत्रालय: रेल मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- पोर्टल को मानव-से-मानव बातचीत की आवश्यकता को कम करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रियाओं के साथ शारीरिक प्रक्रियाओं को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह उन्हें मूल रूप से रेल मोड का उपयोग करने में मदद करेगा।
- माल व्यवसाय पोर्टल का व्यक्तिगत डैशबोर्ड ग्राहकों को रेलवे में उनके व्यवसाय, उत्कृष्ट संकेत, ऑन-रन खेप, विभिन्न इंटरैक्शन की स्थिति और विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन करने और चिंताओं को बढ़ाने के लिए एक दृश्य प्रदान करता है।
- ग्राहकों को छूट स्कीमों, डायवर्सन, रीबुकिंग, डीमर्जेज और घाट छूट, स्टैकिंग अनुमतियों के बारे में भी पता चलता है।

भारतीय रेल ने स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्णिम कोणीय (डायगोनल) खंडों में 130 किमी प्रति घंटा तक गति बढ़ाई

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- भारतीय रेल ने स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्णिम कोणीय (जीक्यू-जीडी) रूट में 1,612 किलोमीटर में से 1,280 किमी लंबाई के लिए अधिकतम गति उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर 130 किमी प्रति घंटा कर देने के द्वारा एक ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित कर नए वर्ष की शुरुआत की है। यह विजयवाड़ा - दुव्वाडा खंड को छोड़कर, जहां सिग्नल अप-ग्रेडेशन कार्य प्रगति पर है, दक्षिण मध्य रेलवे के समस्त जीक्यू-जीडी रूट को कवर करती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह संवर्धित गति सीमा तेज गति से इन खंडों में बाधाओं को हटाने के द्वारा ट्रैक एवं इसकी अवसंरचना की व्यवस्थित और नियोजित सुदृढ़ीकरण के जरिए अर्जित की जा सकी। इसमें भारी छड़ों, 260 मीटर लंबे वेल्डेड रेल पैनल बिछाने, मोड़ों एवं ढलानों में सुधार शामिल थे।

- रेलवे ने सभी आवश्यक अवसंरचना अपग्रेडेशन कार्यों को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष (कोविड-19 महामारी के कारण) लॉकडाउन अवधि एवं रेलगाड़ियों की कम आवाजाही के अवसर का उपयोग किया है।
- जोन द्वारा किए गए इन सुधारों के आधार पर आरडीएसओ/ लखनऊ ने पिछले साल जुलाई और अक्टूबर के दौरान 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सभी वर्गों के इस्ट्रूमेंटेड कोचों से निर्मित कन्फर्मेटरी ऑसिलोग्राफ कार रन (सीओसीआर) के माध्यम से ऑसीलेशन परीक्षण किए।
- इस जांच के दौरान ट्रैक मापदंडों के अतिरिक्त सिग्नलिंग पहलू, ट्रैक्शन वितरण उपकरण, लोकोमोटिव एवं कोच फिटनेस जैसे अन्य क्षेत्रों को भी जांचा और रिकॉर्ड किया गया
- सिकंदराबाद - काजीपेट (132 किलोमीटर की दूरी) के बीच हाई-डेंसिटी नेटवर्क (एचडीएन) में अधिकतम गति सीमा पहले ही 130 किमी प्रति घंटे तक बढ़ा दी गई थी।
- इस प्रकार, इन खंडों में अप और डाउन दोनों लाइनों सहित कुल 2,824 किलोमीटर (1412 रूट किमी) को अब 130 किमी प्रति घंटे की गति से चलाने के उपयुक्त बना दिया गया है। यह विजयवाड़ा - दुव्वाडा खंड को छोड़कर जहां सिग्नल अप-ग्रेडेशन कार्य प्रगति पर है, दक्षिण मध्य रेलवे के समस्त जीक्यू-जीडी रूट को कवर करती है।
- उल्लेखनीय है कि कोविड महामारी के बावजूद भारतीय रेल ने अवसंरचना, नवोन्मेषण, नेटवर्क के क्षमता विस्तार, माल ढुलाई विविधीकरण के विकास में अभूतपूर्व वृद्धि अर्जित की है। रेलवे ने कोविड चुनौती का उपयोग भविष्य के विकास और यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव के अगले स्तर की आधारशिला रखने के एक अवसर के रूप में किया है।

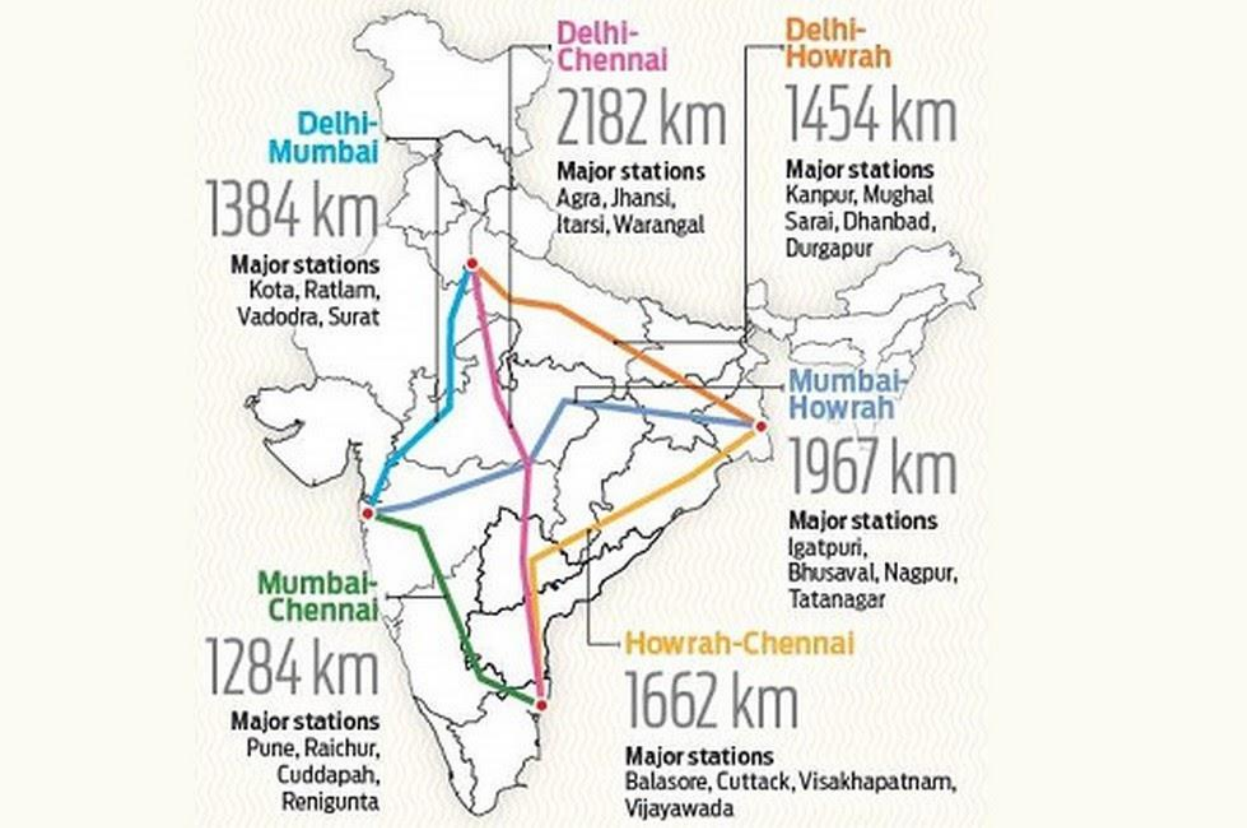

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन

- स्वर्णिम चतुर्भुज (GQ) एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है जो भारत के अधिकांश प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ता है।
- यह भारत के चार प्रमुख मेट्रो शहरों, दिल्ली, (उत्तर), कोलकाता (पूर्व), मुंबई (पश्चिम) और चेन्नई (दक्षिण) को जोड़ने वाला एक चतुर्भुज बनाता है।
- यह भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और दुनिया में पांचवीं सबसे लंबी है।
- यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) का पहला चरण है, और इसमें 600 बिलियन की लागत से निर्मित चार- और छह-लेन एक्सप्रेस हाईवे शामिल हैं।
- स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत किया जाता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

कैबिनेट ने CBIC के तहत कृष्णापटनम और तुमकुरु में औद्योगिक कॉरिडोर नोड्स को मंजूरी दी

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III -इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- मंत्रिमंडल ने सीबीआईसी के तहत आंध्र प्रदेश के कृष्णपट्टनम और कर्नाटक के तुमकुरु में औद्योगिक गलियारे को मंजूरी दी है।
- वहीं ग्रेटर नोएडा में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) को भी मंजूरी दी गई है।
- अनुमोदित प्रस्तावों की कुल अनुमानित लागत **7,725** करोड़ रु. और **2.8** लाख से अधिक व्यक्तियों की अनुमानित रोजगार सृजन है।
- ये उद्योगों को गुणवत्ता, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढांचा प्रदान करके देश में विनिर्माण निवेश की सुविधा प्रदान करेंगे।
- निवेश को आकर्षित करने के लिए तत्काल आवंटन के लिए शहरों में विकसित भूमि पार्सल के साथ ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थान दिया जाएगा।
- स्वीकृत प्रस्ताव "आत्मनिर्भर भारत" और "मेक इन इंडिया" को एक प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब

- लॉजिस्टिक हब परियोजना को एक विश्व स्तरीय सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा जो समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) को माल का कुशल भंडारण प्रदान करेगी।
- यह माल कंपनियों और ग्राहकों को वन-स्टॉप गंतव्य की पेशकश करेगा।
- सुविधा मानक कंटेनर हैंडलिंग गतिविधियाँ प्रदान करेगी।
- यह परिचालन की बेहतर दक्षता के साथ रसद लागत को कम करने के लिए विभिन्न मूल्य वर्धित सेवाएं भी प्रदान करेगा।

मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH) प्रोजेक्ट

- यह एक सहज तरीके से यात्रियों के लिए रेल, सड़क और **MRTS** पहुंच की व्यवस्था के साथ एक परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- **MMTH** में इंटर स्टेट बस टर्मिनल **(ISBT),** लोकल बस टर्मिनल **(LBT),** मेट्रो, कमर्शियल, रिटेल और होटल स्पेस और ग्रीन ओपन स्पेस के लिए जगह होगी।
- यह परियोजना यूपी में आगामी विकास के लिए कैचमेंट ज़ोन की बढ़ती आबादी के लिए विश्व स्तरीय यात्री गतिविधी की सुविधा प्रदान करेगी।
- इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

अमेरिकी ड्रगमेकर मॉडर्न इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन (EUA) के लिए आवेदन किया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- अमेरिकी दवा निर्माता मॉडर्न ने कहा कि वह अपने कोविद **-19** वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए आवेदन कर रहा था।
- भारत में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के एक संस्करण का परीक्षण कर रहा है, ने कहा है कि यह अगले दो हफ्तों के भीतर आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण की तलाश करने की उम्मीद करता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- टीके, दवाइयां, नैदानिक परीक्षण और चिकित्सा उपकरण, एक नियामक प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता होती है इससे पहले कि वे प्रशासित हो सकें।
- भारत में, नियामक प्राधिकरण केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन **(CDSCO)** है।
- टीकों और दवाओं के लिए, परीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, उनकी सुरक्षा और प्रभावशीलता के आकलन के बाद अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
- यह एक लंबी प्रक्रिया है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि एक दवा या टीका बिल्कुल सुरक्षित और प्रभावी है।
- आपातकालीन स्थितियों में, जैसे कि **COVID-19,** दुनिया भर के नियामक अधिकारियों ने अंतरिम अनुमोदन प्रदान करने के लिए तंत्र विकसित किए हैं यदि कोई मेडिकल उत्पाद सुरक्षित और प्रभावी होने का पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता हैं।
- परीक्षण और पूर्ण डेटा के विश्लेषण के पूरा होने के बाद ही अंतिम मंजूरी दी जाती है; तब जाकर आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (ईयूए) दवा या वैक्सीन को जनता पर इस्तेमाल करने की अनुमति देता है।

तिहान-आईआईटी हैदराबाद

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - नवाचार; विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारत की स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली (स्थलीय और हवाई) के लिए प्रथम परीक्षण स्थल 'तिहान-आईआईटी हैदराबाद' **(TiHAN-IIT Hyderabad)** की वर्चुअल माध्यम में आधारशिला रखी

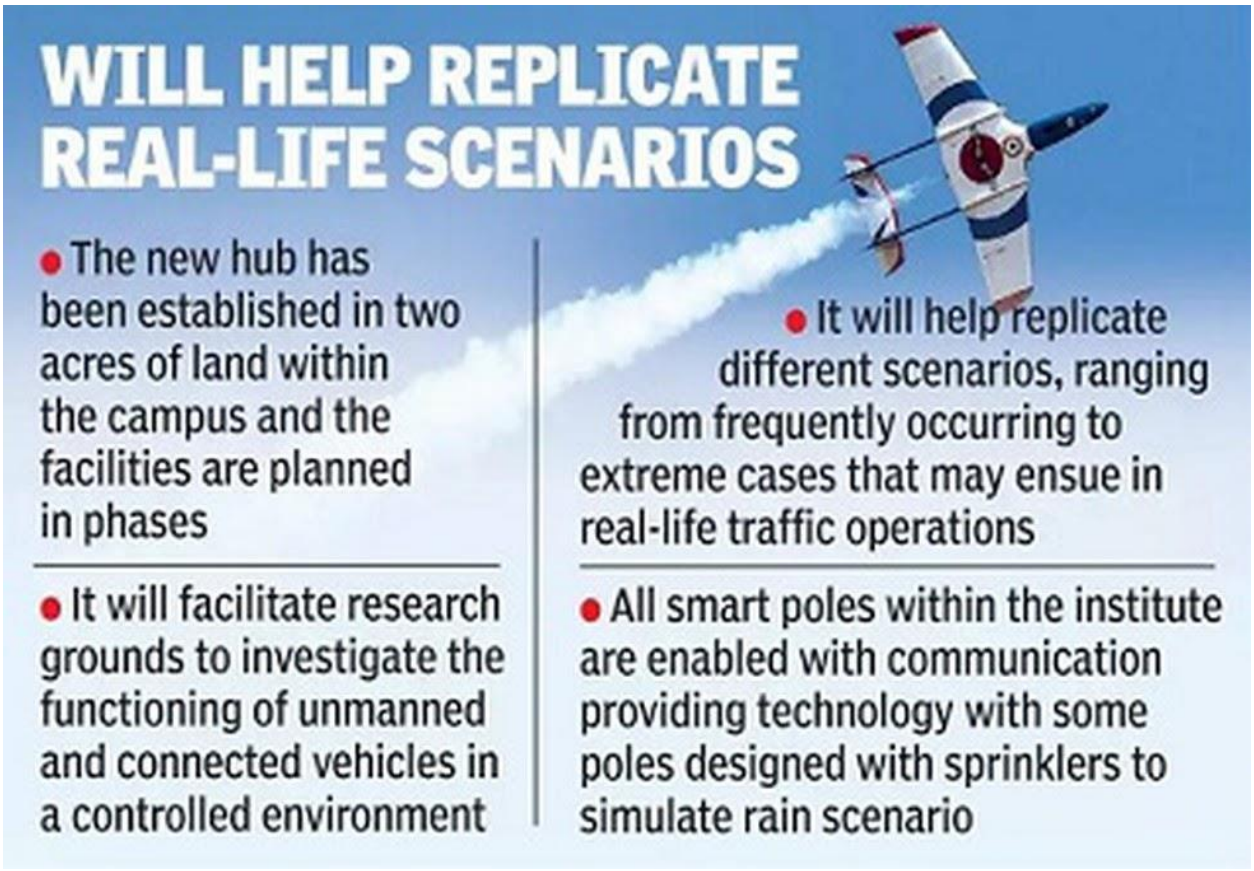

मुख्य विशेषताएं:

- इस इकाई में टेस्ट ट्रैक, वास्तविक-विश्व परिदृश्यों का अनुकरण (Emulation of Real-World Scenarios), आधुनिक सिमुलेशन टेक्नोलॉजी (State of the Art Simulation Technologies), सड़क सुविधा, V2X कम्युनिकेशन, ड्रोन रनवे और लैंडिंग एरिया, मैकेनिकल इंटीग्रेशन सुविधा, केन्द्रीयकृत नियंत्रण कक्ष/भूतल नियंत्रण केन्द्र, हैंगर (Hangars) आदि शामिल हैं।
- भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने राष्ट्रीय अंतर-विषयी साइबर-फिजिकल सिस्टम (National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems: NM-ICPS) मिशन के तहत स्वायत्त नेविगेशन और डेटा अधिग्रहण प्रणाली (UAVs, RoVs आदि) पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार केन्द्र स्थापित करने हेतु आईआईटी हैदराबाद के लिए 135 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
- आईआईटी हैदराबाद में मानव रहित वायुयानों तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों के लिए स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केन्द्र को 'तिहान फाउंडेशन' के रूप में जाना जाता है। इसे जून 2020 में संस्थान द्वारा खंड-8 कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2018 में पांच साल की अवधि के लिए 3660 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय अंतर-विषयी साइबर-फिजिकल सिस्टम मिशन (NM-ICPS) को मंजूरी दी गई थी।

लेह (लद्दाख) में मौसम विज्ञान (मेट) सेंटर का उद्घाटन हुआ

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने लेह (लद्दाख) में मौसम विज्ञान (मेट) केंद्र का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- **3500** मीटर की ऊँचाई पर स्थित, मौसम विज्ञान केंद्र लेह भारत का सबसे ऊँचा मौसम केंद्र होगा।
- केंद्र उच्च ऊंचाई वाले मौसम विज्ञान के लिए एक विश्व स्तरीय सुविधा होगी।
- यह लोगों और लद्दाख के प्रशासन की विभिन्न प्रकार की मौसम और जलवायु आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
- यह नुब्रा, चांगथांग, पैंगोंग झील, ज़ांस्कर जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए पूर्वानुमान प्रदान करेगा।

लेह में एक मेट सेंटर की आवश्यकता

- लद्दाख क्षेत्र में ऊंचे ढलान वाले पहाड़ हैं और कोई वनस्पति नहीं है और बहुत सारी ढीली मिट्टी और मलबे हैं जो इस क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक खतरों जैसे कि बादल फटने **(2010** के), फ्लैश फ्लड्स, हिमस्खलन और हिमनद झील के प्रकोप, आदि के लिए इसे असुरक्षित बनाते हैं।
- भविष्य में ऐसी मौसम की घटनाओं के कारण नुकसान को कम करने के लिए, सरकार ने लद्दाख में संबंधित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए लेह में कला मौसम विज्ञान (मौसम) केंद्र की स्थापना की आवश्यकता महसूस की।

नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - विज्ञान और तकनीक; वातावरण

समाचार में-

- भारतीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में **4** जनवरी **2021** को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- आयोजित: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली
- थीम: राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी।
- इस अवसर पर नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल (**National Atomic Time Scale**) और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली (**Bharatiya Nirdeshak Dravya Pranali**) को राष्ट्र को समर्पित किया गया।
- मेट्रोलॉजी को इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ़ वेट्स एंड मेज़र्स (**BIPM**) द्वारा परिभाषित किया गया है- "माप विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में अनिश्चितता के किसी भी स्तर पर दोनों के प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक निर्धारण को अपनाता है"

क्या आपको पता है?

- नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल भारतीय मानक समय को 2.8 नैनो सेकंड की सटीकता प्रदान करता है।
- अब भारतीय मानक समय 3 नैनो सेकंड से भी कम सटीक स्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के अनुरूप हो गया है।
- राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला परिवेशी वायु और औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण के आत्मनिर्भरता में सहायता करेगी।

अंटार्कटिका के लिए 40 वाँ भारतीय वैज्ञानिक अभियान

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - विज्ञान और तकनीक;

समाचार में-

- भारत ने अंटार्कटिका के लिए **40** वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह भारतीय अभियान अंटार्कटिका के लिए भारत के वैज्ञानिक प्रयास के चार दशकों का प्रतीक है।
- **40** वीं अभियान यात्रा को **5** जनवरी, **2021** को गोवा से रवाना किया जाएगा, जिसमें **43** सदस्य जहाज पर होंगे।
- चार्टर्ड आइस-क्लास पोत एमवी वासिली गोलोविन यह यात्रा करेंगे और **30** दिनों में अंटार्कटिका पहुंचेंगे।
- **40** सदस्यों की एक टीम को पीछे छोड़ने के बाद, यह अप्रैल **2021** में भारत लौट आएगा।
- वापसी पर, यह पूर्ववर्ती यात्रा की शीतकालीन टीम को भी वापस लाएगा।

क्या आपको पता है?

- **1981** में भारतीय अंटार्कटिक अभियान शुरू हुआ।
- भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम को अब अंटार्कटिका में तीन स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाने का श्रेय दिया गया है, जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती है।
- अंटार्कटिका में, भारत के दो परिचालन अनुसंधान स्टेशन हैं जिनका नाम मैत्री और भारती है।
- नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च **(NCPOR)**, गोवा, संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है।

ज्वार के कारण वर्षा में बाढ़ की आशंका: एक नया मापदंड

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I - भूगोल और GS- III - विज्ञान और तकनीकी

समाचार में-

- यह समझने के लिए कि क्या एक तटीय शहर ज्वार की घटनाओं या अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ के खतरे का सामना कर रहा है, आईआईटी बॉम्बे की एक टीम ने एक नया मापदंड तैयार किया, जिसे टाइड-रेनफॉल फ्लड क्वोटिएंट कहा जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पिछले वर्षा के आंकड़ों, ज्वार के आंकड़ों और क्षेत्र की स्थलाकृति का उपयोग करके इसको प्रमुख कारक को इंगित करने के लिए लागू किया जा सकता है।
- टीम ने तीन भौगोलिक रूप से विविध बाढ़-ग्रस्त तटीय क्षेत्रों का चयन किया है - मुंबई में मिथी कैचमेंट, ओडिशा में जगतसिंहपुर जिला और तमिलनाडु में ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन पर इस नई मीट्रिक का परीक्षण किया जायेगा।
- नई पद्धति ने इन क्षेत्रों को ज्वार प्रभुत्व या वर्षा के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में वर्गीकृत करने में मदद की।
- मेट्रिक दीर्घकालिक प्रबंधन की दिशा में बेहतर बाढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को तैयार करने में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों की मदद कर सकता है।

क्या आपको पता है?

- **2018** के **C40** शहरों की रिपोर्ट में कहा गया है कि **2050** तक **570** से अधिक निचले तटवर्ती शहरों में बढ़ते समुद्र और तूफान के प्रभाव के प्रभाव से **800** मिलियन से अधिक लोगों को खतरे में डालते हुए कम से कम **0.5** मीटर तक समुद्र के स्तर में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा।
- जबकि भारी वर्षा के कारण अंतर्देशीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है, तटों में ज्वार-भाटा के प्रभाव से खतरा है।

Covid-19 के रोगियों पर 'स्वस्थ वायु' का उपयोग किया जा सकता है

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II - स्वास्थ्य और GS- III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि स्वस्थ वायु का उपयोग कोविद **-19** रोगियों पर किया जा सकता है, जिन्हें **35%** तक ऑक्सीजन पहुँचाने की आवश्यकता होती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी (एनएएल) ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक नॉन-इनवेसिव वेंटिलेटर बीपैप (बीआईपीएपी) बनाया है। वेंटिलेटर को रिकॉर्ड 36 दिनों के भीतर तैयार कर लिया गया है। इसे 'स्वास्थ्य वायु' नाम दिया गया है।
- उद्देश्य: कोविद -19 महामारी की शुरुआत में वेंटिलेटर की के कमी को दूर करने लिए प्रयोग किया जायेगा।
- यह गैर-इनवेसिव द्वि-स्तरीय सकारात्मक वायुमार्ग दबाव वेंटिलेटर है।
- यह एक माइक्रोकंट्रोलर आधारित सटीक क्लोज-लूप अनुकूली नियंत्रण प्रणाली है जिसमें अंतर्निहित बायोकंपैटिबल "3 डी प्रिंटेड मैनिफोल्ड और कपलर" के साथ **HEPA** फिल्टर (अत्यधिक कुशल पार्टिकुलेट एयर फिल्टर) का प्रयोग किया गया है।
- इसमें ऑक्सीजन सांद्रता या संवर्धन इकाई को बाहरी रूप से जोड़ने के प्रावधान के साथ **CPAP, Bi-Timed, Spontaneous / AUTO** मोड जैसी विशेषताएं हैं।
- सीएसआईआर-एनएएल ने छह निजी कंपनियों के साथ इस तकनीक का व्यवसायीकरण किया है।

डीबीटी-टीएचएसटीआई फरीदाबाद में सीईपीआई केंद्रीकृत नेटवर्क लैब का उद्घाटन किया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II - स्वास्थ्य और GS- III - नवाचार; विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- दुनिया की सात प्रयोगशालाओं में से एक जिसे महामारी संबंधी तैयारी नवाचारों **(CEPI)** के लिए गठबंधन की केंद्रीकृत नेटवर्क लैब कहा जाता है, हाल ही में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट **(THSTI),** फरीदाबाद में स्थापित की गई थी।
- मंत्रालय: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

महत्वपूर्ण बिंदु

- डीबीटी-टीएचएसटीआई फरीदाबाद में सीईपीआई केंद्रीकृत प्रयोगशाला भारत में अपनी तरह की पहली और दुनिया में सात में से एक है।
- टीएचएसटीआई भारत में इस तरह की एकमात्र प्रयोगशाला है और इसे राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा परीक्षण और कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) के लिए भी मान्यता प्राप्त है।
- **CEPI,** सार्वजनिक, निजी, परोपकारी और नागरिक संगठनों के बीच एक अभिनव साझेदारी है, जो **2017** में दावोस में शुरू की गई है, ताकि भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए टीके विकसित किए जा सकें।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत-सीईपीआई मिशन को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका शीर्षक रैपिड वैक्सीन डेवलपमेंट के माध्यम से भारत सेंट्रिक महामारी तैयार करना है: भारतीय वैक्सीन विकास का समर्थन महामारी तैयार करने वाले नवाचारों (सीईपीआई) के लिए गठबंधन की वैश्विक पहल के साथ किया गया।
- उद्देश्य: **(1)** भारत में महामारी क्षमता के रोगों के लिए टीकों के विकास को मजबूत करना; **(2)** भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और वैक्सीन उद्योग में समन्वित तैयारी का निर्माण भारत में मौजूदा और उभरते संक्रामक खतरों को दूर करने के लिए।

डीबीटी-टीएचएसटीआई फरीदाबाद में सीईपीआई केंद्रीकृत नेटवर्क लैब का उद्घाटन किया गया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- II - स्वास्थ्य और GS- III - नवाचार; विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- दुनिया की सात प्रयोगशालाओं में से एक जिसे महामारी संबंधी तैयारी नवाचारों **(CEPI)** के लिए गठबंधन की केंद्रीकृत नेटवर्क लैब कहा जाता है, हाल ही में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट **(THSTI),** फरीदाबाद में स्थापित की गई थी।
- **मंत्रालय**: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

महत्वपूर्ण बिंदु

- फरीदाबाद स्थित डीबीटी-टीएचएसटीआई सीईपीआई (कोंलिएशन फॉर एपिडेमिक प्रीपरेडनेस इनोवेशंस) सेंट्रलाइज्ड प्रयोगशाला, भारत में अपनी तरह का पहली और दुनिया की सातवी प्रयोगशाला है
- **THSTI** भारत में इस तरह की एकमात्र प्रयोगशाला है और इसे राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा परीक्षण और कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं **(NABL)** के लिए भी मान्यता प्राप्त है।
- **CEPI,** सार्वजनिक, निजी, परोपकारी और नागरिक संगठनों के बीच एक अभिनव साझेदारी है, जो **2017** में दावोस में शुरू की गई थी, ताकि भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए टीके विकसित किए जा सकें।
- इंडिया सीईपीआई मिशन का उद्देश्य भारत में महामारी के लिए टीकों के विकास की दिशा में काम करना और साथ ही भारत में मौजूदा और उभरते संक्रामक खतरों को दूर करने के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और वैक्सीन उद्योग में समन्वित तैयारी का निर्माण करना है। वर्तमान में इसका प्रमुख उद्देश देश के सभी प्रयोगशालाओं में मानक विश्लेषण और एक समान क्षमताओं का उपयोग करते हुए नए कोविड-19 टीकों का मूल्यांकन करने में मदद करना है, ताकि उत्पादित वैक्सीन को दुनियाभर में उपयोग के लिए वैश्विक स्वीकृति और परिणाम हासिल हो सके।

बायो-डाइजेस्टर प्रौद्योगिकी

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण

समाचार में-

- हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (**Defence Research and Development Organisation-DRDO)** द्वारा बायो-डाइजेस्टर प्रौद्योगिकी (**Bio-Digester Technology)** विकसित की गई है। इस तकनीकी से आने वाले वर्षों में स्वच्छता क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन की संभावना है।
- **MAHA-METRO** और **DRDO** के बीच इससे सम्बंधित एक समझौता ज्ञापन **(MOU)** शुरू किया गया था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- एमओयू के माध्यम से, डीआरडीओ मेट्रो रेल नेटवर्क में मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए अपनी उन्नत बायोडाइजेस्टर एमके- **II** प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- **DRDO** का बायोडाइजेस्टर एक स्वदेशी, हरित और लागत प्रभावी तकनीक है,

- डल झील में हाउसबोटों से उत्पन्न मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए उपयुक्त इस **MK-II** बायोडाइजेस्टर का एक अनुकूलित संस्करण भी **DRDO** द्वारा **J & K** प्रशासन को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया था।

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन

- इसमें एनएरोबिक माइक्रोबियल इनोकुलम (**Anaerobic Microbial Inoculum**) तकनीकी का उपयोग किया गया है ताकि जीवों को बायोगैस और पानी में परिवर्तित किया जा सके। इसका उपयोग कृषि एवं बागवानी प्रयोजनों के लिये भी किया जा सकता है।
- इस प्रौद्योगिकी का उपयोग पारंपरिक शौचालयों में भी किया जा सकता है।
- इस प्रौद्योगिकी को स्थापित करने में पारंपरिक शौचालयों के टैंको की तुलना में कम स्थान की जरूरत होती है।
- बायो-डाइजेस्टर टैंक के रखरखाव और स्थापना की लागत भी कम होती हैं।
- टंकियों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अनुकूलित किया जा सकता है और माइनस (-) 20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक के तापमान में संचालित किया जा सकता है।
- इस तकनीक का इस्तेमाल स्वतंत्र घरों, अपार्टमेंट ब्लॉक, स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों एवं छात्रावासों में किया जा सकता है।

अरुणाचल प्रदेश का भारत में वैनेडियम के प्रमुख निर्माता बनने की संभावना

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - अर्थव्यवस्था; विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- अरुणाचल प्रदेश भारत का प्रमुख वैनेडियम उत्पादक राज्य बन सकता है. यह एक ऐसी उच्च-मूल्य की धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है.

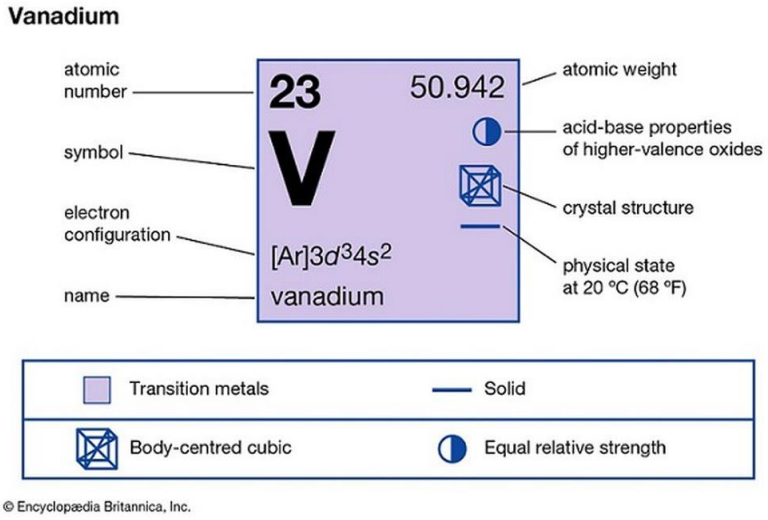

महत्वपूर्ण बिंदु

- दुनिया में सबसे ज्यादा वैनेडियम का भंडार चीन में है, उसके बाद रूस और दक्षिण अफ्रीका का स्थान अतहै।
- चीन, जो विश्व के **57%** वैनेडियम का उत्पादन करता है, ने **2017** में **44%** धातु का उपभोग किया।
- भारत वैनेडियम का एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता है, लेकिन यह धातु का प्राथमिक उत्पादक नहीं है।
- **GSI** द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत ने **2017** में दुनिया भर में उत्पादित **84,000** टन वैनेडियम का **4%** खपत किया।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण **(GSI)** ने अरुणाचल प्रदेश में पापुम पारे ज़िले **(Papum Pare District)** के डेपो और तमांग क्षेत्रों **(Depo and Tamang Areas)** में पैलेओ-प्रोटरोज़ोइक युग की कार्बोनिअस फाइलाइट चट्टानों **(Carbonaceous Phyllite Rocks)** में वैनेडियम के भंडार प्राप्त हुए हैं।
- यह भारत में वैनेडियम के प्राथमिक निक्षेप की पहली रिपोर्ट थी, जिसमें औसत ग्रेड **0.76% V2O5 [**वैनेडियम पेंटॉक्साइड**]** था।
- अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम खनिजकरण भूगर्भीय रूप से "पत्थर के कोयले" के समान है।
- यह उच्च वैनेडियम सामग्री ग्रेफाइट से जुड़ी है, जिसमें एक निश्चित कार्बन सामग्री **16%** तक है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- वेनेडियम प्रतीक **V** और परमाणु संख्या **23** के साथ एक रासायनिक तत्व है। यह एक कठिन, चांदी-ग्रे, निंदनीय संक्रमण धातु है।
- यह एक दुर्लभ तत्त्व **(Scarce Element)** है जिसकी एक उचित संरचना होती है जो अपनी प्रकृति में कठोर, सिल्की ग्रे, मुलायम और लचीली संक्रमण धातु **(Transition Metal)** है।
- वेनेडियम एक उच्च-मूल्य की धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है।

लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग सर्वे (लिडार) तकनीक से नई दिल्ली-वाराणसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - अर्थव्यवस्था; विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- **LiDAR (**एरियल ग्राउंड**)** सर्वेक्षण की शुरुआत के साथ, दिल्ली - वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए हाई स्पीड रेल कार्य की गति बढ़ गई।

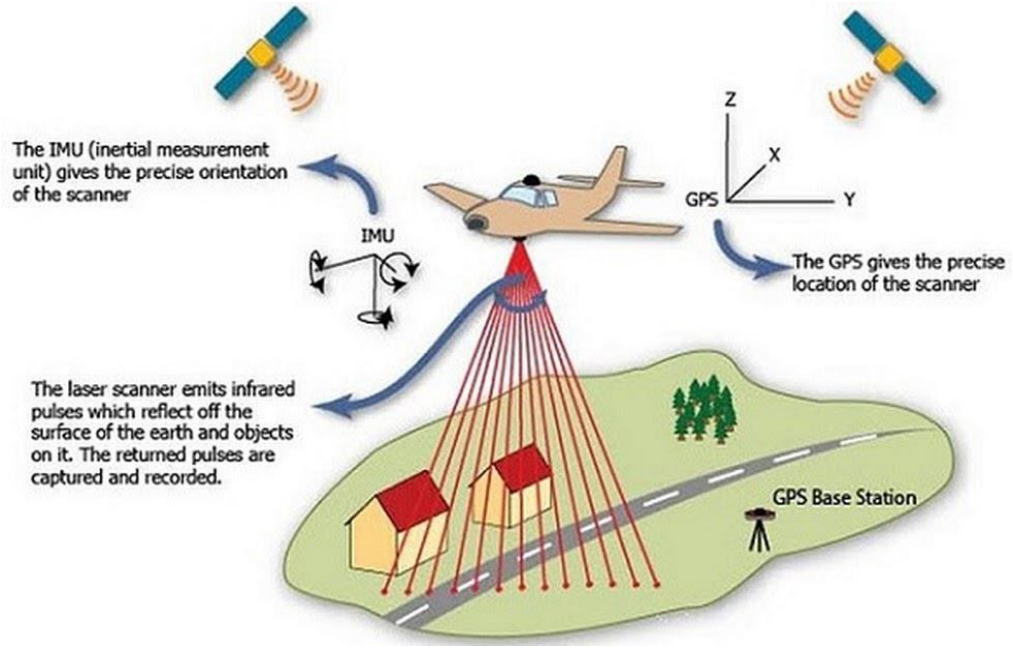

महत्वपूर्ण बिंदु

- दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए **LiDAR** सर्वेक्षण ग्रेटर नोएडा से शुरू हुआ जहां एक हेलीकॉप्टर ने अत्याधुनिक एरियल **LiDAR** और इमेजरी सेंसरों से लैस होकर पहली उड़ान भरी और ग्राउंड सर्वेक्षण से संबंधित डेटा पर कब्जा कर लिया।
- नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे **(LiDAR)** तकनीक को अपना रहा है, जो **3-4** महीनों में सभी जमीनी विवरण और डेटा प्रदान करता है जिसमें इस प्रक्रिया में सामान्य रूप से **10-12** महीने लगते हैं।
- जमीनी सर्वेक्षण किसी भी रैखिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है क्योंकि सर्वेक्षण संरेखण के आसपास के क्षेत्रों का सटीक विवरण प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

लिडार

- लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग सर्वे (लिडार) है, यह रिमोट सेंसिंग विधि है।
- मुख्य रूप से एक **LiDAR** उपकरण में एक लेज़र, एक स्कैनर और एक विशेष **GPS** रिसीवर होता है।
- इस तकनीक का उपयोग ज्यादातर जमीन-आधारित सर्वेक्षणों के लिए किया जाता है।
- **LiDAR** का उपयोग पहली बार **1971** में अपोलो **15** मिशन के दौरान एक अंतरिक्ष यान पर किया गया था, जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की सतह का मानचित्रण किया था।
- हवाई सर्वेक्षण के अलावा, स्व-ड्राइविंग कारों में **LiDAR** सेंसर सबसे महत्वपूर्ण घटक है। **LiDAR** सेंसर लगातार **360** डिग्री दृश्यता और सटीक गहराई की जानकारी प्रदान करता है।

क्या आपको पता है?

- हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर डेटा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मंच हैं।

- इसका उपयोग सटीकता और लचीलेपन के साथ प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों वातावरणों की जांच करने के लिए किया जा सकता है।

दो प्रकार के LiDAR हैं:

- आमतौर पर स्थलाकृतिक भूमि का नक्शा बनाने के लिए एक निकट-अवरक्त लेजर का उपयोग करता है
- बाथिमेट्रिक समुद्र के पानी और ऊंचे स्थानों को मापने के लिए जल-मर्मज्ञ हरी रोशनी का उपयोग करता है।

Related articles:

- About LiDAR: Click here
- Prehistoric settlements discovered through Light Detection and Ranging (LiDAR) data: Click here

---

सुपरमैसिव ब्लैक होल लापता हो गया लगता है

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस गायब हुए ब्लैक होल को खोजने के लिए **NASA** की चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी और हबल स्पेस टेलिस्कोप का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई अता-पता नहीं है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- वैज्ञानिक नासा के चंद्र एक्स-रे वेधशाला और हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके ब्लैक होल की तलाश में हैं।
- हालांकि, अब तक, उन्हें इसके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं मिला है।
- ब्लैक होल एबेल **2261** में स्थित है, जो एक विशाल आकाशगंगा समूह है, पृथ्वी से लगभग **2.7** बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। **2.7** बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर, एबेल आकाशगंगा हमसे बहुत दूरी पर है।

आपको पता है?

- प्रत्येक गैलेक्सी के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल होता है जिसका वजन सूर्य के मुकाबले अरबों ज्यादा होता है। हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे के केंद्र में जो ब्लैक होल है उसे सैगिटेरियस **A* (Sagittarius A*)** कहा जाता है।

आपदा प्रबंधन

हिमाचल प्रदेश में जंगल की आग

संदर्भ: हिमाचल प्रदेश अक्सर शुष्क मौसम की स्थिति के दौरान जंगल की आग का गवाह बनता है। जनवरी **2021** के महीने में, एक जंगल की आग जो कुल्लू के पास शुरू हुई, उसे नियंत्रण में लाने से पहले कई दिनों तक प्रयास करना पड़ा। शिमला और राज्य के अन्य हिस्सों में भी जंगल की आग की सूचना मिली थी।

हिमाचल प्रदेश का वन आवरण क्या है?

- **कानूनी वर्गीकरण:** हालांकि हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का दो-तिहाई कानूनी रूप से वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है।
- **प्रभावी वन आवरण:** घोषित वन क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा स्थायी रूप से बर्फ, ग्लेशियर, ठंडे रेगिस्तान या अल्पाइन घास के मैदानों के नीचे है और पेड़ की रेखा से ऊपर है। यह भारत के वन सर्वेक्षण के अनुसार कुल क्षेत्रफल का लगभग **28%** का एक प्रभावी वन क्षेत्र है, जो **15,434** वर्ग किलोमीटर है।
- **सामान्य पादप :** चीड़ देवदार, देवदार, ओक, कैल, देवदार और स्प्रूस यहां पाए जाने वाले कुछ सामान्य पेड़ हैं।

हिमाचल प्रदेश में जंगल की आग, बार-बार होने वाली घटना है

- मानसून और सर्दियों में वर्षा की अवधि को छोड़कर, जंगल आग की चपेट में रहते हैं। जंगल की आग राज्य में बार-बार होने वाली वार्षिक घटना है, और आमतौर पर यह चीड़ के जंगलों में होती है।
- गर्मियों के मौसम में, राज्य की निचली और मध्य पहाड़ियों में अक्सर जंगल की आग लगती है, जहाँ चीर चीड़ के जंगल आम हैं।
- मार्च से जून तक शुष्क गर्मी का मौसम चिर पाइन के पेड़ों द्वारा अत्यधिक-दहनशील सुइयों के बहाए जाने के साथ मेल खाता है। एक बार गिरी हुई सूखी सुइयों में आग लग जाती है, यह हवा की क्रिया के कारण पूरे जंगल में जल्दी फैल सकती है।
- हालांकि, उनकी मोटी छाल के कारण, चिर पाइन के पेड़ खुद इन आग से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं, और मानसून के मौसम के दौरान जीवन में वापस आ सकते हैं।
- मानसून के बाद के मौसम और सर्दियों में, शिमला, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों के कुछ हिस्सों में, जहां वे आमतौर पर घास के मैदानों में होते हैं, उच्च क्षेत्रों में भी जंगल के आग की सूचना दी जाती है।

आग किन कारणों से लगी?

- प्राकृतिक कारण जैसे बिजली के बांसों को आपस में रगड़ना या रगड़ना कई बार आग का कारण बन सकता है
- **मानव कारक**: जब घास सूखी होती है, तब भी एक छोटी सी चिंगारी, जैसे कोई जलती हुई माचिस, टार्चवुड या बीड़ी / सिगरेट छोड़ने के कारण भीषण आग लग सकती है। एक चिंगारी का उत्पादन तब किया जा सकता है जब सूखी पाइन पत्तियां बिजली के तारों पर गिरती हैं।
- **वन गतिविधियां**: जो लोग अक्सर मामूली उपज इकट्ठा करने के लिए जंगल से गुजरते हैं, वे अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं या अन्य उद्देश्यों के लिए भोजन पकाने या खुद को गर्म करने के लिए अस्थायी चूल्हा स्थापित कर सकते हैं। यदि वे एक सुलगती आग को पीछे छोड़ते हैं, तो यह जंगल की आग में विकसित हो सकता है।
- **कृषि पद्धतियाँ**: इसके अलावा, जब लोग अपने खेतों को जलाने के लिए उन्हें ठूंठ, सूखी घास या पानी के नीचे फेंक देते हैं, तो आग कभी-कभी बगल के जंगल में फैल जाती है।

इस तरह के बड़े पैमाने पर आग के ईंधन क्या हैं?

- वन भूमि पर सूखी पत्ती का कूड़ा एक तैयार ईंधन के रूप में काम करता है। पतझड़ के पेड़ के पत्ते, सूखी घास, घास, कम ब्रशवुड, वन तल पर डेडवुड, लॉग और स्टंप आदि सतह ईंधन बनाते हैं।
- ढीले कूड़े के नीचे, क्षय सामग्री जैसे कि धरण, लकड़ी, झाड़ियाँ, जड़ें, बहुत कुछ और पीट भी दहन का समर्थन कर सकते हैं।
- सतह के स्तर के ऊपर, सूखे खड़े पेड़, काई, लाइकेन, शुष्क एपिफाइटिक या परजीवी पौधे, और नासमझी में फंसी हुई शाखाएं आग को ऊपरी पर्ण और पेड़ के मुकुट तक फैला सकती हैं।

जंगल की आग के कारण क्या नुकसान होते हैं?

- जंगलों पुनर्योजी क्षमता को प्रभावित करता है: वन की आग जंगलों में पुनर्जनन और उनकी उत्पादकता को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ओक्स और देवदार जैसे नमी वाले पेड़ अन्य प्रजातियों और विदेशी खरपतवारों को रास्ता दे सकते हैं।
- जल प्रणाली पर प्रभाव: वन जलधाराओं और धाराओं और झरनों के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने में मदद करते हैं, और स्थानीय समुदायों को जलाऊ लकड़ी, चारा और गैर-लकड़ी उत्पादन प्रदान करते हैं - आग लगने की स्थिति में ये सभी क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती हैं।
- मृदा उत्पादकता पर प्रभाव: जंगल की आग मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को नष्ट कर सकती है और ऊपरी परत को कटाव को उजागर कर सकती है जिससे मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- जानवरों और मानव जीवन पर प्रभाव: जंगल की आग वन्यजीवों को अंडे जलाने, युवा जानवरों को मारने और वयस्क जानवरों को उनके सुरक्षित आश्रय से दूर ले जाने से भी प्रभावित हो सकती है। कभी-कभी, जंगल की आग नियंत्रण से बाहर हो सकती है और मानव बस्तियों तक फैल सकती है, इस प्रकार मानव जीवन और संपत्ति के लिए खतरा पैदा हो सकता है।
- आर्थिक नुकसान: 2016-17 से 2019-20 तक, जंगल की आग के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य को होने वाली वार्षिक हानि 1.7 करोड़ रुपये से 3.5 करोड़ रुपये तक हो गई है। इस अवधि के दौरान हर साल लगभग 1,200 से 2,500 जंगल की आग हज़ारों हेक्टेयर प्रभावित हुई।

हाल ही में लगी आग असामान्य है?

- राज्य में हर बार सूखे की चपेट में आने से जंगल में आग लगना आम है।
- हिमाचल में अगस्त से नवंबर तक पिछले साल **(2020)** में असामान्य रूप से शुष्क मौसम की स्थिति देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप सूखे जैसी स्थिति पैदा हुई।
- उस अवधि में बड़ी संख्या में जंगल की आग भी देखी गई - अगस्त से नवंबर की शुरुआत तक कम से कम **500** आग दर्ज की गई।
- वर्तमान में जनवरी **2021** के दूसरे सप्ताह में, मौसम शुष्क हो गया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ आग लग गई है।

जंगल की आग को रोकने और नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है?

- जंगल की आग से छुटकारा पाना: सूखे बायोमास के समाशोधन स्थलों को साफ करना। वन तल पर सूखे कूड़े का जल्दी जलना
- वन की संरचना में परिवर्तन
- रक्षात्मक तंत्र: जंगलों में आग की रेखाएं बनाना (आग फैलने से रोकने के लिए जंगल में आग की लकीरें वनस्पतियों को साफ रखती हैं)।

- बेहतर भविष्यवाणियां: मौसम संबंधी आंकड़ों का उपयोग करते हुए आग-प्रवण दिनों का पूर्वानुमान करना शुरुआती चरणों में जंगल की आग को नियंत्रित करने में मदद करेगा
- डेडिकेटेड फोर्स: एक बार आग लगने पर, अग्निशमन दस्तों द्वारा शीघ्र पता लगाना और त्वरित कार्रवाई महत्वपूर्ण है। इस तरह की गतिविधियों के लिए, राज्य के वन विभाग में अग्नि सुरक्षा और अग्नि नियंत्रण इकाई है।
- वन गतिविधियों का विनियमन: 1999 में, राज्य सरकार ने वन अग्नि नियमों को अधिसूचित किया जो वन क्षेत्रों में और आस-पास के क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित या विनियमित करते हैं जैसे कि आग जलाना, कृषि ठूंठ को जलाना या अधपका (घासनी) और सूखे पत्तों जैसे ज्वलनशील वन को ढेर करना। और जलाऊ लकड़ी।

Connecting the dots

- Australian Wildfires: Click Here

DRDO ने भू-खतरा प्रबंधन हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ फ्रेमवर्क एमओयू पर हस्ताक्षर किए

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - आपदा प्रबंधन

समाचार में-

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 20 जनवरी 2021 को तकनीकी आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती देने और स्थायी भू-खतरा प्रबंधन में सहयोग पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के साथ एक फ्रेमवर्क समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है

महत्वपूर्ण बिंदु

- **DRDO** के रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान **(DGRE)** विभिन्न प्रकार के इलाकों और हिमस्खलन में युद्ध की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए काम कर रहा है।
- यह सहमति हुई है कि देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन, हिमस्खलन और अन्य प्राकृतिक कारकों से होने वाले नुकसान के लिए स्थायी शमन उपायों को प्रदान करने में **DGRE** की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

रक्षा / आंतरिक सुरक्षा / सुरक्षा

स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर कंटेनर 'SAHAYAK-NG'

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में-

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (**DRDO**) ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर गोवा तट से कुछ दूर समुद्र में **IL** 38**SD** एयरक्राफ्ट (इंडियन नेवी) से भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर कंटेनर **'SAHAYAK-NG'** का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया।

महत्वपूर्ण बिदु

- भारतीय नौसेना ने इसकी परिचालन लॉजिस्टिक क्षमता में वृद्धि करने और तट से 2,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर तैनात पोतों को महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग भंडारण सुविधा मुहैया कराने के लिए परीक्षण किया।
- **SAHAYAK-NG, SAHAYAK Mk I** का आधुनिक संस्करण है।
- नए विकसित जीपीएस एडेड एयर ड्रॉप कंटेनर, 50 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम है और इसे किसी भारी विमान से सतह पर उतारा जा सकता है।
- इस कंटेनर का विकास डीआरडीओर की दो प्रयोगशालाओं – विशाखापत्तनम स्थित नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला और आगरा स्थित हवाई वितरण अनुसंधान और विकास संस्थान ने अपने उद्योग साझेदार मैसर्स अवान्टेल के साथ मिलकर किया है।

भारतीय सेना में स्वदेशी ब्रिजिंग प्रणाली का निर्माण किया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में-

- निजी उद्योग और **DRDO** के साथ घनिष्ठ समन्वय में, भारतीय सेना ने **10** मीटर छोटे स्पैन पुलों के तीन सेट शामिल किए हैं।

महत्वपूर्ण बिदु

- उपकरण ऑपरेशन के दौरान अंतराल को तेज करने के द्वारा स्वयं की सेना को गतिशीलता प्रदान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करेंगे।
- यह उपलब्धि हमारे सशस्त्र बलों को विदेशी निर्मित उपकरणों से दूर करने की दिशा में एक कदम है क्योंकि ब्रिज स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और वितरित किया गया है।
- सभी हितधारकों ने चुनौतियों को दूर करने और सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को साकार करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना की रक्षा जरूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है।

भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 10 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम की आपूर्ति के लिए MoD ने बीईएल के साथ अनुबंध किया

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में-

- रक्षा मंत्रालय **(MoD)** ने भारतीय नौसेना के सीमावर्ती युद्धपोतों के लिए **10** लिंक्स **U2** फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड **(BEL)** के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **डिजाइन और विकसित**: बीईएल

महत्वपूर्ण बिंदु

- लिंक्स प्रणाली आत्मानिर्भर भारत की दृष्टि को आगे बढ़ाएगी।
- 'लिंक्स यू2 जीएफसीएस' **(LYNX U2 GFCS)** एक नेवल गन फायर नियंत्रण प्रणाली **(Naval Gun Fire Control System)** है, जिसे समुद्री हलचल के बीच निगरानी करने और लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह सटीक रूप से हवा/जमीन के लक्ष्यों पर नजर रखने में सक्षम है

- इसे जहाज पर उपलब्ध मध्यम/छोटी रेंज की बंदूकों जैसे रूसी एके 176, ए 190, एके 630 और एसआरजीएम के साथ संचालित किया जा सकता है।
- यह प्रणाली भारतीय नौसेना के लिए विकसित और नौसेना को ही प्रदान की गई है और दो दशकों से सेवा में है।
- यह विभिन्न वर्गों जैसे विध्वंसक, फ्रिगेट,मिसाइल बोट, कोरवेट इत्यादि के भारतीय नौसेना के जहाजों की सामरिक आवश्यकताओं को संतोषजनक रूप से पूरा कर रही है।
- इस प्रणाली का अधिक उन्नयन कर को एनओपीवी (नेवाल आफशोर पेट्रोल वेसेल), तलवार और टीजी श्रेणी के जहाजों पर लगाया जाएगा।
- ट्रैकिंग रडार, सर्वो और हथियार नियंत्रण मॉड्यूल सहित सभी प्रणाली को बीईएल द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
- अनुबंध में प्रस्तावित प्रणाली चौथी पीढ़ की है और पूर्णत: स्वदेशी है, जिसे आत्मनिर्भर भारत की भावना से विकसित किया गया है।

बीईएल ने भारतीय नौसेना के साथ स्वदेशी रूप से विकसित लेजर डैजलर्स की प्रारंभिक आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

भाग- GS **प्रीलिम्स और** GS-III - **रक्षा और सुरक्षा**

समाचार में-

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने रेडिएशन डैजलर्स (लेजर डैजलर्स) (Laser Dazzlers) के तीव्र उत्सर्जन के माध्यम से 20 प्रकाश प्रवर्धन की प्रारंभिक आपूर्ति के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
- विकसित: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)।

महत्वपूर्ण बिंदु

- लेजर डैजलर का उपयोग दिन और रात दोनों के दौरान सुरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने आने वाले संदिग्ध वाहनों/नावों/हवाई जहाजों/यूएवी/समुद्री डाकुओं आदि को चेताने और रोकने के लिए एक गैर-घातक प्रणाली के तौर पर किया जाता है।
- यह अपनी तीव्र चमक से विमान/यूएवी को भी विचलित कर देता है। यह आसानी से ले जाने में सक्षम (portable) है। लेजर डैजलर तकनीक को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है
- यह अस्थायी रूप से एक व्यक्ति को अक्षम / भ्रमित / अंधा कर देता है।
- यह विमान / यूएवी को भी विचलित करता है।
- यह प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में सैन्य उपयोग के लिए एक पोर्टेबल, कंधे से संचालित होने योग्य है।
- यह अनूठा उत्पाद पहली बार सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।

MARCOS को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया जा रहा है

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में-

- भारत ने पूर्वी लद्दाख में चीन से जारी तनातनी के बीच पैंगोंग इलाके में मरीन कमांडो (मार्कोस कमांडो) को तैनात किया है। यहां भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो और आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स पहले से ही तैनात है।, मार्कोस कमांडो की तैनाती का फैसला तीनों सेनाओं के कमांडो के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाने के मकसद से किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- मरीन कमांडो को MARCOS के रूप में संक्षिप्त किया जाता है और आधिकारिक तौर पर मरीन कमांडो फोर्स **(MCF)** कहा जाता है।
- यह भारतीय नौसेना की विशेष बल इकाई है जो विशेष संचालन करने के लिए जिम्मेदार है।
- **MARCOS** की स्थापना फरवरी **1987** में हुई थी।
- **MARCOS** सभी प्रकार के वातावरण में संचालित करने में सक्षम हैं; समुद्र में, हवा में और जमीन पर।
- बल ने धीरे-धीरे अनुभव प्राप्त किया है और व्यावसायिकता के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल की है।
- **MARCOS** नियमित रूप से झेलम नदी और वुलर झील के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में विशेष समुद्री संचालन करता है।

एलसीए तेजस की खरीद को मंजूरी

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में-

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **73** एलसीए तेजस एमके **-1** ए लड़ाकू विमानों और **10** एलसीए तेजस एमके **-1** ट्रेनर विमानों की खरीद को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mk-1A वैरिएंट एक स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक आधुनिक 4+ पीढ़ी का लड़ाकू विमान है।
- यह विमान सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए ऐरे (एईएसए) रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज (बीवीआर) मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (ईडब्ल्यू) सुइट और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग (एएआर) की महत्वपूर्ण परिचालन क्षमताओं से लैस है, जो परिचालन को पूरा करने के लिए एक शक्तिशाली मंच होगा। भारतीय वायु सेना, IAF की आवश्यकताएं।
- यह पहला "खरीदें (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित)" 50% की स्वदेशी सामग्री के साथ लड़ाकू विमानों की श्रेणी खरीद है जो कार्यक्रम के अंत तक उत्तरोत्तर 60% तक पहुंच जाएगा।

- मंत्रिमंडल ने परियोजना के तहत IAF द्वारा बुनियादी ढाँचे के विकास को भी मंजूरी दे दी है ताकि वे अपने बेस डिपो में सर्विसिंग को सक्षम कर सकें ताकि मिशन क्रिटिकल सिस्टम के लिए टर्नअराउंड समय कम हो जाए और विमान की उपलब्धता में वृद्धि हो।

भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 9 मिमी पिस्तौल

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- भारत की पहली स्वदेशी 9 मिमी पिस्तौल DRDO और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मशीन पिस्टल में सर्विस 9 गोला बारूद और एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम से बना एक ऊपरी रिसीवर और कार्बन फाइबर के लिए कम रिसीवर है।
- 3 D प्रिंटिंग प्रक्रिया का उपयोग धातु 3 D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए ट्रिगर घटकों सहित विभिन्न भागों के डिजाइन और प्रोटोटाइप में किया गया है।
- सशस्त्र बलों में हथियार की विशाल क्षमता विद्धमान है।
- हथियार का नाम "अस्मी" है जिसका अर्थ है "गर्व", "आत्म-सम्मान" और "कड़ी मेहनत"।
- यह छोटा कदम आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करेगा और उम्मीद है कि सेवा और अर्धसैनिक बल (PMF) इसे शीघ्रता से लागू करेंगे।

भारतीय सेना ने ideaForge के साथ $ 20 मिलियन का अनुबंध किया है

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में-

- भारतीय सेना ने मानवरहित ड्रोन 'स्विच' को हासिल करने के लिए **ideaForge Technology** नाम की कंपनी के साथ करीब **$** 20 मिलियन का करार किया है।
- इस यूएवी के डैने मानवरहित विमान में फिक्स रहते हैं और यह वर्टिकल टेकऑफ व लैंडिंग में सक्षम है। यह विमान ऊंचे अक्षांशों और खराब मौसम में भी दिन-रात निगरानी कर सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 'स्विच' यूएवी एक स्वदेशी प्रणाली है जिसे भारतीय बलों के सबसे अधिक मांग वाले निगरानी अभियानों को पूरा करने के लिए बनाया गया है।
- यह फिक्स्ड-विंग वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग यूएवी को उच्च ऊंचाई पर और दिन और रात की निगरानी के लिए कठोर वातावरण में तैनात किया जा सकता है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को सौंप दिया है

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - रक्षा और सुरक्षा और विज्ञान और तकनीकी

समाचार में-

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (**CRPF**) को सौंप दिया है

महत्वपूर्ण बिंदु

- 'रक्षिता' में एक स्वनिर्धारित रिक्लाइनिंग कैजुअल्टी इवैक्यूएशन सीट (**CES**) लगाई गई है, जिसे आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जा सकता है.
- हेड इम्मोबिलाइज़र, सुरक्षा हार्नेस जैकेट, हाथों और पैरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा पट्टियाँ, ड्राइवर के लिए वायरलेस मॉनिटरिंग क्षमता और ऑटो चेतावनी प्रणाली के साथ फ़िज़ियोलॉजिकल पैरामीटर मापने वाले उपकरण भी अन्य प्रमुख विशेषताओं में शामिल है.
- यह बाइक एम्बुलेंस भारतीय सुरक्षा बलों और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं में तत्काल मदद करेगी.
- यह बाइक कम तीव्र संघर्ष वाले इलाकों से घायलों को निकालने के दौरान जीवन रक्षक सहायता प्रदान करेगी.

स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन (SAAW)

भाग- GS प्रीलिम्स और GS-III - रक्षा और इतिहास

समाचार में-

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (**Defence Research and Development Organisation- DRDO**) ने स्वदेश में निर्मित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन (**Smart Anti-Airfield Weapon- SAAW**) का सफल 'कैप्टिव एंड

रिलीज़' उड़ान परीक्षण किया है। यह परीक्षण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (**HAL)** के हॉक-**I** विमान के ज़रिये किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- एचएएल के भारतीय हॉक-एमके 132 से स्मार्ट हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
- यह अब तक DRDO द्वारा संचालित SAAW का 9 वां सफल मिशन था।
- **DRDO** द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया।
- यह 125 किलोग्राम वर्ग का स्मार्ट हथियार है, जो 100 किलोमीटर की सीमा तक दुश्मन के हवाई क्षेत्र की संपत्ति जैसे राडार, बंकर, टैक्सी ट्रैक, और रनवे आदि को उलझाने में सक्षम है।

विविध

समाचार	विवरण
1. केला ग्रिट	• वैज्ञानिक एक नया उत्पाद, केला ग्रिट या ग्रैन्यूल्स लेकर आए हैं, जो कच्चे नेंद्रान केलों से विकसित हुए हैं। • एक स्वस्थ आहार के लिए एक आदर्श घटक के रूप में बिल किया गया, केले की चक्की का उपयोग व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने के लिए किया जा सकता है। • उत्पाद 'रवा' और टूटे हुए गेहूं जैसा दिखता है।
2. नेंद्रन केला	• चांगालिकोडन नंद्राण केला या चंगालिकोडन के नाम से मशहूर केरल में केरल के त्रिशूर जिले के चेंगाझिकोडु गाँव में उत्पन्न और खेती की जाती है। • चंगालिकोडन, अब भरतपुझा नदी के किनारे पर खेती की जाती है। • चांगलिकोडन को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, चेन्नई से भौगोलिक संकेत पंजीकरण मिला।
3. पोंग बांध	• हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के पोंग बांध क्षेत्र में एक अस्पष्टीकृत कारण के कारण हाल ही में लगभग 1,400 प्रवासी पक्षी मृत पाए गए। स्थानीय अधिकारियों ने जलाशय की पूर्ववर्ती सभी पर्यटन गतिविधियों को निलंबित कर दिया है • पौंग बांध, जिसे ब्यास बांध के रूप में भी जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश राज्य में ब्यास नदी पर एक पृथ्वी-भरा तटबंध बांध है।
3. सबरि नदी	• एक अनूठी पहल में, प्रवासी मछुआरे-लोक परिवारों ने पूर्वी गोदावरी एजेंसी में आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की त्रि-राज्य सीमा के साथ सबरी नदी की रेत पर अस्थायी घर बनाए हैं। • साबरी नदी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। • यह ओडिशा के पूर्वी घाट के पश्चिमी ढलानों से सिंकदरम पर्वत श्रृंखला से निकलती है। • यह छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के बीच आम सीमा बनाता है और बाद में गोदावरी नदी के साथ विलय करने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रवेश करता है। • इसे ओडिशा में कोलाब नदी के रूप में भी जाना जाता है। • ऊपरी कोलाब परियोजना, सबरी में ओडिशा में स्थित एक प्रमुख बांध परियोजना है जो सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए पानी की आपूर्ति करती है।
4. सिलरू नदी	• सिलरू नदी (इसकी ऊपरी पहुंच में मचकुंड के रूप में जाना जाता है) सबरी की प्रमुख सहायक नदी है। • यह आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के त्रि-जंक्शन सीमा बिंदु पर सबरी नदी से जुड़ता है। • सिलरू नदी में जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएँ हैं।
5. चटरगला सुरंग	• जम्मू और कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग जिला कठुआ को जिला डोडा के साथ जोड़ेगी और भटवाह और डोडा को छूने के लिए चट्टरगला के माध्यम से बसोहली-बानी के माध्यम से नए राजमार्ग को जोड़ेगी। • यह एक ऐतिहासिक लैंडमार्क परियोजना है जो दो दूर के क्षेत्रों के बीच सभी मौसम वैकल्पिक सड़क संपर्क प्रदान करती है और पंजाब सीमा पर डोडा से लखनपुर तक की यात्रा के समय को लगभग चार घंटे तक कम करती है।

	• यह 6.8 किलोमीटर लंबी सुरंग बनने जा रही है। • सुरंग को निष्पादन कार्य शुरू होने के बाद पूरा होने में लगभग 4 साल लगने की संभावना है और इसकी निर्माण लागत लगभग 3,000 करोड़ रु है।
6. विश्व हिंदी दिवस	• विश्व हिंदी दिवस हाल ही में 10 जनवरी को मनाया गया। • विदेशों में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल इस दिन को मनाया जाता है। • इस दिन 2006 में, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था। • तब से, हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
7. एलुरु बीमारी	• आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के एलुरु शहर में 550 से अधिक लोग आक्षेप, दौरे, चक्कर आना और मतली से पीड़ित हैं। • अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने कुछ पीड़ितों के रक्त के नमूनों में लेड और निकल पाए हैं। • भारी धातुओं द्वारा पानी के संदूषण पर प्राथमिक संदेह है • वैज्ञानिकों को संदेह है कि कीटनाशक या पीने के पानी के स्रोतों में फैल गए हैं। • एलुरु ने गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियों से नहरों के माध्यम से पानी प्राप्त किया। • नहरें कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं जहाँ अपवाह कीटनाशकों के साथ मिला कर नहरों में पानी मिलाते हैं। • रहस्य बीमारी के कई पहलुओं ने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है। • जो लोग केवल पैकेज्ड पेयजल का उपयोग करते हैं, वे भी बीमार पड़ गए हैं।
8. सी विजिल 21	• द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल -21 का दूसरा संस्करण 12-13 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाएगा। • यह अभ्यास पूरे भारत के 7516 किलोमीटर के तटीय और विशेष आर्थिक क्षेत्र के साथ किया जाएगा। • इसमें मछली पकड़ने और तटीय समुदायों सहित सभी 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ अन्य समुद्री हितधारक शामिल होंगे। • इस अभ्यास का भारतीय नौसेना द्वारा समन्वय किया जा रहा है। • व्यायाम प्रमुख रंगमंच स्तर के व्यायाम TROPEX [रंगमंच-स्तरीय रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज] है, जो भारतीय नौसेना हर दो साल में आयोजित करती है। • SEA VIGIL और TROPEX मिलकर शांति से लेकर संघर्ष तक संक्रमण सहित समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करेंगे।
9. खेलो इंडिया ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021	• लद्दाख पर्यटन विभाग के सहयोग से खेलो इंडिया के बैनर तले खेल और युवा सेवाओं के विभाग द्वारा 18 से 30 जनवरी 2021 तक ज़ांस्कर शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है। • ज़ांस्कर, या ज़ंगस्कर को जंगस्कर के रूप में भी जाना जाता है। • ज़ांस्कर रेंज लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है जो ज़ांस्कर को लद्दाख से अलग करती है। • भूवैज्ञानिक रूप से, ज़ांस्कर रेंज टेथिस हिमालय का एक हिस्सा है, जो लगभग 100 किमी चौड़ा सिनक्लिनोरियम (एक प्रकार का छोटा रूप जिसमें छोटे सिलवटों की एक श्रृंखला शामिल है) दृढ़ता से मुड़ा और कमजोर रूप से रूपांतरित रूप से निर्मित तलछटी श्रृंखला

	द्वारा निर्मित है। • ज़ांस्कर रेंज की औसत ऊँचाई लगभग 6,000 मीटर है। • इसके पूर्वी भाग को रूपशु के नाम से जाना जाता है।
10. आइस क्लाइम्बिंग उत्सव	• लेह में, नुब्रा घाटी में पहली बार आइस क्लाइम्बिंग उत्सव मनाया गया। • नुब्रा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में एक उपखंड और एक तहसील है। • इसके बसे हुए इलाके नुब्रा और श्योक नदियों द्वारा काटकर एक त्रिकोणीय सशस्त्र घाटी बनाते हैं। • श्योक नदी एक बड़ी घाटी बनाने के लिए नुब्रा नदी (या सियाचन नदी) से मिलती है जो लद्दाख और काराकोरम पर्वतमाला को अलग करती है। • श्योक नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है।
11. शीज़ीयाज़ूआंग	• शिजियाझुआंग कोरोनावायरस के लिए का चीन का नया हॉटस्पॉट बन गया है। • यह उत्तरी चीन के हेबेई प्रांत की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। • यह ताइहांग पर्वत के पूर्व में स्थित है। • यह शहर उत्तरी चीन के मैदान के किनारे पर स्थित है, जो शहर के पश्चिम में ताइहंग पर्वत तक जाता है, और हटुओ नदी के दक्षिण में स्थित है।
12. कायाकल्प पुरस्कार	• सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को स्वच्छता और स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। • सरकार ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए 15 मई 2015 को एक राष्ट्रीय पहल कायाकल्प शुरू की थी।
13. Collab CAD	• राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के साथ MeitY, शिक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से Collab CAD सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहा है। • CollabCAD सॉफ्टवेयर का उपयोग विभिन्न प्रकार के 3 डी डिज़ाइन और 2D ड्रॉइंग बनाने के लिए विषय पाठ्यक्रम के भाग के रूप में व्यावहारिक असाइनमेंट के लिए किया जाएगा। • देश भर के लगभग 140 प्लस स्कूलों और मध्य पूर्व (सीबीएसई, नई दिल्ली से संबद्ध) स्कूलों के छात्रों को इस सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्राप्त होगी जिसका उपयोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की व्यावहारिक परियोजनाओं और समझ की अवधारणाओं के लिए किया जा सकता है।
14. दज़ुको घाटी	• दो सप्ताह तक हंगामा करने के बाद दज़ुकौ घाटी में जंगल की आग बुझाई गई। • दजुको घाटी नागालैंड और मणिपुर राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। • घाटी हर मौसम में फूलों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध एक दजुको लिली है और यह केवल इस घाटी में पाई जाती है।
15. धाराशिव गुफाएं	• धाराशिव गुफाएं हाल ही में खबरों में थीं जब महाराष्ट्र के सीएम ने उस्मानाबाद को धर्मशिव (6 वीं शताब्दी की गुफाओं के नाम पर) के रूप में संदर्भित किया। • उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद के अंतिम शासक मीर उस्मान अली खान के नाम पर रखा गया है, जबकि धर्मशिव शहर के पास छठी शताब्दी की गुफाओं के नाम से लिया गया है। • महाराष्ट्र में बालाघाट पर्वतों में धराशिव गुफाएँ 7 गुफाओं का समूह हैं। • इन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। • माना जाता है कि इनका निर्माण लगभग 5 वीं -7 वीं शताब्दी में हुआ था।

	• गुफाओं पर बहस हुई है कि क्या वे बौद्ध या जैन कृतियां हैं। • ऐसा माना जाता है कि ये गुफाएं मूल रूप से बौद्ध थीं, लेकिन बाद में कुछ गुफाओं को जैन गुफाओं में बदल दिया गया।
16. सुलावेसी	• इंडोनेशिया में, सुलावेसी द्वीप पर शक्तिशाली भूकंप के बाद बचे लोगों के लिए खोज अभियान में बाधा आ रही है। • सुलावेसी इंडोनेशिया में एक द्वीप है। • यह बोर्नियो के पूर्व में, मलूकु द्वीप के पश्चिम में, और मिंडानाओ के दक्षिण में और सुलु द्वीपसमूह में स्थित है। • मकासर की स्ट्रेट द्वीप के पश्चिमी भाग के साथ चलती है और बोर्नियो से द्वीप को अलग करती है। • इंडोनेशिया के भीतर, यह सुमात्रा से छोटा और जावा द्वीप से बड़ा है। • इंडोनेशिया प्रशांत "रिंग ऑफ फायर" पर स्थित है जहां विवर्तनिक प्लेटें टकराती हैं, और देश में विनाशकारी भूकंप और सुनामी का इतिहास है।
17. हरिके वेटलैंड	• मध्य एशियाई फ्लाईवे का उपयोग करने वाले शीतकालीन प्रवासी जल पक्षियों ने पक्षी प्रेमियों को खुश करने के लिए पंजाब के हरिके वेटलैंड के लिए एक बीलाइन बनाना शुरू कर दिया है। • हरिके वेटलैंड उत्तरी भारत में तरनतारन साहिब जिले और पंजाब के फिरोजपुर जिले की सीमा में स्थित सबसे बड़ा वेटलैंड है। • 1953 में सतलज नदी के पार हेडवर्क्स का निर्माण करके आर्द्रभूमि और हरिके झील का निर्माण किया गया था। • इसे भारत में रामसर साइटों में से एक के रूप में नामित किया गया है।
18. फुरफुरा तीर्थ	• फुरफुरा तीर्थ स्थल पश्चिम बंगाल में मुस्लिम राजनीति का उपरिकेंद्र बनने के कारण खबरों में था। • फुरफुरा शरीफ हुगली जिले, पश्चिम बंगाल में एक गाँव है। • यह बंगाली मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थान है। • स्थानीय लोगों के अनुसार, राजस्थान में अजमेर शरीफ के बाद यह देश की दूसरी सबसे प्रमुख मजार है।
19. एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट -21	• भारतीय वायु सेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल 20 से 24 जनवरी 2021 तक वायु सेना स्टेशन जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास, एक्स डेजर्ट नाइट -21 का आयोजन करेंगे। • यह अभ्यास अद्वितीय है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों द्वारा राफेल विमानों का क्षेत्ररक्षण शामिल है।
20. कवच अभ्यास	• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रक्षा के लिए कवच युद्धाभ्यास भी एम्फैक्स - 21 के भाग के रूप में आयोजित किया गया । एकीकृत मुख्यालय स्टाफ के तत्वावधान में एक संयुक्त आसूचना, निगरानी और टोही अभ्यास भी एक साथ चलाया गया ताकि कई संवेदकों का इस्तेमाल कर समुद्री डोमेन जागरूकता को प्राप्त किया जा सके ।
21. लीनग टेडोंग्नेज गुफा	• पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कला की खोज की है - एक जंगली सुअर की आदमकद तस्वीर जो कम से कम 45,500 साल पहले इंडोनेशिया में चित्रित की गई थी।

	• सुलावेसी वार्टी पिग पेंटिंग लीनग टेडॉन्गे की चूना पत्थर की गुफा में पाई गई थी। • पेंटिंग में दर्शाया गया मस्सा सुअर इस इंडोनेशियाई द्वीप के लिए स्थानिक है। • गुफा एक घाटी में है, जो खड़ी चूना पत्थर की चट्टानों से घिरा है, और केवल शुष्क मौसम में एक संकीर्ण गुफा मार्ग द्वारा सुलभ है। • इस छिपी घाटी में रहने वाले अलग-थलग बुगिस समुदाय का दावा है कि यह पहले कभी पश्चिमी देशों से नहीं गया था। • कम से कम 43,900 साल पुराना सबसे पुराना दिनांकित रॉक आर्ट 'दृश्य', संकर मानव-जानवरों का चित्रण था जो सुलावेसी मस्तिष्कीय सूअर और बौने गिद्धों का शिकार करते थे।
22. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबन्धन पुरस्कार 2021	• आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने और सम्मानित करने के लिए, भारत सरकार ने एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की है, जिसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। • वर्ष 2021 के लिए, (i) सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी (संस्थागत श्रेणी में) और (ii) डॉ। राजेंद्र कुमार भंडारी (व्यक्तिगत श्रेणी में) को उनके उत्कृष्ट के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करते हैं। • यह पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर घोषित किया जाता है। • पुरस्कार रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान करता है। 51 लाख और एक संस्था के मामले में एक प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपये और एक व्यक्ति के मामले में एक प्रमाण पत्र
23. भावना कंठ	• फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली हैं। • वह भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की झांकी का एक हिस्सा होगा जो हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुखोई -30 लड़ाकू विमान का प्रदर्शन करेगा। • वह वर्तमान में राजस्थान के एक एयरबेस में तैनात है जहां वह मिग -21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती है। • कंठ भारतीय वायुसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक है।
24. पद्म पुरस्कार 2021	• इस वर्ष राष्ट्रपति ने 119 पद्म पुरस्कारों के सम्मान को मंजूरी दी है। • महत्वपूर्ण नीचे सूचीबद्ध हैं।
25. पद्म विभूषण	• भारत रत्न के बाद भारत गणराज्य का दूसरा-सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार • शिंजो आबे (जापान) - सार्वजनिक मामले • एस पी बालासुब्रमण्यम (मरणोपरांत) - कला • बेले मोनप्पा हेगड़े - चिकित्सा • मौलाना वहीदुद्दीन खान - अन्य: आध्यात्मिकता
26. पद्म भूषण	• भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण भारतीय गणराज्य का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है • कृष्णन नायर शांतकुमारी चित्र - कला • तरुण गोगोई (मरणोपरांत) - सार्वजनिक मामले

	• चंद्रशेखर कंबरा - साहित्य और शिक्षा • सुमित्रा महाजन - सार्वजनिक मामले • कल्बे सादिक (मरणोपरांत) - अन्य: अध्यात्मवाद
27. मारुत	• नेहरू विज्ञान केंद्र, मुंबई ने रेल लोकोमोटिव के अपने कलाकृतियों को फिर से प्रदर्शित किया, जो आगंतुकों के लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान बहाल किए गए हैं। • भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लड़ाकू विमान मारुत अब जनता के देखने के लिए उपलब्ध होगा।
28. समुद्र में युद्धाभ्यास	• डमान और निकोबार द्वीप समूह की रक्षा के लिए कवच युद्धाभ्यास भी एम्फैक्स - 21 के भाग के रूप में आयोजित किया गया। • एकीकृत मुख्यालय स्टाफ के तत्वावधान में एक संयुक्त आसूचना, निगरानी और टोही अभ्यास भी एक साथ चलाया गया ताकि कई संवेदकों का इस्तेमाल कर समुद्री डोमेन जागरूकता को प्राप्त किया जा सके।
29. एएमपीएचईएक्स – 21	• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल-थल-नभ युद्धाभ्यास एम्फीमेक्स -21 का आयोजन किया गया था। इस अभ्यास में नौसेना के जहाजों, ज़मीन, हवा और पानी तीनों के युद्ध में प्रवीण सैनिकों और वायु सेना के विभिन्न प्रकार के विमानों की भागीदारी शामिल थी। • इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य अपने द्वीप क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन करना था। इसमें सेना के तीनों अंगों के बीच परिचालन तालमेल और संयुक्त रूप से युद्ध लड़ने की क्षमताओं को बढ़ाने का उद्देश्य भी शामिल था।

IAS baba
WE ARE COMING TO THE CITY OF NAWABS
Launching IASBABA'S
Prelims Exclusive Programme (PEP)
With Mentorship in
LUCKNOW
WALK-IN ADMISSIONS START FROM 25th JANUARY
ADMISSIONS OPEN!
ADMISSIONS OPEN!

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

मॉडल प्रश्न(उत्तर अंत में दिए गए हैं) :

Q.1 पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है?

a) आंध्र प्रदेश

b) ओडिशा

c) केरल

d) राजस्थान

Q.2 Build - Operate - Transfer contract के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल में से एक है।

2. शुरू में परियोजनाएं एक सार्वजनिक संस्था द्वारा बनाई और संचालित की जाती हैं और बाद में आमतौर पर दो या तीन दशकों के बाद इसे निजी संस्था को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.3 SAHAYAK - NG के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रोपेबल कंटेनर है।

2. इसमें 200 किलोग्राम वजन वाले पेलोड को ले जाने की क्षमता है।

3. इसे केवल एक हल्के विमान से ही गिराया जा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है?

a) केवल 1

b) केवल 1 और 2

c) केवल 1, 2 और 3

d) केवल 2 और 3

Q.4 इथेनॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?

a) ईंधन के रूप में इथेनॉल गैर प्रदूषणकारी है।

b) इथेनॉल सम्मिश्रण जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर सकता है।

c) वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल का उपयोग किया जा सकता है।

d) सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ ईंधन ग्रेड इथेनॉल के 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है।

Q.5 काला अजार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानिक है?

1. बिहार
2. झारखंड
3. छत्तीसगढ़
4. ओडिशा
5. पश्चिम बंगाल

सही कोड का चयन करें:

a) केवल 1, 2 और 3

b) केवल 4 और 5

c) केवल 2, 4 और 5

d) केवल 1, 2 और 5

Q.6 काला अजार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह लीशमैनिया फंगस के संक्रमण के कारण होता है।

2. विसेरल लीशमैनियासिस सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.7 निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी खेती के अंतर्गत आता है?

a) फल

b) सब्जियां

c) नट्स

d) उपरोक्त सभी

Q.8 एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है?

a) चीन

b) भारत

c) मलेशिया

d) फिलीपींस

Q.9 जुलाई 2014 में ADB बोर्ड द्वारा अनुमोदित असम पावर सेक्टर निवेश कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी पर संचालित नदी परियोजना है।

2. यह 2030 तक 469 गीगावाटौर (GWh) द्वारा स्वच्छ ऊर्जा से आपूर्ति की गई बिजली को बढ़ाने में मदद करेगा।

3. गरीबी में कमी (JFPR) के लिए जापान फंड से 2 मिलियन $ का अनुदान भी परियोजना से जुड़ा है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है?

a) केवल 1 और 3

b) केवल 2 और 3

c) केवल 3

d) 1, 2 और 3

Q.10 पोंग बांध किस राज्य में स्थित है?

a) आंध्र प्रदेश

b) ओडिशा

c) केरल

d) हिमाचल प्रदेश

Q.11 संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह यूरोपीय संघ के साथ मिलकर ईरान और P5 + 1 (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य-चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका-जर्मनी) के बीच एक समझौता था।

2. जेसीपीओए के तहत, ईरान ने मध्यम-समृद्ध यूरेनियम के अपने भंडार को खत्म करने पर सहमति जताई, इसके कम-समृद्ध यूरेनियम के भंडार को 98% तक कम कर दिया, और लगभग एक-तिहाई गैसों सेन्ट्रीफ्यूगल की संख्या को 13 साल तक कम कर दिया।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.12 जिब्राल्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जिब्राल्टर इबेरियन प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित भूमि का एक छोटा सा हिस्सा है।

2. स्पेन और फ्रांस के बीच जिब्राल्टर को लेकर एक संप्रभुता विवाद है

उपरोक्त में से कौन सा/ से सही है?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.13 राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (NBM) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (BIRAC) द्वारा लागू किया गया है।

2. यह AIDB द्वारा 50% सह-वित्त पोषित है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है ?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.14 निम्नलिखित में से कौन-सा अंटार्कटिका में भारत के परिचालन अनुसंधान स्टेशन है / हैं?

a) दक्षिण गंगोत्री

b) मैत्री

c) भारती

d) दोनों (a) और (b)

Q.15 कोलार लीफ-नोस्ड बैट (Kolar leaf-nosed bat) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह केवल आंध्र प्रदेश की एक गुफा में पाया जाता है।

2. यह IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.16 निम्न में से कौन पूर्वोत्तर भारत का रामसर स्थल नहीं है?

a) लोकतक झील

b) रुद्रसागर झील

c) दीपोर बील

d) काबरतल वेटलैंड

Q.17 एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस के कारण होता है।

2. AI वायरस दूषित पोल्ट्री उत्पादों की खपत के माध्यम से मनुष्यों में प्रेषित हो सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.18 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जापान की रस्ट बेल्ट कहा जाता है?

a) शिकोकू

b) होन्शा

c) क्यूशू

d) चुबु

Q.19 हीराकुंड बांध, दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध, निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है?

a) पुरी

b) संबलपुर

c) कांगड़ा

d) नागपुर

Q.21 चटरगला सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस पर किया जाएगा?

a) जम्मू और कश्मीर

b) गोवा

c) सिक्किम

d) असम

Q.22 निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र नदी का प्रमुख बंदरगाह है?

a) मुंबई

b) कांडला

c) मैंगलोर

d) कोलकाता

Q.23 विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है?

a) वाशिंगटन

b) पेरिस

c) स्विट्जरलैंड

d) नीदरलैंड

Q.24 एक बायोडाइजेस्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन गलत है?

a) उर्वरक और बायोगैस के उत्पादन के लिए एक बायोडाइजेस्टर प्रणाली जैविक कचरे, विशेष रूप से पशु और मानव उत्सर्जन का उपयोग करती है।

b) इसमें एक एयरटाइट पॉलीइथिलीन कंटेनर होता है, जिसके भीतर लगातार पानी के बहाव होता रहता है।

c) किण्वन प्रक्रिया एरोबिक है।

d) अपघटन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया मेथेनोजेनिक हैं।

Q.25 काराकल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. IUCN रेड लिस्ट की स्थिति कम से कम चिंता जनक है

2. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (NBWL) ने कैराकल को गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.26 सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है?

a) मध्यप्रदेश

b) उत्तर प्रदेश

c) सिक्किम

d) राजस्थान

Q.27 धनिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वाणिज्य मंत्रालय ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की सूची में कोटा जिले को धनिया का चयन किया है

2. मध्य प्रदेश का केवल गुना जिला देश से धनिया निर्यात में प्रमुख योगदान देता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है?

a) केवल 1

b) केवल 2

c)1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.28 नेचुरल कैपिटल एकाउंटिंग और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (NCAVES) भारत फोरम -2021 का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है?

a) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

b) वित्त मंत्रालय

c) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

d) दोनों (a) और (b)

Q.29 निम्नलिखित देशों के प्राकृतिक पूंजी लेखा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (NCAVES) के मूल्यांकन का हिस्सा हैं?

1. ब्राजील

2. चीन

3. दक्षिण अफ्रीका

4. भारत

5. पाकिस्तान

6. यूएसए

सही कोड का चयन करें:

a) केवल 1, 2 और 3

b) केवल 3, 4, 5 और 6

c) केवल 2, 4 और 6

d) केवल 1, 2, 3 और 4

Q.30 निम्नलिखित समुद्री सीमाओं में से कौन लीबिया के उत्तर में हैं?

a) भूमध्य सागर

b) काला सागर

c) अरल समुद्र

d) कैस्पियन सागर

Q.31 सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन हटा सकता है?

a) सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

b) केवल राष्ट्रपति

c) केवल संसद

d) संसद और राष्ट्रपति दोनों

Q.32 गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिये':

1. यह भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है

2. इसकी "IUCN स्थिति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.33 वैनेडियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह धातु शायद ही कभी प्रकृति में पाई जाती है।

2. धातु का उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.34 निम्न में से कौन से राज्य की भारत में वैनेडियम का प्रमुख उत्पादक बनने की संभावना है?

a) असम

b) महाराष्ट्र

c) गुजरात

d) अरुणाचल प्रदेश

Q.35 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. LiDAR एक रिमोट सेंसिंग विधि है, जो पृथ्वी तक श्रेणियों को मापने के लिए एक स्पंदित लेजर के रूप में प्रकाश का उपयोग करती है।

2. यह पृथ्वी के आकार और उसकी सतह की विशेषताओं के बारे में सटीक, त्रि-आयामी जानकारी उत्पन्न करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/ हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.36 निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का एकमात्र देश है जो सभी पांच प्रमुख प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है?

a) भारत

b) चीन

c) जापान

d) यूएसए

Q.37 निम्नलिखित में से कौन दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी चट्टान वाली पहाड़ी हैं?

a) तिरुमाला हिल्स

b) अनंतगिरी हिल्स

c) पार्वती हिल्स

d) सुसुनिया हिल्स

Q.38 UDAN योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है?

a) नीति आयोग

b) नागरिक उड्डयन मंत्रालय

c) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

d) विदेश मंत्रालय

Q.39 कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स (CoS) की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के साथ की गई है?

a) बैंकिंग क्षेत्र में विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षण को मजबूत करना।

b) केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर पर्यवेक्षण को मजबूत करना।

c) ट्रेडिंग सेक्टर पर पर्यवेक्षण को मजबूत करना

d) आईएएस और आईएफएस अधिकारियों पर पर्यवेक्षण को मजबूत करना।

Q.40 खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक स्वायत्त निकाय है।

2. यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.41 नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह पूर्वोत्तर का एकमात्र उद्यम कोष है।

2. प्रारंभ में 1000 करोड़ के फण्ड के साथ इसकी शुरुआत हुई है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/ हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.42 सी-विजिलेंस 2021 निम्न में से किस देश के बीच चलाया जाएगा?

a) भारत और जापान

b) भारत और रूस

c) भारत और अफगानिस्तान

d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.43 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है?

a) विद्युत मंत्रालय

b) व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय

c) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

d) वित्त मंत्रालय

Q.44 बिहू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का फसल त्योहार है?

a) ओडिशा

b) तमिलनाडु

c) असम

d) पंजाब

Q.45 लेक चाड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की एक ताजा पानी की झील है?

a) पश्चिम अफ्रीका

b) उत्तरी अमेरिका

c) हिमालयी क्षेत्र

d) दक्षिण अफ्रीका

Q.46 प्रतिभूतियों और भारत के विनिमय बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था।

2. यह केवल निवेशकों की जरूरतों के लिए जिम्मेदार है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.47 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

a) कृषि मंत्रालय

b) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

c) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

d) उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय

Q.48 निम्न में से कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है?

a) ईरान

b) कतर

c) ओमान

d) इराक

Q.49 निम्न में से कौन सा वायुमंडल में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात को मजबूत करने का कारक नहीं है?

a) गर्म समुद्र की सतह का तापमान

b) कोरिओलिस बल ताकि कम दबाव विकसित किया जा सके

c) क्षोभमंडल के निचले से मध्यम स्तर तक उच्च आर्द्रता

d) क्षोभमंडल में बिजली की चमक

Q.50 भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा निम्नलिखित में से कहाँ से कहाँ तक के लिए प्रारंभ होगी?

a) चंडीगढ़ से हिसार

b) मुंबई से नागपुर

c) दिल्ली से लखनऊ

d) शिमला से मसूरी

Q.51 राष्ट्रीय नवाचार पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है?

a) नीति आयोग

b) सी.एस.आई.आर.

c) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन - भारत

d) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

Q.52 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

a) वित्त मंत्रालय

b) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

c) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

d) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

Q.53 धर्मशिव गुफाएं, हाल ही में खबरों में थी,यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं?

a) महाराष्ट्र

b) मध्य प्रदेश

c) राजस्थान

d) छत्तीसगढ़

Q.54 गावी गंगाधरेश्वर मंदिर स्थित है:

a) आंध्र प्रदेश

b) तेलंगाना

c) तमिलनाडु

d) कर्नाटक

Q.55 निम्नलिखित में से कौन सा लाल पांडा के लिए IUCN की स्थिती है:

a) लुप्तप्राय

b) गंभीर रूप से संकटग्रस्त

c) कमजोर

d) कम से कम चिंताजनक

Q.56 मुकुंदपुरा CM2 उल्कापात निम्नलिखित में से किस शहर में पाया गया था?

a) जयपुर

b) नागपुर

c) रांची

d) रायपुर

Q.57 कलारिपट्टू के बारे में गलत है?

a) इसकी उत्पत्ति केरल में हुई।

b) यह मार्शल आर्ट के सबसे पुराने रूपों में से एक है।

c) केवल पुरुषों को कला का अभ्यास करने की अनुमति है।

d) चिकित्सकों के पास आयुर्वेद और योग के ज्ञान को शामिल करने वाली उपचार तकनीकों का गहन ज्ञान है।

Q.58 हरिके वेटलैंड कहाँ स्थित है?

a) हिमाचल प्रदेश

b) पंजाब

c) जम्मू और कश्मीर

d) राजस्थान

Q.59 अनुभव मंतप भारत के निम्नलिखित में से किस दार्शनिक से सम्बंधित है?

a) भर्तृहरि

b) घोषा

c) याज्ञवल्क्य

d) बसवेश्वरा

Q.60 विस्टाडोम कोच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इन कोचों में 360 डिग्री घूमने लायक सीटें होंगी।

2. यह हाल ही में अहमदाबाद से केवडिया जनशताब्दी एक्सप्रेस में लगाया गया था।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.61 माउंट सेमरू हाल ही में खबरों में था। यह कहाँ स्थित हैं?

a) सिंगापुर

b) जापान

c) वियतनाम

d) इंडोनेशिया

Q.62 दक्षिणी दोलन (Southern Oscillation) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) एल नीनो

b) जेट स्ट्रीम

c) दक्षिण-पश्चिम मानसून

d) पश्चिमी विक्षोभ

Q.63 व्यायाम डेजर्ट नाइट -21 निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है?

a) फ्रांस और चीन

b) भारत और फ्रांस

c) रूस और पाकिस्तान

d) यूएसए और भारत

Q.64 भारत इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था?

a) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

b) एनआईटीआईयोग

c) वाणिज्य मंत्रालय

d) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF) - भारत

Q.65 ड्रैगन फल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह केवल वियतनाम के लिए स्थानिक है।

2. यह सभी प्रकार की मृदा में उगता है।

3. इसमें बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है / हैं?

a) केवल 1 और 3

b) केवल 3

c) केवल 1 और 2

d) केवल 2

Q.66 समुद्री व्यायाम SITMEX निम्नलिखित देशों में से किसके बीच आयोजित किया जाता है?

a) सिंगापुर और थाईलैंड

b) सिंगापुर, थाईलैंड और भारत

c) सिंगापुर और भारत

d) थाईलैंड और भारत

Q.67 ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ निम्नलिखित में से कौन-सी हैं?

1. तीस्ता

2. लोहित

3. सुबनसिरी

4. मानस

सही कोड का चयन करें

a) केवल 1 और 3

b) केवल 2

c) केवल 2, 3 और 4

d) 1, 2, 3 और 4

Q.68 पाट काई के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है?

1. पटकाई बम

2. गारो-खासी-जयंतिया पहाड़ियाँ

3. लुशाई हिल्स

सही कोड का चयन करें

a) केवल 2

b) केवल 1 और 3

c) केवल 1 और 2

d) 1, 2 और 3

Q.69 देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है?

a) वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय

b) सीमा सड़क संगठन

c) नीती अयोग

d) सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

Q.70 युद्धअभ्यास कवच निम्नलिखित में से किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है?

a) भारतीय और ब्रिटिश सेना

b) भारतीय सेना और भारतीय नौसेना

c) भारत और चीनी वायु सेना

d) भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय तटरक्षक

Q.71 रिसा निम्नलिखित में से किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक प्रथागत हाथ का कपड़ा है?

a) झारखंड

b) ओडिशा

c) असम

d) त्रिपुरा

Q.72 वैकोम सत्याग्रह निम्नलिखित में से किसके खिलाफ शुरू किया गया था?

a) अस्पृश्यता

b) सती

c) महिलाओं की शिक्षा

d) भारतीय कारीगरों का आर्थिक पतन

Q.73 भारत की पहली समाधान खनन परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू होगी?

a) राजस्थान

b) गुजरात

c) महाराष्ट्र

d) मध्यप्रदेश

Q.74 पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है?

a) केरल

b) तमिलनाडु

c) कर्नाटक

d) आंध्र प्रदेश

Q.75 पहला अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकी मॉडल जो अपशिष्ट जल को शुद्ध करता है हाल ही में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए इसका अनावरण किया गया था?

a) खेती

b) ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उद्देश्य

c) कागज बनाने के लिए लकड़ी का प्रसंस्करण

d) ऑटोमोबाइल के लिए स्टील का उत्पादन करने में

Q.76 भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है?

a) दक्षिण गंगोत्री

b) मैत्री

c) भारती

d) हिमाद्री

Q.77 बोडो जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?

a) असम

b) मेघालय

c) झारखंड

d) मणिपुर

Q.78 ग्रीन बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह आम तौर पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कर प्रोत्साहन के साथ आता है।

2. पहला आधिकारिक ग्रीन बांड 2009 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया था।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.79 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

सागर	सीमावर्ती देश
1. एड्रियाटिक सागर	अल्बानिया
2. काला सागर	क्रोएशिया
3. कैस्पियन सागर	कजाकिस्तान
4. भूमध्य सागर	मोरक्को
5. लाल सागर	सीरिया

ऊपर दिये गये युग्म में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है?

a) केवल 1, 2 और 4

b) केवल 1, 3 और 4

c) केवल 2 और 5

d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q.80 इलेक्ट्रिक वाहनों के निम्नलिखित लाभों पर विचार करें:

1. उत्सर्जन में कमी

2. कम दीर्घकालिक रखरखाव लागत

3. रिचार्जेबल बैटरी की असीमित जीवन प्रत्याशा

4. पैसे बचाता है

उपरोक्त में से कौन सही है या सही है?

a) केवल 3 और 4

b) केवल 1, 2 और 4

c) केवल 3 और 4

d) केवल 1

Q.81 निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर-सरकारी वार्ता ढांचे का हिस्सा है

1. अरब लीग

2. कैरिबियन समुदाय

3. सर्वसम्मति समूह के लिए एकजुट होना

4. G 4 राष्ट्र

5. एशियाई

6. ब्रिक्स

सही कोड का चयन करें

a) केवल 1, 4, 5 और 6

b) केवल 1, 2, 3 और 4

c) केवल 5 और 6

d) केवल 3, 5 और 6

Q.82 धनीपुर मस्जिद हाल ही में खबरों में थी। इसका निर्माण कहां होने जा रहा है?

a) उत्तर प्रदेश

b) असम

c) दिल्ली

d) नागपुर

Q.83 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है।

2. सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.84 विश्व आर्थिक मंच स्थित है?

a) स्विट्जरलैंड

b) फ्रांस

c) नीदरलैंड

d) ऑस्ट्रिया

Q.85 भविष्य निवेश पहल फोरम की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जाती है?

a) इज़राइल

b) यूएसए

c) रूस

d) सऊदी अरब

Q.86 भारत में कछुए की कौन सी प्रजाति पायी जाती हैं?

1. ओलिव रिडले

2. हरा कछुआ

3. लकड़हारा

4. हॉक्सबिल

5. लेदर बैक

सही कोड का चयन करें:

a) केवल 1 और 3

b) केवल 3, 4 और 5

c) केवल 1, 2 और 3

d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q.87 हाल ही में, पर्यावरण का इंडो-फ्रेंच वर्ष शुरू किया गया था। उसी के तहत शामिल विषयों पर विचार करें:

1. पर्यावरण संरक्षण

2. जलवायु परिवर्तन

3. जैव विविधता संरक्षण

4. सतत ग्रामीण विकास

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है / हैं?

a) केवल 1, 2 और 3

b) केवल 2 और 4

c) केवल 1 और 3

d) केवल 1

Q.88 कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?

a) विश्व आर्थिक मंच

b) विश्व बैंक

c) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

d) यूनेस्को

Q.89 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी?

a) एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग

b) इस्लामिक सहयोग संगठन

c) दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ

d) आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन

Q.90 निम्न में से कौन सा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों में शामिल नहीं है?

a) डेंगू

b) रेबीज

c) ट्रेकोमा

d) एड्स

Q.91 निम्नलिखित में से कौन गलत है?

a) छात्रों और शिक्षकों के लिए शिक्षा के लिए बहु-मोड और न्यायसंगत पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट करने के लिए एक व्यापक पहल है।

b) SWAYAM जो एक स्वदेशी रूप से विकसित MOOCs (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स) प्लेटफॉर्म है।

c) MANODARPAN पहल छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करती है।

d) स्कूलों में लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए PRAGYATA दिशानिर्देश लॉन्च किए गए थे।

Q.92 बुनियादी आवश्यकता सूचकांक (BNI) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2012 की तुलना में 2018 में अधिकांश राज्यों में पीने के पानी की पहुंच में सुधार हुआ है।

2. 2012 की तुलना में शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण और ओडिशा और असम को छोड़कर 2018 में सभी राज्यों के लिए सूक्ष्म वातावरण में सुधार है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है / हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही

January 2021 महीने के करेंट अफेयर्स MCQs की उत्तरकुंजी

1	B	39	A	77	A
2	A	40	B	78	A
3	A	41	A	79	B
4	D	42	D	80	B
5	D	43	A	81	B
6	B	44	C	82	A
7	D	45	A	83	A
8	D	46	A	84	A
9	A	47	B	85	D
10	D	48	D	86	D
11	C	49	D	87	A
12	A	50	A	88	A
13	A	51	C	89	D
14	D	52	D	90	D
15	B	53	A	91	D
16	D	54	D	92	C
17	A	55	A		
18	A	56	A		
19	B	57	C		
20	D	58	B		
21	A	59	D		
22	D	60	B		
23	A	61	D		
24	C	62	A		
25	C	63	B		
26	D	64	B		
27	D	65	D		
28	A	66	B		
29	D	67	D		
30	A	68	D		
31	D	69	D		
32	A	70	D		
33	C	71	D		
34	D	72	A		
35	C	73	A		
36	A	74	A		
37	A	75	A		
38	B	76	D		

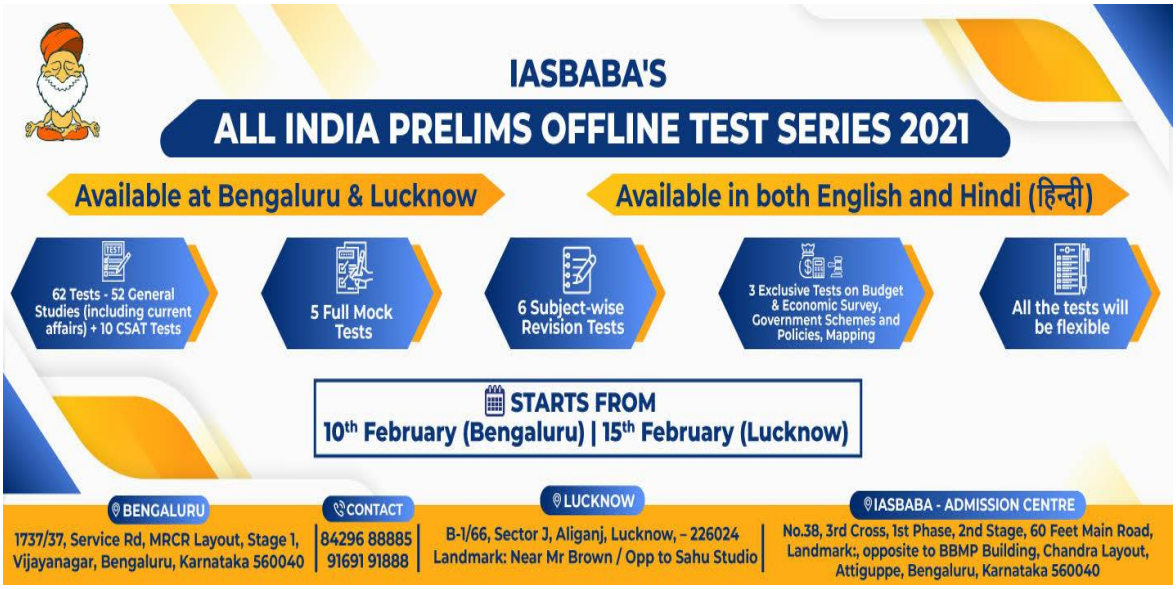
IASBABA'S
ALL INDIA PRELIMS OFFLINE TEST SERIES 2021
Available at Bengaluru & Lucknow
Available in both English and Hindi (हिन्दी)
62 Tests - 52 General Studies (including current affairs) + 10 CSAT Tests
5 Full Mock Tests
6 Subject-wise Revision Tests
3 Exclusive Tests on Budget & Economic Survey, Government Schemes and Policies, Mapping
All the tests will be flexible
STARTS FROM
10th February (Bengaluru) | 15th February (Lucknow)
BENGALURU
1737/37, Service Rd, MRCR Layout, Stage 1, Vijayanagar, Bengaluru, Karnataka 560040
CONTACT
84296 88885
91691 91888
LUCKNOW
B-1/66, Sector J, Aliganj, Lucknow, – 226024
Landmark: Near Mr Brown / Opp to Sahu Studio
IASBABA - ADMISSION CENTRE
No.38, 3rd Cross, 1st Phase, 2nd Stage, 60 Feet Main Road, Landmark:, opposite to BBMP Building, Chandra Layout, Attiguppe, Bengaluru, Karnataka 560040